बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 3

एक स्थिर बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर निकासी की पाबंदी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस निर्णय ने एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि बैंकों की अक्षमता और कुप्रबंधन के कारण लोगों को किस प्रकार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में जमा राशि पर ही तमाम लोगों का जीवन निर्भर करता है। इस बात को लेकर भी बहस चल रही है कि क्या भारत को अभी भी सहकारी बैंकों की आवश्यकता है, क्योंकि तकनीक की बदौलत वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच का बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। एक अन्य संबद्ध क्षेत्र जिस पर बहस करना उपयुक्त होगा वह यह है कि क्या ऐसे मामले में लोगों को ही मुसीबत झेलनी चाहिए जबकि यह अपर्याप्त नियामकीय निगरानी और संबंधित बैंक के कुप्रबंधन का नतीजा होता है। इस मामले में जमाकर्ताओं को बचाने के लिए पांच लाख रुपये तक की जमा राशि जमा बीमा एवं ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा गारंटीड होती है। बहरहाल, जैसा कि मंगलवार को इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया, केवल लगभग 43.1 फीसदी पहुंचयोग्य जमा ही बीमित है। खबर है कि सरकार बीमा की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

सरकार जहां इस विषय में जल्दी से जल्दी फैसला करके सही करेगी, वहीं कई ऐसे संबद्ध मुद्दे भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। बैंकों का कारोबार आपसी विश्वास पर निर्भर रहता है क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट में अस्थिरता अंतर्निहित होती है। जमा के मामले में अक्सर बैंकों की देनदारी अल्पकालिक होती है और वे अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए ऋण जारी करते हैं। इससे परिसंपत्ति और देनदारी में अंतर पैदा हो जाता है। जहां जमाकर्ता आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं, वहीं बैंक अपने ऋण को आसानी से वापस नहीं ले सकते। तकनीक को अपनाने के बाद प्रबंधन और अधिक जटिल हो गया है। जमाकर्ता अपनी जमा राशि को तत्काल बिना बैंक शाखा गए एक खाते से दूसरे खाते में डाल सकते हैं। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि बैंकों को हर समय स्वस्थ और स्थिरता वाला माना जाए। यहां तक कि एक अफवाह भी बैंक के पतन का कारण बन सकती है। इससे घबराहट का माहौल बनता है जो अन्य बैंकों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका में 2023 में ऐसा हो चुका है। इसकी शुरुआत सिलिकन वैली बैंक के साथ हुई थी। भरोसे का संकट समूचे बैंकिंग तंत्र को ध्वस्त कर सकता है, इसका असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर होगा।

यही वजह है कि बैंकों का सही नियमन किया जाना चाहिए। बहरहाल, गड़बड़ियों की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अंशधारक भी अच्छे प्रदर्शन का दबाव बनाते हैं। ऐसे में तैयार रहना जरूरी है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे जोखिम हैं बल्कि इसका मकसद स्थिरता प्रदान करना है। ऐसे में यह भी महत्त्वपूर्ण है कि अधिकांश बैंक जमा का बीमा हो। इसकी शुरुआत सभी व्यक्तिगत खातों का बीमा कवर बढ़ाकर की जा सकती है। एक साधारण जमाकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह निरंतर बैंक की स्थिति का आकलन करेगा। यह नियामक का काम है और इसे नियामक को ही अंजाम देना चाहिए। बैंक खाता नागरिकों की बुनियादी जरूरत है और राज्य को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

यकीनन इसके साथ संबद्ध लागत भी होगी। यह लागत जमाकर्ताओं, बैंकों और सरकार के बीच साझा की जा सकती है क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था की स्थिरता अर्थव्यवस्था के सहज काम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। अगर जमाकर्ता को पता होगा कि उसकी राशि सुरक्षित है तो वे पैसे निकालने की हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। अमेरिका में सिलिकन वैली बैंक संकट में बीमा का विस्तार हर जमा तक किया गया जिससे बड़ा बैंकिंग संकट टाला जा सका। भारत में बीमा कवरेज बढ़ाने से सरकारी और निजी बैंकों के बीच समान अवसर बन सकेंगे। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा की ऐसी गारंटी से बैंक प्रबंधनों में जोखिम की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे व्यवस्था और संकट में पड़ जाएगी। बहरहाल यह सुनिश्चित करना नियामक का काम है कि जोखिम का भलीभांति प्रबंधन हो। यह ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि सुरक्षा का दायरा केवल बैंक जमा तक बढ़ाया जाना चाहिए, न कि उन सभी वित्तीय योजनाओं तक जिनका चयन लोग उच्च रिटर्न के लिए करते हैं।

कैसे चलाएं चरणबद्ध विनियमन परियोजना

प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक नियमन के मामले में विनियमन परियोजनाओं को तीन प्रश्नों का जवाब अवश्य तलाश करना चाहिए। बता रहे हैं अजय शाह

लोगों के जीवन में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर अनेक चिंताएं हैं। बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक उच्चस्तरीय समिति की घोषणा की जो गैर वित्तीय क्षेत्र में विनियमन की पड़ताल करेगी और वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद में एक कार्यक्रम तैयार करेगी ताकि वित्तीय क्षेत्र को लेकर भी ऐसा ही किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उस समय नई रोशनी डाली जब उन्होंने कहा, 'जिस तरह कुछ भी निःशुल्क नहीं होता उसी तरह उपभोक्ता संरक्षण और स्थिरता बढ़ाने वाले नियमन भी बिना कीमत के नहीं होते। स्थिरता और किफायत के बीच एक किस्म का समझौता होता है।' यूनाइटेड किंगडम में एक नए 'नियामकीय नवाचार कार्यालय' को लेकर आशावाद है। अमेरिका में एक नए 'सरकारी किफायत विभाग' को लेकर बहुत अधिक उम्मीद नहीं है।

नियमन को लेकर दलील लागत और लाभ की तुलना की बात करती है। पूर्ण स्वतंत्रता लोगों को यह इजाजत देती है कि वे आर्थिक किफायत हासिल कर सकें। बदले में यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि तैयार करती है। ऐसा नवाचार और कंपनियों की उचित डिजाइनिंग की मदद से किया जाता है। सरकार का हर हस्तक्षेप आर्थिक किफायत को कम करता है और जीडीपी वृद्धि पर असर डालता है। सरकार का हस्तक्षेप केवल तब उचित है जब नियामकीय अनुपालन से होने वाले सामाजिक लाभ सामाजिक लागत से अधिक हों।

विशुद्ध आर्थिक स्वायत्तता का माहौल बाजार की कुछ नाकामी से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए बाजार की शक्ति, बाह्य कारक, विसंगतिपूर्ण सूचना आदि के चलते। बेहतर नियमन वह होता है जो बाजार की नाकामियों को दूर करे किंतु जिसके अनचाहे परिणाम न हों और जो समाज पर न्यूनतम लागत आरोपित करे। यानी यह बाजार की नाकामी दूर करने को लेकर स्वीकार्य नतीजे पेश करे जबकि इस दौरान आर्थिक किफायत, नवाचार और जीडीपी वृद्धि पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव डाले। भारत में राज्य की क्षमता सीमित है। ऐसे में अक्सर समझदारी यह होती है कि आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले खराब हस्तक्षेप के बजाय बाजार विफलता को ही कुछ हद तक झेल लिया जाए।

वास्तविक दुनिया की सरकारों को सार्वजनिक चयन का सिद्धांत आकार देता है। यानी अधिकारी और राजनेता प्रोत्साहन को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। राज्य के कर्मचारियों के पास आम लोगों के विरुद्ध बहुत अधिक दमनकारी शक्तियां होती हैं। ऐसे में सरकार के हस्तक्षेप का अक्सर बाजार की नाकामी से कोई रिश्ता नहीं होता। यही समझ इस बात को रेखांकित करती है कि वह चरणबद्ध ढंग से विनियामकीय परियोजनाओं का इस्तेमाल करे। राज्य के हस्तक्षेप के हर मामले में विनियामकीय परियोजना को निम्न चरणों से गुजरना चाहिए।

पहला प्रश्नः हस्तक्षेप की जरूरत ही क्यों पड़ी?

हर हस्तक्षेप के दस्तावेजों में उद्देश्य दर्शाना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि यह उद्देश्य बाजार की नाकामी पर आधारित है। जब किसी हस्तक्षेप का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता है तो उसे तुरंत बदलना सही होता है। मिसाल के तौर पर, वर्तमान भुगतान कानून की स्पष्ट प्रस्तावना के मुताबिक कानून का उद्देश्य आरबीआई को भुगतान के व्यवसाय को विनियमित करना है। इस उद्देश्य का बाजार की नाकामी से कोई लेना-देना नहीं है।

जब कोई हस्तक्षेप उस बाजार विफलता के बारे में दावा करता है जिसे वह हल करना चाहता है तो इनका पूरी आशंका के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए। सरकार के कामकाज में काफी हद तक प्रलोभन और छल कपट शामिल होता हैः केरल में हस्तक्षेप के लिए तिब्बत के एक शैतान को दिखाया जाता है। ऐसे में आलोचनात्मक विचार की आवश्यकता है ताकि हस्तक्षेप के बारे में दस्तावेजों को पढ़ें और कथ्य से संबंधित कानूनी उपायों के बारे में विचार करें।

दो बातों को परखेंः पहली, क्या हस्तक्षेप डिजाइन करते समय ही उद्देश्य बताया गया था और दूसरा क्या उद्देश्य, बाजार विफलता को हल करता है। ऐसा करने से चीजें बहुत सुसंगत हो जाएंगी।

दूसरा प्रश्नः क्या यह कारगर साबित हुआ?

जो नियमन पहले सवाल से उबर सके वे ऐसे नियम थे जिनको अतीत में पेश किया गया था, ये बाजार की विफलता से प्रेरित थे और इनका उद्देश्य स्पष्ट था। अब हमें पूछना चाहिएः क्या हस्तक्षेप कारगर रहा? क्या उद्देश्य प्राप्त हुए? कई हस्तक्षेप नाकाम रहते हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए। लोक नीति में अच्छे इरादों की कोई खास भूमिका नहीं। जो बात मायने रखती है वह है चीजों को हल करना।

तीसरा प्रश्नः क्या लागत लाभ से अधिक रही?

सरकारी हस्तक्षेप निजी लोगों के भाग लेने की संभावना कम करता है। प्रतिक्रिया स्वरूप वे कम नवाचार अपनाते हैं और निवेश भी कम करते हैं। परियोजनाओं का नियमन समाप्त करने का तीसरा चरण है सफल हस्तक्षेपों पर शंकालु ढंग से दृष्टि डाली जाती है। हां, ठीक है नियमन सही रहा लेकिन किस कीमत पर? न्यूनतम इक्विटी पूंजी की जरूरतें लागू करने वाले विनियमन के साथ छोटी फर्मों के प्रवेश को रोकने और प्रतिस्पर्धा को कम करने की लागत आती है। ऐसा विनियमन जो निजी लोगों को जमीन बरबाद करने पर विवश करता है, वह कंपनियों द्वारा आवश्यक पूंजी को बढ़ाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा वह जमीन के उपयोग में आर्थिक कुशलता को भी बाधित करता है।

अनुपालन की प्रत्यक्ष लागत भी होती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निजी लोगों के नवाचार, रचनात्मकता और निवेश पर अदृश्य नकारात्मक प्रभाव होता है। सीमा में देखें तो भारत की केंद्रीय नियोजन व्यवस्था समूचे निजी क्षेत्र को सार्वजनिक उपक्रमों की तरह व्यवहार करने पर विवश करती है जहां सभी अहम निर्णय सरकार लेती है। निजी बैंकों के उत्पादों और प्रक्रियाओं पर भी सरकारी बैंकों की तरह काफी हद तक रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। नवाचार, वृद्धि और गतिशीलता के रूप में अधिक लागत थोपने वाला नियमन बदला जाना चाहिए।

यह महत्त्वपूर्ण है कि हम कानून में लिखी बातों के परे और इस बात पर ध्यान दें कि हस्तक्षेप किस तरह काम करते हैं। जब शक्ति भारतीय राज्य के पास केंद्रित हो जाती है तो इनका संपर्क विधि के शासन की कमी से होता है। देश के शक्तिशाली सरकारी संस्थानों के पास मनमानी ताकत होती है। विनियमन के एजेंडे के अलावा विधि के शासन में सुधार भी समस्या को हल करने में मददगार साबित हो सकता है।

यह विश्लेषण दिखाता है कि चरणबद्ध विनियमन परियोजना कैसे संचालित की जानी चाहिए और क्यों आमतौर पर इनका प्रदर्शन कमजोर रहता है? किसी एक क्षेत्र में सिद्धहस्त होकर ऐसी टीम बनाना मुश्किल काम है जिसमें उपरोक्त तीन सवालों को हल करने की बौद्धिक क्षमता हो और सरकारी संस्थानों को चुनौती देने की भी।

इसके अलावा इनमें से कोई भी हल बुनियादी कारण को हल नहीं करता क्योंकि राज्य के ढांचे में समस्या है जिसके चलते वह निरंतर नए हस्तक्षेप भी कर रहा है। ऐसे नए नुकसान चरणबद्ध विनियामकीय परियोजनाओं की संभावनाओं को दबा देता है। आवश्यकता यह है कि मूल कारण का विश्लेषण करने की जो नियामकों के काम करने के तरीके को बदल देगा। भारत में विनियामक क्षेत्र सिद्धांत को पता है कि यह कैसे करना है।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

मीडिया : आंकड़ों पर टिका विज्ञापन का खेल

भारतीय अखबारों के कारोबार का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। दैनिक भास्कर और अन्य ब्रांडों की प्रकाशक कंपनी डी बी कॉर्प ने मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में 2,482 करोड़ रुपये के राजस्व पर 703 करोड़ रुपये का एबिटा (ब्याज, कर, मूल्यह्रास से पहले की कमाई) दर्ज किया। यह एक ऐसे कारोबार का 28 फीसदी सकल मार्जिन है जिसमें दुनिया के अधिकांश हिस्से में कमी आ रही है।

डीबी कॉर्प की तरह ही अन्य अखबार प्रकाशकों के लिए भी पिछले कुछ साल अच्छे रहे हैं और इसकी वजह न्यूजप्रिंट की कम होती कीमतें और विज्ञापन की बढ़ती आमदनी है।

यह बात बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। पिछला भारतीय पाठक सर्वेक्षण 2019 में किया गया था। अब पांच साल से पाठकों का कोई डेटा नहीं है। बेची जाने वाली प्रतियों या उसके प्रसार का डेटा अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि प्रकाशक सर्वेक्षणों का सहारा लेते रहते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस संस्करण के लिए या किस बाजार में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और कहां अपनी उपस्थिति कम करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन देने के लिए अखबारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? यदि कोई मापदंड नहीं है तो वे किस आधार पर अखबारों में विज्ञापन देने के लिए खर्च कर रहे हैं? इस लेख का यही मुख्य बिंदु है।

जो अखबारों के लिए सच है वही थोड़े अलग मायने में टेलीविजन, डिजिटल, रेडियो और अन्य मीडिया के लिए भी सच है। तकरीबन 2.3 लाख करोड़ रुपये मूल्य वाले भारतीय मीडिया और मनोरंजन कारोबार में विज्ञापनदाता, मीडिया खरीदार और विश्लेषक हवा में तीर मारकर काम कर रहे हैं।

वर्ष 2022 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) को मीडिया के साथ कोई भी डेटा साझा करने से मना कर दिया गया था। इसके सबस्क्राइबर जैसे कि प्रसारणकर्ता, विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां डेटा हासिल करती हैं।

इसकी वेबसाइट पर भी कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं लेकिन यदि आप विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं या श्रेणी के आधार पर रुझान का विश्लेषण करना चाहते हैं तब यह और कठिन हो जाता है। वर्ष 2023 में 69,600 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ टेलीविजन ही मीडिया एवं मनोरंजन कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा दिखा।

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हममें से अधिकांश लोग अपनी जरूरत के मुताबिक अपने किसी दोस्ताना मीडिया एजेंसियों से आंकड़े हासिल करते हैं लेकिन यह इतने बड़े कारोबार का विश्लेषण करने का एक टिकाऊ तरीका नहीं है।

अगर आप सोचते हैं कि डिजिटल मीडिया सबसे अच्छा है तो इस पर दोबारा सोचिए। कई सालों से बार्क कोशिश कर रहा था कि विभिन्न मीडिया माध्यमों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक ऐसा पैमाना बनाया जाए जिससे उदाहरण के तौर पर यह पता चल सके कि स्टार प्लस को कितने लोग टीवी पर और ऑनलाइन, डिज्नी+हॉटस्टार, यूट्यूब आदि पर देखते हैं। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि इससे जुड़े विभिन्न पक्ष आपस में सहमति नहीं बना पाए।

वहीं दूसरी तरफ डिजिटल के लिए कॉमस्कोर, नीलसन, ऐप एनी, सिमिलर वेब और दूसरी कंपनियां हैं। लेकिन कई बड़े ऐप और वेबसाइट थर्ड-पार्टी की पैमाइश की अनुमति नहीं देते। अगर आप शीर्ष10 स्ट्रीमिंग ब्रांड की ऐसी सूची कोई पाना चाहे जिस पर सब सहमत हों और इसको लेकर कोई विरोध ना हो तो यह नामुमकिन है। विज्ञापन देने वाली कंपनियां अमूमन, गूगल (यूट्यूब) और मेटा (फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम) के आंकड़े को मान लेती हैं। ऑनलाइन जिसे सबसे अधिक पारदर्शी माध्यम माना जाता है वह दरअसल आंकड़ों की एक अंधेरी सुरंग है।

यह दिलचस्प है कि अखबार पढ़ने वाले प्रत्येक हजार लोगों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन देने वाली कंपनियां ऑनलाइन के मुकाबले छह गुना अधिक पैसे का भुगतान करती हैं। मीडिया एजेंसी लोडेस्टार यूएम के आंकड़े के मुताबिक टीवी पर वे डिजिटल की तुलना में चार गुना ज्यादा पैसे (जनवरी 2024 तक) का भुगतान करती हैं। बिना किसी उपयुक्त थर्ड-पार्टी के मापदंड के क्या डिजिटल, प्रिंट या टीवी के बराबर विज्ञापन दरें पा सकता है, भले ही उसकी पहुंच का दायरा या कमाई उनसे ज्यादा क्यों ना हो? हालांकि अभी प्रिंट के पास भले ही कोई पैमाना न हो लेकिन ज्यादातर खर्च पिछले आंकड़ों और उनके अनुमानों पर आधारित होता है।

अखबार के प्रकाशक, पाठकों की डेटा की कमी के बावजूद आशावादी हैं। उनका मानना है कि अगर गूगल या मेटा को अपने आंकड़ों को प्रमाणित करने या ऑडिट करने के लिए नहीं कहा जाता तब आखिर अखबार के प्रकाशकों के लिए ऐसा क्यों कहना चाहिए।

इसके अलावा कई बड़े अखबारों जैसे कि मलयाला मनोरमा या दैनिक भास्कर जैसे कई बड़े अखबारों की विज्ञापन राजस्व का तीन-चौथाई हिस्सा उन शहरों और कस्बों के स्थानीय खुदरा कारोबारियों से मिलता है जहां अखबार की बिक्री होती है। रिटेलर इसलिए विज्ञापन देते हैं क्योंकि उन्हें उसी दिन विज्ञापन पर प्रतिक्रिया मिल जाती है। आमतौर पर शहर के दो शीर्ष अखबार ही सबसे बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं।

एक दशक से भी पहले, अखबारों के ज्यादातर विज्ञापन 'राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापनदाताओं' से मिलते थे जो अपनी पहुंच पूरे देश में बनाना चाहते थे। कई मायनों में, आंकड़ों के मापदंड की कमी ने अखबारों को डिजिटल की तरह बना दिया है जिसमें प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ ही स्थानीय विज्ञापन के साधनों पर जोर दिया जाता है।

आंकड़ों की कमी, होम डिलिवरी और कम कीमत मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय अखबार एक बेहतर कारोबार बना रहे भले ही अमेरिकी बाजार दो दशक पहले के अपने कारोबार की तुलना में आधे से भी कम आकार का हो गया।

इन आंकड़ों की कमी का टीवी पर ज्यादा असर पड़ा है। अगर बार्क का कोई मिश्रित पैमाना होता तब आपको अंदाजा मिलता है कि भारतीय दर्शक जो स्ट्रीमिंग पर देखते हैं उनमें से आधे से अधिक कैचअप टीवी यानी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो टीवी पर पहले प्रसारित हो चुके हैं और उन्हें ही दोबारा स्ट्रीमिंग माध्यमों के जरिये देखा जाता है। यह भी अंदाजा मिलता है कि मुख्यधारा की फिल्मों को स्ट्रीमिंग के दर्शक खूब देखते हैं। लेकिन ये पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिससे टेलीविजन की कमाई के नुकसान को कुछ हद तक रोका जा सके।

परंपरागत तौर पर मीडिया को मापने के तरीके को भारत में गंभीरता से लिया गया है। अखबार कितने लोग पढ़ते हैं इसका सर्वेक्षण 1974 में शुरू हुआ। टीवी की रेटिंग की माप के लिए कि लोग क्या देख रहे हैं, उसके लिए डायरी में लिखने का तरीका 1983 में शुरू हुआ। इसके बाद 1991 में टैम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग की परंपरा शुरू हुई। इसका अर्थ यह था कि विज्ञापनदाता यह देख सकते थे कि किस माध्यम में अधिक वृद्धि हो रही है और वे इसमें निवेश कर सकते थे। जो प्रोग्राम बना रहे थे उन्हें भी पता चल जाता था कि क्या लोकप्रिय हो रहा है और क्या नहीं चल सकता है। अब यह सब काफी अस्पष्ट हो गया है। इसके अलावा एक और परेशानी यह है कि भारत की जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई है। मीडिया शोध से जुड़े जितने भी आंकड़े दिखाए जाते हैं वे सभी 2011 के जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं। 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई। इसलिए मीडिया में जो विज्ञापन खर्च हो रहा है वह अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है।

शायद अखबारों के प्रकाशक भी सही हैं कि अगर बड़े मंच और विज्ञापनदाता डेटा की परवाह नहीं करते हैं तब आखिर प्रकाशकों को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए?

आपका पक्ष

भीड़ और भगदड़ रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल हो

रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ और भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार देश भर के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग जोन बनाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ से सबक लेते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत, यात्रियों को स्टेशन में अनावश्यक भीड़ से बचाने के लिए स्थायी और अस्थायी इंतजाम किए जाएंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी, जिससे किसी भी संकट की स्थिति में त्वरित तथा सटीक निर्णय लिए जा सके। रेलवे ने भीड़ पर नियंत्रण के लिए और कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक शामिल है। इससे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ कम होगी और केवल यात्रियों को ही प्रवेश मिलेगा। यह कदम रेलवे के इतिहास में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की दिशा में एक नई क्रांति लाएगा।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए पटना रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को ट्रेन पर सवार होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी

दिल्ली चुनावः रेवड़ी वादों का रहा असर

दिल्ली चुनाव में रेवड़ी संस्कृति का बड़ा प्रभाव रहा। राजनीतिक दलों ने लोकलुभावन घोषणाएं की। लेकिन भरोसेमंद नेतृत्व और डबल इंजन सरकार ने जनता को अधिक प्रभावित किया। देखा जाए तो प्रभावी रेवड़ी ने ही भाजपा को जीत दिलाई। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दंभ और झूठे दावों के आरोप भारी पड़े। यमुना जल विवाद से विश्वास कमजोर हुआ। इन सब वजहों से आप सत्ताच्युत हुई और भाजपा को जीत मिली।

अमृतलाल मारू, इंदौर

भाजपा का वनवास खत्म, अब वादे पूरे करने की बारी

केजरीवाल ने जीत के लिए काफी प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह की जोड़ी ने जोरदार प्रचार करके 27 साल के भाजपा के वनवास को खत्म किया। अब भाजपा के लिए किए हुए वादों को पूरा करना व पिछली सरकार की सभी योजनाओं को चालू रखना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आम जनता ने बड़े ही विश्वास से भाजपा को वोट किया और अब केंद्र व राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में किसी भी प्रकार की योजना व विकास में रुकावट नहीं आना चाहिए।

अवधेश मंगल, मुरैना

भ्रष्टाचार मुक्त का दंभ भरने वालों को दिखाया आईना

भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का झूठा दम्भ भरने वाली आम आदकी पार्टी को लोगों ने आईना दिखा दिया। सत्ता के लिए लोक सभा चुनाव में विपक्षी दल एक होकर लड़े और विधान सभा चुनाव में अलग-अलग। यह दोहरा रवैया केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को ले डूबा। मोदी की गारंटी के साथ भाजपा ने हिंदुत्व और विकास के नाम पर वोट जुटाए। भाजपा के सामने अब चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है, तो वहीं आप के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, उनके नीतिकारों को अपनी विचारधारा और नेतृत्व पर चिंतन की जरूरत है।

मोहित सोनी कुक्षी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते कानून और व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते।
नि:स्पृह: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।।

भावार्थ : मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है।

विदेश में नौकरी

इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पंजाब में युवाओं को सुहाने सपने दिखाकर और मोटा पैसा लेकर अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगता यही है कि अमेरिका की ओर से अपने यहां अनुचित तरीके से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी रही है, उससे बचने के लिए ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले कई वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा भी नहीं है कि यह किसी से छिपा हो कि हमारे युवा अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यह बार-बार सामने आ रहा था कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में युवाओं को अवैध तरीकों से पश्चिमी देशों में भेजने वाले तथाकथित ट्रैवल एजेंट बेलगाम होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन न तो इन राज्यों की सरकारों ने उन पर कोई शिकंजा कसा और न ही केंद्र सरकार ने इसकी चिंता की कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगे। यदि अमेरिका अपने यहां अवैध तरीके से घुसे लोगों को हथकड़ी-बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजता तो शायद अभी भी सरकारों की नींद टूटने वाली नहीं थी।

यह ठीक है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी का सिलसिला कायम होने के बाद केंद्र सरकार इसके उपाय करने जा रही है कि दूसरे देशों में नौकरी के इच्छुक युवा वहां जाने के लिए अवैध तौर-तरीके न अपनाएं, लेकिन सच तो यह है कि वह भी इस बारे में समय रहते सक्रिय नहीं हो सकी। अब तो उसे गंभीरता दिखानी ही चाहिए। देखना है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं को विधिवत विदेश भेजने और उनके वहां रोजगार के अवसर भुनाने में समर्थ बनने के लिए जो प्रयास करने जा रहा है, उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि तमाम संभावनाओं के बाद भी अभी तक इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। यह बार-बार सामने आता रहा है कि विदेश में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब हमारे दूतावास और उच्चायोग यह देखेंगे कि भारतीय युवाओं के लिए किस देश में रोजगार के कैसे मौके हैं? यह भी जतन करने होंगे कि हमारे युवा विदेश में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता-दक्षता से भी लैस हों।

सड़क पर बेजा शक्ति प्रदर्शन

प्रदेश में जन्मदिन मनाने के बहाने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की एक नई प्रवृत्ति का जन्म लेना चिंताजनक है। राहगीरों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों को किसी भी प्रकार का प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ युवा अल्प शक्ति प्रदर्शन के लिए इस तरह के कृत्य करके कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर चुका है। हाल ही में रायपुर में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उसके साथियों को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। यह घटना कोई अकेली नहीं है, पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें युवा सड़क पर केक काटने, आतिशबाजी करने और वाहनों पर जश्न मनाते हैं। सड़कें सार्वजनिक स्थान हैं, जहां लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह के अशोभनीय कृत्य न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं, बल्कि इनसे समाज में अव्यवस्था फैलती है।

> यह घटना कोई अकेली नहीं है, पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें युवा सड़क पर केक काटने, आतिशबाजी करने और वाहनों पर जश्न मनाते हैं।

पुलिस और प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को यह समझाना बेहद जरूरी है कि इस तरह के अवसरों पर वे अपने जश्न को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से मना सकते हैं। सड़क पर इस तरह का उल्लंघन दूसरों के अधिकारों का भी हनन है। युवाओं को अपनी ऊर्जा और उत्साह को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। उन्हें समाज के लिए रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे समाज का भला हो। सड़क पर इस तरह के अनावश्यक प्रदर्शनों से किसी को कोई फायदा नहीं होता। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की पहली जिम्मेदारी माता-पिता की है, वे अपने बच्चों को समझाएं। समाज और प्रशासन को भी आगे आकर युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। जिससे कि इस बेजा शक्ति प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सके।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

नईदुनिया जनमत — कल का परिणाम

क्या चीन पर सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है?

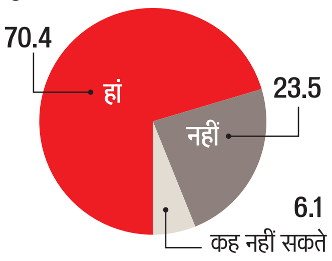

आज का सवाल
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में राहुल गांधी की आपत्ति उचित है?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता

आदित्य सिन्हा

भारत में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है, ताकि वह अर्थव्यवस्था की क्षमताएं बढ़ाने में सहायक हो

अमेरिका पर दुनिया भर के तमाम मामलों मे दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी हस्तक्षेप की बातें सामने आईं। भारत में भी चुनावों एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में बड़ी रकम दांव पर लगाने की बात सामने आई है। अपने ऐसे अभियानों को सफल बनाने से लिए अमेरिका को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह रकम मुख्य रूप से सरकारी खजाने से आती है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि इस सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के पक्ष में वहां तमाम आवाजें बुलंद हो रही हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन एलन मस्क की अगुआई में डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) यानी सरकारी दक्षता विभाग के जरिये बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। इसमें अनावश्यक नौकरशाही के आकार को घटाने से लेकर फिजूलखर्च रोकने के उपाय तलाशे जाएंगे। डीओजीई की इस पहल ने दुनिया भर में सरकारी मशीनरी के दायरे को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत भी ऐसे सवालों से अछूता नहीं है, लेकिन अगर इस पर गहराई से विचार करें तो क्या भारत में सरकारी खर्च को घटाया जाना आवश्यक है? इसका जवाब है-नहीं। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। अगर वर्ष 2022 के दौरान भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो यह जीडीपी का 28.62 प्रतिशत रहा। यह चीन (33.4 प्रतिशत), ब्राजील (46.38 प्रतिशत), अमेरिका (36.2 प्रतिशत) और फ्रांस (58.32 प्रतिशत) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। पूंजीगत व्यय में सड़क और राजमार्गों को ही लें तो उन पर किया जाने वाला खर्च बहुत गुणात्मक प्रभाव वाला होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सड़कों पर किया जाने वाला एक रुपये का खर्च समग्र अर्थव्यवस्था में ढाई रुपये के बराबर लाभ दिलाने वाला होता है। इससे कनेक्टिविटी की स्थिति सुधरती है। परिवहन लागत घटती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। हालांकि यह गुणात्मक प्रभाव पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाता है, क्योंकि यदि उसमें हीलाहवाली की जाती है तो फिर उसके अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से रहे। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बुनियादी ढांचे में न केवल मात्रात्मक, बल्कि गुणात्मक रूप से भी सुधार हो। इसके बावजूद, यह पूरी प्रक्रिया अभी प्रगति में ही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हों।

अवधेश राजपूत

डीओजीई को लेकर भारत के दृष्टिकोण से यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है कि नियामकीय स्तर पर सुगमता कैसे स्थापित की जाए। ये नियामकीय बाधाएं ही आर्थिक वृद्धि में अवरोध बनती हैं। भारत के मामले में तो यह कोई दबी-छिपी बात नहीं है। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार ने नियामकीय बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें सुसंगत बनाने के हरसंभव प्रयास किए हैं। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ी है, जो ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग में भी झलकती है। फिर भी इस दिशा में बहुत किया जाना अभी शेष है। इन्हीं प्रयासों को और विस्तार देते हुए सरकार ने जन विश्वास अधिनियम, 2023 पारित कराया है। इस कानून के जरिये कई पुरातन प्रविधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त किया गया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस विधेयक के नए स्वरूप को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य नियमन के पहलुओं को तार्किक बनाते हुए व्यापक कारोबार हितैषी परिवेश तैयार करना है। एक फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट में नियामकीय तालमेल बेहतर बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा भी हुई है। इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में नियामकीय सुगमता एवं आर्थिक सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पुनः रेखांकित भी किया। अब सभी की नजरें उच्चस्तरीय समिति पर टिकी हैं। इस समिति को आखिर क्या करना चाहिए? वैसे तो अभी तक न तो इस समिति का औपचारिक खाका सामने रखा गया है और न ही उसके स्वरूप एवं सदस्यों के विषय में कुछ बताया गया है। ऐसे में, उसके लिए कुछ बिंदुओं को सामने रखना उपयोगी होगा कि उसे किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समिति को किस्तों में सुधार के बजाय निरंतर रूप से साहसिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो उसे नियामकीय मोर्चे पर कायम विसंगतियों एवं विरोधाभासों को दूर करना होगा। ऐसे कानून बनाने होंगे जो उद्यमों के अनुकूल हों। दांडिक प्रविधानों को सीमित करना होगा। संसदीय गतिरोधों का तोड़ निकालकर प्रक्रियाओं को गति देने वाले तौर-तरीके तलाशने होंगे। पुराने कानूनों को अनिश्चितकाल तक कायम रखने के बजाय सनसेट क्लाज का सहारा उपयोगी होगा। नियामकीय ढांचे की निरंतर समीक्षा और उसमें सुधार के सतत प्रयास भी आवश्यक होंगे। श्रम सुधारों के लिए भी कोई रूपरेखा तैयार करनी होगी। अनुपालन बोझ घटाने के उपाय भी तलाशने होंगे।

विधायी परिवर्तनों से इतर उच्चस्तरीय समिति को नियामकीय संस्थाओं की मनमानी और अप्रत्याशितता को भी नियंत्रित करना होगा। उसे नियामकीय अधिसूचनाओं के लिए एक नियत शेड्यूल बनाना होगा और उद्यमों को अप्रत्याशित एवं एकाएक किए जाने वाले परिवर्तनों की तपिश से बचाना होगा। निरीक्षण भी जोखिम आधारित ढांचे के आधार पर ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। स्व-नियमन और थर्ड पार्टी आडिट से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ उत्पीड़न एवं अक्षमताओं के लिए गुंजाइश खत्म करनी होगी। इस प्रकार के समन्वित प्रयासों से हमारे उद्यम लालफीताशाही के भंवर में फंसने के बजाय कारोबारी वृद्धि और नवाचार पर अपनी ऊर्जा एवं संसाधन लगाने में सक्षम हो सकेंगे।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

भगदड़ की घटनाओं से त्रस्त भारत

राजीव सचान

भगदड़ वहीं मचती है, जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है और भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं

भगदड़ वाले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन • फाइल

भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि यहां के लोग भीड़ वाले स्थानों में बदइंतजामी के कारण रह-रह कर मरते रहें। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म पर भगदड़ मचने से 18 लोग मारे गए और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। इनमें अधिकांश वे थे, जो प्रयागराज जाने के लिए आए थे। इसके पहले महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से 30 लोग मारे गए थे। भगदड़ वहीं मचती है, जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है और भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण के उपाय नदारद थे। रेलवे की ओर से कितना भी कहा जाए कि ऐसा नहीं था, लेकिन सच यही है कि इसकी परवाह नहीं की गई कि रेल यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से यात्रा कर सकें। इसकी पुष्टि भगदड़ में मौतों के बाद रेलवे की ओर से किए गए इन उपायों से होती है कि अब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें निर्धारित प्लेटफार्म से जाएंगी, यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और इतनी से इतनी अवधि के बीच प्लेटफार्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? केवल यही कि हादसे के बाद होश आया। ये सारे उपाय पहले कर लिए जाते तो 18 जिंदगियों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता था।

देश की राजधानी में प्रमुखतम रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के उपायों की अनदेखी और उसके चलते 18 यात्रियों की मौत से भी खराब बात यह रही कि हादसे के बाद अधिकारी भगदड़ मचने और उसमें यात्रियों के मारे जाने-घायल होने की बात छिपाने के जतन करते रहे। अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की सूचना नहीं है। इसी कारण इस पर यकीन करना कठिन है कि जांच सही तरह होगी और लापरवाह अधिकारी दंड के पात्र बनेंगे। महाकुंभ में भगदड़ से 30 श्रद्धालुओं की मौत की भी जांच हो रही है। जांच पुलिस भी कर रही है और न्यायिक आयोग भी। पता नहीं कि इन दोनों जांच से क्या सामने आएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महाकुंभ में भगदड़ के करीब 15 घंटे बाद यह बताया गया कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके उपरांत मृतकों की सूची और मृत्यु प्रमाणपत्र देने में भी देरी की खबरें आईं। इसके चलते विपक्षी नेताओं को यह आरोप लगाने का अवसर मिला कि महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा छिपाया जा रहा है। अपने देश में यह सदैव देखने को मिलता है कि सरकारी अधिकारी पहले तो किसी घटना-दुर्घटना की गंभीरता कम करके बताते हैं और फिर उसमें मारे गए लोगों का विवरण देने में। यह हमारी नौकरशाही की वह विचित्र प्रवृत्ति है, जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कारण उन जांच पर भी भरोसा नहीं होता, जिनमें अधिकारी ही अधिकारी की जांच करते हैं।

जब भी कहीं भीड़ भरे स्थलों में कोई हादसा होता है और उसमें लोग मारे जाते हैं तो घटना की जांच करने-कराने वालों से यही सुनने को मिलता है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि भविष्य में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए? ऐसा केवल सुनने को ही मिलता है, क्योंकि बार-बार वैसे ही हादसे होते रहते हैं, जैसे पहले हो चुके होते हैं। कभी-कभी तो उन्हीं स्थलों पर हो जाते हैं, जहां पहले हो चुके होते हैं। इसका उदाहरण कुंभ भी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी। भगदड़ की घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो केवल जनहानि ही नहीं होती, बल्कि देश की बदनामी भी होती है। एक ऐसे समय जब देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बातों के साथ इसके लिए प्रयत्न भी हो रहे हैं, तब फिर सार्वजनिक स्थलों में भीड़ नियंत्रण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। सच तो यह है कि भीड़ नियंत्रण के लिए नियम-कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन मुश्किल से होता है।

अपने यहां नियम-कानूनों के उल्लंघन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कारण केवल यह नहीं कि लोगों को उनकी परवाह नहीं होती, बल्कि यह भी है कि शासन-प्रशासन के स्तर पर उनके अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता। प्रायः यह अनुपालन मनचाहे तरीके से होता है। बीते वर्ष 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की जांच के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें आयोजन की अनुमति मांगने वालों को तो भगदड़ का जिम्मेदार माना गया, लेकिन बाबा की कोई गलती नहीं पाई गई। उनका नाम एफआइआर तक में नहीं था। इसके विपरीत जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के समय थियेटर में भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी तो अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहना कठिन है कि एक जैसे मामले में अलग-अलग तरह की कार्रवाई में कौन उचित थी और कौन नहीं, लेकिन अपने देश में भगदड़ जनित घटनाओं में कार्रवाई होने या न होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे हादसों से जरूरी सबक सीखे जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मृग मरीचिका

मृग मरीचिका को मृगतृष्णा भी कहा गया है। इसका अर्थ है जीवन में उन भ्रामक आकर्षणों एवं इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहना, जो कभी पूरी होना संभव नहीं। इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन मृग मरीचिका के वशीभूत मनुष्य उन सपनों के पीछे भी दौड़ने लगता है, जिनका कोई औचित्य नहीं। मृग मरीचिका ही तमाम मिथ्या लालसाओं का आकर्षण उत्पन्न करती है। उनके लिए मनुष्य प्रयास भी करता है, लेकिन अंततः परिणाम शून्य ही रहता है। कारण यही कि वह भ्रामकता दिवास्वप्न होती है, जिसका कोई यथार्थ भावी अस्तित्व नहीं होता। क्षितिज के उदाहरण से मृग मरीचिका को सहज ही समझा जा सकता है। दूर से पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, किंतु उस छोर तक पहुंचने पर उस मिथ्या भ्रम की वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार होता है।

मनीषियों का मत है कि ऐसी भ्रामकता के आकर्षण में निरर्थक दौड़-भाग के बजाय निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए अपने मूल लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। सदैव याद रहे कि मनुष्य को ऐसी अनेकों मृग मरीचिकाओं ने अपने अंतहीन जंजाल में सम्मोहित कर रखा है, जिनका शमन और सृजन अबाध गति से सतत चलता रहता है। इसके परिणामस्वरूप इस राह में कुछ लालसाएं छूटती हैं तो बहुत कुछ नई जुड़ती रहती हैं। अतः उनके पीछे दौड़-भाग करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बदहवासी में अपनी अंतरात्मा में बैठे विवेक की शरण लेकर मन की निरंकुश चंचलता को नियंत्रित करने के लिए उद्यत रहना ही श्रेयस्कर होता है। भ्रामक आकर्षण का संबंध लालसा एवं आकांक्षा जैसे सांसारिक विकारों से होने के कारण उम्र का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वृद्धावस्था में तरुणाई की लालसा देखी जा सकती है, इसलिए मन की चंचलता पर विवेक की लगाम लगाए रखना ही मृग मरीचिकाओं से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।

-एसएन दुबे 'स्नेही'

पाठकनामा

letter@naidunia.com

महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा

आजकल महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। यह न केवल महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर खतरा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई रूप हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, और दहेज हत्या, जो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई कारण हैं, जैसे कि सामाजिक असमानता, पितृसत्तात्मक मानसिकता, और शिक्षा की कमी। इन सभी कारणों को दूर करने के लिए समाज को एकजुट होकर काम करना होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। हमें महिलाओं को पुरुषों के समान समझना होगा और उन्हें सम्मान देना होगा। महिलाओं को शिक्षित करना होगा और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। हमें हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी और दोषियों को सजा दिलवानी होगी। अगर मिलकर प्रयास करें तो हिंसा को रोका जा सकता है और एक सुरक्षित और समतापूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है।

– शिल्पी नायक, रायपुर

शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का समाधान

आजकल, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, जो छात्रों पर दबाव डाल रही है। यह दबाव उन्हें डिप्रेशन, चिंता और तनाव का शिकार बना रहा है। लेकिन, इसका समाधान संभव है। छात्रों को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार विषय चुनने चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को उन्हें तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। शिक्षा को व्यापार के बजाय एक साधन बनाना चाहिए, जो छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करे। इसके अलावा, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना भी जरूरी है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वे छात्रों को बेहतर ढंग से सिखा सकें। स्कूलों में संसाधनों की कमी को पूरा करना चाहिए, ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, हमें शिक्षा के उद्देश्य को बदलना होगा। शिक्षा को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए। हमें उन्हें समझना चाहिए कि शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अंत में, शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का समाधान संभव है। हमें शिक्षा को एक साधन बनाना चाहिए, जो छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करे, न कि व्यापार।

–हेमकुमार वर्मा, रायपुर

एआइ से शोध का गिरता स्तर

तकनीक की नई विधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) ने शोधार्थियों के शोध कार्य को अत्यधिक सरल किया है। शोधार्थियों को घर बैठे ही देश-विदेश के संदर्भ ग्रंथ चुटकियों में मिल जाते हैं। यहां से वह कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। शोध से संबंधित उत्तरदाताओं और विशिष्ट व्यक्तियों से घर बैठे ही इंटरव्यू लेने के लिए भी इन टूल्स का प्रयोग होने लगा है, जिसका उपयोग करना शोधार्थी के समय और धन को निश्चित रूप से बचाता है। दूसरी ओर शोधार्थी बिना किसी परिश्रम के एआइ टूल्स का उपयोग कर शोध से संबंधित तैयार कंटेंट या सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। इस अनुवादित कंटेंट से न सिर्फ वाक्य विन्यास और शब्दों की मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं, अपितु शोध का स्तर भी कमजोर होता जा रहा है। कार्य करने से ही शोध की गुणवत्ता बनी रह सकती है। तभी अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। शोध क्षेत्र में प्रत्यक्ष जाकर अध्ययन और अवलोकन करने से ही शोध विषय से संबंधित समस्याओं, चुनौतियों और निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। यूजीसी को एआइ की सहायता से तैयार कंटेंट के लिए भी सख्त नियम बनाने चाहिए।

–**रामबाबू सोनी,** कसेरा बाजार, इंदौर

पोस्ट

पहले कहा गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई। यात्रियों के एक-दूसरे पर गिरने से हादसा हुआ। प्लेटफार्म बदलने की मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया गया। अब आरपीएफ की जांच रिपोर्ट कह रही है प्लेटफार्म बदलने से भगदड़ हुई ...।

पंकज झा@pankajjha_

लगभग 79 देशों के स्कूलों में बच्चों को मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया जाता है। इन देशों में फोन मुक्त अधिनियम लागू किए गए हैं। अमेरिका के भी 50 में से करीब 20 राज्यों में स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी है। मोदी सरकार को भी भारत में यह व्यवस्था लागू करने के बारे में सोचना चाहिए।

पंकज शर्मा@Pankaj__Sharma

चैंपियंस ट्राफी में बुमराह के बिना हमारी गेंदबाजी अधूरी है। स्पिन विभाग ठीकठाक है। अगर हमें खिताब जीतना है तो बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा। धीमी पिचों पर भारत को बल्लेबाजी में महारत भी हासिल है। विराट और रोहित का फार्म में लौटना भी टीम के लिए शुभ संकेत है।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/18897 जागरण प्रकाशन लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस प्लॉट नं. 47/3, भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर से मुद्रित एवं तीसरी मंजिल, कृष्णा ग्लोरी कॉम्प्लेक्स, सांई नगर, होटल बेबीलॉन इन के पीछे, जेल रोड, रायपुर से प्रकाशित
फोन नं. 0771-4711000 फैक्स : 0771-4711024 इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com **संपादक** : सदगुरु शरण* *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

नेकदिल लोग शांत और स्थिर रहते हैं। छोटे लोग हमेशा झगड़ते और परेशान रहते हैं : कनफ्यूशियस

कांग्रेस का 'चीन के प्रति आकर्षण'

कांग्रेस की विदेशी इकाई के प्रमुख एवं राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जानेवाले सैम पित्रोदा अपने बयानों से कांग्रेस को अकसर मुश्किल में डालते रहते हैं। इस बार उन्होंने चीन का पैरोकार बनकर कांग्रेस के सामने दुविधा खड़ी कर दी। उनका दावा है कि "चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत की है"। सैम पित्रोदा ने भारत के दृष्टिकोण को गलत अर्थों से प्रस्तुत करके भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत अपने पड़ोसी देश चीन को शत्रु नहीं मानता है। चूँकि चीन की विस्तारवादी नीति ने भारत के हितों का अतिक्रमण करने का कार्य किया है, इसलिए चीन के साथ टकराव है। वह स्वाभाविक ही है। भारत की सोच तो सबके साथ मिलकर काम करने की है। संभवतः यह बात विदेश में रहनेवाले कांग्रेस के नेता एवं सलाहकार सैम पित्रोदा को पता नहीं होगी। भाजपा ने कांग्रेस की इस सोच का उचित ही विरोध किया है। भारत के दृष्टिकोण को गलत अर्थों में प्रस्तुत करने का किसी को अधिकार नहीं है। पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर भाजपा ने कांग्रेस के चीन के प्रति आकर्षण पर भी सवाल उठाए हैं। याद हो कि कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल गांधी पिछले दिनों न केवल चीनी कंपनी के ड्रोन उड़ाकर उसका विज्ञापन एवं विपणन (मार्केटिंग) कर रहे थे अपितु ड्रोन के निर्माण के संबंध में भारतीय उद्योग जगत की आलोचना भी कर रहे थे। उनके इस व्यवहार एवं बयान पर भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने तीखी आलोचना की है। यह कैसा संयोग है कि राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा चीन की प्रशंसा कर रहे हैं और स्वयं राहुल गांधी चीनी कंपनी के उत्पाद के प्रति उत्साहजनक वातावरण बना रहे हैं? यह भी याद रहे कि राहुल गांधी भी विदेश में चीनी नीतियों की प्रशंसा कर चुके हैं। गलवान में हुए संघर्ष को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं की बोली चीन के हितों के अनुरूप रही है। भाजपा ने ठीक सवाल उठाया है कि चीन की प्रशंसा में कांग्रेसी नेताओं के जो बयान समय-समय पर आते रहते हैं, क्या उसके पीछे कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुआ समझौता है? भाजपा का दावा है कि पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ समझौते की खुलकर पोल खोल दी है। गंभीर बात यह है कि पित्रोदा ने जिस तरह की बात कही है, वह भारत की अस्मिता, कूटनीति और संप्रभुता पर गहरा आघात है। निःसंदेह, पित्रोदा का बयान घोर आपत्तिजनक है इसलिए ही कांग्रेस को उनके बयान से किनारा करना पड़ा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पित्रोदा का बयान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा, और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह सफाई देने की अपेक्षा कांग्रेस को चाहिए कि वह सैम पित्रोदा को भारत के विचार से परिचित कराए। क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सैम के बयान से किनारा किया है। लोकसभा चुनाव के पूर्व तो एक विवादित बयान के कारण कांग्रेस को उन्हें हटाना भी पड़ गया था, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव में नुकसान का अंदेशा था। लेकिन इसके कांग्रेस की चतुराई ही कहा जाएगा कि चुनाव सम्पन्न होने के बाद पित्रोदा को पुनः उनके दायित्व पर वापस ले लिया गया। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि कांग्रेस सैम पित्रोदा की सोच का पोषण करती है। अन्यथा इस प्रकार की सोच रखनेवाले व्यक्ति को पद पर बनाए रखने का क्या कारण है?

भारत की सोच सबके साथ मिलकर काम करने की है। संभवतः यह बात विदेश में रहनेवाले कांग्रेस के नेता एवं सलाहकार सैम पित्रोदा को पता नहीं होगी। भाजपा ने कांग्रेस की इस सोच का उचित ही विरोध किया है। भारत के दृष्टिकोण को गलत अर्थों में प्रस्तुत करने का किसी को अधिकार नहीं है। पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर भाजपा ने कांग्रेस के चीन प्रेम पर भी सवाल उठाए हैं।

बोध कथा

आत्म निरीक्षण

एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। भला वो उन्हें क्या पहचानता सो, अजनबी की तरह देखता रहा। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा तो उस व्यक्ति ने उनकी तरफ पानी बढ़ा दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने अपना मंतव्य बताद यिा कि वो उसके प्राण लेने आए हैं लेकिन चूँकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं।

यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा-तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था-उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए।

इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपनी कलम उठाई, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा- वत्स! तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अतः तुम्हारा अन्त निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाए पछतावे के अलावा कुछ नहीं था।

यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी- कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके, अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्म ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहें। आत्मावलोकन ही सदमार्ग पर चलने की कुंजी है।

जयंती : श्री गुरुजीशक्तिशाली भारत की अवधारणा के अद्भुत, उद्भट व अनुपम संवाहक थे

श्री गुरुजी: शक्तिशाली भारत के कल्पनाकार

डॉ. प्रवीण गुगनानी
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार, राजभाषा

श्री गुरुजी, माधव सदाशिव राव गोलवलकर, शक्तिशाली भारत की अवधारणा के अद्भुत, उद्भट व अनुपम संवाहक थे। वे भारत की सौम्यता, अनेकता में एकता, समरसता के मर्मज्ञ थे। श्री गुरुजी के संदर्भ में 'थे' शब्द कहना सर्वथा अनुचित होगा, वे आज भी हमारे मध्य, पराक्रमी भारत, ओजस्वी भारत, अजेय भारत, निर्भय भारत, संपन्न-समृद्ध-स्वस्थ भारत व राष्ट्रवाद भाव के झर-झर बहते निर्झर झरने बने हुए हैं।

श्री गुरुजी, माधव सदाशिव राव गोलवलकर, शक्तिशाली भारत की अवधारणा के अद्भुत, उद्भट व अनुपम संवाहक थे। वे भारत की सौम्यता, अनेकता में एकता, समरसता के मर्मज्ञ थे। श्री गुरुजी के संदर्भ में 'थे' शब्द कहना सर्वथा अनुचित होगा, वे आज भी हमारे मध्य; पराक्रमी भारत, ओजस्वी भारत, अजेय भारत, निर्भय भारत, संपन्न-समृद्ध-स्वस्थ भारत व राष्ट्रवाद भाव के झर-झर बहते निर्झर झरने बने हुए हैं। वे शक्तिशाली भारत के अग्रदूत, संवाहक, प्रणेता के रूप में आज भी हमारे मध्य हैं, एक वैचारिक मूर्ति के रूप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी के संदर्भ में, शक्तिशाली भारत की अवधारणा के संवाहक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पुस्तक 'श्रीगुरूजी एक स्वयंसेवक' में लिखते हैं – 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की थी, लेकिन इसे वैचारिक आधार द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 'श्रीगुरुजी' ने प्रदान किया था।

द्वितीय विश्वयुद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी का देश की आजादी में योगदान, भारत विभाजन, देश की आजादी, कश्मीर विलय, गांधी हत्या, देश का पहला आम चुनाव, चीन से भारत की हार, पाकिस्तान के साथ 1965 व 1971 की लड़ाई, भारत का इतिहास बदलने और बनाने वाली इन घटनाओं के महत्त्वपूर्ण काल में न केवल श्रीगुरुजी संघ के प्रमुख थे, बल्कि अपनी सक्रियता और विचारधारा से उन्होंने इन सबको प्रभावित भी किया था।'

शक्तिशाली भारत की श्री गुरुजी की अवधारणा को अटलबिहारी वाजपेयी व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी हुई कोई आधा दर्जन केंद्रीय सरकारों ने मात्र ही स्वीकार नहीं किया; अपितु, इस अवधारणा को उन्होंने अपना गीता-रामायण माना हुआ है।

शक्तिशाली राष्ट्र की गुरुजी की अवधारणा को स्वतंत्रता संघर्ष के मध्य ही कांग्रेस ने व स्वतंत्रता के पश्चात बनी हुई नेहरूजी व शास्त्रीजी की सरकारों ने भी स्वीकार किया है। यद्दपि नेहरू ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने व श्री गुरुजी को जेल में बंदी बनाने जैसा पाप भी किया था किंतु इसके बाद उन्होंने गोलवलकर गुरुजी का अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वर्ष 1963 की गणतंत्र

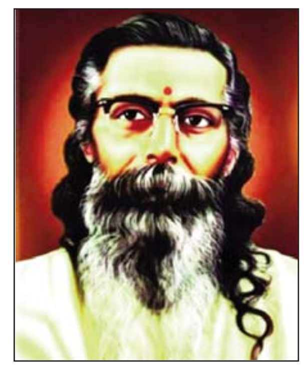

दिवस की परेड में भाग लेने हेतु आमंत्रित भी किया था।

वस्तुतः श्री गुरुजी के नेतृत्व काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती लोकप्रियता, स्वीकार्यता, मान्यता को देखकर नेहरूजी के हृदय में कुटिलता व डाह के भाव आने लगे थे। नेहरू जिस प्रकार की छुद्र, अंग्रेज-मुस्लिम परस्त राजनीति किया करते थे; श्रीगुरुजी उसके विरुद्ध थे। नेहरू जी ने संघ व श्रीगुरुजी को अपनी सत्ता के प्रति आसन्न असुरक्षा के भाव से ग्रसित होकर ही गांधीजी की हत्या के बाद श्रीगुरुजी को गिरफ़्तार कर संघ को प्रतिबंधित किया था।

गांधी जी की हत्या व हत्या के आरोप में संघ पर प्रतिबंध लगाना, आज भी एक उनसुलझा रहस्य ही है। इस रहस्य का एक सूत्र गांधीजी की हत्या के ठीक एक दिन पूर्व के नेहरू के एक भाषण में भी है, जिसमें नेहरू ने संघ को कुचलने की बात कही थी। नेहरू जी का संघ को कुचलने वाला भाषण देना, चौबीस घंटे के भीतर गांधी जी की हत्या होना और संघ पर प्रतिबंध लगाकर श्रीगुरूजी को गिरफ़्तार कर लेना, एक अनसुलझी गुत्थी ही है। गांधी जी की हत्या व इस संदर्भ में संघ पर प्रतिबंध, यह पहेली, क़ानूनी दृष्टि से असुलझी लग सकती है किंतु भीतरखाने के सच जानने वाले तत्कालीन राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता इस संदर्भ में दबी जबान बहुत कुछ कहा-सुना करते थे। विकसित भारत की नेहरू की परिकल्पना पर श्रीगुरूजी का 'शक्तिशाली भारत' की योजना कल्पक, अत्यंत भारी, परिणामकारी व युगांतरकारी है।

श्री गुरुजी की यह योजना, नेहरू की अंग्रेज व मुस्लिम परस्त नीतियों पर बहुत भारी पड़ती हुई दिखने लगी थी। सार्वजनिक चौक-चौराहों, सड़क-संसद, मठ-मंदिर, व्यावसायिक परिसरों आदि सर्वत्र स्थानों पर श्री गुरुजी की 'शक्तिशाली भारत' की योजना की चर्चा में भारतीय न केवल रुचि लेने लगे थे, अपितु, श्रीगुरुजी के प्रति भारतीयों में श्रद्धा का वातावरण बनता जा रहा था।

यह सब तब था जबकि, श्रीगुरु जी का प्रत्यक्ष राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं था। नेहरू जी को भय था कि, देश के आगामी प्रथम लोकसभा चुनाव में उनकी सर्वोच्चता को केवल तीन लोग चुनौती दे सकते थे; वे तीन व्यक्ति थे – पहले श्री गुरुजी, गांधीजी व बाबासाहेब अंबेडकर जी। इन तीनों के प्रति नेहरूजी ने तरह-तरह की ज्ञात-अज्ञात दुरभिसंधियां की थीं।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में श्रीगुरुजी की 'शक्तिशाली भारत' की अवधाणा से लोग ऐसे प्रभावित होने लगे थे कि उनके प्रति श्रद्धा का ज्वार उमड़ने लगा था। 1965 के 'भारत चीन युद्ध' में भी, प्रधानमंत्री शास्त्रीजी ने, श्रीगुरुजी से नीतिगत व सामरिक विषयों पर परामर्श करके निर्णय लिए थे। जनप्रिय प्रधानमंत्री अटलजी तो श्रीगुरुजी के समकक्ष कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे व नीचे ही स्थान ग्रहण करते थे।

गोवा के भारत विलय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमि उनकी 'शक्तिशाली भारत की अवधारणा' का ही परिणाम था। गोवा मुक्ति आंदोलन में उस समय कांग्रेस सरकार की भूमिका राष्ट्रहित की पीठ में ही छुरा घोंपने वाली थी। गुरुजी ने तब कहा था, 'गोवा में पुलिस कार्रवाई करने और गोवा को मुक्त कराने का इससे ज्यादा अच्छा अवसर कोई नहीं आएगा। भारत सरकार ने गोवा मुक्ति आन्दोलन का साथ न देने की घोषणा करके मुक्ति आन्दोलन की पीठ में छुरा मारा है।

भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय नागरिकों पर हुए इस अमानुषिक गोलीबारी का प्रत्युत्तर दे और मातृभूमि का जो भाग अभी तक विदेशियों की दासता में सड़ रहा है, उसे अविलम्ब मुक्त करने के उपाय करे।'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व वामपंथियों में मूलतः वैचारिक मतभेद है व कम्युनिस्ट स्वभावतः ही संघ को पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। श्रीगुरूजी अपनी 'शक्तिशाली भारत' की अवधारणा के प्रति इतने समर्पित थे कि वे कम्युनिस्ट्स के प्रति भी राष्ट्रहित में समन्वय की दृष्टि रखते थे। श्रीगुरुजी कार्ल मार्क्स के प्रति कहा करते थे- 'भारतीय कम्युनिस्ट्स ने कार्ल मार्क्स के साथ अन्याय किया है। मार्क्स केवल भौतिकतावादी नहीं थे, वे नीतिशास्त्र में भी विश्वास रखते थे।

यह लेखक के निजी विचार है

नर्मदा का सीना छलनी करते 'रेत दस्यु'

रक्षा दुबे (चौबे)
उपायुक्त जीएसटी (राज्य) भोपाल

इस बार नर्मदा की खंड परिक्रमा के दौरान मैया के सौंदर्य के मूर्तिमान महोल्लास के बीच मन को गहरे तक विषाद में भर देने वाला दृश्य उपस्थित हुआ। इस दृश्य से हम सभी सुधिजनों और जवाबदेहों का परिचित होना आवश्यक है। मैया का आंचल पकड़े-पकड़े चलने की हमारी घनीभूत इच्छा ने बाबरी (हरदा) में मैया का किनारा समाप्त हो जाने पर सड़क मार्ग से जाने के स्थान पर नाव से आगे बढ़ने का विकल्प चुना। कदाचित हम यह विकल्प न चुनते तो इस भीषण और क्रूर वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार न हो पाता। बाबरी घाट मूलतः मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है लेकिन हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए जिला हरदा में बाबरी घाट हमारे दाहिनी ने हाथ पर था।

बाबरी घाट पर नर्मदा में रेत उत्खनन का दृश्य किसी भी मैया और पर्यावरण प्रेमी को अवसाद में भर देने के लिए काफी था। अभी तक हमें नर्मदा के किनारे मिलने वाली रेत के उत्खनन की जानकारी थी, पर यहां तो नर्मदा की धारा के ठीक बीच से रेत उलीची जा रही थी।

नर्मदा की धारा को चीरती हुई सैकड़ों मोटर बोट और उन पर हज़ारों की संख्या में सवार मल्लाह और मजदूर हम पदयात्रियों को किसी दूसरी ही दुनिया में ले गए। मुझे बारंबार फिल्म 'पाइरेट्स आफ कैरीबियन सी' के दृश्य याद आ रहे थे। रंग- बिरंगी पताकाओं से सजी मोटरबोटों पर सवार रेत दस्यु बांस से नर्मदा की गहराई और रेत की उपलब्धता का अनुमान लगाते हुए जालीदार बाल्टियों से रेत निकाल रहे थे।

उन मोटरबोटों की आपसदारी में क्रूर उल्लास और उत्साह के वातावरण में अधिक से अधिक रेत निकाल लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। एक मोटरबोट से ललकार उठती और प्रत्युत्तर में दूसरी मोटरबोट से अट्टहास।

मोटरबोट नर्मदा की नाभि से रेत उठाकर किनारे खड़े ट्रैक्टर पर स्थानांतरित करती और वहाँ से वह रेत ट्रकों पर शिफ्ट की जाती है। तट पर सैंकड़ो की तादाद में हाइवा और ट्रक खड़े थे। पाथाड़ा से नीलकंठ (नसरुल्लागंज) तक यह नज़ारा आम है। इस हृदय विदारक दृश्यशृंखला में हम नर्मदाप्रेमी परिक्रमा वासी एक दूसरे से नज़रें बचाते ग्लानि में डूबे जा रहे थे। अनुभव हो रहा था मानो किसी स्त्री के गर्भस्थान से सृजन का नमक उलीच कर उसे बांझ बनाने के षड्यंत्र में हम भी शामिल हैं।

परिक्रमा के बाद के दिनों में नर्मदा के अप्रतिम सौंदर्य के बीच भी यह संदर्भ कभी छूट नहीं पाया। ग्रामीण जनों से बातचीत में वे भी इस उत्खनन से अप्रसन्न और चिंतित दिखाई दिए। इस पूरे परिक्षेत्र का रहवासी नर्मदा को अपनी माँ की तरह प्रेम करता है और इस प्रेम का प्रमाण स्थान-स्थान पर परिक्रमा वासियों के प्रति उनके अहेतुक प्रेम को देखकर लगाया जा सकता है। स्थानीय जनों से बातचीत में यह भी समझ आया कि रेत उत्खनन ने नदी के प्राकृतिक और परिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल असर

डाला है और इससे इस नदी पर निर्भर रहने वाले मछुआरों की आजीविका पर बहुत असर आया है। एक मछुआरे ने बताया कि इन दोनों नर्मदा में पाई जाने वाली महाशीर मछली लगभग विलुप्त हो चुकी है।

यह नर्मदा में मिलने वाली एक बड़े आकार की मछली है जो औसतन 20 किलोग्राम की होती है और यह मछली बहुत सारे प्रदूषण कारक जीव जंतुओं का आहार करने के कारण 'नर्मदा की बाघ' भी कहलाती है। तटीय रहवासियों ने यह भी बताया कि मछलियों की अन्य प्रजातियां जैसे घोघरा और गुरमुच भी अब कम मिल रही हैं। नदी के किनारे रहने वाले सारस, बगुले और टिटहरी भी मात्रात्मक रूप से कम हुए हैं। जल मुर्गियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो पानी की खराब गुणवत्ता और प्रदूषण की गवाह है।

नर्मदा को अपने मूल प्रवाह और सहायक नदियों को इस प्रवाह में सम्मिलित होने के लिए रेत की आवश्यकता होती है, यह नदी के बहाव को संतुलित करने का कार्य भी करती है। अत्यधिक रेत उत्खनन ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित किया है, जिससे नर्मदा के प्रवाह पर विपरीत असर पड़ रहा है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी नदी सिर्फ उसमें बहने वाला पानी नहीं बल्कि उसमें सांस लेने वाला पूरा जीवन होता है।

हम जानते हैं कि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी पृथ्वी की टेक्नोनिक प्लेट्स के आपसी टकराव की प्रक्रिया में बनती है न कि मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया से। जब प्लेटों में खिंचाव बढ़ जाता है या शिलाओं पर उनकी सहनशक्ति से अधिक दबाव पड़ता है तब शिलाएं टूटकर भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं> इस दबाव के कारण भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों में भूगर्भीय हलचल और बाढ़ आने का खतरा सदैव बना रहता है। अत्यधिक रेत उत्खनन से नदी की तलछट व्यवस्था में व्यवधान आने के साथ-साथ तीव्र ढलान वाले ऊंचे और अस्थिर तटबंधों का निर्माण होता है। अस्थिर तटों के ढहने से नदी का दबाव और प्रवाह विकसित इलाकों की ओर मुड़ सकता है। भ्रंश घाटी का आयतन सीमित होने के कारण आयतन और वेग की अनुपातहीनता भविष्य के बड़े संकट की ओर इशारा है।

रेत के नियमन हेतु मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत सीमांकित रेत खदानों से पर्यावरणीय अनुमति के उपरांत निश्चित मात्रा में ही रेत का उत्खनन किया जा सकता है। रेत उत्खनन के लिए मशीनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और इस रेत उत्खनन के एवज में रॉयल्टी दी जाती है। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण पर कार्यवाही की प्रभावी नवीन नीति के अनुसार रेत का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर रॉयल्टी का 15 गुना अधिक जुर्माना तथा उतनी ही राशि पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाएगी। इस कार्य में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही का भी प्रावधान है।

ृष्ट है कि इस विषय में कानून और शासन की मंशा निर्विवाद है लेकिन प्रश्न यह है कि, क्या इतना ही होना पर्याप्त है? क्या जवाबदेहों तक इन घटनाओं की सूचना है? क्या रेत की बढ़ती आवश्यकताओं की दृष्टि से टिकाऊ तथा भविष्यदृष्टा रेत नीति बनाने का यह सही समय नहीं है? पिछले कुछ वर्षों में अधोसंरचनागत आवश्यकताओं के मद्देनज़र रेत की माँग बहुत अधिक बढ़ गई है।

रेत की माँग और पूर्ति के इस असंतुलन को दूर करने के लिए यदि समय रहते सम्यक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो यह न केवल नर्मदा के स्वास्थ्य बल्कि इस क्षेत्र की संपूर्ण भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिकी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित होगा। 'क्रश्ड सैंड' के उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक व्यवस्था की ओर बढ़ाया गया पहला कदम हो सकता है। नर्मदा न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। प्रत्येक परिस्थिति में इसकी शुचिता को अक्षुण्ण रखना सरकार, शासन और नागरिकों का दायित्व भी है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मंत्र देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज

लोकेन्द्र सिंह

एक उन्नत राष्ट्र के लिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। शासन में 'स्व बोध' की स्थापना करनेवाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने रक्षा उत्पादन में भी स्वदेशी के महत्व को स्थापित किया। उन्होंने पैदल सैनिकों के हथियारों से लेकर नौसेना के लिए लड़ाकू जहाज तक स्वदेशी तकनीक पर तैयार कराए थे। सैन्य उपकरणों एवं हथियारों के निर्माण में छत्रपति की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी, वे देश-काल-परिस्थिति को ध्यान में रखकर हथियारों के डिजाइन को अंतिम रूप देते थे। छत्रपति ने विदेशी नौकाओं एवं जहाजों की होड़ करके वैसे ही बड़े जहाज नहीं बनवाए बल्कि उन्होंने अपने समुद्री तटों पर तेजी से चलनेवाली छोटी नौकाओं पर जोर दिया। इन्हीं छोटी लड़ाकू नौकाओं ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और मुगलों के हथियारों से सुसज्जित सैन्य जहाजों को हिन्द महासागर के किनारे पर डुबो दिया था। हिन्दवी स्वराज्य की नौसेना के बेड़े में बड़े आकार के जहाज भी शामिल थे।

हिन्दवी स्वराज्य की सेना के पास अलग-अलग प्रकार के अस्त्र-शस्त्र थे। इनमें से कई अस्त्र ऐसे थे, जिनके निर्माण एवं उपयोग का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। महाराज की सेना की यह ताकत थी कि उनके पास ऐसे अस्त्र-शस्त्र रहते थे, जिनकी कोई पूर्व जानकारी शत्रुसेना को नहीं होती थी। उन शस्त्रों से बचने का उपाय भी शत्रु सैनिक नहीं कर पाते थे। ऐसा ही एक शस्त्र था- बाघनखा, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के आदिलशाही वंश के सेनापति अफजल खान का पेट चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पहुँचा दिया था। 'बाघनखा' ऐसा हथियार है, जिसे अंगुलियों के पोर में सटीक बैठने के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें बाघ के नाखूनों की तरह तेज धारवाले चार-पांच लोहे के नख होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों द्वारा उपयोग में लाए जानेवाले कुछ प्रमुख शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं- कट्यार (कटार), खंजीर, गदा, गोफण, तलवार, तिरकमठा (धनुष-बाण), दगडधोंडे, दांडपट्टा, बरची, बिचवा, भाला (विभिन्न प्रकार के भाले) इत्यादि। हिन्दवी स्वराज्य के योद्धा भाला और कुरहाड़ जैसे कई तरह के हथियार प्रयोग में लाते थे। गुर्ज– लोहे की गदा जैसा था, जिस पर कीलें उभरी होती थीं। इससे उस योद्धा पर वार किया जाता था, जिसने सिर पर टोप और शरीर पर कवच पहन रखा हो। मदु– हैंडल वाला कवच था, जिसके दोनों ओर से हिरण की तरह सींग निकले होते थे। बिछवा– दोधारी, एस के आकार की कटार थी जो दिखने में बिच्छू जैसी लगती थी।

मुगलों से मुकाबला करने के लिए हथियार भी उच्च कोटि के चाहिए। इस बात को समझ-बूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज हथियारों के निर्माण पर खूब ध्यान देते थे। आज भी किसी देश की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उनके पास कितने घातक हथियार हैं। हथियार निर्माण के कार्य में छत्रपति कुशल कारीगरों को नियोजित करते थे। हथियार निर्माण करनेवालों को महाराज विशेष निर्देश देते थे। उन्होंने तलवार की धार के तीखेपन और मूठों के बारे में कड़े निर्देश दे रखे थे। अपनी पुस्तक 'नियति को चुनौती' में मेधा देशमुख-भास्कर लिखती हैं कि शिवाजी महाराज तलवार की मूठ भी एक खास आकार में बनवाते थे। मूठ पर बेहतर पकड़ के लिए उन पर अच्छा और गद्देदार कपड़ा मढ़वाया जाता। तलवार की धार को भारी बनाने के लिए मूठ के पास वाले हिस्से में और अधिक धातु लगाई जाती थी। इस तरह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र मूठ के पास आ जाता यानी तलवार पकड़ने वाले के हाथ के पास आ जाता।

हिन्दवी स्वराज्य के मावले युद्ध में कई तरह की तलवारों का प्रयोग करते थे। धोप तलवार लगभग चार फीट लंबी होती थी। इससे घोड़े पर सवार योद्धा पैदल सैनिक को मार सकता था। धार का निचला हिस्सा इतना तेज था कि उससे आसानी से

किसी को चीरा जा सकता था। ऊपरी धार पिपला भी आसानी से मांस को चीर सकती थी। अगर शत्रु तलवार के वार से बच जाता तो उसके पिछले वार से नहीं बच पाता था। मूठ के कोने को भी इतना तीखा बनाया जाता था कि वह किसी को भी मारने के लिए काफी थी। अगर शत्रु बहुत पास होता तो मूठ को इस तरह पकड़ा जा सकता था कि तलवार को कटार की तरह प्रयोग में लाया जा सके।

दांडपट्टा तलवार चार फीट से ज्यादा लंबी होती थी उसे तोड़ना या मोड़ना आसान नहीं था। इसका आर्म–गार्ड तलवारबाज की बाजू को कोहनी तक छिपाए रखता था। इस तरह तलवार उसके हाथ का ही हिस्सा बन जाती। एक बार उसे हाथ में जमाने के बाद अपनी बाजुओं का पूरा जोर लगाया जा सकता था। यह दूसरी तलवारों की तरह नहीं थी, इसका हैंडलबार सीध में नहीं था। इस तरह यह क्षितिज की समानांतर दिशा में वार करने वाला हथियार बन जाता था। तलवारबाज अक्सर एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लेते थे पर पट्टा तलवारबाज दोनों हाथों में तलवार लेते थे। कुछ लोग कुल्हाड़ों का भी प्रयोग करते थे। बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, मुरारबाजी देशपांडे और छत्रपति शिवाजी को भी पट्टा तलवार चलाने में महारत हासिल थी। सिनेमाघरों में प्रदर्शित फिल्म 'छावा' में छत्रपति शंभूराजे को हम एक दृश्य में दांडपट्टा चलाते हुए देख सकते हैं।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।)

भारत की कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) क्षेत्र की सफलता: किफायती नवाचार के साथ भविष्य को सशक्त बनाना

भारत कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) में एक परिवर्तनकारी क्रांति देख रहा है, और इस बदलाव के केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है। भारत के इतिहास में पहली बार, सरकार प्रत्यmक्ष रूप से एक एआई क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जहां कंप्यूटिंग पावर, ग्राफिक्सत प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) और शोध के अवसर किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध हैं। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एआई सिर्फ़ कुछ खास लोगों के लिए न हो और इस पर बड़ी तकनीकी कंपनियों और वैश्विक दिग्गजों का वर्चस्व न हो। आइए एक नज़र डालते हैं कि मोदी सरकार भारत को वैश्विक एआई दिग्गेज बनाने के लिए क्या कर रही है:

इंडियाएआई मिशन: एआई को सुलभ बनाने में अग्रणी भूमिका : भारत के एआई क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मोदी सरकार ने 2024 में 10,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी। अगले पांच वर्षों में यह निर्धारित निधि इंडियाएआई मिशन के विभिन्न घटकों को गति प्रदान करने के लिए तैयार है।

जीपीयू आधारभूत ढांचा और खुला जीपीयू बाजार : इंडिया एआई मिशन के लॉन्च होने की 10 माह की अवधि में, नोडल मंत्रालय जबर्दस्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने और लगभग 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू की एक उच्च-स्तरीय और मजबूत सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा बनाने में सक्षम रहा है। यह ओपन सोर्स मॉडल डीपसीक की तुलना में लगभग नौ गुना और चैटजीपीटी की तुलना में लगभग दो तिहाई है।

ओपन डेटा के साथ एआई नवाचार को सक्षम बनाना : डेटा वह शक्ति है जो एआई शोध और नवाचार को आगे बढ़ाता है, और समृद्ध, विविध और प्रचुर डेटासेट के बिना, सबसे कुशल डेटा वैज्ञानिक और डेवलपर्स भी अवरोधों का सामना करते हैं। इसे पहचानते हुए, मोदी सरकार बड़े शोध समुदाय के लिए ओपन डेटासेट को सुलभ बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना : वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने नई दिल्ली में हेल्थकेयर, कृषि और बेहतर शहरी नियोजन एवं प्रबंधनयुक्त शहरों पर केंद्रित तीन एआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की घोषणा की। बजट 2025 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एआई के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई।

भारत के आधारभूत वृहद भाषा मॉडल : भारत न केवल एक मजबूत एआई क्षेत्र विकसित कर रहा है, बल्कि आधारभूत एआई मॉडल बनाने में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भारत की एआई उन्नति स्वदेशी हो। इंडियाएआई ने प्रस्तावों के लिए कॉल के माध्यम से एलएलएम और एसएलएम सहित स्वदेशी आधारभूत एआई मॉडल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।

डिजिटल इंडिया भाषिणी उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो भारत का एआई-आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करना है, जिसमें आवाज़-आधारित पहुंच शामिल है, और भारतीय भाषाओं में कंटेंट के सृजन में मदद करना है।

भारत वैश्विक एआई कौशल पैठ में पहले स्थान पर : स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार, भारत एआई कौशल पैठ में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है। भारत 2.8 के स्कोर के साथ एआई कौशल पैठ में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जो अमेरिका (2.2) और जर्मनी (1.9) से आगे है। भारत ने 2016 से एआई प्रतिभा संकेन्द्रण में उल्लेखनीय 263 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जिसने खुद को एआई में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।

एआई नवाचार में बढ़ती उपस्थिति : जब नवाचार और तकनीक की बात आती है, तो भारतीय युवा सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली डेवलपर आबादी के रूप में उभरा है, जो गिटहब पर पब्लिक जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स में दूसरे स्थान पर है।

भारत में एआई बाज़ार की वृद्धि : भारत का एआई बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि बीसीजी-नैसकॉम रिपोर्ट 2024 द्वारा उजागर किया गया है। एआई बाज़ार 25-35 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ेगा, जो नवाचार और रोज़गार सृजन क्षमता पर भी जोर देगा। (पीआईबी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

इस्तीफे की कड़वी दवा गले उतारी

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से भेंट करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह 2017 में पहली दफा मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे। उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का राज्य में यह दूसरा कार्यकाल था, परंतु राज्य में हो रही हिंसा पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब रहने के आरोप लग रहे थे। इसी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातीय हिंसा में सिंह की भूमिका को लेकर आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता को लेकर सील बंद फोरेंसिक रिपोर्ट मांगने के बाद ताजा विवाद शुरू हो गया। इतना ही नहीं, विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार थी। बीते दो वर्षो से राज्य में मैतई समुदाय व कुकी जनजातियों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष से निपटने में सिंह असफल ही नहीं रहे। बल्कि उन पर मैतई विद्रोहियों के समर्थन का भी आरोप है। उनके दल के ही कुछ विधायकों के मुख्यमंत्री से खासा नाराज होने और विपक्ष के संपर्क में होने की चर्चा भी जोरों से है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व को आनन-फानन यह निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा। नाराज धड़ा यदि टूटकर विपक्ष के पाले में जा मिलता तो सरकार पर संकट आना लाजमी था। जो मोदी सरकार की फजीहत करने वाला साबित होता। इधर दिल्ली सरकार में पताका फहराने का जोश मन्दा भी नहीं पड़ा था कि हिंसा से झुलस रहे मणिपुर की सत्ता पर संकट गहराता भांपते ही स्थिर पर काबू करने के लिहाज से इस्तीफे की कड़वी दवा गले उतारी गई। मणिपुर के अकेले चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी रहे बीरेन पत्रकारिता में भी हाथ अजमा चुके हैं। खिलाड़ी और संपादक रहने के नाते उन्हें दांवपेंच का महारथी माना जाता रहा है। कुछ ही दिन पहले उनका कथित इस्तीफा भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसे फटा हुआ बताकर शरारत साबित करने की कोशिशें की गई थीं। सबसे लंबे समय तक वहां के मुख्यमंत्री रहे ओकराम इबोबी के सबसे करीबी रहने और उनसे राजनीतिक दांव-पेच सीखने वाले सिंह ने न सिर्फ उनसे बगावत की बल्कि पलटवार करते हुए सत्ता भी हासिल की।

आतंकवादी का भी कोई धर्म होता है

आरती कुमारी

यदि हम इस समय भारत सहित वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि सारा संसार इस समय एक अघोषित युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है । आतंकवाद के नाम पर एक वर्ग के लोग निर्दोष लोगों का खूनबहाना और अपना मजहबी विस्तार करना अपनी विरासत का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। वास्तव में निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर उन लोगों ने जिस प्रकार अपना विस्तार किया है, वह उनके लिए इस समय एक मार्गदर्शक अनुभव है। उस अनुभव की पिछली कई शताब्दियों से शेष संसार के लोग आलोचना करते आ रहे हैं। परंतु उन पर इस प्रकार की आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ । इसके विपरीत ये लोग इस प्रकार का विमर्श बनाने में भी सफल रहते हैं कि आतंकवाद मात्र मुट्ठी भर लोगों की सोच है । इस्लाम का आतंकवाद से दूर-दूर का भी संबंध नहीं है। इस दुष्प्रचार के लिए उनके पास एक पूरी फौज होती है , जो केवल इसी मोर्चे पर लड़ती है कि आतंकवाद को इस्लाम के साथ न जोड़ा जाए। अली सिना अपनी पुस्तक ' अंडरस्टैंडिंग मुहम्मद और मुस्लिम ' में लिखते हैं कि 11 सितंबर सन 2001 के बाद 13 वर्षों में 24300 आतंकी हमले हुए । परिणाम स्वरुप पूरे संसार में सैकड़ों हजारों नागरिकों की मृत्यु हुई और चोट पहुंची । औसतन प्रतिदिन पांच आतंकी हमले हुए। आक्रमणकारी अपराधकर्ता कोई दैत्य नहीं थे, अपितु मुसलमान ही थे। अपने मजहब में उनका विश्वास था और उसके अनुसार ही उन्होंने यह काम किया । ऐसी ही सोच वाले दसियों करोड़ और भी हैं , जो वह सब भी वही करने के लिए तैयार बैठे हैं। वह लिखते हैं कि इस्लाम अपनी सफलता के लिए आतंकवाद का ही ऋणी है। विद्वान लेखक की इस बात में बहुत ही बल है कि ' इस्लाम आतंकवाद का ऋणी है।' आज जितने भर भी देशों में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वहां कभी सनातनी हिंदुओं का वर्चस्व था। धीरे-धीरे सनातन के लोगों में जड़ता ने प्रवेश किया और वे कई स्थानों पर दोराहे की बजाए चौराहे पर आते चले गए। उनकी किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति का लाभ इस्लाम और ईसाई मत के लोगों ने कहीं तलवार से तो कहीं प्यार से, कहीं बहला फुसलाकर तो कहीं लालच देकर उठाने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस्लाम ने आतंकवाद के माध्यम से लोगों का भयादोहन करके ही अपना विस्तार किया है। जब तथ्य चीख चीखकर सच्चाई को बयां कर रहे हों, तब भी कुछ लोग यदि यह ना कहें कि इस्लाम और आतंकवाद का चोली दामन का साथ है तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पर तरस ही आता है। अली साहब हमें बताते हैं कि मदीना में अपना कदम रखने के साथ ही मोहम्मद ने अपने आतंक का अभियान आरंभ कर दिया था, तब से उनके अनुयाई भी यही करते चले आ रहे हैं। भारतीय मान्यता में किसी पर घात लगाकर हमला करना नैतिकता और मानवता के विरुद्ध है, जबकि इस्लाम इसे जायज मानता है। वीरता इसी में है कि शस्त्रयुक्त व्यक्ति से ही युद्ध किया जाए । इतना ही नहीं, जिस पर जैसा हथियार है वैसा ही हथियार वाला व्यक्ति उससे युद्ध करे। जब 10 वर्ष में 24300 आतंकी हमलों का एक कीर्तिमान एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम अंकित हो और प्रतिदिन पांच आतंकी हमले संसार में हो रहे हों , तब विश्व शांति की बात करना कितना उचित हो सकता है ?- यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह तथ्य और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग प्रतिदिन की पांच आतंकवादी घटनाओं को लगभग जीवन का एक अनिवार्य अंग मान चुके हैं । तभी तो इतने निर्मम अत्याचारों पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा को पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत इस प्रकार विषयांतरित कर दिया जाता है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता और आतंकवाद इस्लाम की मूल भावना के विपरीत है। टी0वी0 चैनलों पर या समाचार पत्रों में इस विषय में जो भी चर्चाएं होती हैं, उनमें कितने ही लोग आपको इसी प्रकार के विमर्श के इर्द-गिर्द घूमते लेख लिखते हुए या चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। इस प्रकार सत्य को मिट्टी में मिला दिया जाता है और अपराधी को भी मानव मानकर उसके अधिकारों का समर्थन करने के लिए लोग उठ खड़े होते हैं। इसका परिणाम यह आता है कि गजवा , सरिया और आतंकवाद के आधार पर काम करने वाले लोग निसंकोच अपने मिशन में लगे रहते हैं। इसके लिए धर्म परिवर्तन के नाम पर

लोगों को भेड़ की भांति मूंडा जाता है । लोगों की फटेहाली, गरीबी और लाचारी का लाभ उठाकर उनकी आत्मा का सौदा किया जाता है। पहले तो उन्हें शांति और उन्नति के सपने दिखाए जाते हैं, फिर उनके सपनों को निर्ममता से रौंदकर उनसे बेगार ली जाती है। उन्हें नारकीय जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में स्वाधीनता के समय लगभग ढाई से तीन करोड हिंदू रह गया था। आज मुट्ठी भर हिंदुओं को छोड़कर लगभग सारे हिंदुओं को पाकिस्तान का जिहादी आतंकवाद लील गया है। यदि स्वाधीनता के समय भारत में रहा 3 करोड़ मुसलमान 20-25 करोड़ हो सकता है तो माना जा सकता है कि पाकिस्तान का हिंदू भी कम से कम आज 10 करोड़ तो होता ही। इस प्रकार यदि देखा जाए तो सनातन को पिछले 75 वर्षों में 10 करोड हिंदू अकेले पाकिस्तान में ही खोने पड़े हैं। हमने अपनी हानि का भी आंकलन नहीं किया, जबकि धर्मांतरण के खेल में लगे रहकर अपनी संख्या बढ़ाने वाले लोग निरंतर अपने लाभ का आंकलन करते जा रहे हैं। वह जानते हैं कि यह लाभ उन्हें केवल और केवल आतंकवाद को फैलाए रखने से मिला है। ऐसे में उनसे यह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे आतंकवाद को छोड़कर सचमुच शांति की बातें करने लगेंगे ? बिल्ली को यदि झपट्टा मारने से कबूतर खाने को मिल सकता है तो वह झपट्टा मारने को कभी छोड़ने वाली नहीं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि झपट्टा मारना बिल्ली का मूल स्वभाव है और मूल स्वभाव को ही गीता में ' धर्म ' कहा गया है। यह मूल स्वभाव जब धर्म के रूप में आतंकवाद के साथ जुड़ जाता है तो यह इस्लाम बन जाता है। इस दृष्टिकोण से इस्लाम आतंकवाद का धर्म सिद्ध होता है। अतः यह भी मान लेना चाहिए कि आतंकवादी का भी कोई धर्म होता है।

सूडोकु नवताल- 7346

✶✩✩✩✩ सरल

	9				6			
4	7				8	3		9
		8	7	3		1	2	
	8	9		5	1		7	6
5	1		8	7		4	9	
	2	4		6	5	7		
7		1	3				5	8
			1				4	

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7345 का हल

1	9	3	7	5	4	2	6	8
8	4	2	1	6	3	9	7	5
5	7	6	8	2	9	3	1	4
4	1	5	6	3	2	8	9	7
7	2	9	4	8	1	6	5	3
3	6	8	5	9	7	1	4	2
2	5	1	9	4	8	7	3	6
9	8	4	3	7	6	5	2	1
6	3	7	2	1	5	4	8	9

यूरोप को राजनीतिक और कूटनीतिक झटके

डॉ. दिलीप चौबे

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक झटके यूरोप में महसूस किए जा रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में चल रहे सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भाषण ने यूरोप के सत्ता प्रतिष्ठानों को हिला दिया है। कुछ महीने पहले तक अमेरिका यूरोप के नेता एक ही सुर में बोलते थे। यूक्रेन युद्ध सहित अनेक विश्व मामलों में दुनिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बजाय आग में घी डालने का काम किया। यूक्रेन, रूस और यूरोप को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वायदे के अनुसार कार्यकाल के आरंभ में ही युद्ध समाप्त कराने तथा शांति वार्ता आयोजित करने के संबंध में ठोस पहल की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत की। ट्रंप का शांति फार्मूला है यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम हो तथा बातचीत शुरू हो। रूस को भरोसा दिलाया जाए कि यूक्रेन को कभी पश्चिमी देश सैन्य संगठन नाटो एवं सदस्य नहीं बनाया जाएगा। वास्तव में कुछ वर्ष पहले यदि यह घोषणा की गई होती तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग सेथ ने नाटो की बैठक में अमेरिका के इसी रवैये को दोहराया जो यूरोपीय सदस्य देशों को नागवार गुजरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुलकर ट्रंप प्रशासन का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि पर्दे के पीछे वह अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय देशों की लामबंदी का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का संबोधन यूरोप की सरकारों और नेताओं की नीतियों पर खुला प्रहार था। उन्होंने इन देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अपनाई जा रही पाखंडपूर्ण नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप को रूस और चीन सहित बाहरी शक्तियों के बजाय घरेलू ताकतों से असल खतरा है। जेडी वेंस ने आरोप लगाया कि यूरोपीय देशों में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तोरियस ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में आव्रजन, इस्लामी कट्टरवाद, गर्भपात, पर्यावरण और वैक्सीन आदि मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन तथा यूरोपीय नेताओं में मतभेद है। पिछले चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ ट्रंप को भारी जनादेश दिया था। ट्रंप प्रशासन अब इन्हीं नीतियों को अन्य देशों में फैलाना चाहता है। उपराष्ट्रपति वेंस का संबोधन ऐसे समय सामने आया है जब जर्मनी में आम चुनाव होने वाले हैं। चांसलर शोल्ज को कड़ी चुनौती का सामना है। यूरोप की अन्य देशों की तरह जर्मनी में भी आव्रजन और इस्लामी कट्टरवाद विरोधी राजनीतिक दलों की ताकत बढ़ रही है। जर्मनी के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी दल एडीएफ की ताकत में इजाफा हो रहा है। मस्क एडीएफ का समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में यह धारणा बन रही है कि ट्रंप प्रशासन चुनाव में दखलअंदाजी कर रहा है। यह विडंबना है कि कुछ दिन पहले जो यूरोपीय देश अन्य देशों को अभिव्यक्ति की आजादी की नसीहत दे रहे थे, वे आज खुद कठघरे में खड़े हैं। वास्तव में पश्चिम का वर्चस्ववादी वैकि तंत्र सूचना युद्ध पर टिका था। सूचना के सभी माध्यमों पर इन देशों का एकाधिकार था। किसी भी मुद्दे पर घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जनमत का निर्माण करने के लिए इस सूचना तंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। ट्वीटर, फेसबुक और व्हाट्सएप आदि के प्रचलन के बाद लोगों को सूचना के वैकल्पिक माध्यम हासिल हुए। एलन मस्क ने ट्वीटर का स्वामित्व हासिल करने के बाद इसे आंतरिक सेंसरशिप से मुक्त किया। वास्तव में भारत पश्चिमी देशों के सूचना एकाधिकार के दुष्परिणाम का भुक्तभोगी रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर कहते रहे हैं कि भारत और उसकी सरकार की छवि खराब करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जाता है। जयशंकर ने कुछ वर्ष पूर्व इसी म्यूनिख सम्मेलन में कहा था कि यूरोपीय देश यह मानते हैं कि इस महाद्वीप की समस्या विव्यापी है जबकि अन्य देशों की समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रकारांतर से जयशंकर के तर्क को ही आगे बढ़ाया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष राशि- आज आपको लोगों का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आज जीवनसाथी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। शाम को मेहमानों के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है, जिससे आपके धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

वृष राशि- आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। आपकी खुशियों में इजाफा होगा। ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम मिलने की संभावना है, जिसे पूरा करने पर फायदा होगा। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा, ग्राफिक डिजाइन कोर्स सीखने का मौका मिलेगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे। आज आप संतान के करियर की समस्याओं को किसी अनुभवी और जानकार की मदद से सुलझा लेंगे। विपरीत परिस्थितियों में सूझ-बूझ से काम लेंगे तो, आज किसी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। आज लम्बी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आप जोखिम भरे कामों से दूर रहें।

कर्क राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करें। कोई भी छोटा-बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको मुनाफा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी, परिवार में सभी एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनकी काम करने की क्षमता बेहतर होगी, आज आपका काम समय से पहले पूरा हो सकता है। महिलाएं अपने बिजनेस में ज्यादा एक्टिव रहेंगी, आपको ज्यादा धनलाभ होगा। घर में सुखद और अच्छा माहौल रहेगा, शाम का समय बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएंगे। आज आपकी सोची हुई कोई योजना पूरी होगी।

कन्या राशि- आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो आपके संतुलित रवैया से फायदा मिलेगा। आज थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थान पर बिताएंगे। आज शाम माता जी से आप भविष्य को लेकर विचार-विमर्श करेंगे। आज आपके मन में तरह-तरह की बाते चलेंगी। नजदीकी लोगों से बातचीत करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें।

तुला राशि- आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाया है। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनायेंगे। आप दूसरों पर अपना प्रभाव बनाने में सफल होंगे, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो आस-पास के लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज ऑफिस के सहकर्मी आपके कामों में सहयोग करेंगे, आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आज किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया जल्दी न दें, पहले स्थितियों को समझें फिर अपनी राय सोच समझ कर दें इससे लोगों के बीच आपकी अहमियत बढ़ जाएगी।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हर एक बात पर ध्यान देकर स्थिति को सुधारने कोशिश करें। आज पुरानी गलती दोबारा न हो, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ रहा है, नई जिम्मेदारियों के लिए आप खुद को तैयार करेंगे।

मकर राशि- आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। अपने दोस्तों से निजी समस्याओं को शेयर करने से बचना चाहिए। नये व्यवसाय में पैसा लगाने के बारे में आप सोच सकते हैं, एक्सपर्ट से राय लेना न भूलें। पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे।

कुंभ राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज किसी करीबी व्यक्ति से चल रही अनबन दूर होगी। जिन बातों में आपकी ज्यादा रुचि है, उन पर ध्यान देंगे आपको ख़ुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको जल्द ही सफलता मिलेंगी।

मीन राशि- आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आज व्यापार के मामलों में आपके मन में नए-नए विचार आएंगे। नए लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी।

क्या बिहार चुनाव तक लंबित होगा वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल ?

अशोक भाटिया , मुंबई

बीते दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इस संबंध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर संसद के सदनों में चर्चा चल रही है। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से हैं, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने की आहट से ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई । माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना चाहती है। जिससे वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की शक्ति कम हो जाएगी। इस बिल को लेकर जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार सरकार के मॉडल की तारीफ की है, वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का यह भी कहना है कि इस बिल की पूरी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन बिहार में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भू-राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिलों में डीएम को अधिकार दिए हैं। बताया जाता है कि मुस्लिम संगठनों को वक्फ बोर्ड विधायक के 44 बिंदुओं में से 33 पर आपत्ति है. जेपीसी में जो विरोधी दल है, वह बहिष्कार कर रहे हैं. तो ऐसे में बिहार में क्या स्थिति बनेगी. इस पर मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी संगठनों को आश्वासन दिया है कि बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान हो. मुस्लिम संगठनों को मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है. हमारे नेता ने ही जेपीसी में मामले को रखा है.मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धमकी देने की भी बात भी आ रही थी, इस सवाल पर मंत्री जमा खान ने कहा वैसी कोई बात नहीं है. कुछ लोग बोलते रहते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है. नीतीश कुमार वोट का लालच नहीं करते हैं. वोटरों का सम्मान करते हैं. सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं. माइनॉरिटी समाज के साथ हमेशा खड़े रहे हैं. उनके साथ कोई परेशानी आएगी तो खड़े रहेंगे. माइनॉरिटी समाज की नाराजगी को लेकर मंत्री जमा खान कहना है कि माइनॉरिटी समाज की कहीं से कोई नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं है. जमा खान ने कहा कि जेपीसी के दौरान जहां भी दिक्कतें थी उस पर बैठकर हम लोग बातचीत की है और उसे दूर किया जा रहा है और उन्हें दूर करने के बाद ही विधेयक को लागू किया जाएगा. बता दें कि वक्फ बोर्ड विधेयक संसद में पेश होने के बाद जदयू ने इसका समर्थन किया था. केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने समर्थन करते हुए कहा था कि मुसलमानों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है. लेकिन उसके बाद बिहार में भी सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री के सामने रखी थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर ललन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई थी. जिसमें सभी मुस्लिम संगठनों को भी बुलाया गया था. मुक़्तलिफ़ मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदार "वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल" के सिलसिले में मिले और वाज़ेह और तफ़्सील-वार गुफ़्तुगू हुई थी उनका कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी शुरू से ही अक़्लियत के हरेक मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं और किसी भी धार्मिक मामलों में सरकार के दख़ल-अंदाज़ी के ख़िलाफ़ हैं। इन संशोधनों से ना सिर्फ़ मुस्लिम बल्कि दीगर मज़हबों के मज़हबी, सकाफ़ती और जायदाद के हुक़ूक़ पर असर पड़ेगा और एक ग़लत नज़ीर क़ायम होगी। हमारी पार्टी मोदी-नीतीश NDA की इस ग़ैर संवैधानिक, ग़ैर ज़रूरी प्रस्तावित संशोधन बिल जो की मुल्क के सेक्युलर ताने-बाने को तोड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मक़सद से लाया गया है उसका पुरज़ोर विरोध करती है। हमने आये हुए डेलीगेशन को तसल्ली दिलाया कि हम उनके साथ हैं और किसी क़ीमत पर इसको संसद से पारित नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को सभी फोरम पर लड़ेंगे। अफ़सोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में हैं गौरतलब है की इस समय वक्फ बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों का निशाना बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ भी है। तो वहीं, विपक्ष की कोशिश है कि जेडीयू के ऊपर दबाव डालकर इस बिल को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक खींचा जाए। जिसे कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जीत मानकर उसे विधानसभा चुनाव में जोर-शोर से प्रचारित करेगा। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम समाज में सुधार हो और जरूरत के हिसाब से लोगों को उनके अधिकार सुनिश्चित हो सकें।आगे उन्होंने बताया कि वक्त बिल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चुनाव के दौरान ही जोर पकड़ते हैं, यह एक प्रकार का ट्रेंड बन चुका है। जो हमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिख चुका है और इसी प्रकार की कोशिश बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी हो रही है। इसके अलावा भी आगे असम और बंगाल विधानसभा चुनावों को भी सभी राजनीतिक दल जीतने की कोशिश करेंगे और यही लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ना तो जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया और ना ही इसे इस मानसून सत्र में भी लागू नहीं किया। एडिटर नीरज कुमार दुबे ने इस बिल को लेकर अपनी राय देते हुए बताया कि यह बिल वर्तमान समय की मांग है। तो वहीं, इसके प्रावधानों को और भी अधिक सख्त किया जा सकता है। भाजपा का मानना है कि इसके लिए सभी समुदायों से बात करना जरूरी है इससे मुस्लिम समाज में लोगों को उनके अधिकार निश्चित रूप से मिलेंगे। आगे उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के दौरान हुए आंदोलन से सबक लिया है। इसीलिए सरकार एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। जिससे इस विधेयक को लेकर कोई बड़ा जनांदोलन आकर ना ले सके। तो वहीं, इसी प्रकार केंद्र सरकार छोटे-छोटे टुकड़ों में राज्यों में यूसीसी लागू करके लोगों के मन में जो संदेह व्याप्त है, उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। जब यूसीसी से सभी समुदायों के अंदर का डर खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का विचार जरूर करेगी।उन्होंने आशंका जताई कि अगर कोविड ना आया होता तो शायद नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन अभी भी चल रहे होते और इस एक्ट को लेकर पूरी दुनिया में सरकार की आलोचना हुई थी। इसी प्रकार का सबक सरकार ने किसान आंदोलन से भी लिया है। यह एक गठबंधन की सरकार है। इसीलिए मोदी सरकार सभी दलों और संगठनों के साथ सामंजस्य से ही आगे बढ़ने का विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की उस शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के कई अधिकारों पर रोक लग सकती है। वर्तमान में देशभर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस बिल को लेकर क्या बहस होती है और इसका बिहार समेत पूरे देश पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए हाल में ही कहा कि मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार नहीं कर सकता।उन्होंने यह भी कहा कि संसद से इस विधेयक के पारित होने पर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।मदनी ने यह बयान उस वक्त दिया जब बृहस्पतिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया।मुस्लिम संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मदनी ने कहा कि शंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, वे सही साबित हुईं। इन संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलना चाहती है, ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए और उनका मुस्लिम वक्फ का दर्जा खत्म हो जाए।''उनका कहना था कि पहले के कानून की धारा 3 में वक्फ बोर्ड यह तय करता था कि कोई वक्फ वैध है या नहीं, अब मौजूदा संशोधन में यह अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है, लेकिन अब मौजूदा 14 संशोधनों में जो अभी संसद में पेश किए गए हैं, एक नए संशोधन ने कलेक्टर से लेकर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी को जांच का अधिकार दिया है जो यह तय करेगा कि यह संपत्ति सरकारी है या वक्फ की जमीन है।मौलाना मदनी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद वक्फ नियम में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा है कि हम इस तानाशाही कानून को स्वीकार नहीं कर सकते।मदनी ने कहा कि ''धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों'' के पास अभी भी मौका है कि वे इस कानून को संसद में पारित होने से रोकें और इसका खुलकर विरोध करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि यह कानून पारित हो जाता है तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों और न्यायप्रिय लोगों के साथ मिलकर सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का भी उपयोग करेगी।

संपादकीय

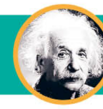

❝ शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। -अल्बर्ट आइन्स्टीन

भुवनेश्वर के एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान की छात्रा प्रकृति लामसाल की आत्महत्या वाकई क्षुब्ध करने वाली है। सच तो सामने आ ही जाएगा, पर ऐसे मामलों में शिक्षण संस्थान भी कम दोषी नहीं, जो छात्रों की शिकायतों पर लापरवाही दिखाते ही हैं, कोई अनहोनी होने पर पर्दा डालने की भी भरसक कोशिश करते हैं।

प्रकृति के दोषी

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान में अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या, जैसा पुलिस बता रही है, जितनी क्षुब्ध करने वाली है, कॉलेज प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप भी उतने ही संगीन हैं। छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला उसका कथित प्रेमी हिरासत में है। अस्तु, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन जिस तरह आनन-फानन अन्य नेपाली छात्रों को हॉस्टल से निकालते हुए बसों में बैठाकर कटक रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया, जबकि 28 फरवरी को उन्हें परीक्षा देनी थी, उससे संस्थान के इरादों पर संदेह तो गहराता ही है। यह मान भी लिया जाए कि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था, तो वैसी सूरत में मामले के तूल पकड़ने पर संस्थान ने अपना फैसला वापस लेते हुए नेपाली छात्रों को दोबारा छात्रावास में रहने की अनुमति क्यों दे दी? ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी छात्र या छात्रा की मौत की घटना को लेकर सवाल उठे हों। अक्सर देखा गया है कि कॉलेज प्रशासन ऐसे मामलों में लीपापोती करने की कोशिश करता है, ताकि संस्थान की छवि खराब न हो। कोलकाता में पिछले वर्ष प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज ने भी यही रवैया दिखाया था, लेकिन क्या यह सही तरीका है? किसी भी संस्थान की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण छात्रों की सुरक्षा और उनका भरोसा होता है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामले में तो यह और भी महत्वपूर्ण है। होना तो यह चाहिए कि विदेशी छात्रों के लिए एक अलग से सहायता तंत्र हो, ताकि वे किसी भी कठिनाई में कॉलेज प्रशासन से उचित मदद पा सकें। लेकिन इस मामले में प्रथमदृष्टया जो स्थितियां दिख रही हैं, वे एकदम उलट हैं। सोशल मीडिया पर नेपाली छात्रों के साथ संस्थान के शिक्षकों की बहस के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अगर वे वास्तविक हैं, तो उनमें शिक्षकों का नेपाली छात्रों के प्रति रवैया

वाकई बेहद शर्मनाक दिख रहा है। यदि हम अपने शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्र, चाहे वह किसी भी देश से हो, सुरक्षित व सम्मानित महसूस करे। ऐसे में, जरूरी है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में शीघ्र व निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और छात्रों का भी भरोसा बना रहे। यह महज एक संस्थान का नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का भी सवाल है। नेपाली छात्रा की मौत सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यवस्था से पूछा गया एक सवाल भी है, जिसका सही जवाब 'न्याय' ही होगा।

ट्रंप, मोदी और चाणक्य नीति

मोदी व ट्रंप की मुलाकात में संकेत मिला कि 2025 में भारत एक आत्मविश्वासी वैश्विक नेता बनकर उभरेगा। यह कहकर कि उन्होंने ट्रंप से सीखा कि देश को सर्वोपरि रखना कितना अहम है, मोदी उसी चाणक्य नीति का पालन करते दिखे, जो कहती है कि प्रतिद्वंद्वी को आदर्श बताकर उसे निहत्था करना सर्वोत्तम कूटनीति है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में मिले। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे चौथे विदेशी नेता थे, जो दूसरी पारी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं। उनसे पहले अमेरिका के कट्टर सहयोगी इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के राजा ट्रंप से मिल चुके हैं, जो गाजा पट्टी से निकाले जाने वाले फलस्तीनियों को अपने यहां लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो इस बार की मुलाकात में क्या खास बात रही? इससे यह संकेत मिला है कि वर्ष 2025 में भारत एक आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर वैश्विक नेता के रूप में पहचाना जाएगा।

दीपक वोहरा
पूर्व राजनयिक

हालांकि, दो दिग्गज वैश्विक नेताओं की यह मुलाकात पूरी तरह से व्यापार को लेकर थी। व्यापार एक ऐसा विषय है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और उनके भारतीय गुजराती समकक्ष, दोनों पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फोकस के क्षेत्र होंगे-प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, लचीली आपूर्ति, ऊर्जा (विशेष रूप से छोटे परमाणु रिएक्टर)। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत अमेरिका से बहुत सारा तेल और गैस खरीदेगा, जिसकी भारत को जरूरत है और अमेरिका के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से सीखा है कि देश को सर्वोपरि रखना कितना महत्वपूर्ण है और वह भी यही कर रहे हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना और उसे आदर्श बताकर निहत्था करना चाणक्य की प्राचीन रणनीति है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को हल करने की पहल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, दोनों से समाधान खोजने का आग्रह किया। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा चीन था। हाल ही में बीजिंग ने अमेरिका, भारत तथा सामान्य रूप से विश्व को दी जाने वाली धमकियों में नरमी बरती है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ते हैं।

अपने शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने बांग्लादेश की हिंसा और शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद वहां अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की आलोचना की थी। ट्रंप अपने देश को वैश्विक संकटों से अलग रखना, न कि नए संकटों में उलझाना चाहते हैं। इसके अलावा, कमजोर बांग्लादेश अमेरिका से कोई भी सार्थक वस्तु नहीं खरीदता, इसलिए व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप को वास्तव में उसकी परवाह नहीं है। लगता तो यही है कि हिलेरी क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस के करीबी मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता से हटा देंगे। भारत और अमेरिका, दोनों इस्लामी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इसलिए संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि आतंकवाद के वैश्विक संकट से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरे देखे द्विपक्षीय संयुक्त बयानों में यह पहला ही है, जिसमें अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा (अंतिम दो पाकिस्तान में स्थित हैं) सहित आतंकी गुटों का विशेष उल्लेख किया गया है। 'हमारे नागरिकों' को नुकसान पहुंचाने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की साझा इच्छा के चलते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी और पूर्व पाकिस्तानी सेना कप्तान तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की घोषणा की। संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान से आग्रह किया गया कि वह 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमलों के दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाए तथा यह सुनिश्चित करे कि उसके भू-भाग का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न किया जाए।

भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते हुए। इस तरह अमेरिका ने भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण के साथ एक प्रमुख रक्षा साझेदार और एक प्रमुख क्वाड साझेदार के रूप में मान्यता दी। जाहिर है, नरेंद्र मोदी की यह यात्रा रक्षा सहयोग पर केंद्रित थी, जिसमें अमेरिका भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार कर अंतर-संचालन और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों में अमेरिकी और भारतीय सेनाओं की विदेशी तैनाती का समर्थन करते हैं और उसे बनाए रखेंगे। साफ है कि दोनों देश इस अहम क्षेत्र में अपने अड्डे साझा कर सकते हैं।

अरब सागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद के लिए संयुक्त समुद्री सेना नौसैनिक टास्क फोर्स में भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भारत को अमेरिका का खुला समर्थन स्पष्ट रूप से चीन के कारण है। इस यात्रा से अमेरिका-भारत ट्रस्ट की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत तेल एवं गैस (ऊर्जा) के लिए भूखा है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। भारत ने अमेरिका से अवैध भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया, और यात्रा से ठीक पहले 104 भारतीयों को वापस भेजने के तरीके पर भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को देखते हुए ट्रंप को अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया।

ट्रंप चाहते थे कि भारत विशिष्ट अमेरिकी उत्पादों पर अपने सीमा शुल्क (टैरिफ) को कम करे व भारत ऐसा कर रहा है। ट्रंप ने माना कि नरेंद्र मोदी उनसे भी बेहतर सौदेबाज हैं। इसके अलावा, अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं के आव्रजन व आसान वीजा प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के बारे में भी चर्चा हुई। यात्रा से कुछ दिन पहले, अमेरिकी विदेश विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया कि कैसे अमेरिकी डार्क स्टेट ने 2019 में नरेंद्र मोदी की लगातार चुनावी जीत से भयभीत भारतीयों को शामिल करके भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2025 को भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में याद किया जाएगा।

जीवन धारा

परमहंस योगानंद

प्रशंसा आपको बेहतर नहीं बनाती, न ही निंदा बदतर बनाती है। फिर इन दोनों पर ध्यान क्यों दें? जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उससे मुग्ध होने के बजाय खुद का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें।

प्रशंसा और निंदा दोनों पर ध्यान दें

***रचनात्मक** आध्यात्मिक चेतना मनुष्य की आत्मा में निवास करती है। ईश्वर द्वारा दी गई इस शक्ति का उपयोग करेंगे, तो आप खुद के भाग्य के स्वामी बन जाएंगे। हम इस चेतना का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से ही खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। इस विषय पर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि 'विचार ही वस्तु है।' हम अक्सर एक कहावत कहते हैं कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में विचार करता है, वैसा ही वह होता है। इस बात ने हजारों लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है और उन्हें पहले से बदल दिया है। इस चेतना को विकसित करें कि आप ब्रह्मांड के सम्राट की संतान हैं और अपने पिता के सबसे प्रिय। अपने पिता के प्रिय होने के नाते आपको अधिकार है कि इस चेतना को आप अपने अनुसार इस्तेमाल करें। कभी भी किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगें, बल्कि यह विचार रखें कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। ईश्वर की संतान के रूप में आपको आत्मविश्वास हासिल करना है। हमें उस बच्चे की तरह रहना चाहिए, जो अपने माता-पिता के समक्ष सुरक्षित होकर सुखपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ सभी भय को त्याग देता है। इसके विपरीत, जो इन्सान अपने भीतर छिपे हुए बालसुलभ गुणों को विकसित नहीं कर पाता, वह आत्मग्लानि से लगातार पीड़ित रहता है। इस तरह शर्म, चिंता, भय और आसक्ति, उसकी शांति को दुख के सागर में डुबो देती है और असफलताएं बार-बार घेरती हैं। इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर मौजूद रचनात्मक आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। असफलता के बाद हर नए प्रयास को अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए और ध्यान के माध्यम से खुद को ऊर्जावान बनाना चाहिए। अगर कोई बुरी आदत आपको परेशान करती है, तो दो काम करें, इसके नकारात्मक रूप से बचने की कोशिश करें और हर उस चीज से बचें जिससे यह उत्पन्न हुई है, बिना उस पर ध्यान केंद्रित किए। वहीं, सकारात्मक रूप से अपने दिमाग को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें और इसे तब तक पूरी तरह से विकसित करने में व्यस्त रखें, जब तक कि यह आपका एक हिस्सा न बन जाए। जितना अधिक आप स्वयं में सुधार करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने आसपास के अन्य लोगों को भी बुलंद करेंगे। चूंकि, प्रशंसा आपको बेहतर नहीं बनाती, न ही निंदा आपको बदतर बनाती है। फिर इन दोनों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उससे मुग्ध होने के बजाय खुद का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। दूसरी ओर, जब लोग निंदा करें, तो उसका बुरा न मानें। यह विचार करें कि हमारे अंदर ऐसी कौन-सी बात है, जिसको हम सुधार सकते हैं।*

गलती स्वीकार करना सीखें

सूत्र

अगर आपकी गलती के लिए कोई भी आपको दोषी ठहराता है और आप वाकई दोषी हैं, तो तुरंत खुद की गलती को स्वीकार कर लें और उसमें सुधार करें। लेकिन अगर आप दोषी नहीं हैं, तो हंसें और उसे भूल जाएं। साथ ही बुरी आदतों को अपने विचारों की धारा में बहने न दें। एक समय बाद सत्य खुद आपके लिए बोलेगा।

दूसरा पहलू

हवाई हादसे टालने के लिए लगभग सभी यात्री विमान टीसीएएस तकनीक से युक्त होते हैं, फिर भी चूक हो रही है।

अत्याधुनिक विमान क्यों हो रहे क्रैश

बीते माह अमेरिका में यात्री विमान और सेना के हेलिकॉप्टर के टकराने से 60 लोगों की मौत हो गई थी, तो इससे पहले दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान में सवार 181 लोगों में से दो को छोड़कर सभी की मौत हो गई। हाल ही में कनाडा के टोरंटो में हुए विमान हादसे में 18 लोग घायल हो गए। अमेरिका के पास विमान हादसे रोकने के लिए सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, जिसे इस तरह से विकसित किया गया है कि वह पायलटों को हवा में विमान के टकराने की आशंका होने पर सूचित कर देती है। इस तकनीक को ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (टीसीएएस) कहते हैं। टीसीएएस ट्रांसपोंडर से युक्त अन्य विमानों के लिए विमान के आसपास के हवाई क्षेत्र की निगरानी करती है। इसके उपकरण आने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। बाहरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से स्वतंत्र रूप से संचालित इस प्रणाली को कभी-कभी एयरबोर्न कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (एसीएएस) भी कहा जाता है, जो पायलटों को पास के विमानों और संभावित टकराव के प्रति तुरंत सचेत करती है, ताकि पायलट विमान को ऊपर या नीचे कर या फिर उसकी दिशा मोड़कर हादसे को टाल सकें। ये नई प्रणालियां एक-दूसरे से संवाद करने में भी सक्षम हैं। वर्ष 1974 में विकसित हुई यह तकनीक धीरे-धीरे उन्नत होती गई। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी विमान को शिकागो कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, टीसीएएस से सुसज्जित होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सैन्य हेलिकॉप्टर इस नियम के तहत नहीं आते। इसलिए रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टकराए सैन्य हेलिकॉप्टर में टीसीएएस प्रणाली नहीं थी। टीसीएएस तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं। लगभग 300 मीटर ऊंचाई से नीचे विमान के उड़ने पर टीसीएएस ठीक से काम नहीं करती। बताया जाता है कि जब हादसा हुआ, तब अमेरिकी एयरलाइंस के विमान की अंतिम ऊंचाई करीब 90 मीटर और सैन्य हेलिकॉप्टर की ऊंचाई 60 मीटर के आसपास थी। इतनी कम ऊंचाई पर विमानों के आमने-सामने होने की स्थिति में उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल होता है। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट अमेरिका का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। फिलहाल जांच की जा रही है कि हादसा तकनीकी खामी की वजह से हुआ या किसी अन्य चूक की वजह से।

क्रिस्टल झांग

यह तकनीक पायलटों को संभावित टकराव के प्रति सचेत करती है, ताकि पायलट विमान को ऊपर या नीचे कर या दिशा मोड़कर हादसे को टाल सकें।

टीसीएएस तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं। लगभग 300 मीटर ऊंचाई से नीचे विमान के उड़ने पर टीसीएएस ठीक से काम नहीं करती। हादसे के वक्त यात्री विमान 90 व सैन्य विमान 60 मीटर की ऊंचाई पर थे।

आंकड़े

पर्यटकों की पसंद

वर्ष 2024 में पर्यटकों ने विभिन्न देशों की यात्रा की, लेकिन उनकी पहली पसंद फ्रांस के पर्यटन स्थल रहे।

फ्रांस	8.94
स्पेन	8.37
अमेरिका	7.93
चीन	6.57
इटली	6.45

आंकड़े करोड़ में, भारत में बीते वर्ष 1.79 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे | स्रोत : UNT

एक व्यक्ति ने दयालदास स्वामी से कहा कि स्वामी कभी दास नहीं होते। उन्होंने कहा, हर कोई अपने शिष्यों का स्वामी और गुरु का दास होता है।

सदाचार ही साधु का जीवन है

दयालदास स्वामी का जन्म पंजाब के कपियाल गांव में हुआ था। उनके पिता साधु-संतों की सेवा करते थे, जिसके कारण दयालदास को बाल्यकाल में ही साधु-संगति प्राप्त हुई। बारह वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया व पटियाला के बेसरा गांव में परमहंस बाबा ठाकुरदास से दीक्षा ग्रहण की।

इसके बाद उन्होंने पंद्रह वर्ष तक गुप्त साधना की। गुरुदेव के समाधि लेने पर दयालदास ने बहुत बड़ा भंडारा किया। अब उनकी सिद्धि सब ओर फैल गई। इसलिए वह उस स्थान को छोड़कर तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। दयालदास स्वामी जी स्वतंत्र आसन या गद्दी पर नहीं बैठते थे। वह कुशासन या बालू का आसन ही पसंद करते थे। राजा से लेकर साधारण पुरुष तक उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन अपने ज्ञान के अभिमान में चूर व्यक्ति ने दयालदास स्वामी के पास जाकर पूछा, 'आप कौन स्वामी हैं?' दयालदास स्वामी जी बोले, 'मैं केवल स्वामी ही नहीं हूं, बल्कि दासस्वामी भी हूं।' उन्होंने कहा, 'संन्यासी तो कभी दास नहीं होते, स्वामी होते हैं।' इस पर दयालदास स्वामी बोले- 'भैया! अपने शिष्यों के सामने सभी स्वामी होते हैं और गुरुओं के सामने सभी दास होते हैं।' दयालदास स्वामी के इस विचारपूर्ण वार्तालाप से उसका का भ्रम दूर हो गया और वह उनके शरणागत हो गए। दयालदास स्वामी दैवी संपत्ति पर बड़ा जोर देते थे। उनका कहना था कि सदाचार ही साधु का जीवन है।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

पत्थर में प्राण फूंकने वाले शिल्पकार का जन्मदिन

कुछ लोगों में ऐसी विलक्षण प्रतिभा होती है, जो उन्हें बाकी सबसे अलहदा और खास बना देती है। अपनी सधी उंगलियों से पत्थर और मिट्टी में प्राण फूंकने वाले देश के महान शिल्पकार राम वनजी सुतार भी एक ऐसी ही शख्सियत है गुजरात में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा का मूल स्वरूप भी इस महान शिल्पकार ने तैयार किया है। उन्नीस फरवरी 1925 को जन्मे सुतार ने महात्मा गांधी की बहुत सी प्रतिमाओं को आकार दिया है। पद्मश्री और पद्मभूषण राम वनजी सुतार ने गांधी की साढ़े तीन सौ से ज्यादा मूर्तियां गढ़ी हैं जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में पूरे सम्मान के साथ लगाई गई हैं। संसद में लगी इंदिरा गांधी, मौलाना आज.ाद और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमाएं भी सुतार ने बनाई हैं। 1630: मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। 1986 : भारत में पहली बार कंप्यूटर द्वारा रेलवे टिकटों के आरक्षण की प्रणाली शुरू की गई। 2002 : हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में प्लेग के कुछ मामले सामने आए।

अब तदर्थ न्यायाधीशों पर दारोमदार

उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में अब तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिका बढ़ जाएगी।

सीबीपी श्रीवास्तव | कानून

न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर चर्चा में रहती है। कई बार विवादों में या फिर प्रक्रियाओं की व्यावहारिकता को लेकर। 30 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अनुमति दी है कि वे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति करें, ताकि लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके। तदर्थ न्यायाधीश एक प्रकार से अस्थायी न्यायाधीश होते हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती है, जबकि अस्थायी न्यायाधीश एक निश्चित समय-सीमा के लिए नियुक्त होते हैं।

उच्च न्यायालयों के लिए कई प्रकार के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के प्रावधान संविधान में हैं। कारण यह है कि उच्च न्यायालय की विषय वस्तु अधिकारिता उच्चतम

न्यायालय से अधिक विस्तृत है और मामलों का बोझ भी उन पर अधिक है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति दो वर्षों के लिए तब की जाएगी, जब उच्च न्यायालय पर कार्य का बोझ बढ़ गया हो, जबकि यदि कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, तो अस्थायी रूप से कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ये दोनों ही नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। चूंकि नियुक्ति करने की शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति है और राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कार्यपालिका का प्रधान भी है, अतः उसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 से अनुच्छेद 224-ए जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी जरूरत पड़ने पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। ध्यातव्य हो कि उच्चतम न्यायालय ने 2021 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिए गए दिशा-निर्देश में कहा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तब की जाएगी, जब रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20 फीसदी से अधिक हैं, या एक श्रेणी के मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं, या 10 फीसदी से अधिक लंबित मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं या निपटान दर नए केस दायर करने की दर से कम है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 2021 के अपने निर्णय में परिवर्तन करते हुए यह कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय दो से पांच तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो उसकी स्वीकृत क्षमता के 10 फीसदी से अधिक नहीं होंगे। ऐसे न्यायाधीश आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर सकेंगे, जिससे लंबित मामलों की संख्या घटेगी। उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जोर दिया कि प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। विचारणीय है कि उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। 2021 के फैसले से 80 फीसदी कार्य क्षमता की स्थिति ने कई उच्च न्यायालयों में तदर्थ नियुक्तियों को रोक दिया था। उल्लेखनीय है कि कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, न्यायालय ने 'निरंतर परमादेश' के माध्यम से लोक प्रहरी मामले में कार्यवाही को खुला रखा था। निरंतर परमादेश न्यायालय का वह आदेश है, जिसका उपयोग जांच की निगरानी करने, उचित जांच सुनिश्चित करने और कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है। न्यायालय के ऐसे निर्णय के बाद कई प्रश्नों का उत्तर देना समीचीन होगा। पहला, क्या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से नियमित नियुक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? यहां विचारणीय है कि नियमित और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक-दूसरे से स्वतंत्र है। अतः ऐसी कोई आशंका नहीं है। दूसरा, यह प्रश्न कि क्या इससे कार्यरत न्यायाधीशों की वरिष्ठता प्रभावित होगी, भी प्रासंगिक प्रतीत नहीं होती।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 06 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

संपादकीय

हादसों का महाकुंभ?

लगता है प्रयागराज में जारी महाकुंभ डुबकी लगाने वालो के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ हादसों का महाकुंभ भी बनता जा रहा है। ताजा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को हुआ, जब वहां मची भगदड़ में 18 लोग बेमौत मारे गए। कई घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये सभी प्रयागराज जाने की जल्दी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रयागराज जाने वाली दो ट्रेनों के रद्द होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हजारों यात्री बेचैन हो गए। इस बीच एक अन्य ट्रेन वहां से निकली तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस बीच प्लेटफार्म आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला निरंतर जारी रहा। धक्का मुक्की से बचने के लिए कुछ लोगों ने तेजी से सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां से आने वाली भीड़ के चलते वह ऐसा नहीं कर सके। परिणामस्वरूप कई लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। इस दौरान उमड़ी भीड़ का अंदाजा न तो रेलवे अधिकारी लगा पाए और न ही आरपीएफ के अधिकारी। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्ट्या रेलवे की गलती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने हादसे की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक रेलवे द्वारा अचानक गाड़ी का प्लेटफार्म बदलने से अफरा तफरी की स्थिति बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिवगंगा एक्सप्रेस जा रही थी। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म 14- 15 पर आ गई। प्रयागराज की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से जा रही हैं। प्लेटफॉर्म भीड़ संभाल नहीं पाया और भगदड़ मच गई। सामान्य परिस्थिति में भी अगर अचानक प्लेटफार्म बदलने की सूचना रेलवे द्वारा दी जाए तो यात्रियों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है। वर्तमान में तो सभी रेलवे स्टेशनों पर कुंभ यात्रियों की भारी भीड़ है। ऐसे में रेलवे के अधिकारियों को हालात की गंभीरता को देखते हुए कोई निर्णय लेना और तदनुसार ही प्लेटफार्म बदलने की घोषणा करनी चाहिए थी, जोकि नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं की गई। बताया जाता है कि हादसे के वक्त रेलवे पुलिस का भी कोई अता पता नहीं था। साथ ही ट्रेन की रवानगी और प्लेटफार्म बदलने की घोषणा में यात्रियों को इतना वक्त दिया जाना चाहिए था कि वो आराम से सामान लेकर दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंच सकें। ध्यान रहे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल 16 प्लेटफार्म्स हैं। अगर रेलवे विशेष परिस्थिति में भी विशेष इंतजाम और सतर्कता नहीं बरत सकती और वो भी देश की राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर तो इतने बड़े लवाजमें का मतलब क्या है? शनिवार रात 11 बजे तक टीवी न्यूज चैनलों पर यह खबर आने लगी थी, लेकिन तब भी रेलवे के आला अधिकारी इसे 'अफवाह' बताकर खारिज करते रहे। यह रेल अधिकारियों की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। विडंबना यह है कि एक तरफ सरकार महाकुंभ में हर दिन बढ़ती भीड़ के आंकड़े गर्व के साथ जारी कर रही है। इसे सही मानें तो कुंभ में हर रोज औसतन करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वह भगदड़ व हादसों की बात को यथा संभव दबा रही है। करीब एक माह पूर्व शुरू हुए कुंभ मेले में अब तक आगजनी के चार हादसे हो चुके हैं। जबकि दो बार भगदड़ हो चुकी है, जिसमे केवल 30 लोगो की मौत की पुष्टि सरकार ने की है। ताजा हादसा भले दिल्ली में हुआ हो, लेकिन उसका सम्बन्ध भी महाकुंभ से ही है। इनके अलावा कुंभ जाने और लौटने वाले श्रद्धालुओं के अलग अलग सड़क हादसों में भी दो दर्जन लोग जानें गवां चुके हैं।

भारत की कृत्रिम बुद्धिमता से किफायती नवाचार के साथ सशक्त होता भविष्य

भारत कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) में एक परिवर्तनकारी क्रांति देख रहा है और इस बदलाव के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्?द्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है। भारत के इतिहास में पहली बार, सरकार प्रत?यक्ष रूप से एक एआई क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जहां कंप्यूटिंग पावर, ग्राफिक?स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) और शोध के अवसर किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध हैं। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एआई सिर्फ़ कुछ खास लोगों के लिए न हो और इस पर बड़ी तकनीकी कंपनियों और वैश्विक दिग्गजों का वर्चस्व न हो। विशेष नीतियों के ज़रिए, मोदी सरकार छात्रों, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को विश्व स्तरीय एआई क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम बना रही है, जिससे वास्तव में समान अवसर मिल रहे हैं। चाहे वह इंडिया एआई मिशन हो या एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। मोदी सरकार की ये सभी पहल देश के एआई क्षेत्र को बेहतर बनाने का इरादा रखती हैं।

आइए एक नज़र डालते हैं कि मोदी सरकार भारत को वैश्विक एआई दिग?गज बनाने के लिए क्या कर रही है-

इंडियाएआई मिशन- एआई को सुलभ बनाने में अग्रणी भूमिका –भारत के एआई क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मोदी सरकार ने 2024 में 10,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी। अगले पांच वर्षों में यह निर्धारित निधि इंडियाएआई मिशन के विभिन्न घटकों को गति प्रदान करने के लिए तैयार है। एक उच्च-स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा द्वारा समर्थित, इंडिया एआई मिशन अब भारतीय भाषाओं का उपयोग करके भारतीय संदर्भ के लिए स्वदेशी एआई कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने करने के करीब है। एआई मॉडल की शुरुआत लगभग 10000 जीपीयू की कम्प्यूटेशन सुविधा से हो रही है। इसमें जल्द ही शेष 8693 जीपीयू जोड़े जाएंगे।

जीपीयू आधारभूत ढांचा और खुला जीपीयू बाजार – इंडिया एआई मिशन के लॉन्च होने की 10 माह की अवधि में, नोडल मंत्रालय जबर्दस?त प्रतिक्रिया प्राप्त करने और लगभग 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू की एक उच्च-स्तरीय और मजबूत सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा बनाने में सक्षम रहा है। यह ओपन सोर्स मॉडल डीपसीक की तुलना में लगभग नौ गुना और चैटजीपीटी की तुलना में लगभग दो तिहाई है। मोदी सरकार ने उल्लेखनीय रूप से, भारत के जीपीयू बाज़ार को खोलने की शानदार पहल की है और यह भारत में जीपीयू बाज़ार खोलने वाली पहली सरकार है, जिससे छोटे स्टार्टअप, शोधकर्ता और छात्र उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। जबकि प्रमुख देशों में एआई बाज़ार पर अक्सर बड़े उद्योग दिग?गजों का दबदबा होता है। मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में देश में संस्थाओं को एआई विकास के लिए 18,000 उच्च-स्तरीय जीपीयू-आधारित कंप्यूट सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उनमें से 10,000 पहले से ही उपलब्ध हैं। सरकार ने 10 कंपनियों का भी चयन किया है जो 18,693 जीपीयू की आपूर्ति करेंगी।

इसके अतिरिक्त, भारत अगले तीन से पांच वर्षों में अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करेगा और अगले 10 महीनों में एक घरेलू आधारभूत एआई प्लेटफ़ॉर्म की उम्मीद की जा सकती है। सरकार जल्द ही एक सामान्य कंप्यूट सुविधा शुरू करेगी जहां स्टार्टअप और शोधकर्ता कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुंच सकते हैं। जबकि वैश्विक जीपीयू एक्सेस की लागत लगभग ढाई से तीन डॉलर प्रति घंटा है, मोदी सरकार इसे केवल एक डॉलर प्रति घंटा पर प्रदान करेगी। शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षाविद, कॉलेज, आईआईटी, सभी को इस कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुंच मिल सकती है, और वे आधारभूत मॉडल शुरू कर सकते हैं।

इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म- ओपन डेटा के साथ एआई नवाचार को –सक्षम बनाना डेटा वह शक्ति है जो एआई शोध और नवाचार को आगे बढ़ाता है, और समृद्ध, विविध और प्रचुर डेटासेट के बिना, सबसे कुशल डेटा वैज्ञानिक और डेवलपर्स भी अवरोधों का सामना करते हैं। इसे पहचानते हुए, मोदी सरकार बड़े शोध समुदाय के लिए ओपन डेटासेट को सुलभ बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकार का लक्ष्य उच्च-गुणवत्ता वाले, गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना और एक एकीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म बनाना है। यह भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए सहज पहुंच को सक्षम बनाता है, जिससे एआई-संचालित नवाचार में तेज़ी आती है। इस एआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म में अज्ञात डेटा का सबसे बड़ा संग्रह होगा जो नवाचार को बढ़ावा देगा और एआई अनुप्रयोगों की क्षमताओं को बढ़ाएगा।

एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना – वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने नई दिल्ली में हेल्थकेयर, कृषि और बेहतर शहरी नियोजन एवं प्रबंधनयुक्त शहरों पर केंद्रित तीन एआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की घोषणा की। बजट 2025 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एआई के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। शिक्षा में एआई के लिए घोषित उत्कृष्टता केंद्र चौथा ऐसा केंद्र है। सरकार ने कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की योजना की भी जानकारी दी, जो युवाओं को उद्योग-संबंधित विशेषज्ञता से दक्ष करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक भागीदारी के साथ इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

भारत के आधारभूत वृहद भाषा मॉडल –भारत न केवल एक मजबूत एआई क्षेत्र विकसित कर रहा है, बल्कि आधारभूत एआई मॉडल बनाने में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भारत की एआई उन्नति स्वदेशी हो। इंडियाएआई ने प्रस्तावों के लिए कॉल के माध्यम से एलएलएम और एसएलएम सहित स्वदेशी आधारभूत एआई मॉडल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। डिजिटल इंडिया भाषिणी उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो भारत का एआई-आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करना है, जिसमें आवाज़-आधारित पहुंच शामिल है, और भारतीय भाषाओं में कंटेंट के सृजन में मदद करना है। भारतजेन दुनिया की पहली सरकारी वित्तपोषित मल्टीमॉडल एलएलएम पहल है। भारतजेन, एक जनरेटिव एआई है, जिसे भारत में वर्ष 2024 में दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भाषा, भाषण और कंप्यूटर विज़न आधारभूत मॉडलों का एक समूह विकसित करके सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाना और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। भारतजेन में देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के शीर्ष एआई शोधकर्ताओं का एक संघ शामिल है। सर्वम-1 एआई मॉडल, यह अभिनव बृहद भाषा मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है, जो एआई परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अंतर से संबद्ध है। सर्वम-1, 2 बिलियन मापदंडों का दावा करता है, दस प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जो भाषा अनुवाद, पाठ सारांश और सामग्री निर्माण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में क्रांति लाने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। चित्रलेखा एआई4भारत द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स वीडियो ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफ़ॉर्म है। उन्नत एआई मॉडल का लाभ उठाते हुए, चित्रलेखा उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में आसानी से ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने और संपादित करने की शक्ति प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म की ओपन-सोर्स प्रकृति सामुदायिक योगदान को प्रोत्साहित करती है और एआई-संचालित वीडियो प्रोसेसिंग में नवाचार को बढ़ावा देती है। एसएमएल के हनुमान ने एवरेस्ट 1.0 का अनावरण किया है, जो हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुमुखी बहुभाषी एआई प्रणाली है। यह प्रणाली वर्तमान में 35 भाषाओं का समर्थन करता है और जल्द ही यह भाषा क्षमताओं को 90 तक बढ़ाने के लिए तैयार है।

भारत वैश्विक एआई प्रतिभा और कुशलता में अग्रणी – मेट्रो शहरों से परे एआई प्रतिभा संभावनाएं और एआई शिक्षा इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स पहल के अंतर्गत एआई पाठ्यक्रमों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में विस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 50 एनआईआरएफ-रैंक वाले शोध संस्थानों में एआई पर शोध करने वाले पूर्णकालिक पीएचडी विद्वानों को फेलोशिप प्रदान की जा रही है। एआई शिक्षा तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित कर रही है। ये लैब व्यापक जनसांख्यिकी के लिए मूलभूत एआई पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) में एक मॉडल इंडियाएआई डेटा लैब पहले ही स्थापित की जा चुका है।

भारत वैश्विक एआई कौशल पैठ में पहले स्थान पर – स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार, भारत एआई कौशल पैठ में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है। भारत 2.8 के स्कोर के साथ एआई कौशल पैठ में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जो अमेरिका (2.2) और जर्मनी (1.9) से आगे है। भारत ने 2016 से एआई प्रतिभा संकेन्द्रण में उल्लेखनीय 263 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जिसने खुद को एआई में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत महिलाओं के लिए एआई कौशल पैठ में भी 1.7 की प्रवेश दर के साथ अग्रणी है, इसके बाद अमेरिका (1.2) और इज़राइल (0.9) का स्थान है। यह उपलब्धि एआई कौशल विकास में लैंगिक असमानता को पाटने के लिए भारत के जारी प्रयासों को दर्शाती है।

एआई नवाचार में बढ़ती उपस्थिति – जब नवाचार और तकनीक की बात आती है, तो भारतीय युवा सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली डेवलपर आबादी के रूप में उभरा है, जो गिटहब पर पब?लिक जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स में दूसरे स्थान पर है। भारत खुद को एआई के लिए एक नवाचार केन्?द्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसमें दुनिया की 16 प्रतिशत एआई प्रतिभाएं हैं और एआई कौशल को तेज़ी से अपनाया जा रहा है।

भारत शीर्ष 5 सबसे तेज़ी से बढ़ते एआई प्रतिभा केन्?द्रों में से एक – व्हीबॉक्स द्वारा ÷इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024÷ का अनुमान है कि भारत का एआई उद्योग 2025 तक 45 प्रतिशत सीएजीआर के साथ 28.8 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत में एआई-कुशल कार्यबल में 2016 से 2023 तक 14 गुना वृद्धि देखी गई है। सिंगापुर, फ़िनलैंड, आयरलैंड और कनाडा के साथ भारत शीर्ष पांच सबसे तेज़ी से बढ़ते एआई टैलेंट हब में से एक है। भारत में एआई पेशेवरों की अनुमानित मांग 2026 तक लगभग 1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

वैश्विक मंदी के बीच उल्लेखनीय रूप से विकसित – नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की नवंबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक मंदी के बीच भारत का जनरेटिव एआई क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है। इसने कहा कि भारतीय जेन एआई स्टार्टअप फंडिंग, वित?त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में लगभग 51 मिलियन यूएस डॉलर थी, जिसमें बी2बी और एजेंटिक एआई स्टार्टअप्स के नेतृत्व में तिमाही-दर-तिमाही 6 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई। प्रायोगिक उपयोग के मामलों से लेकर स्केलेबल, उत्पादन-तैयार समाधानों तक भारतीय जेन एआई क्षेत्र का विकास इसकी बढ़ती परिपक्वता में परिलक्षित होता है।

भारत एआई अपनाने में अग्रणी – बीसीजी द्वारा संकलित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत एआई अपनाने में अग्रणी है, जिसमें 80 प्रतिशत कंपनियां एआई को मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में पहचानती हैं, जो वैश्विक औसत 75 प्रतिशत से अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 69 प्रतिशत भारतीय कंपनियां 2025 में अपने तकनीकी निवेश को बढ़ाने की योजना बना रही हैं, इनमें से एक तिहाई कंपनियां एआई पहलों के लिए 25 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक आवंटित करने वाली हैं। यह एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन एजेंडे की दिशा में देश के अभियान को दर्शाता है। रैंडस्टैड एआई और इक्विटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, एआई ने भारत में कार्यस्थलों में तेज़ी से पैठ बनाई है, 2024 में 10 में से सात कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग कर रहे हैं, जबकि एक साल पहले यह संख्या 10 में से 5 थी।

भारतीय एआई क्षेत्र का निरंतर उदय – स्वायत्त एजेंटों जैसी एआई-संचालित तकनीकों का लाभ उठाकर, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय (एसएमबी), व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करने और बैक-ऑफ़िस संचालन को अनुकूलित करने के कुशल तरीके खोज रहे हैं। 'सेल्सफोर्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, एआई का उपयोग करने वाले भारत में 78 प्रतिशत छोटे और एसएमबी में आय वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में शामिल 93 प्रतिशत भारतीय एसएमबी ने कहा कि एआई ने आय बढ़ाने में मदद की है।

भारत में एआई बाज़ार की वृद्धि – भारत का एआई बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि बीसीजी-नैसकॉम रिपोर्ट 2024 द्वारा उजागर किया गया है। एआई बाज़ार 25-35 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ेगा, जो नवाचार और रोज़गार सृजन क्षमता पर भी जोर देगा। एआई नियमित कार्यों को स्वचालित करता है। साथ ही यह डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और एआई-संचालित अनुप्रयोगों में नए रोज़गार के अवसर पैदा करता है।

एक्सिलरेटर का बढ़ता नेटवर्क – भारत में इस समय 520+ टेक इनक्यूबेटर और एक्सिलरेटर उपकरण है। दुनिया में एआई क्षेत्र में कुल सक्रिय कार्यक्रमों में भारत में इसकी तीसरी सबसे बड़ी संख?या है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में भारतीय स्टार्टअप की जरूरतों को पूरा करने के लिए 42 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

टी-हब मैथ जैसे एक्सेलेरेटर एआई स्टार्टअप को उत्पाद विकास, व्यावसायिक रणनीति और स्केलिंग पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 के शुरुआती महीनों में, मैथ के पास 60 से अधिक स्टार्टअप थे, और उनमें से पांच वित्त पोषण के लिए विचारधीन है।

कावेरी इंजन- भारत के रक्षा क्षेत्र में सामरिक महत्व का केन्द्र

मोदी सरकार के बाद से भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित सैन्य बल में बदल गया है। वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक के रूप में, भारत क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,346 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 6,21,940.85 करोड़ हो गया है। यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, मेक इन इंडिया पहल और नीति सुधारों के माध्यम से, मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और विदेशी खरीद पर निर्भरता कम की है।

डॉ भूपेन्द्र कुमार

यह बदलाव रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक रहा है, जिसने देश को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के उत्पादन के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत ने विमान निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या यूसीएवी को बनाने के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही चीजें बदलने वाली हैं क्योंकि देश अपना स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन बनाने की ओर बढ़ रहा है जिसे कावेरी इंजन कहा जाता है। कावेरी इंजन विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य लड़ाकू जेट इंजन बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम है और इसके लिए मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दुनिया में अब तक केवल पांच देश ही ऐसे उन्नत इंजन बना सकते हैं और वे हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। भारत भी इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सबसे पहले 1989 में कावेरी नाम से जेट इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर 1990 के दशक में, जब भारत आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, तब देश ने स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसका नाम भी कावेरी रखा गया।

डिफेंसएक्सपी के अनुसार , कावेरी इंजन तेजस के लिए आवश्यक थ्रस्ट स्तर प्राप्त करने में असमर्थ था। शुरू में आफ्टरबर्नर के साथ 81 केएन का थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह केवल 70-75 द्मह ही प्राप्त कर सका, जो एलसीए की परिचालन आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, कावेरी इंजन शुरू में नियोजित की तुलना में भारी हो गया, जिसने तेजस विमान के समग्र प्रदर्शन और वजन-से-थ्रस्ट अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कावेरी डेरिवेटिव इंजन का आदर्श वजन 1000 किलोग्राम के भीतर होना चाहिए और अगले कुछ वर्षों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को बेहतर बनाने और ओवर-इंजीनियरिंग घटकों को कम करने के लिए काम चल रहा है।

कावेरी परियोजना, जिसे 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त पोषित किया गया था, ने कावेरी इंजन के 17 प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, पहली बोली में केवल 'कबीनी' नामक मुख्य मॉड्यूल ही मिल सका। तीसरा प्रोटोटाइप पहले तीन कंप्रेसर चरणों पर परिवर्तनीय इनलेट गाइड वैन पाने वाला पहला प्रोटोटाइप था और इसका पहला रन 1995 में हुआ था।

कावेरी इंजन का पहला पूर्ण परीक्षण 1996 में हुआ था, और सभी पाँच ग्राउंड-टेस्ट प्रोटोटाइप का परीक्षण 1998 में किया गया था। प्रारंभिक उड़ान परीक्षण 1999 के लिए योजनाबद्ध थे, और तेजस पर परीक्षण 2000 में होना था। लेकिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रौद्योगिकी अधिग्रहण में देरी के कारण कावेरी परियोजना धीमी हो गई। कावेरी परियोजना 2004 के मध्य तक लगातार आगे बढ़ती रही, जब रूस में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण के दौरान विफलता ने तेजस लड़ाकू विमान के पहले उत्पादन बैच के साथ इसके लॉन्च की सभी उम्मीदों को समाप्त कर दिया।

स्पुतनिक इंडिया के अनुसार , ड्राई कावेरी इंजन, जिसका रूस में उच्च-ऊंचाई परीक्षणों में परीक्षण किया गया था, भारत के पहले स्टील्थ यूसीएवी घातक को शक्ति प्रदान कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया ड्राई कावेरी इंजन एक टर्बोफैन इंजन है। इसे मूल रूप से भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के लिए सरकारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। हालाँकि, चूंकि इंजन आईएएफ द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए इसे 2008 में आधिकारिक तौर पर तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत लंबे समय से अपने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहा है और कावेरी इंजन परियोजना इसी लक्ष्य का हिस्सा है। यह ध्यान देने योग्य है कि जीटीआरई ने 23 दिसंबर, 2024 को घोषणा की थी कि भारत के पहले स्टील्थ, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी), घातक को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित नॉन-आफ्टरबर्निंग इंजन कावेरी को उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह भारत के स्वदेशी एयरो-इंजन विकास कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। जीटीआरई को उम्मीद है कि 2024-25 तक सभी परीक्षण पूरे हो जाएंगे और 2025-26 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि, इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह तेजस की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही।

क्या प्रगति हुई है?

स्पुतनिक इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2022 में, कावेरी के उच्च-ऊंचाई वाले परीक्षणों से पहले इंजन की दहन स्थिरता को मान्य करने के लिए भारत में कई परीक्षण किए गए थे, कथित तौर पर फरवरी 2023 में रूस के बारानोव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर डेवलपमेंट में आयोजित किए गए थे। सितंबर 2022 में, डीआरडीओ ने 2025 तक सभी परीक्षणों के अपने नियोजित पूरा होने से पहले अधिक परीक्षण करने के लिए आठ कावेरी इंजन बनाने के लिए गोदरेज एयरोस्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डीआरडीओ ने कावेरी को विकासाधीन यूसीएवी घटक में शामिल करने के लिए 2026 की समय सीमा तय की है।

एचएएल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन भी बना रहा है गौरतलब है कि 2023 में अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने भारतीय विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने का समझौता किया है। इस तकनीक के आने के बाद भारत लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने वाला दुनिया का पांचवां देश होगा। लड़ाकू विमानों के लिए विशेष इंजन बनाने की तकनीक अभी तक रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के पास ही है। यह समझौता भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान एमके2 के लिए इंजन बनाने के लिए किया गया है। भारत को जेई के एफ 414 इंजन के निर्माण का लाइसेंस दिया गया है। अभी तक एफ 414 इंजन के इस्तेमाल का लाइसेंस सिर्फ 8 देशों के पास है। अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। साथ ही एचएएल ने वायुसेना को सुखोई का पहला इंजन 'एएल-31 एफपी' भी दिया है

भारत में स्वदेशीकरण एक बड़ा सपना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ही अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने के सिद्धांत पर चल रही है। सैन्य जेट इंजन बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे बनाने के लिए दशकों के अनुभव की आवश्यकता होती है।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके घर किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है।

वृषभ
भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन बिजनेस में आपको जितने लाभ की उम्मीद थी, उतना न मिलने से मन थोड़ा परेशान रहेगा।

मिथुन
आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखना होगा। आपके मन में किसी बात को लेकर संशय बना रहेगा, तो उस काम में बिल्कुल आगे ना बढ़े।

कर्क
दिन मिला-जुला रहने वाला है। आप अपने काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पारिवारिक सदस्यों से किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना है।

सिंह
आप अपने घर की साज-सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे और यदि आपको काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होगी।

कन्या
लेनदेन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके काम में यदि कुछ रुकावट आ रही थी, तो वह भी दूर होंगी।

तुला
आर्थिक क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ कमाएंगे। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा।

वृश्चिक
सरकारी कामों में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आप अपने मन में किसी तरह की कोई ऐसी बात ना रखें, जिससे की आपका मन परेशान हो।

धनु
आज का दिन आपके लिए कुछ नये संपर्कों से लाभ लेकर आने वाला है। आपको अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आपको कोई सहयोगी मित्र के रूप में आपका शत्रु हो सकता है।

मकर
आज का दिन आपके लिए टेंशन भरा रहने वाला है। आपका स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन बना रहेगा, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी परेशान रहेंगे। आप किसी से कुछ भी बोल सकते हैं।

कुंभ
दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। दानपुण्य के कार्यों में भी आपकी काफी रुचि रहेगी। अपने कामो में सुख शांति बनाए रखने की आवश्यकता है।

मीन
आज का दिन आपके लिए आलस्य को दूर भगाकर कामों को करने के लिए रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दें और कामों को सूझबूझ दिखाते हुए करें।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बीमा कराने वालों के हितों की रक्षा का अहम कदम

बीमा योजनाओं को और अधिक भरोसेमंद बनाने तथा बैंकों में जमा राशि को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार के दो कदम स्वागत योग्य कहे जा सकते हैं। केंद्र ने बीमा कंपनियों को पॉलिसीधारकों के लिए फ्री लुक अवधि को एक माह से बढ़ाकर एक साल करने को कहा है। इसके तहत बीमा कराने के बाद बीमा पॉलिसी पसंद नहीं आने पर इसे एक साल के अंदर वापस कर सकेंगे। बीमा कंपनी को जमा किया गया प्रीमियम अमाउंट लौटाना होगा। इसी प्रकार सरकार बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवरेज को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे बैंक बंद होने या डूबने पर ग्राहक को अब पांच लाख रुपए से अधिक की रकम वापस मिल सकेगी।

बीमा कंपनियां अक्सर ग्राहकों को लुभावने वादों के साथ पॉलिसी बेचती हैं और कई बार विवादों में भी फंस जाती हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023–24 में मिससेलिंग यानी गलत तरीके से पॉलिसी बेचने के 23 हजार मामले सामने आए। पॉलिसी पसंद नहीं आने पर ग्राहक अभी एक महीने के भीतर पॉलिसी वापस कर सकता है, जिसे बढ़ाकर अब एक साल करने के लिए कहा गया है। ऐसे में ग्राहक अपने पॉलिसी विकल्पों को अधिक समय तक देख सकेंगे। ऐसी अवधि को फ्री लुक अवधि कहते हैं। इस अवधि में संतुष्ट नहीं होने पर रद्द करने के प्रावधान से निश्चित ही बीमा उद्योग में पारदर्शिता और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। हालांकि फ्री लुक अवधि के विस्तार से बीमा कंपनियों को नुकसान की आशंका तो रहेगी पर दीर्घावधि में उन्हें फायदा भी हो सकेगा। एक साल तक पॉलिसी वापस करने का विकल्प देने से ज्यादा संख्या में पॉलिसी रद्द होने का खतरा रहेगा। इससे बीमा कंपनियों के प्रीमियम का मुनाफा घट सकता है। साथ ही जमा राशि वापस करने से कंपनी में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। सीधे तौर पर बीमा कंपनियों को अधिक समय तक ग्राहकों के पॉलिसी निर्णय पर नजर रखनी होगी। ग्राहकों को जोड़े रखने के प्रयासों के तहत कंपनियां ग्राहकों के अनुभव और उनकी संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगी। साथ ही बीमा कंपनियां पॉलिसी की शर्तों, लाभों और शुल्कों के बारे में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता अपनाएंगी। इस सुधार से न केवल ग्राहक अनुभव में वृद्धि होगी, बल्कि कंपनियों को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्राप्त होगी।

इसी तरह बैंकों में जमा राशि पर भी बीमा कवरेज बढ़ने से पांच लाख से अधिक की रकम मिल पाएगी। सरकार के इस कदम से भी जनता में बैंकों के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।

सामयिक : अप्रत्यक्ष रूप से वसूले जा रहे टोल टैक्स को लेकर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत

टोल टैक्स वसूली के नियमों में उलझा आमजन

विजय गर्ग
आर्थिक विशेषज्ञ, भारतीय एवं विदेशी कर प्रणाली के जानकार
@patrika.com

टोल टैक्स प्लाजा से गुजरना वाहन चालकों के लिए किसी पीड़ा से कम नहीं है। अधिकांश टोल टैक्स प्लाजा पर आधी लेन अक्सर बंद रहती हैं। यदि किसी वाहन का फास्टैग सही से काम नहीं कर रहा तो पीछे खड़े वाहन चालक परेशान होते हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की थी कि अगर सड़कें खराब हैं तो इस पर सफर करने वाले टोल टैक्स भी क्यों दें? आम आदमी इसका खामियाजा क्यों भुगते? सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर शायद न तब सरकार पर हुआ था और न अब हो रहा है, क्योंकि खस्ताहाल हाईवे के बावजूद आम जनता टोल टैक्स देने के लिए मजबूर है। टोल टैक्स एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, जो नेशनल और स्टेट हाईवे पर इसलिए लिया जाता है, ताकि सरकार अच्छी सड़कें मुहैया करा सके, लेकिन आए दिन ऐसे समाचार हमें पढ़ने को मिलते हैं कि हाईवे जर्जर है, फिर भी टोल टैक्स की वसूली निरंतर जारी है। टोल टैक्स के मकड़जाल से आम आदमी निकल भी पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टोल टैक्स घटने के बजाय साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, टोल टैक्स प्लाजा की अव्यवस्थाओं से वाहन चालकों को रोजाना जूझना पड़ रहा है। फास्टैग में एडवांस पैसे देने के बावजूद अधिकांश वाहन चालक हाईवे पर चलते समय स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं।

एक छोटा सा उदाहरण राजस्थान के मनोहरपुर टोल प्लाजा का ले लीजिए। सितंबर 2024 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला था कि 1900 करोड़ में बने हाईवे के 8000 करोड़ रुपए टोल टैक्स के रूप में वसूले जा चुके हैं। अब आप ही बताइए 1900 करोड़ की सड़क के 8000 करोड़ किस हिसाब से वसूल लिए गए। शायद आम आदमी सरकार के इस गणित को समझ न पाए। देश में अभी करीब 980 टोल प्लाजा नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल हाईवे हैं और इस श्रेणी में राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन टोल टैक्स वसूली में राजस्थान सबसे ऊपर है। सबसे अधिक 142 टोल टैक्स प्लाजा राजस्थान में चल रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 457 टोल प्लाजा तो पिछले 5 साल में शुरू हुए हैं। इसमें भी राजस्थान जैसा राज्य सबसे ऊपर है। यहां पिछले 5 साल में 58 टोल प्लाजा शुरू हुए हैं।

दरअसल, टोल टैक्स प्लाजा का मकसद सड़क निर्माण और रखरखाव से जुड़ा हुआ है। यदि हाईवे को बेहतर क्वालिटी में बनाए रखना है तो वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूला जाता है, ताकि बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बशर्ते हाईवे उस क्वालिटी का हो। परंतु, स्थिति यह है कि हाईवे पर टोल टैक्स प्लाजा जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे व्यवस्थाओं की पोल भी खुल रही है। जब वाहनों की संख्या टोल टैक्स प्लाजा पर बढ़ने लगी तो सरकार फास्टैग को लेकर आई, यानी टोल टैक्स प्लाजा पर गाड़ी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधा निकल जाएगी, वाहन चालक के खाते से टोल टैक्स कट जाएगा, लेकिन फास्टैग भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रहा है। टोल टैक्स प्लाजा से गुजरना वाहन चालकों के लिए किसी पीड़ा से कम नहीं है। अधिकांश टोल टैक्स प्लाजा पर आधी लेन अक्सर बंद रहती हैं। फास्टैग के बावजूद टोल कर्मी वाहन को आगे-पीछे कराता है और बटन दबाकर वाहन को पास कराता है। यदि किसी वाहन का फास्टैग सही से काम नहीं कर रहा तो पीछे खड़े वाहन चालक परेशान होते हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। यदि एक वाहन के फास्टैग में कोई परेशानी है तो एडवांस पेमेंट कर चुके अन्य वाहन क्यों भुगतें?

अब सरकार के नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैक लिस्टेड टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लग रहा है। यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग निष्क्रिय रहता है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेन-देन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि वाहन के टोल रीडर से गुजरने के समय से 15 मिनट से अधिक समय के बाद टोल लेन-देन अपडेट होता है तो फास्टैग यूजर को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, यानी सारा भार टैक्स पेयर पर है। वैसे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियम के मुताबिक अगर कोई गाड़ी 10 सेकंड से अधिक तक टोल टैक्स की कतार में फंसी रहती है तो उसे टोल टैक्स का भुगतान किए बिना जाने दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जब ऐसे नियम के तहत किसी गाड़ी से टोल टैक्स न वसूला गया हो? पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब फास्टैग से आगे बढ़कर सरकार ग्लोबल नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम तकनीक से टोल टैक्स वसूली का प्लान बना रही है। इस सिस्टम की मदद से टोल रोड पर वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया जाता है और हाईवे पर यात्रा की दूरी के आधार पर टोल टैक्स कट जाता है, लेकिन यह सिस्टम पूर्ण रूप से कब लागू होगा, इससे जनता को क्या वाकई राहत मिलेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

सरकार ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम निवेश किया है। नए-नए हाईवे बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। देश की प्रगति के लिए यह एक सुखद चीज है, लेकिन टोल टैक्स के बहाने जनता की जेब से पैसा निकालना कहां तक उचित है? अप्रत्यक्ष रूप से वसूले जा रहे इस टैक्स को लेकर सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को कुछ नियम या नियमों के अनुपालना टोल प्लाजा के लिए भी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे टोल टैक्स देने वालों को परेशानी न हो तथा वे स्वयं को ठगा सा महसूस ना करें। जैसा हाईवे-वैसा टोल टैक्स लेने और एक समय के बाद टोल टैक्स से राहत देना समय की मांग है।

पलमायरा के खंडहर

प्राचीन धरोहर और संघर्षों के बीच एक जीवित इतिहास

पलमायरा, जिसे 'सीरिया का मणि' कहा जाता है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, जो हजारों वर्षों से मध्य-पूर्वी सभ्यता का हिस्सा रहा है। यह शहर प्राचीन रोम, ग्रीस और पारसी सभ्यताओं के मिलेजुले प्रभावों का प्रतीक है। यह शहर सीरिया के मध्य में स्थित है। पलमायरा के खंडहरों में सुंदर इमारतें, विशाल कॉलम और ऐतिहासिक स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण मिलते हैं। हालांकि, यह शहर पिछले कुछ वर्षों में संघर्षों और युद्धों से काफी प्रभावित हुआ है। सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान पलमायरा के कई महत्त्वपूर्ण स्मारक और संरचनाएं तबाह हो गईं, जिनमें से कुछ को आतंकवादी संगठनों ने नष्ट कर दिया था। इतने अधिक नुकसान के बावजूद पलमायरा के खंडहरों में जीवित इतिहास की महक अब भी मौजूद है। यह स्थल आज भी सीरिया की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और इसे फिर से बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यह चित्र पलमायरा के ऐतिहासिक महत्त्व और उसकी पुनर्निर्माण प्रक्रिया के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है।

पत्रिका डिजिटल पर भी पढ़ें विशेष लेख

भारतीय संस्कृति का महाकुंभ है ताज महोत्सव
योगेश कुमार गोयल
shorturl.at/rdcnB

यदि आप भी समसामयिक विषयों, सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं तो हमें writers@in.patrika.com पर ई-मेल करें।

प्रसंगवश

डिग्रीधारी नहीं, डिग्री का सही उपयोग करने वाला बनें

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मिले उचित प्लेटफॉर्म व स्टार्टअप को प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा के सरकारी व निजी संस्थानों से हर साल हजारों की संख्या में डिग्रीधारी युवा बाहर निकल रहे हैं। संस्थान से बाहर आते ही इनमें से अधिकतर की डिग्री कागज का पुलिंदा साबित हो जाती है। ये सभी जीवन-यापन के सरल तरीके अपनाते हुए अपनी डिग्री से इतर किसी भी तरह से एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। जिन्हें यह हासिल हो जाती है, वे आरामतलबी से गुजर-बसर में लग जाते हैं। शेष बचे डिग्रीधारी प्राइवेट सेक्टर या परंपरागत व्यवसाय में अपने आप को झोंक देते हैं। इनसे पूछा जाए कि डिग्री का क्या हुआ तो साफ जवाब होता है उससे होता ही क्या है? दरअसल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों, एलुमिनी व उद्यमियों के नवाचार व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। छिटपुट स्तर पर ऐसे प्रयास तो किए जा रहे हैं, पर वे रुटीन सेमिनार तक ही सीमित होकर रह जाते हैं।

हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप इन एकेडेमिया पर आधारित कार्यशाला में मुख्य वक्ता रहे अचिंत गुलाटी ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि शिक्षा जगत में डिग्रीधारी युवाओं की संख्या तो अधिक है, लेकिन वे अपनी डिग्री का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उम्मीद की किरण जताते मुख्य वक्ता ने कहा कि ऐसे युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपने कौशल और रुचियों को व्यवसाय में बदलना चाहिए। डिग्री की शिक्षा के साथ ही साथ युवाओं को बिजनेस शुरू करने के तरीके, जोखिम उठाने की मानसिकता, बिजनेस में खुद को लगातार अपडेट करते रहने जैसी सीख यदि शिक्षण संस्थान पर्याप्त दें, तो कुछ हद तक डिग्री की अहमियत सार्थक साबित हो सकती है।

बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाके को ही उदाहरण मानें, तो यहां हर साल दस हजार से अधिक डिग्रीधारी युवा निकलते हैं। पर स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति उनकी जागरुकता बेहद कम दिखाई देती है। सरकार को चाहिए कि नवाचार व स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने आधारभूत संस्थान बनाए। युवा उद्यमियों को आर्थिक व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिससे डिग्री की अहमियत बरकरार रहे।

- अजय श्रीवास्तव
ajay.shrivastav@gmail.com

आत्म दर्शन

कार्य में दक्षता का मार्ग श्रम साधना

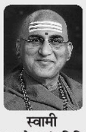

स्वामी अवधेशानंद गिरि
@patrika.com

किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए उत्साह एवं निष्ठापूर्वक अपने कर्मों का संपादन करें। हमें यह समझना आवश्यक है कि एकाग्रतापूर्वक किए गए हमारे छोटे एवं संक्षिप्त प्रयास ही बड़ी उपलब्धियों की भूमिका तैयार करेंगे। जो भी करें, उसे पूरे मनोयोग के साथ करें। किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करने का मार्ग उत्साह, लगन और हमारी श्रम साधना है। जो व्यक्ति काम को बोझ मानते हैं, उनसे कभी बड़े कार्य नहीं हो पाते और वे जीवन की बड़ी उपलब्धियों से वंचित रहते हैं। कई बार अपने आलस्य व मनोमालिन्य के कारण मनुष्य अपने कार्यक्षेत्र एवं निकटस्थ संबंधियों के मध्य विश्वसनीयता खो देते हैं। अपने प्रत्येक कर्म को भगवदीय उपासना मानते हुए उनका निष्ठापूर्वक संपादन करना चाहिए।

भगवन्नाम स्मरण सर्वथा हितकर है। प्रत्येक पल भगवदीय स्मृति में रहें। जीवन संघर्ष करते हुए परमात्मा की विस्मृति न होना ही श्रेष्ठ है। श्रद्धा से ही मन में सकारात्मक विचारों का आगमन होता है। श्रद्धा हमें जीवन की नई राह दिखाती है। यह किसी के प्रति हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम उचित-अनुचित का विचार अपने मन-मस्तिष्क से कभी ओझल न होने दें। उस परम तत्त्व को जाने बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। उस परम सत्ता को हर-पल अनुभव करें और ये भाव बनाए रखें कि सारे संसार में वह रचे बसे हैं। यह ज्ञान मात्र शब्दों का न हो, बल्कि यह भाव हमारे हर कर्म में, इंद्रियों में, मन और बुद्धि आदि सभी में रहना चाहिए। प्रभु हर जगह हैं, उनके बिना यहां कुछ घटित नहीं होता। जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं तब मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेते, 'परमपद' प्राप्त कर लेते हैं।

समाज: पश्चिमी दुनिया में समलैंगिक विवाह और पारंपरिक विवाह ढांचे से बाहर परिवार बनाने जैसी गंभीर समस्याएं

पश्चिमी दुष्प्रभावों से बचाते भारतीय पारिवारिक मूल्य

रवि कुमार
चेन्नई सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज में सलाहकार
@patrika.com

प्राचीन ज्ञान में निहित परंपराओं, नैतिकता और सिद्धांतों की समृद्ध विरासत भारतीय मूल्यों में शामिल है। इन मूल्यों के केंद्र में पारिवारिक सामंजस्य की अवधारणा है।

एक अनुमान के अनुसार बेल्जियम, क्यूबा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, रूस और स्पेन जैसे देशों में तलाक की दर 50 प्रतिशत से अधिक है। भारत में यह लगभग एक प्रतिशत है। भारत अत्यधिक आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक देश है। इसलिए एक प्रतिशत की भी हमें चिंता होनी चाहिए। हालांकि बाल विवाह अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन देर से विवाह करना और लिव-इन रिलेशनशिप में वृद्धि भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय है। पश्चिमी दुनिया में समलैंगिक विवाह और पारंपरिक विवाह ढांचे से बाहर परिवार बनाने जैसी कुछ गंभीर समस्याएं हैं। एकल परिवार और पुरुष अपने बच्चों की जिम्मेदारी न लेने का विकल्प भी चुन रहे हैं। आज भारतीयों का वेतन कई गुना बढ़ गया है, लेकिन पश्चिमी जीवनशैली उनके परिवारों को बर्बाद कर रही है।

प्राचीन तमिल संत तिरुवल्लुवर के अनुसार, 'एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति वह है जो तीनों रिश्तों (माता-पिता, पत्नी, बच्चे) के प्रति समर्पित है और संतों, गरीबों और जरूरतमंदों को संतुलित और धार्मिक तरीके से सहायता प्रदान करता है। एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति वह है जो अच्छा कमाता है तथा दान व परोपकार करके धन जमा करने के दोष से बचता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी शिकायत के पूर्ण जीवन जीएगा। जीने का एकमात्र तरीका सही ढंग से जीना है। यदि कोई सद्गुणों के साथ रहता है और दूसरों को भी ऐसा करने में सहायता करता है, तो ऐसा पारिवारिक जीवन संतों की तपस्या से बेहतर है।' प्राचीन ज्ञान में निहित परंपराओं, नैतिकता और सिद्धांतों की समृद्ध विरासत भारतीय मूल्यों में शामिल है। इन मूल्यों के केंद्र में पारिवारिक सामंजस्य की अवधारणा है, जो कर्तव्य, धार्मिकता, नैतिक व्यवस्था, बड़ों के प्रति सम्मान और आतिथ्य पर जोर देती है। ज्ञान की खोज, जैसा कि शिक्षा और विद्वानों के प्रति श्रद्धा द्वारा दर्शाया गया है, एक और हमारी पहचान है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ, ये भारतीय मूल्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई और सुदूर पूर्व एशियाई देशों में फैल गए। आज पश्चिमी जगत में भी भारतीय पारिवारिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है।

इंद्रा नूई एक भारतीय मूल की अमरीकी बिजनेस कार्यकारी हैं, जो 2006 से 2018 तक पेप्सिको की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं। उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में स्थान दिया गया था। 2015 और 2017 में उन्हें फॉर्च्यून सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला का दर्जा दिया गया था। इंद्रा अपनी शानदार सफलता का श्रेय गर्व से अपने परिवार को देती हैं। इंद्रा की मां एक गृहिणी थीं। स्वयं औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद, उनकी मां ने अपनी बेटियों के लिए रात्रि भोज में रणनीतिक खेल तैयार किए थे। जैसे जब इंद्रा और उनकी बहन 8 व 11 साल की थीं, तो उनकी मां ने उन्हें लिखने के लिए कहा कि अगर वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे शक्तिशाली पद पर हों तो वे क्या करेंगी। इस तरह के उपायों ने इंद्रा को बेहद प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट जीवन में चुनौतियों से पार पाने के लिए काफी मजबूत और सख्त बना दिया।

अपनी व्यस्त यात्राओं और कॉर्पोरेट गतिविधियों के बावजूद इंद्रा अपने बच्चों और उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत सतर्क रहतीं। यदि पेप्सिको की सीईओ अपनी बेटियों के उचित विकास और संस्कार में रुचि ले सकती हैं, तो क्या हममें से कोई कह सकता है कि वह बहुत व्यस्त हैं! कई प्रसिद्ध और सफल लोग जैसे इंफोसिस की सुधा मूर्ति, डीआरडीओ की मिसाइल महिला टेसी थॉमस और इसरो चंद्रयान से जुड़ी कई महिलाएं समान भाव से देश और अपने परिवार दोनों की सेवा कर रही हैं। अमरीका में जन्मी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने पिता डॉ. दीपक पंड्या के माध्यम से हिंदू धर्म में निहित थीं। वह अंतरिक्ष मिशन पर पवित्र भगवत् गीता, संस्कृत में एक पत्र और अपना पसंदीदा व्यंजन समोसा ले गईं। हरिलेला परिवार लगभग 80 सदस्यों के साथ हांगकांग में 40 बेडरूम वाली हवेली में रहता है और अगली पीढ़ी एक जुड़े हुए घर में रहती है। यह हांगकांग में सबसे सफल हिंदू सिंधी परिवार है। ये लगभग सौ वर्षों से भारत से दूर हैं। उनकी मां देवीबाई अक्सर उन्हें याद दिलाती थीं कि 'चाहे आपका पासपोर्ट किसी भी देश का हो, लेकिन जब आप दर्पण के सामने खड़े हों, तो याद रखें कि आप एक भारतीय हैं...।'

प्रवासी भारतीयों ने उनके देशों में अनेक छोटे-बड़े मंदिर बनवाए हैं। माता-पिता अपने बच्चों को विशेष रूप से हिंदू त्योहारों के दौरान नियमित रूप से इन मंदिरों में लाते हैं। इससे पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। प्रवासी भारतीयों में अधिकांश विवाह अभी भी माता-पिता और दादा-दादी द्वारा तय किए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है हमारी सदियों पुरानी परिवार व्यवस्था इस 21वीं सदी में हमें बचा रही है। हमारी सुंदर परिवार प्रणाली, सभी सामाजिक त्रासदियों का अमृत है।

आपकी बात

गुरुकुल व्यवस्था पुन: शुरू हो

बच्चों के समग्र विकास के लिए प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था वापस शुरू होनी चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। माता-पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अनुशासन, जीवदया, परोपकार की बातें सिखाएं। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान देना भी जरूरी है।

- रामनरेश गुप्ता, जयपुर

उचित माहौल मिलना जरूरी

बालकों का समग्र विकास तभी संभव है, जब उन्हें घर में एक उचित माहौल मिले और अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिले। दादी-नानी की कहानियां और अनुभव भी बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि करते हैं। शारीरिक खेलकूद से बच्चों में नेत्तृत्व क्षमता विकसित होती है।

- शुभम वैष्णव, सवाईमाधोपुर

आज का सवाल

क्या आप मानते हैं कि बच्चों की सोशल मीडिया चैनल्स पर उपस्थिति उनका बचपन छीन रही है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'आप बच्चों के समग्र विकास के लिए क्या जरूरी मानते हैं?' अन्य पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

इसे स्कैन करें
https://shorturl.at/YgCL5

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 19 फरवरी 2025

शीर्ष अदालत पर नज़रें

राष्ट्रपति द्वारा सोमवार देर रात की गई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सरकार पर नियम-कानूनों के दायरे से बाहर जाने का कोई आरोप नहीं है। इसके बावजूद अगर फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और विवादों से नहीं बचा जा सका तो स्पष्ट है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में नियम-कानूनों के पालन की रस्म अदायगी हमेशा काफी नहीं होती।

सीईसी: नियुक्ति प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई | फैसला ऐसे समय आया, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को 48 घंटे भी नहीं रह गए थे। तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति के एक अहम सदस्य के तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने बैठक में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए फैसले को स्थगित करने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत सदस्य गृहमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की राय को दरकिनार करते हुए बहुमत से फैसला कर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेज दीं।

सवाल अधिकारों के इस्तेमाल का | हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी। इससे साफ है कि सरकार ने नियुक्ति को अंतिम रूप देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। उसे इस फैसले का अधिकार था। सवाल यह है कि क्या ऐसा करके सरकार ने अपने अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल सुनिश्चित किया है?

मुद्दा है विश्वसनीयता | मूल प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को विश्वसनीय और विवाद रहित कैसे बनाया जाए। नियुक्ति समिति में देश के मुख्य न्यायाधीश के बदले कैबिनेट मंत्री को जगह देने से विपक्ष को बेशक एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया को एक हद से ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। अच्छी से अच्छी प्रक्रिया भी दुरुपयोग का शिकार हो सकती है।

कोर्ट का रुख | सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बुधवार को ही होनी है। देखना होगा कि कोर्ट का रुख कैसा होता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की विश्वसनीयता का सवाल जितना जरूरी है उतना ही व्यापक भी। इसे महज एक नियुक्ति या नियुक्ति की प्रक्रिया तक सीमित नहीं माना जा सकता। जाहिर है, सरकार और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग को भी अपनी भूमिका विश्वसनीयता और जिम्मेदारी की दोहरी कसौटी पर परखते हुए आगे बढ़ना होगा।

कभी-कभी

लापता उम्मीदें

ललित वर्मा

तमाम तमन्नाओं और कोशिशों के बावजूद कुछ न मिल सके, तो मन में टीस रह जाती है। यह टीस उस दर्द से बड़ी नहीं होती, जो किसी मिले हुए के खो जाने पर होता है। यह खो जाना अपने बच्चे का हो तो इस तकलीफ को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसे वही महसूस कर सकता है, जिस पर यह बीतती है।

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 5 साल में लापता हुए बच्चों में से 36 हजार नहीं ढूंढे जा सके। यह अधूरा आंकड़ा है। इसमें कई राज्यों के गुम बच्चों की संख्या नहीं है। गुम हुए 3 लाख बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन जो नहीं मिले, वह भी बड़ी संख्या है। मसलन, महाराष्ट्र से 2,592 बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका। कहां गए ये बच्चे? जमीन निगल गई, या आसमान खा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्यादातर मानव तस्करी करने वाले गिरोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं।

जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं, उनकी आंखों में इंतजार और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं रह जाता। चैन यूं रूठ जाता है कि एक पल के लिए भी नहीं आता। मीठी यादें और रुलाती हैं। कोई मां जब खो गए बेटे या बेटी के बारे में बात करती है, तो सुनने वाले का भी कलेजा फटकर आता है। दिल्ली के ऐसे ही खोए हुए बच्चों पर विवेक आसरी ने एक डॉक्युमेंट्री बनाई थी - 110002। यह दरियागंज का पिन कोड है। दूरदर्शन पर आपने गुमशुदा तलाश केंद्र का पता सुना होगा, तो आप समझ जाएंगे।

बात बच्चों की ही नहीं है। कई बार बड़े भी गुम जाते हैं। उनके मामले में इंतजार, उम्मीदों और आशंकाओं का घालमेल हमेशा जेहन को कचोटता रहता है। उनके परिजन कहीं भी जाएं, उन्हें लगता है कि अब सामने से वह चेहरा नजर आ जाएगा। दिल्ली में हमारे मित्र नलिन चौहान सरकार में डिप्टी डायरेक्टर रहे। अखबारों के लिए भी लिखते थे। कोविड आया तो अचानक एक दिन कहीं निकल गए। उसके बाद कभी नहीं लौटे। उनके फेसबुक पेज पर आज भी 'लौट आओ नलिन' की मनुहार कहीं न कहीं से आती रहती है। खैर, उम्मीदें कभी मरती नहीं। जैसे शेरू के साथ हुआ था। 5 साल की उम्र में मां-बाप से बिछड़ा और 25 साल बाद गूगल मैप से मां-बाप को ढूंढ लिया। उसी पर 2016 में मूवी आई थी- LION।

एकदा

गुमनाम हॉकी प्लेयर

तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ग्वालियर के विक्टोरिया स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाला जो बालक खेल-कूद में भी होशियार था, प्रिंसिपल का भी चहेता बन गया। प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। एक दिन स्कूल से सटे एक बंगले से एक अंग्रेज सज्जन गुस्से से तमतमाए प्रिंसिपल के केबिन में आए। वह सज्जन ऊंची आवाज में प्रिंसिपल से कह रहे थे, आपके स्कूल के एक स्टूडेंट ने हॉकी की गेंद को इतनी जोर से मारा कि मेरे बंगले की दीवार चटक गई। प्रिंसिपल को जब उस लड़के का पता चला तो वह उसे देखकर मुस्कुरा दिए और लड़के की पीठ थपथपाते हुए उसे हॉकी की गेंद पुरस्कार के रूप में दी। वह खिलाड़ी कोई और नहीं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह थे। रूप सिंह ने 1932 के लॉस एंजिलिस ओलिंपिक्स में ध्यानचंद से भी अधिक गोल किए थे। 1936 ओलिंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के कारण म्यूनिख में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। लंदन में 2012 ओलिंपिक्स में भी ध्यानचंद और लेस्ली क्लाडियन्स के साथ रूप सिंह के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया। आज इस महान हॉकी खिलाड़ी की पहचान केवल कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के रूप में रह गई है, जो 1978 में उनके गृहनगर ग्वालियर में उनके निधन के एक साल बाद बनाया गया था।

Subrato Dhar

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

देश की राजधानी में BJP से मिली हार के बाद केजरीवाल की आगे की राह कठिन हो गई है

दिल्ली के बाद AAP की अगली परीक्षा

राज कुमार सिंह

दिल्ली की सत्ता गंवाने के कारण AAP को समाप्त मान लेना विरोधियों का उतावलापन ही होगा। लेकिन दिल्ली से पंजाब तक चुनौतियां बेहद गंभीर हैं। बेशक, अतीत में कुछ दल और नेता चुनावी पराजय के कोहरे के बाद फिर सत्ता-राजनीति में चमकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन AAP की स्थितियां अलग हैं।

वादों पर अमल | सच यह है कि AAP को 2013 और फिर 2015 में दिल्ली की सत्ता बिना ज्यादा कुछ किए, तश्तरी में रखी मिल गई। उसमें अन्ना आंदोलन से बनी श्रीमान ईमानदार की छवि और देश को दिखाए गए वैकल्पिक राजनीति के सपनों की बड़ी भूमिका रही। हां, 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP की जीत में अवश्य चुनावी वायदे पूरे करने की निर्णायक भूमिका रही।

सीमाएं उजागर हुईं | 2020 के बाद बदले हालात से उत्पन्न चुनौतियों ने आंदोलन से जनमी इस पार्टी की राजनीति और मुफ्त रेवड़ी के शासन-मॉडल, दोनों की सीमाएं उजागर कर दीं। यमुना सफाई और स्वच्छ पेयजल सप्लाई जैसे अधूरे वादों का कारण केजरीवाल भले ही कोरोना और फिर जेल के खेल को बताएं, सच यही है कि उनके और केंद्र सरकार के बीच निरंतर तकरार से दिल्ली जरूरी विकास कार्यों तक से वंचित रही।

मतदाताओं का मोहभंग | 27 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए BJP ने केजरीवाल के 'मुफ्त रेवड़ी कल्चर' का भी सहारा लिया, लेकिन AAP की हार के पीछे मतदाताओं का मोहभंग सबसे बड़ा कारण रहा। इसीलिए BJP का मत प्रतिशत तो 3.6 ही बढ़ा, लेकिन AAP का 10 प्रतिशत कम हो गया।

साख पर सवाल | हमारी व्यवस्था में सच की तलाश भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। इसीलिए राजनीति में अक्सर सच से ज्यादा प्रभावी जनता की धारणा साबित होती है। शराब घोटाले और शीश महल का सच पता नहीं कब सामने आएगा, लेकिन फिलहाल उनसे केजरीवाल की साख पर लगे सवालिया निशान उनकी चुनावी पराजय सुनिश्चित कर गए।

भगदड़ मचने का डर | चुनाव पूर्व दलबदल भारतीय राजनीति का स्थायी चरित्र बन गया है, लेकिन AAP में ऐसी भगदड़ पहले कभी नहीं दिखी। दिल्ली की सत्ता गंवाने और केजरीवाल के खुद भी चुनाव हार जाने के बाद भगदड़ और भी तेज हो सकती है। आठ फरवरी को दिल्ली के चुनाव परिणाम आए और 11 फरवरी को केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों की दिल्ली में बैठक बुला ली। 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 विधायकों के साथ पंजाब में AAP की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अगर वहां उसे टूट का डर सता रहा है, तो दिल्ली को कौन बचा सकता है?

दिल्ली का मेयर कौन | केजरीवाल के समक्ष चुनौतियां अपार हैं और संसाधन बेहद सीमित। उन्हें कानूनी मोर्चे पर भी कई लड़ाई लड़नी हैं, लेकिन सबसे अहम होंगी राजनीतिक चुनौतियां। 22 विधायकों में टूट की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी के समक्ष पहली चुनौती दिल्ली नगर निगम में सत्ता बचाने की होगी। इस बीच 11 पार्षदों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। अगर AAP उपचुनाव के जरिये बहुमत बरकरार रखने में सफल नहीं रही तो पहला झटका मेयर चुनाव में ही लग जाएगा।

राह के रोड़े

- कई अहम वादे नहीं हुए पूरे
- निजी छवि को हुआ नुकसान
- अब पंजाब मॉडल पर दारोमदार

पंजाब मॉडल कितना कारगर | दूसरी बड़ी चुनौती 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव हैं। बेशक 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने AAP को ऐतिहासिक बहुमत दिया था, लेकिन उसका आधार बहुप्रचारित दिल्ली मॉडल था। अब जबकि दिल्ली मॉडल को दिल्ली में ही मतदाताओं ने खारिज कर दिया है, पंजाब को देश भर में मॉडल की तरह पेश करना होगा। तीन साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। एक हजार रुपये मासिक महिला सम्मान का वायदा अभी तक अधूरा है तो राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।

नेतृत्व परिवर्तन के खतरे | पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन का दांव जोखिम भरा है, इसलिए केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में ही पंजाब मॉडल को 'चुनाव जिताऊ' बनाना होगा, वरना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी का संकेत दे चुकी है।

मजबूत जमीन की दरकार | बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में BJP और शिरोमणि अकाली दल में दोबारा गठबंधन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले वक्त में दिल्ली से पंजाब तक असली परीक्षा केजरीवाल की होनी है, जिसके परिणाम पर उनके साथ ही AAP का भी भविष्य निर्भर करेगा। अपने पैरों के नीचे मजबूत जमीन के बगैर विपक्षी ब्लॉक I.N.D.I.A. में भी उन्हें कोई नहीं पूछेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

ट्रंप का टैरिफ टेरर

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह इस बार दुनिया से 'हिसाब बराबर' करके रहेंगे। अब वह इसी काम में जुटे हैं। वह नहीं चाहते कि अमेरिका को किसी भी देश के साथ व्यापार में घाटा हो, इसलिए वह आयात शुल्क बढ़ाने की बात कह रहे। क्या टैरिफ लगाने में US वाकई पीछे है, भारत और दूसरे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ उसका आंकड़ा कैसा है, इसे समझते हैं :

अमेरिका को किससे कितना घाटा

देश	घाटा
EU	235.6
चीन	295.4
मैक्सिको	171.8
वियतनाम	123.5
भारत	43.65
कनाडा	63.34

आंकड़े बिलियन डॉलर में। अमेरिका ने इन देशों को जितना सामान बेचा, उससे ज्यादा खरीदा।

आयात शुल्क कितना

देश	आयात शुल्क
भारत	17%
द. कोरिया	13%
ब्राजील	11%
चीन	8%
मेक्सिको	7%
यू. यूनियन	5%
ब्रिटेन	4%
जापान	4%
अमेरिका	3%
ऑस्ट्रेलिया	2%

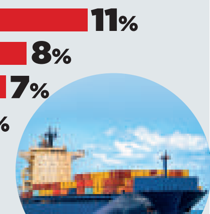

WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन के सिद्धांत के हिसाब से लगाया गया औसत टैरिफ। विकसित देशों में आमतौर पर कम आयात शुल्क है।

अमेरिका को चीनी झटका

34B$ *औसत व्यापारिक घाटा था अमेरिका का 1990 के दशक में चीन के साथ*

2000 से इसमें तेजी आई। इसे China Shock कहा गया। वजह रही चीन की आर्थिक नीतियां

26% वर्कफोर्स काम करती थी 1970 के दशक में अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में

8.5% वर्कफोर्स रह गई 2016 में, क्योंकि चीन से बना-बनाया सामान आने लगा

गुड्स एंड सर्विसेज का बोझ

1.2T$ अमेरिका का कुल व्यापार घाटा रहा पिछले साल

4.1T$ का आयात गुड्स एंड सर्विसेज में रहा था

3.2T$ का निर्यात अमेरिका ने किया साल 2024 में

भारत-अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते

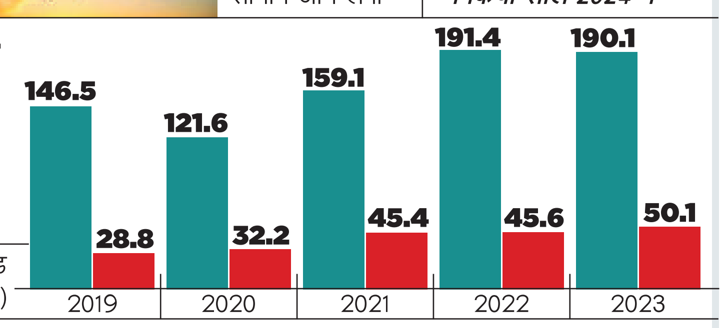

भारत से जो अमेरिका जाता है

17.2 मशीनरी, इंजीनियरिंग का सामान

8.8 टेक्सटाइल और कार्पेट

9.9 हीरे और जूलरी

8.1 दवाएं

5.8 तेल उत्पाद

अमेरिका से जो भारत आता है

13 खनिज तेल

5.2 कच्चा हीरा

6.1 इंजीनियरिंग का सामान

2.3 एयरक्राफ्ट

1.9 मेडिकल उपकरण

(डेटा 2023-24 का, बिलियन डॉलर में)

अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा दूसरे देशों के साथ उसके ट्रेड डेफिसिट के मुकाबले काफी कम है। दोनों ओर से इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। भारत अमेरिका से तेल सहित कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में ले सकता है।

*- **डॉ. अजय सहाय,** डायरेक्टर जनरल, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस*

https://t.me/AllNewsPaperPaid

NTA यह ग़लती सुधार ले तो बदलेंगे हालात

भूपेंद्र शर्मा

इस साल हुए पहले बड़े एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE- MAIN) के प्रश्नपत्रों पर फिर से सवाल उठ गए हैं। परीक्षा सुधारों की कड़ी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) को अपनाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, फिर भी लगातार प्रश्नपत्रों में गलत या सिलेबस से बाहर के सवाल आ रहे हैं। देश में परीक्षा सुधारों के लिए शिक्षा मंत्रालय की डॉ. के. राधाकृष्णन कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद भी न तो पेपर सेट करने वालों की जवाबदेही तय हुई है, न पेपर सेटिंग की प्रक्रिया सुधरी है।

NTA पर सवाल | परीक्षाओं में सुधार का रोडमैप गंभीरता से लागू करना है तो इसके लिए पेपर सेट करने के तरीकों में बदलाव बहुत जरूरी है। देश में 23 IIT में दाखिले के लिए होने वाली JEE (Advanced) की परीक्षा को लेकर ज्यादा सवाल नहीं उठते, क्योंकि जवाबदेही एक IIT की होती है। ऐसे में सवाल है कि नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की इंजिनियरिंग, मेडिकल, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जैसे बड़े एंट्रेंस टेस्ट में ही क्यों गड़बड़ियां होती हैं? इन सवालों के जवाब तलाशना ज्यादा मुश्किल नहीं है।

तय हो जवाबदेही | पहले तो पेपर सेट करने वालों की जवाबदेही तय हो। पेपर सेटिंग की प्रक्रिया में देश के बड़े संस्थानों के एक्सपर्ट्स को शामिल करना होगा। IP यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी संभाल चुके ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु का कहना है कि जिन प्रफेसरों को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे अपने रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च स्कॉलरों से पेपर सेट करवा देते हैं। ऐसे में गलतियां होनी लाजिमी हैं। बेहतर होगा कि पेपर सेट करने वालों को कैंपस में बुलाकर सवाल तय करवाए जाएं।

बार-बार गलती | NTA का इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहता है कि सभी जरूरी उपाय बरतने के बाद भी अगर कोई गलत सवाल आता है तो सभी छात्रों को उस सवाल के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। गलत सवाल करीब-करीब हर वर्ष आ रहे हैं। यानी पेपर सेटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी है और इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। NTA का दावा है कि इस बार 6 गलत सवाल आए हैं, और इतने ही विदेश में हुए एग्जाम सेंटरों में भी आए हैं। इस तरह से 12 गलत क्वेश्चन का दावा किया जा रहा है।

AI Image

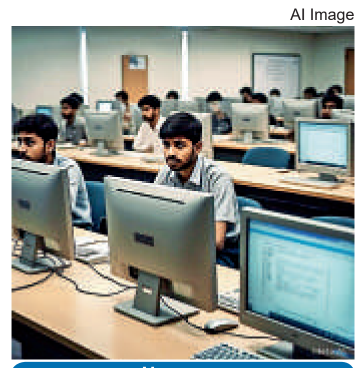

कॉमन रूम

सवालों का लेवल | जब तक क्वेश्चन पेपर को मानक के मुताबिक तैयार नहीं किया जाता, तब तक यह समस्या बरकरार रहेगी। क्वेश्चन पेपर का ठीक से वर्गीकरण किया जाना भी जरूरी है। ध्यान रहे, दो सवालों का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता। दो शिफ्ट में एग्जाम देने वालों में से एक छात्र से भारत का क्षेत्रफल पूछा गया तो दूसरे से मलेशिया का। कंप्यूटर की नजर में तो दोनों सवाल एक लेवल के हैं, लेकिन एक छात्र की नजर में इनमें भारत-मलेशिया का अंतर है।

स्कोर कार्ड की समस्या | छात्रों का एक बड़ा सवाल यह भी है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन में सभी को बराबरी के मौके नहीं मिल पाते। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश में अपनाए जाने वाले नॉर्मलाइजेशन और पर्सेंटाइल के फॉर्म्युले से छात्रों के स्कोर कार्ड में एक से तीन फीसदी तक की वेरिएशन बने रहने की संभावना रहती है। इस समस्या का भी समाधान अभी तक नहीं खोजा गया है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

जैसा भाव वैसा प्रभाव, यही हमारा असली अस्तित्व

सुरक्षित गोस्वामी

जीवन एक अनूठी यात्रा है, जहां हमारे कर्म और भाव मिलकर इसे आकार देते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा किए गए भौतिक कर्म ही देखे जाएं, हमारे भाव ही असली मापदंड होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमारे भाव पर निर्भर करता है। कर्म का स्वरूप चाहे जो भी हो, भाव की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है।

कई बार ऐसा होता है कि हम बाहरी रूप से अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर का भाव शुद्ध नहीं होता। ऐसे में अच्छे कर्म भी मनचाहा परिणाम नहीं देते। दूसरी ओर, अगर प्रेम और भलाई की भावना से कभी कठोर शब्द कहे गए हों या कड़ी प्रतिक्रिया दी गई हो, तो उसका फल सकारात्मक होता है। वास्तव में हमारे कर्म और भाव अक्सर अलग-अलग होते हैं। हम जो बोलते या करते हैं, वह बाहरी दुनिया के लिए होता है, लेकिन हमारे भीतर का भाव ही हमारी सच्ची पहचान है।

इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य सत्ता काम कर रही है, जिसे हम प्रभुता, भव्यता या cosmic intelligence कहते हैं। यह बुद्धिमत्ता हर कण में व्याप्त है, चींटी से लेकर विशाल हाथी तक। यही दिव्यता इस सृष्टि की हर गतिविधि को संचालित करती है। हमारे भावों को वही देखती है, महसूस करती है। जैसे बीज से वृक्ष बनना, उसमें फूल-फल आना और खुशबू का फैलना प्रकृति के नियंत्रण में है, वैसे ही हमारे हर कर्म और भाव उस cosmic intelligence की नजर में होते हैं। हम वही हैं, जो हमारे भाव हैं।

अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें वैसा फल नहीं मिलता। वे कहते हैं कि मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुख कम नहीं होता। इसका कारण यही है कि cosmic intelligence हमारे कर्मों को नहीं, बल्कि हमारे भावों को देखती है। हमारी आंतरिक भावना ही उसका मापदंड है।

जीवन की इस यात्रा में हमारे भाव ही हमारा असली परिचय है। अगर भाव शुद्ध है, तो प्रभाव भी सकारात्मक होगा। लेकिन जब हमारी इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती जाती हैं, तो तृप्ति कहीं पीछे छूट जाती है और हम अधूरे रह जाते हैं। पूर्णता तभी मिलती है, जब हमारे भीतर से लालसा समाप्त हो जाती है। यही शुभ भाव जीवन को सार्थक बनाता है। तो करना क्या है? भाव शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें। भाव शुद्ध होगा तो प्रेम झरने लगेगा। अंदर से माधुर्य प्रकट होगा, निस्वार्थ भाव प्रकट हो जाएगा।

आइए, इस जीवन यात्रा में अपने भावों को शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक बनाएं, क्योंकि वास्तव में भाव ही हमारा वास्तविक अस्तित्व है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 19 फरवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

बेवजह के विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित मामले में नयी याचिकाएं दायर होने पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा नये अंतरिम आवेदन को केवल तभी अनुमति दी जा सकती है, जब कोई नया बिन्दु या नया कानूनी मुद्दा हो, जो लंबित याचिकाओं में न उठाया गया हो। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, लोग नई याचिकाएं दायर करते रहते हैं और दावा करते हैं, उन्होंने नये आधार उठाए हैं। पीठ ने स्पष्ट कहा कि पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनी गई लंबित याचिकाओं पर दो न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने दिसम्बर 2024 के अपने आदेश में विभिन्न हिन्दू पक्षों द्वारा दायर लगभग अट्ठारह

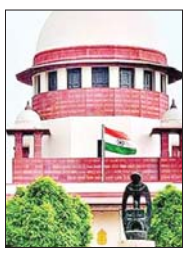

मुकदमों में कार्यवाही को प्रभावी तौर पर रोक दिया था, जिसमें वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद व संभल की शाही जामा मस्जिद समेत दस मस्जिदों के मूल धार्मिक चरित्र का पता लगाने को सर्वेक्षण की माग की गई थी। 1991 में अयोध्या में विवादित बाबरी विध्वंस के बाद देश में पूजास्थल कानून लागू किया गया था, जिसके तहत आजादी से पूर्व मौजूद किसी भी धर्म के पूजास्थल को दूसरे धर्म के पूजास्थल में नहीं बदला जा सकता। जिन लोगों ने 1991 के इस अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी, उनका आरोप है यह अधिनियम हिन्दुओं के साथ ही जैनियों, बौद्धों, सिखों को अपने पूजास्थलों को पुनः प्राप्त के लिए अदालतों में जाने से रोकता है। जिन पर कट्टरपंथी बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण या अतिक्रमण किया गया था। निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक जनहित याचिकाओं का अंबार है। इस पर जबरन विवाद उछालने, चर्चा में आने या राजनीतिक दलों द्वारा बहुसंख्यकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगातार इन विवादास्पद धार्मिक स्थलों के खिलाफ याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इन पर आक्रामक बयानबाजियां की जाती हैं और उन्मादी धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास होता रहता है। जनहित याचिकाओं की आड़ में न्यायालय का वक्त जाया करने और भारी धनराशि का अपव्यय करने वाली मानसिकता पर सख्ती जरूरी है। सांप्रदायिक सौहार्द व सद्भावना बनाये रखने के लिहाज से अदालतें संतुलित निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। अदालतों द्वारा ही धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने व विवादों को बिला-वजह तूल देने की प्रवृत्ति को थामा जा सकता है। ताकि देश में शांति रहे व विश्व पटल पर छवि धवल बनी रह सके।

शांति में भारतीय हित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी घोषणा के अनुसार कार्यकाल की शुरुआत में ही रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने तथा शांति वार्ता आयोजित करने के संबंध में ठोस पहल की है। उन्होंने शांति वार्ता को जमीन पर उतरने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत की। इसी का परिणाम है कि मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री शांति वार्ता का प्रारूप तैयार करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन के संबंध में उठाया गया यह कदम अमेरिका की पुरानी नीति से एकदम अलग है और इसमें यूरोप के साथ गहराते मतभेदों के संकेत हैं। अगर ट्रंप युद्ध समाप्ति की दिशा प्रयास कर रहे हैं तो उनके प्रयास की

सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत तबाही मोल ली है। इसलिए इसे रुकना ही चाहिए। बाइडन ने पुतिन को 'हत्यारा तानाशाह' कहा था और युद्ध को भड़कने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर यूरोपीय नेताओं ने सोमवार को पेरिस में आपातकालीन बैठक कर यूक्रेन मुद्दे पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर चर्चा की। वास्तव में ट्रंप की यूक्रेन पर बवंडर नीति ने यूरोप और स्वयं यूक्रेन के सामने हाशिये पर जाने का खतरा पैदा कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सऊदी अरब में आयोजित शांति वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया है। नतीजतन शांति वार्ता की सफलता संदिग्ध है। जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय देश रूस के साथ अपने विरोधपूर्ण संबंधों के कारण उसके आगे समर्पण करना नहीं चाहते। यूरोपीय देश यूक्रेन को हारता देखना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें यह समझ में क्यों नहीं आता कि अपनी थोड़ी सी सहायता के बल पर यूक्रेन को युद्ध में झोंके रखना वस्तुतः कीव को विनाश के कगार पर पहुंचाना है। अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद पर तुलसी गबार्ड की नियुक्ति पर मोहर लगने के बाद यूरोपीय देशों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें युद्ध विरोधी नेता माना जाता है। भारत शुरू से युद्ध समाप्त करने के पक्ष में खड़ा रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान यूक्रेन पर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत तटस्थ नहीं रह सकता। भारत रूस को अपना विश्वसनीय सहयोगी मानता है और वह किसी भी ऐसे कदम का स्वागत करेगा जो चीन और उसके गहराते संबंधों पर लगाम लगाए।

दिल्ली मेट्रो/मुनीष भाटिया

अनियंत्रित भीड़ पर सख्ती जरूरी

भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है, आज बेतहाशा भीड़ के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ साबित हो रही है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में निर्दोष यात्रियों की जान चली गई, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हर यात्री को अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करना होगा? यात्रा के दौरान ना तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रेलवे पुलिस मौजूद होती है और ना ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस प्रबंधन। सिर्फ रेलवे ही नहीं, बल्कि दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। गत दिनों दिल्ली मेट्रो मे शब्बे बरात की रात में जो हुड़दंग देखने को मिला वो मेट्रो की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर यही स्थिति रही तो मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को कब तक असुरक्षित महसूस करना पड़ेगा? यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हर साल इन मौकों पर कुछ असामाजिक तत्व सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, लेकिन अब मेट्रो जैसी संवेदनशील जगह भी इनकी गिरफ्त में आने लगी है। अगर आज हम नहीं चेते, तो कल को यह लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सरकार, सीआईएसएफ और दिल्ली मेट्रो प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे और सुरक्षा को हाई-टेक और सतर्क बनाना होगा। हर स्टेशन पर सुरक्षा जांच और कड़ी होनी चाहिए। अगर अब भी सही कदम नहीं उठाए गए, तो आगे स्थिति और बिगड़ सकती है। यह सिर्फ दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेल की बात नहीं, बल्कि पूरे देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है। अगर अब भी सही कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में यह लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा रेलवे और मेट्रो में सफर करना यात्रियों के लिए और भी अधिक खतरनाक हो सकता है।

अनमोल वचन

सत्ता की महत्ता तो मोहक भी बहुत होती है, एक बार हांथ में आने पर और कंटीली होने पर भी छोड़ी नहीं जाती

-वृंदावनलाल वर्मा

साझेदारी हुई मजबूत

अमेरिका-भारत संबंध

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर संपूर्ण विश्व की दृष्टि थी। दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइली प्रधानमंत्री, जापानी प्रधानमंत्री और जॉर्डन के राजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। मोदी ऐसे चौथे वैश्विक नेता है जिनकी ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ विस्तृत बातचीत हुई, समझौते हुए तथा इससे भविष्य के संबंधों का संकेत मिला। टैरिफ यानी सीमा शुल्क को लेकर ट्रंप का रवैया पहले जैसा ही कठोर है।

उन्होंने घोषणा किया हुआ है कि रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश उनकी सामग्रियों पर जितना शुल्क लगाता है उतना ही लगाएंगे। उन्होंने अमेरिका के पुराने मित्र और साझेदारों जापान तथा यूरोपीय संघ को भी नहीं बक्शा है। वह केवल भारत को अलग से रियायत देंगे यह मानकर नहीं चलना चाहिए। भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि वहां शुल्क इतना ज्यादा है कि व्यापार करना कठिन है। संयुक्त पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने कहा कि हम 45 अरब डॉलर के भारत से व्यापार घाटे को कम करने की ओर बढ़ रहे है। उन्होंने कहा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अनुचित और बहुत कड़े टैरिफ को घटाने की घोषणा की है, जो भारतीय बाजार में अमेरिकी पहुंच को कम करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप पहले कार्यक्रम में भी इस पर कठोर रहे हैं लेकिन भारत के विरुद्ध शुल्क वाली दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।

भारत को द्विपक्षीय व्यापार में सर्वाधिक लाभ अमेरिका के साथ है और वे शुल्क बढ़ाते हैं तो भारतीय सामग्रियों के लिए अमेरिकी बाजार में स्थान बनाना कठिन होगा। हमारा निर्यात घट सकता है और यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चिंताजनक होगा। किंतु अब केवल अमेरिका नहीं संपूर्ण विश्व को उसके साथ संबंधों के पुनर्संयोजन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। सत्ता संभालने के साथ ही ट्रंप लगातार आक्रामक होकर अपनी दृष्टि से अमेरिकी हित के संदर्भ में कदम उठा रहे हैं और उनसे अन्य देशों को परेशानी हुई है। हम यह मानकर नहीं चलें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत और विश्व की दृष्टि से सकारात्मक उपलब्धियां नहीं हुई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जिस तरीके से मोदी का स्वागत किया वैसा पूर्व के तीन नेताओं का नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा भी कि मुझे आपकी कमी यहां महसूस हो रही थी। जहां तक प्रतिक्रियात्मक शुक्ल का प्रश्न है तो ऐसा लगता नहीं कि अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक उसका सही आकलन और रूपरेखा निर्धारित किया है। माना जा सकता है कि हमारे पास अपने हितों को सुरक्षित रखने का रास्ता खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता मुक्त व्यापार समझौते पर जल्दी पहुंचने की बात की और इसी वर्ष पूरा होने का संकेत दिया। वर्तमान में भारत

और अमेरिका के बीच व्यापार 129.2 अरब डॉलर है, 2030 तक इसे 500 अरब डॉलर तक ले जाने का संकल्प मोदी ने व्यक्त किया। ट्रंप ने भारत का नंबर एक तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश बनने पर मोदी के साथ बातचीत की चर्चा की। इस तरह भारत ने रास्ता निकाला है।

संभवतः उन्हें बताया है कि आप शुल्क लगाकर अपना नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि हम बड़े खरीदार हैं। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि साझा उत्पादन, तकनीक आदि के मामले में हम रक्षा साझेदार हैं और सबसे बड़ी बात कि गैस और तेल हम आपसे खरीदेंगे। इसमें समस्या भी नहीं है। कहीं से हमको लेना है तो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और लाभ वाले ऐसे देश से, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याओं से निपटने में सहयोग कर सकता है उससे खरीदने मे समस्या नहीं है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा हाइड्रोकार्बन खरीद में विविधता बढ़ेगा, कुछ देशों पर निर्भरता में कमी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नये उभर रहे क्षेत्र में सहयोग द्विपक्षीय एवं वैश्विक व्यवस्था की दृष्टि से हमारे लिए लाभकारी है। एक महत्त्वपूर्ण बात भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा पर अमेरिका की हरी झंडी है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इससे ईरान स्थित चाबाहार बंदरगाह सुरक्षित हो सकता है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन चाबहार उन्होंने विदेश मंत्री मार्क रुबियो पर छोड़ दिया है। यह मार्ग चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का प्रत्युत्तर है। इससे हमारे दूरगामी व्यापारिक एवं सामरिक हित सधने वाले हैं। बोस्टन ओर लॉस एंजेलिस में दो नये दूतावास खोलने की घोषणा महत्त्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि अमेरिका में भारत की राजनयिक, आर्थिक और दोनों देशों के नागरिकों के बीच अंतर्संवाद का काफी विस्तार हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख अधिकारियों और नेताओं से भी मुलाकात की जिनमें अमेरिकी खुफिया सेवाओं की निदेशक तुलसी गबार्ड, अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज एवं डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख एलन मस्क शामिल है। इन सबका असर सुरक्षा एवं अन्य मामलों में आने वाले समय में धीरे-धीरे दिखाई देगा। रूस-यूक्रेन के बीच तनाव घटाने पर ट्रंप सक्रिय हैं और इसमें हमारा भी हित है क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों से समस्याएं बढ़ी हुई हैं। हिन्द-प्रशांत में हिन्द महासागर पहल की घोषणा महत्त्वपूर्ण है। ट्रंप स्वतंत्र एवं मुक्त हिन्द प्रशासन क्षेत्र की बात करते हुए कहते रहे हैं कि भारत क्षेत्र की महाशक्ति है और भारत की साझेदारी को हमेशा महत्त्व दिया है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इस यात्रा की दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां है। संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का स्पष्ट नाम लिया गया है तथा 2008 के मुंबई हमले के अपराधियों को सजा देने की भी मांग है।

प्रधानमंत्री की यात्रा की पूरी तैयारी कर कर जाते हैं और इसमें उनकी भाषा और शब्दचयन भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ट्रंप की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' यानी 'मागा' की चर्चा करते हुए कहा कि मैं इस नाते उनका प्रशंसक हूं। उसी तरह भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए मैं भी 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' पर काम कर रहा हूं। इस यात्रा के बाद आर्थिक ,सामरिक एवं रणनीतिक संबंध व साझेदारी पर बनी व्यापक सहमति से पता चलता है कि भविष्य की दृष्टि से दोनों नेताओं ने संबंधों को सही दिशा और आकार देने की पहल की है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे।

(लेख में विचार निजी हैं)

प्रधानमंत्री की यात्रा की पूरी तैयारी कर कर जाते हैं और इसमें उनकी भाषा और शब्दचयन भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ट्रंप की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' यानी 'मागा' की चर्चा करते हुए कहा कि मैं इस नाते उनका प्रशंसक हूं। उसी तरह भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए मैं भी 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' पर काम कर रहा हूं

कौशल, भाषा दक्षता की कमी के कारण बढ़ जाता है नौकरी के लिए संघर्ष

- देश के 40 प्रतिशत ग्रामीण युवा मुख्य रूप से कौशल और भाषा दक्षता की कमी के कारण रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है
- सर्वे में पांच राज्यों-दिल्ली, उप्र, कर्नाटक, पंजाब और आप्र-के 1,200 युवाओं और कामकाजी व्यक्तियों से जानकारी एकत्र की गई थी
- रिपोर्ट के मुताबिक, कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल परिणामोन्मुख बनाया जाना जरूरी है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर बहुत विवाद चल रहा है। विवाद का समाधान नहीं दिख रहा, लेकिन इसी विषय पर साढ़े सात दशक पहले संविधान सभा में एक महत्त्वपूर्ण सुझाव **Prof. Shibban Lal Saxena** ने दिया था। वो ये कि संसद दो-तिहाई बहुमत से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे तो आयोग निष्पक्ष काम करेगा!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

गंगा घाट पर गोदावरी का संगम

आस्था **नितिन प्रधान**

देश दुनिया में अभी प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे महाकुंभ को लेकर भारतीय संस्कृति की चर्चा हो रही है। तीन नदियों के संगम में करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह क्रम जारी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तक यह सिलसिला देखने को मिलेगा। इसी बीच काशी में गंगा तट पर काशी तमिल संगमम 3.0 चल रहा है। अपने तीसरे संस्करण में यह 24 फरवरी तक सनातनियों के लिए आत्मीय संबंध को नया आयाम देगा। काशी के पवित्र घाटों पर आयोजित काशी तमिल संगमम 3.0 वास्तव में गंगा और गोदावरी के मिलन जैसा अनुभव कराता है। गंगा घाटों पर जब तमिलनाडु और दक्षिण भारत के श्रद्धालु पहुंचते हैं तो यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि संस्कृतियों के अभूतपूर्व संगम का उत्सव बन जाता है। काशी तमिल संगमम 3.0 इस भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता का सजीव उदाहरण है, जहां दक्षिण और उत्तर भारत की परंपराएं एक-दूसरे में समाहित होती नजर आती हैं।

भारत की दो प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं का आत्मीय संगम है। गंगा के किनारे लोग एक-दूसरे को 'वणक्कम काशी' कहकर संबोधित करते हैं, तो यह अनूठा और भावनात्मक अनुभव बन जाता है। काशी तमिल संगमम 3.0 न केवल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संस्कृति सेतु का कार्य कर रहा है बल्कि यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को भी साकार कर रहा है। यह संगमम 3.0 भारतीय परंपराओं, संस्कृतियों और जीवन मूल्यों का उत्सव है, जो विविधताओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना को और प्रबल करता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। जब तमिलनाडु से यात्री वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो उनका स्वागत 'हर हर महादेव' के जयघोष से किया जाता है। ढोल-नगाड़ों की थाप, स्वस्तिवाचन और पुष्पवर्षा से हर यात्री स्वयं को विशिष्ट अनुभव करता है। कांचीपुरम, जिसे संक्षेप में कांची कहा जाता है, तमिलनाडु का महत्त्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह क्षेत्र हिन्दू धर्म के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से है, यहां कई ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। कांची पलार नदी के किनारे बसी है, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है बल्कि अपनी रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्मा ने यहां देवी के दर्शन हेतु तपस्या की थी। कांची को मोक्षदायिनी

सप्त पुरियों में स्थान प्राप्त है, जिनमें अयोध्या, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, काशी, उज्जैन और कांची शामिल हैं। यह नगरी हरिहरात्मक पुरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां शिवकांची और विष्णुकांची नामक दो भागों में विभिन्न मंदिर स्थित हैं। तमिलनाडु के लोग के लिए काशी केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है। भगवान विश्वनाथ, मां गंगा और देवी विशालाक्षी सदियों से तमिल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। आदि शंकराचार्य के काशी आगमन और उनके द्वारा अद्वैत वेदांत के प्रचार के बाद, तमिल संतों का काशी से लगाव और गहरा हो गया। काशी केवल शहर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, मां अन्नपूर्णा, देवी विशालाक्षी, आंध्र के मल्लिकार्जुन और तेलंगाना के भगवान राजराजेश्वर जैसे तीर्थस्थल भारत की सांस्कृतिक पहचान को परिपूर्ण बनाते हैं। इस पवित्र नगरी ने अनेक संतों और महात्माओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की है, जिसका प्रभाव आज भी तमिल समाज में देखा जा सकता है। काशी का तेलुगु संस्कृति से भी गहरा नाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। तेलुगु संतों और आचार्यों ने भी इस नगरी को विशेष रूप से गौरवान्वित किया है। तेलुगु संत तेलंगस्वामी, जिनका जन्म विजयनगरम में हुआ था, को स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने काशी का 'जीवंत शिव' कहा था। इसके अलावा, जिद्दू कृष्णमूर्ति और अन्य महान संतों को आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है।

काशी और तेलुगु संस्कृति का संबंध साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। आंध्र प्रदेश के वेमुलावाड़ा तीर्थ को 'दक्षिण का काशी' कहा जाता है, यहां की मंदिर परंपराओं में 'काशी दारम' (विशेष काला सूत्र) का प्रचलन आज भी है। इसी प्रकार, तेलुगु साहित्य में 'काशीखंडम' जैसे ग्रंथ काशी की महिमा का बखान करते हैं। समय के साथ काशी में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। बाबा विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, गंगा घाटों का नवीनीकरण और बेहतर परिवहन सुविधाओं ने काशी यात्रा को और सुगम बना दिया है। पहले जहां दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने में घंटों लगते थे, वहीं अब हाईवे और नई परिवहन व्यवस्थाओं से यह समय काफी कम हो गया है। गंगा में सीएनजी चालित नावें चलाई जा रही हैं। बनारसी खानपान लस्सी, ठंडाई, चाट, लिट्टी-चोखा और बनारसी पान जैसे पारंपरिक स्वाद काशी यात्रा को और यादगार बना देते हैं। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने आंध्र प्रदेश के एटिकोपाका खिलौनों की तरह ही प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को दशाते हैं।

समर्पण **श्रीराम शर्मा आचार्य**

मित्रो ! एक बार लैला ने मजनूं की परीक्षा लेनी चाही और जानना चाहा कि मजनूं कैसा है? पहले तो उसने ऐसा इंतजाम कर दिया कि उसको कुछ पैसे मिल जाया करें, दुकानदारों से खाने को मिल जाया करे। फिर उसने सोचा, ऐसा तो नहीं कि वह हरामखोर हो और फोकट का खा रहा हो। उसने अपनी बांदी से यह कहला भेजा कि लैला बहुत बीमार है। सुनकर मजनूं बड़ा दुःखी हुआ। बांदी ने कहा-दुःखी होने से क्या फायदा? आप कुछ मदद कीजिए न उनकी। उसने कहा-लैला को हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हो तो कुछ दीजिए न। मजनूं ने कहा-मैं क्या दूं? बांदी ने कहा-डॉक्टरों ने यह कहा है कि लैला की नसों में खून का एक प्याला चढ़ाया जाएगा, आप अपना खून देंगे क्या, जिससे कि लैला की जिंदगी बचाई जा सके। मजनूं फौरन तैयार हो गया। उसने जो कटोरा बांदी लेकर आई थी, खून से लबालब भर दिया। बांदी जब खून लेकर चली, तब उसने बांदी से एक और बात कही-बांदी जल्दी आना, अभी कई कटोरे खून मेरे शरीर में है। वह मैं उसके सुपुर्द करूंगा, क्योंकि उससे मैं मुहब्बत करता हूं और मुहब्बत का मतलब होता है-देना। बांदी जब एक कटोरा खून लेकर के गई, तो नकली मजनूं जो थे, सब भगा दिए गए। लैला ने अपने बाप से कह दिया-जो मुझसे इतनी मुहब्बत करता है और जो मुहब्बत की कीमत को समझता है, उसके ही साथ मैं रहूंगी। लैला और मजनूं की शादी हो गई। आपकी भी शादी भगवान के साथ में हो सकती है, लेकिन करना क्या चाहिए? सिर्फ एक बात करनी चाहिए कि भगवान की मर्जी पर चलने के लिए आप आमादा हो जाइए। भगवान जो आपसे चाहते हैं, उसको कीजिए। आपका चाहना भी ठीक है, लेकिन आप जो चाहते हैं, उससे पहले बहुत कुछ दे दिया है भगवान ने। आपको इंसान की जिन्दगी दी है और ऐसी जिन्दगी दी है कि आप अपनी मनमर्जी पूरी कर सकते हैं। अपनी दैनिक जरूरतों की भगवान से अपेक्षा मत कीजिए। आप अपनी हविश, इच्छाओं, महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भगवान को मजबूर करेंगे कि कर्तव्य की बात को छोड़कर वह पक्षपात करने लगे और कर्मफल की महत्ता का परित्याग कर दे?

रीडर्स मेल

बदले परीक्षा की परिपाटी

परीक्षा का उद्देश्य केवल अंकों की प्राप्ति नहीं, बल्कि मानसिक विकास, तार्किक सोच और आत्मविश्वास को परखना होना चाहिए। किंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा एक बोझिल प्रक्रिया बन चुकी है, जहां छात्रों को अंकों के आधार पर आंका जाता है, न कि उनकी मौलिकता और विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पर। प्रयागराज और वाराणसी जैसे शिक्षा केंद्रों में परीक्षा का तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि छात्र मानसिक अवसाद तक पहुंच रहे हैं। अभिभावक और शिक्षक भी परीक्षा को एक निर्णायक कसौटी मानते हैं, जिससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनता है। इस समस्या का मूल कारण पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली और समाज में परीक्षा को लेकर बनी अवधारणाएं हैं। परीक्षा केवल स्मरणशक्ति का परीक्षण बनकर रह गई है, जिससे विद्यार्थी की सृजनात्मकता और तार्किक क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए मूल्यांकन प्रणाली को अधिक समावेशी बनाया जाए। लिखित परीक्षा के आधार पर छात्रों की योग्यता निर्धारित करने के बजाय प्रायोगिक ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता और रचनात्मकता को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र

रेलवे ने दिखाई समझदारी

रेलवे स्टेशनों पर अनियंत्रित भीड़ और भगदड़ रोकने के लिए सरकार ने 60 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग जोन बनाने का साहसिक निर्णय लिया है। नई दिल्ली स्टेशन पर हालिया भगदड़ से सबक लेते हुए स्थायी व अस्थायी इंतजाम किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय संभव होगा। रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री रोककर अनावश्यक भीड़ पर लगाम कसने का प्रभावी कदम उठाया है। यह ऐतिहासिक निर्णय रेलवे यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और निर्बाध बनाएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और संरक्षा सुनिश्चित होगी।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत', ई मेल से

कांग्रेस करे तैयारी

संगठन में बदलाव निसंदेह एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन यह बदलाव इस उद्देश्य के साथ होना चाहिए की जो नये चेहरे जिम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्त किए जाएं वह आम जनता से जमीन पर संपर्क साधने में कामयाब हों और जमीन से जुड़े हुए नेता हों। जहां तक नेताओं का कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का प्रश्न है तो नेता तो पार्टी बदलते रहेंगे, महत्त्वपूर्ण यह है कि क्यों गांधी परिवार दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में रोकने में सफल नहीं हुआ। कांग्रेस के नेताओं को इस बात से बल लेने की जरूरत यही की इसी पार्टी ने पिछले वर्ष संपन्न हुए लोक सभा चुनाव में 52 से 99 सीटों का सफर तय किया है। राहुल गांधी ने ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक नेताओं को संगठन के बदलाव में पद देते हुए अपनी सामाजिक न्याय की वकालत की बात को अमल करके दिखाया है और यह अच्छी बात है। कांग्रेस संगठन आम जनता की समस्याओं को उठाए और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए। भले कांग्रेस ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में शिकस्त खाई, परन्तु बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के चुनाव अगले 15-20 महीने में होने हैं और उसे आज से ही इन चुनाव की तैयारी पर लग जाना चाहिए।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 184
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त

भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्थाई संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सम्भालता है। भारतीय निर्वाचन आयोग सरकार के तहत नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है। संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बजट होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग का प्रमुख होता है और उसके साथ दो निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्य वाली समिति की बैठक के बाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया है, जबकि विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इस संबंध में बैठक में फैसला 2-1 से हुआ। इन नियुक्तियों के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त विवादों के घेरे में रहे हैं और उन पर सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों पर लगातार आरोपों से इस संस्था की साख प्रभावित हुई है जो लोकतंत्र के लिए नुक्सानदेह है। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने ही राजनेताओं के खिलाफ कमर कसकर निष्पक्ष और बेदाग चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग में कड़े तेवरों की शुरूआत की थी। उसे आज तक लोग याद करते हैं। जब 1990 में टी.एन. शेषन ने पद सम्भाला था तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण चुनाव सुधार किए। उन्होंने ही फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र की शुरूआत की थी।

इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए गठित समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर गृहमंत्री को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। जिस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उत्तराधिकारी का फैसला किया गया, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर सहमति जताई और राष्ट्रपति को उनके नाम की सिफारिश की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी का कहना था कि नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तक के लिए टाल दिया जाए। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या रुख अपनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसी चयन समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश होंगे लेकिन केन्द्र सरकारर ने जो कानून बनाया, इसमें ऐसी चयन समिति का प्रावधान किया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया। इसे दखते हुए विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था क्योंकि ऐसी समिति में विपक्ष का नेता तो अल्पमत में ही रहेगा। नैतिकता का तकाजा तो अल्पमत में ही रहेगा। नैतिकता का तकाजा तो यही था कि चयन समिति की बैठक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक टाल दी जाती। तब न्यायालय का रुख भी साफ हो जाता लेकिन सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर लिया।

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त विवादों के घेरे में रहे हैं और उन पर सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों पर लगातार आरोपों से इस संस्था की साख प्रभावित हुई है जो लोकतंत्र के लिए नुक्सानदेह है। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने ही राजनेताओं के खिलाफ कमर कसकर निष्पक्ष और बेदाग चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग में कड़े तेवरों की शुरूआत की थी। उसे आज तक लोग याद करते हैं। जब 1990 में टी.एन. शेषन ने पद सम्भाला था तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण चुनाव सुधार किए। उन्होंने ही फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र की शुरूआत की थी। 2022 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक कई चुनाव आयुक्त हुए हैं, मगर टी.एन. शेषन जैसा कोई कभी-कभार ही होता है।

ज्ञानेश कुमार अनभुवी अधिकारी है। गृह मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो वह गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर डेस्क के प्रभारी थे। वह संसदीय कार्यालय में सचिव भी रहे और वे केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय में भी सचिव रहे हैं। उनके सामने बहुत से काम पड़े हुए हैं।

2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में होंगे। आगामी बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में ही होंगे। इसके अलावा कई राज्यों में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव भी होंगे।

उम्मीद की जाती है कि ज्ञानेश कुमार किसी भी राजनीतिक दल के प्रति किसी भी तरह की पक्षपात नहीं करेंगे और सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तभी निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बहाल होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद बहुत ही गरिमामय और प्रतिष्ठा वाला है और आशा की जाती है कि वह इसी के अनुरूप काम करेंगे।

आप से उम्मीदें अपार

"श्री ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव आयुक्त चुने जाने पर
ढेर सारी बधाई हैं,
चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रखने की
अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी आयी हैं,,
सवा सौ करोड़ देशवासियों ने आपसे उम्मीदें अपार लगायी हैं,
क्योंकि अयोग्य निर्वाचन आयोग के कारण
समस्त लोकतांत्रिक प्रणाली हो सकती धराशाही हैं...।।"

गीता पाढा

भाजपा का समय अब शुरू होता है

कलम-दवात
कुमकुम चड्ढा

अब जब दिल्ली चुनावों की हलचल थम गई है, ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि भारत की राजधानी पर शासन कौन करेगा। फिलहाल, बीजेपी के पास कई विकल्प हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कोई कमी नहीं है—हर कोई अपनी अलग योग्यता और दावेदारी के साथ खड़ा है। आखिरकार किसका चयन होगा, यह कहना मुश्किल है।

मोदी सरकार की कार्यशैली की खासियत गोपनीयता और चौंकाने वाले फैसले हैं, खासकर जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इस फैसले की जानकारी केवल दो लोगों को होती है—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का नाम प्रक्रिया में आता तो जरूर है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह महज औपचारिकता भर होती है।

अगर शुरुआत से देखा जाए, तो साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिली, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए क्या योजना बनाई जा रही है। चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बाद वे थोड़ा विश्राम चाहते थे, और प्रस्तावित विदेश दौरा उनके लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन मोदी-शाह की जोड़ी ने कुछ और ही तय कर रखा था। विदेश यात्रा रोकने के कुछ ही दिनों बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए कह दिया गया।

कुछ वर्षों बाद, जब भूपेंद्र पटेल गुजरात में अपने गृहनगर अहमदाबाद में पौधारोपण कर रहे थे, उन्हें अचानक पार्टी कार्यालय बुलाया गया। जब उनके नाम की घोषणा मुख्यमंत्री पद के लिए हुई, तो लोगों ने हैरानी से पूछा—"भूपेंद्र पटेल कौन?", "कौन सा पटेल?", "क्यों पटेल?" इन सवालों के कोई आसान जवाब नहीं थे, और मोदी-शाह के फैसले पर सवाल उठाना तब भी उतना ही असंभव था, जितना आज है।

इसके अलावा, बीजेपी नेतृत्व लॉबिंग (गुटबंदी) को बिल्कुल पसंद नहीं करता। राजस्थान में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और 40 विधायकों का समर्थन जुटाया, तब भी पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह, राजस्थान में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना, मध्य प्रदेश में मोहन यादव या छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का चयन मोदी की "परंपराओं से हटकर" फैसले लेने की नीति का ही उदाहरण है।

दिल्ली की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां बीजेपी नेतृत्व के पास पूरी छूट है। वह अपनी पसंद के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है और चाहे जितने भी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है, चाहे वह मुख्यमंत्री के चयन से जुड़ा हो या कैबिनेट गठन से। इसके अलावा, दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 70 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी ने आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। रिकॉर्ड के लिए, बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) को केवल 22 सीटें मिलीं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता खोलने में भी नाकाम रही। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2013 में सत्ता गंवाई थी, जबकि उससे पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में उसने 15 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन शून्य ही रहा। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है। 1993 से 1998 के बीच जब पार्टी दिल्ली की सत्ता में थी, तब उसने तीन मुख्यमंत्रियों को बदलते देखा। मदन लाल खुराना, जिन्होंने 27 महीने बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा दिया; साहिब सिंह वर्मा, जिन्हें 31 महीने बाद हटाया गया क्योंकि वे दिल्ली में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और सुषमा स्वराज, जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, हालांकि केवल 52 दिनों के लिए।

दिलचस्प बात यह है कि खुराना और वर्मा—दोनों के बेटों ने हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। हरीश खुराना मोती नगर से विधायक बने, जबकि परवेश सिंह वर्मा ने नई दिल्ली से जीत दर्ज की। उधर, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी भी एक जानी-पहचानी शख्सियत हैं, क्योंकि वे नई दिल्ली से सांसद हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया था। परवेश वर्मा का विधानसभा क्षेत्र भी बांसुरी स्वराज के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है।

अब सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वर्मा और स्वराज के नाम चर्चा में हैं। परवेश वर्मा को "जायंट स्लेयर" कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है।

दूसरी ओर, बांसुरी स्वराज युवा, प्रभावशाली वक्ता हैं और सबसे अहम बात—महिला हैं। 41 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। हालांकि, वर्मा के लिए स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है। वे दो बार पश्चिम दिल्ली से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। यदि वे केजरीवाल को नहीं हराते, तो शायद वे इस दौड़ में होते भी नहीं। इसके अलावा, उनके पिता का नाम भी उनके समर्थन में काम कर सकता है।

अटकलें तेज हैं कि बीजेपी दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री देने पर विचार कर रही है—जो पार्टी की दूसरी और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज (बीजेपी), शीला दीक्षित (कांग्रेस) और आतिशी (आम आदमी पार्टी) इस पद पर रह चुकी हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री हाल ही में चुने गए विधायकों में से होगा या किसी सांसद को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर बीजेपी लिंग आधारित राजनीति करती है, तो इसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को और मजबूत करना होगा, खासकर जब मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं ने अच्छे परिणाम दिए हैं। लिंग से इतर, यह संभावना भी बनी हुई है कि बीजेपी दिल्ली में किसी सिख को मुख्यमंत्री बना सकती है।

1984 के सिख विरोधी दंगों के घाव अब भी ताज़ा हैं। साथ ही, इंदिरा गांधी द्वारा स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के फैसले ने सिख समुदाय को कांग्रेस से दूर कर दिया था। ऐसे में, यदि बीजेपी किसी सिख को मुख्यमंत्री बनाती है, तो इससे न सिर्फ समुदाय की भावनाओं को संतुष्ट किया जा सकेगा, बल्कि यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी होगा कि बीजेपी सिखों और पंजाबी मतदाताओं के साथ खड़ी है, जिन्होंने इस बार पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है। जातीय समीकरण भी मुख्यमंत्री के चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी पूर्वांचली समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहेगी। पार्टी ने पूर्वांचली बहुल 14 सीटों में से 11 पर जीत दर्ज की है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, और बीजेपी बिहार में पूर्वांचली वोटरों को लुभाना चाहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में विशेष रूप से पूर्वांचली मतदाताओं का धन्यवाद किया था।

जहां तक दलितों की बात है, यह पहली बार है जब बीजेपी को विधानसभा स्तर पर दलित वोटरों का समर्थन मिला है। इस चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में गई हैं। इस मोड़ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या इतनी मज़बूत स्थिति में होने के बावजूद बीजेपी प्रतीकात्मक राजनीति का सहारा लेगी? क्या वह जाति और लिंग के आधार पर वोट साधने की कोशिश करेगी, या फिर केवल कुछ वर्गों को खुश करने के लिए पदों का बंटवारा करेगी? क्या वह वंशवाद की राजनीति का शिकार होगी? या फिर वह सुशासन को प्राथमिकता देकर ऐसे नेता का चयन करेगी जो विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके और पटरी से उतरी राजधानी को फिर से सही दिशा में ले जाए? यह भी एक तथ्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम जनता के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें मोहल्ला क्लीनिक और स्कूलों का आधुनिकीकरण प्रमुख हैं। बीजेपी के लिए यही बेहतर होगा कि वह इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाए, न कि सिर्फ इसलिए उन्हें नष्ट कर दे क्योंकि वे आप सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थीं। अब समय आ गया है कि पार्टी संकीर्ण और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करे, जिन्होंने उम्मीद और विश्वास के साथ उसे सत्ता में लाया है। बीजेपी की प्रभावशाली जीत को देखते हुए, उसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है।

पश्चिम बंगाल में संघ का विस्तार

फिरोज बख्त अहमद

राष्ट्रीय स्तर पर जब भी डॉ. मोहन भागवत अपना कोई व्याख्यान लेकर आते हैं, तो भारत को लेकर उनका कोई न कोई रूपोश या अदृश्य, मगर सकारात्मक एजेंडा अवश्य होता है। अपने भाषणों में उनकी यही विशेषता रही है कि किसी के खिलाफ़ न तो वे ज़हर उगलते हैं और न ही मुजरिम को बख्शते हैं, अर्थात वे भारत विरोधी तत्वों से ख़ूब लोहा लेना जानते हैं, जिसके कारण आज भारत जगत गुरु बनने के मार्ग पर है। इस प्रकार से एक तीर से कई शिकार खेल लेते हैं भागवत।

उन्होंने देश के पश्चिमी भाग बंगाल के वर्धमान के साई ग्राउंड में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू समाज के भीतर एकता की जरूरत दोहराई और कहा कि अच्छे समय में भी चुनौतियां बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, "हमें हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करने की जरूरत है। समस्या की प्रकृति अप्रासंगिक है; महत्वपूर्ण यह है कि हम उसका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं।" हाल में ही, जिन तीन राज्यों में भाजपा जीती है, उसका श्रेय जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम को जाता है, उतना ही मोहन भागवत और उनकी टीम को जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि, "आज कोई खास कार्यक्रम नहीं है। संघ के उत्सव होते हैं वह भी नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि, इतनी कड़ी धूप में हम बैठे रहें। यहां आने में कई तरह बाधाएं आई होंगी। संघ से अनभिज्ञ लोगों के मन में यह सवाल है कि, संघ क्या करना चाहता है? अगर हमें यह जवाब देना है कि 'संघ' क्या चाहता है तो मैं कहूंगा कि यह 'संघ' हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है क्योंकि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है।"

पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाना काफी अहम है। बताना होगा कि मोहन भागवत की वर्धमान में हुई इस सभा के लिए संघ को कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। पिछले 10 सालों में बंगाल में आरएसएस ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया है। अपने बंगाल दौरे के दौरान मोहन भागवत ने आरएसएस में युवाओं को शामिल करने पर जोर दिया। एक अन्य तथ्य यह भी है कि केरल को तरह पश्चिम बंगाल में भी संघ और भाजपा के कई कार्यकर्ता अपना बलिदान दे चुके हैं, अतः वहां के ऐसे दंगाई तत्वों को काउंसलिंग

और क़ानून की सहायता से नेकी के सही रास्ते पर लाना भी भागवत का ध्येय है। एक बात यह भी है कि 2025 का साल संघ का शताब्दी वर्ष भी है। इसमें आरएसएस जाति व्यवस्था को खत्म करना, पारंपरिक हिंदू परिवार की स्थापना, लोगों में नागरिक भावना विकसित करना सहित 5 बिंदुओं पर काम कर रहा है। इन पांच बिंदुओं में सर्वधर्म समभाव भी एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। यूं तो भागवत मुस्लिम तबके के विरुद्ध नहीं बोलते, मगर हिंदू समाज को एकजुट होने की बात के साथ उन्होंने यह अवश्य कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ़ वे कभी नहीं रहे, मगर भारत विरोधी मुसलमानों को जो वे चाहते थे, वह मिल गया, अतः जिन मुस्लिमों ने 1947 में पाकिस्तान के विचार को त्याग कर हिंद को अपनी जन्नत बनाया था, उन्हें पूर्ण रूप से स्वयं को भारत को समर्पित कर देना चाहिए। मुसलमानों के संबंध में इस से पूर्व भी भागवत ने कुछ अच्छी बातें कहीं हैं, जैसे लगभग दस वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था कि उनके योगदान के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हर मस्जिद के नीचे खुदाई कर मंदिर ढूंढने की बात चली तो उस समय भी भागवत ने सरकार व संघ परिवार से कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की बात नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को भी मानते हैं कि मुस्लिम उनकी संतान की भांति हैं। भले ही संघ परिवार के कुछ घटक, मुस्लिमों की घर वापसी की बात करें, मगर भागवत का इस संदर्भ में सदा से ही यही विचार रहा हैं कि धर्म एक है और उसकी पद्धतियां और रंग रूप अनेक हैं और इसी प्रकार से मुस्लिम भी हैं और वे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं चाहते। वे कहते चले आए हैं कि हम सब का डीएनए एक है।

इस में कोई दो राय नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजा राम मोहन रॉय और गुरु रविन्द्र नाथ टैगोर के कर्म स्थलों पर भागवत की तेज़-तर्रार और सटीक निगाहें हैं जहां वे अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को स्थापित करना चाहते हैं, जिस में सभी का विकास, विश्वास और प्रयास शामिल होगा। दूसरे यह कि पश्चिमी बंगाल और चीन से निकट है और माओवादी संगठनों से भी ग्रसित है। बीजेपी 2016 और 2021 में बंगाल में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है लेकिन तब उसे कामयाबी नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया है। पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के चुनाव में जीत दर्ज की है और अब पार्टी बंगाल में भगवा झंडा फहराना चाहती है। वैसे भी पिछले दो चुनावों से भाजपा बंगाल में अपनी जीत दर्ज करने के लिए प्रगाढ़ परिश्रम किया है। कामयाबी भले ही मिली हो, मगर "हम होंगे कामयाब" वाले मंत्र में अपनी आस्था जताते हुए, आरएसएस और भाजपा पूर्ण रूप से परिश्रम करने में लगे हुए हैं।

वक्फ संशोधन बिल से लोकतंत्र में मिलेगी और मजबूती

रोहित माहेश्वरी

संसद के बजट सत्र में एक नया विधेयक लाया गया जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतव्वली द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है।

इतिहास के पन्ने पलटें तो भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइज्जुद्दीन सैम गौर (मुहम्मद गौरी) की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गईं। साल 2013 में, अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया।

वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने बीती 13 फरवरी को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में जेपीसी ने एएसआई के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि एएसआई की कई संरक्षित स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है। जेपीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद घोषित किया हुआ था। इन स्मारकों में कई राजधानी दिल्ली में हैं। कुतुब मीनार, फिरोजशाह कोटला, पुराना किला, अग्रसेन की बावड़ी, हुमायूं का मकबरा, जहांआरा बेगम की कब्र और कुतुब मीनार क्षेत्र में स्थित आयरन पिलर, अल्तमश का मकबरा जैसे स्मारक भी वक्फ की संपत्ति हैं। समिति की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इन स्मारकों की फेहरिस्त सौंपी थी। इसके अलावा, शहरी विकास मंत्रालय ने कमेटी को बताया कि भूमि एवं विकास विभाग की 108 और डीडीए की 130 संपत्तियां वक्फ के कब्जे में दी गईं। वक्फ ने बाद में इन स्मारकों पर अपना दावा बता दिया। बता दें कि एक समय देश में वक्फ बोर्ड की 52 हजार पंजीकृत संपत्तियां थीं। आज 9.4 लाख एकड़ जमीन पर 8.72 लाख अचल संपत्तियां हैं। भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है। कानून का राज है, तटस्थ और विवेकी न्यायपालिका है। इस देश में वक्फ बोर्ड भी है। वह जिस इमारत, जमीन, गांव और सैकड़ों साल पुराने मंदिर और मठ की तरफ अपनी अंगुली उठाता है, तो वह उसकी संपत्ति मान ली जाती है। बेशक विवादों के लिए एक ट्रिब्यूनल भी है, लेकिन उसमें 40,950 से अधिक मामले अब भी लंबित पड़े हैं। 9942 मामले ऐसे भी हैं, जो मुसलमान वादियों ने ही वक्फ के खिलाफ कर रखे हैं। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक वक्फ बोर्ड के अधीन 9.40 लाख एकड़ जमीन है। आर्थिक विश्लेषण किया जाए, तो उस जमीन से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। वक्फ जमीन के कब्जेबाज सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आमदनी ही मानते रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। क्या यह किसी घोटाले की ओर संकेत करता है? क्या ऐसी निरंकुशता और कानूनहीनता किसी संवैधानिक देश में स्वीकार्य हो सकती है? द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, यह कानून वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2022 में, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गांव पर अपना दावा जताया था। यह बुनियादी आधार है, जिस पर वक्फ बोर्ड के नए कानून, नए नियमों और पूरी तरह कानूनी प्रारूप के लिए मौजूदा कानून में संशोधन अनिवार्य है। भारत में सेंट्रल और राज्य के कुल 30 बोर्ड कार्यरत हैं। लाखों संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन हैं, लेकिन आम मुसलमान के लिए कोई फायदा नहीं। आम मुसलमान के लिए कोई अधिकृत अस्पताल नहीं। आधुनिक स्कूल, कॉलेज नहीं हैं। जरूरतमंद के लिए आर्थिक मदद की कोई विशेष योजना नहीं है। यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। पहले वक्फ अधिनियम, 1995 कहते थे। आगे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहेंगे। पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट में भी कर सकेगा। पहले ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। पहले जिस जमीन पर मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होता हो, वो वक्फ की होती थी। अब दान की ही जमीन वक्फ की होगी, भले ही उस पर मस्जिद हो। पहले वक्फ बोर्ड में महिला और गैर धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते थे। अब दो महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने होंगे। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर नामित अधिकारी करेगा। जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर हैं, उन पर असर नहीं। जो रजिस्टर नहीं, उन्हें नए मानकों के अनुरूप रहेंगी। जो बोर्ड को जमीन दान करना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि वह 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं।

मुस्लिम और उनके वोट बैंक पर जिंदा राजनीतिक दलों के नेता औसत मुसलमान को भड़काने और आंदोलित करने की सियासत कर रहे हैं, लिहाजा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 655 पन्नों की रपट को 'फर्जी' करार दिया है। उसे अलोकतांत्रिक, संविधान-विरोधी और प्रक्रिया-विरोधी भी माना है। लोकतांत्रिक भारत में 'असंवैधानिक' तो यह है कि वक्फ संपत्तियों का कोई 'सेंट्रल डाटा' ही उपलब्ध नहीं है। वक्फ वाले तो संसद भवन की जमीन को भी वक्फ की संपत्ति मानते हैं। शुक्र है कि अभी राष्ट्रपति भवन उनकी निगाहों से बचा हुआ है। वक्फ को लालकिला और कुतुब मीनार की जमीन को भी वक्फ की संपत्ति मानने में कितना वक्त लग सकता है?

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

अनुशासन चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है

विदेश में नौकरी

इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पंजाब में युवाओं को सुहाने सपने दिखाकर और मोटा पैसा लेकर अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगता यही है कि अमेरिका की ओर से अपने वहां अनुचित तरीके से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उससे बचने के लिए ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा भी नहीं है कि यह किसी से छिपा हो कि हमारे युवा अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यह बार-बार सामने आ रहा था कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में युवाओं को अवैध तरीकों से पश्चिमी देशों में भेजने वाले तथाकथित ट्रैवल एजेंट बेलगाम होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन न तो इन राज्यों की सरकारों ने उन पर कोई शिकंजा कसा और न ही केंद्र सरकार ने इसकी चिंता की कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगे। यदि अमेरिका अपने यहां अवैध तरीके से घुसे लोगों को हथकड़ी-बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजता तो शायद अभी भी सरकारों की नींद टूटने वाली नहीं थी। यह ठीक है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी का सिलसिला कायम होने के बाद केंद्र सरकार इसके उपाय करने जा रही है कि दूसरे देशों में नौकरी के इच्छुक युवा वहां जाने के लिए अवैध तौर-तरीके न अपनाएं, लेकिन सच तो यह है कि वह भी इस बारे में समय रहते सक्रिय नहीं हो सकी। कम से कम अब तो उसे गंभीरता दिखानी ही चाहिए, क्योंकि अवैध प्रवासी देश की बदनामी का कारण भी बन रहे हैं। देखना है कि कौशल विकास मंत्रालय युवाओं को विधिवत ढंग से विदेश भेजने और उनके वहां रोजगार के अवसर भुनाने में समर्थ बनने के लिए जो प्रयास करने जा रहा है, उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि तमाम संभावनाओं के बाद भी अभी तक इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। हाल के समय में यह बार-बार सामने आता रहा है कि विदेश में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब हमारे दूतावास और उच्चायोग यह देखेंगे कि भारतीय युवाओं के लिए किस देश में रोजगार के कैसे मौके हैं? यह देखने के साथ ही इसके भी जतन करने होंगे कि हमारे युवा विदेश में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता-दक्षता से भी लैस हों।

हाथ खोलें बैंक

यह चिंता की बात है कि बैंक राज्य के जरूरतमंदों को ऋण बांटने में कोताही बरत रहे हैं। राज्य सरकार ने बैंकर्स के साथ हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसे तत्काल दुरुस्त करें। विकास दर के मामले में बिहार देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है, इसका मतलब है कि यहां अर्थव्यवस्था के पैमाने पर जमकर काम हो रहा। स्टार्टअप के माध्यम से खुद का काम करने को इच्छुक युवा हों, पापड़-अचार के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हों या उन्नतशील किसान, सभी ने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का संकल्प लिया है। चाहिए तो बस ऋण, लेकिन बैंक हाथ बांधे हैं। पूंजी के अभाव में सपने दम तोड़ रहे हैं। दरअसल, छोटे-मोटे लोन चाहने वालों के आवेदन खारिज करने के लिए बैंक दर्जनों पैंतरे अपनाते हैं। उनसे अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाते हैं, जमकर दौड़ाया जाता है। थककर आवेदनकर्ता अपने कदम पीछे खींच लेता है। अर्थव्यवस्था को जरूरी रफ्तार में यह बहुत बड़ी बाधा है। बैंकों के उच्चाधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए कि उनके यहां आवेदन क्यों खारिज किए जा रहे हैं। अनावश्यक पेच फंसाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिर डीएम और राज्य सरकार को भी चिन्हित करना चाहिए कि कौन से बैंक लचर प्रदर्शन कर रहे। आईना दिखाकर इन्हें पटरी पर लाया जाना चाहिए। बैंकों के अनावश्यक आवेदन खारिज करने का नतीजा है कि नान बैंकिंग कंपनियां और सूदखोरों का धंधा फलता-फूलता है।

बैंक लोन बांटने में कोताही कर रहे, यह उचित नहीं है। इस पर कड़ाई होनी चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या चीन पर सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है?

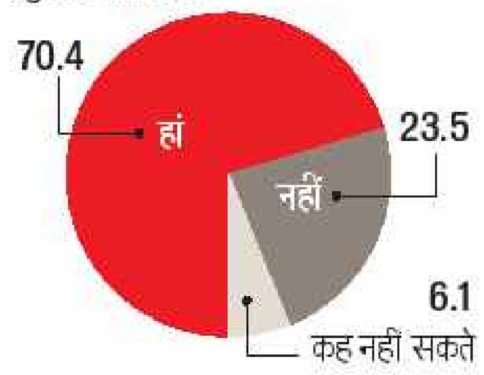

आज का सवाल

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में राहुल गांधी की आपत्ति उचित है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता

आदित्य सिन्हा

भारत में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है, ताकि वह अर्थव्यवस्था की क्षमताएं बढ़ाने में सहायक हो

अमेरिका पर दुनिया भर के तमाम मामलों में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी हस्तक्षेप की बातें सामने आईं। भारत में भी चुनावों एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में बड़ी रकम दांव पर लगाने की बात सामने आई है। अपने ऐसे अभियानों को सफल बनाने से लिए अमेरिका को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह रकम मुख्य रूप से सरकारी खजाने से आती है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि इस सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के पक्ष में वहां तमाम आवाजें बुलंद हो रही हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन एलन मस्क की अगुआई में डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) यानी सरकारी दक्षता विभाग के जरिये बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। इसमें अनावश्यक नौकरशाही के आकार को घटाने से लेकर फिजूलखर्च रोकने के उपाय तलाशे जाएंगे। डीओजीई की इस पहल ने दुनिया भर में सरकारी मशीनरी के दायरे को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत भी ऐसे सवालों से अछूता नहीं है, लेकिन अगर इस पर गहराई से विचार करें तो क्या भारत में सरकारी खर्च को घटाया जाना आवश्यक है? इसका जवाब है-नहीं। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। अगर वर्ष 2022 के दौरान भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो यह जीडीपी का 28.62 प्रतिशत रहा। यह चीन (33.4 प्रतिशत), ब्राजील (46.38 प्रतिशत), अमेरिका (36.2 प्रतिशत) और फ्रांस (58.32 प्रतिशत) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। पूंजीगत व्यय में सड़क और राजमार्गों को ही लें तो उन पर किया जाने वाला खर्च बहुत गुणात्मक प्रभाव वाला होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सड़कों पर किया जाने वाला एक रुपये का खर्च समग्र अर्थव्यवस्था में ढाई रुपये के बराबर लाभ दिलाने वाला होता है। इससे कनेक्टिविटी की स्थिति सुधरती है। परिवहन लागत घटती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। हालांकि यह गुणात्मक प्रभाव पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाता है, क्योंकि यदि उसमें हीलाहवाली की जाती है तो फिर उसके अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से रहे। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बुनियादी ढांचे में न केवल मात्रात्मक, बल्कि गुणात्मक रूप से भी सुधार हो। इसके बावजूद, यह पूरी प्रक्रिया अभी प्रगति में ही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हों।

अवधेश राजपूत

डीओजीई को लेकर भारत के दृष्टिकोण से यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है कि नियामकीय स्तर पर सुगमता कैसे स्थापित की जाए। ये नियामकीय बाधाएं ही आर्थिक वृद्धि में अवरोध बनती हैं। भारत के मामले में तो यह कोई दबी-छिपी बात नहीं है। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार ने नियामकीय बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें सुसंगत बनाने के हरसंभव प्रयास किए हैं। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ी है, जो ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग में भी झलकती है। फिर भी इस दिशा में बहुत किया जाना अभी शेष है। इन्हीं प्रयासों को और विस्तार देते हुए सरकार ने जन विश्वास अधिनियम, 2023 पारित कराया है। इस कानून के जरिये कई पुरातन प्रविधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त किया गया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस विधेयक के नए स्वरूप को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य नियमन के पहलुओं को तार्किक बनाते हुए व्यापक कारोबार हितैषी परिवेश तैयार करना है। एक फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट में नियामकीय तालमेल बेहतर बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा भी हुई है। इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में नियामकीय सुगमता एवं आर्थिक सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पुनः रेखांकित भी किया। अब सभी की नजरें उच्चस्तरीय समिति पर टिकी हैं। इस समिति को आखिर क्या करना चाहिए? वैसे तो अभी तक न तो इस समिति का औपचारिक खाका सामने रखा गया है और न ही उसके स्वरूप एवं सदस्यों के विषय में कुछ बताया गया है। ऐसे में, उसके लिए कुछ बिंदुओं को सामने रखना उपयोगी होगा कि उसे किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समिति को किस्तों में सुधार के बजाय निरंतर रूप से साहसिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो उसे नियामकीय मोर्चे पर कायम विसंगतियों एवं विरोधाभासों को दूर करना होगा। ऐसे कानून बनाने होंगे जो उद्यमों के अनुकूल हों। दांडिक प्रविधानों को सीमित करना होगा। संसदीय गतिरोधों का तोड़ निकालकर प्रक्रियाओं को गति देने वाले तौर-तरीके तलाशने होंगे। पुराने कानूनों को अनिश्चितकाल तक कायम रखने के बजाय सनसेट क्लाज का सहारा उपयोगी होगा। नियामकीय ढांचे की निरंतर समीक्षा और उसमें सुधार के सतत प्रयास भी आवश्यक होंगे। श्रम सुधारों के लिए भी कोई रूपरेखा तैयार करनी होगी। अनुपालन बोझ घटाने के उपाय भी तलाशने होंगे।

विधायी परिवर्तनों से इतर उच्चस्तरीय समिति को नियामकीय संस्थाओं की मनमानी और अप्रत्याशितता को भी नियंत्रित करना होगा। उसे नियामकीय अधिसूचनाओं के लिए एक नियत शेड्यूल बनाना होगा और उद्यमों को अप्रत्याशित एवं एकाएक किए जाने वाले परिवर्तनों की तपिश से बचाना होगा। निरीक्षण भी जोखिम आधारित ढांचे के आधार पर ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। स्व-नियमन और थर्ड पार्टी आडिट से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ उत्पीड़न एवं अक्षमताओं के लिए गुंजाइश खत्म करनी होगी। इस प्रकार के समन्वित प्रयासों से हमारे उद्यम लालफीताशाही के भंवर में फंसने के बजाय कारोबारी वृद्धि और नवाचार पर अपनी ऊर्जा एवं संसाधन लगाने में सक्षम हो सकेंगे।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

भगदड़ की घटनाओं से त्रस्त भारत

राजीव सचान

भगदड़ वहीं मचती है, जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है और भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं

भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि यहां के लोग भीड़ वाले स्थानों में बदइंतजामी के कारण रह-रह कर मरते रहें। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म पर भगदड़ मचने से 18 लोग मारे गए और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। इनमें अधिकांश वे थे, जो प्रयागराज जाने के लिए आए थे। इसके पहले महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से 30 लोग मारे गए थे। भगदड़ वहीं मचती है, जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है और भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण के उपाय नदारद थे। रेलवे की ओर से कितना भी कहा जाए कि ऐसा नहीं था, लेकिन सच यही है कि इसकी परवाह नहीं की गई कि रेल यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से यात्रा कर सकें। इसकी पुष्टि भगदड़ में मौतों के बाद रेलवे की ओर से किए गए इन उपायों से होती है कि अब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें निर्धारित प्लेटफार्म से जाएंगी, यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और इतनी से इतनी अवधि के बीच प्लेटफार्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? केवल यही कि हादसे के बाद होश आया। यदि ये सारे उपाय पहले कर लिए जाते तो 18 जिंदगियों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता था।

देश की राजधानी में प्रमुखतम रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के उपायों की अनदेखी और उसके चलते 18 यात्रियों की मौत से भी खराब बात यह रही कि हादसे के बाद अधिकारी भगदड़ मचने और उसमें यात्रियों के मारे जाने-घायल होने की बात छिपाने के जतन करते रहे। अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की सूचना नहीं है। इसी कारण इस पर यकीन करना कठिन है कि जांच सही तरह होगी और लापरवाह अधिकारी दंड के पात्र बनेंगे। महाकुंभ में भगदड़ से 30 श्रद्धालुओं की मौत की भी जांच हो रही है। जांच पुलिस भी कर रही है और न्यायिक आयोग भी। पता नहीं कि इन दोनों जांच से क्या सामने आएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महाकुंभ में भगदड़ के करीब 15 घंटे बाद यह बताया गया कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके उपरांत मृतकों की सूची और मृत्यु प्रमाणपत्र देने में भी देरी की खबरें आईं। इसके चलते विपक्षी नेताओं को यह आरोप लगाने का अवसर मिला कि महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा छिपाया जा रहा है। अपने देश में यह सदैव देखने को मिलता है कि सरकारी अधिकारी पहले तो किसी घटना-दुर्घटना की गंभीरता कम करके बताते हैं और फिर उसमें मारे गए लोगों का विवरण देने में। यह हमारी नौकरशाही की वह विचित्र प्रवृत्ति है, जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कारण उन जांच पर भी भरोसा नहीं होता, जिनमें अधिकारी ही अधिकारी की जांच करते हैं।

भगदड़ वाले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ● फाइल

जब भी कहीं भीड़ भरे स्थलों में कोई हादसा होता है और उसमें लोग मारे जाते हैं तो घटना की जांच करने-कराने वालों से यही सुनने को मिलता है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि भविष्य में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए? ऐसा केवल सुनने को ही मिलता है, क्योंकि बार-बार वैसे ही हादसे होते रहते हैं, जैसे पहले हो चुके होते हैं। कभी-कभी तो उन्हीं स्थलों पर हो जाते हैं, जहां पहले हो चुके होते हैं। इसका उदाहरण कुंभ भी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी। भगदड़ की घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो केवल जनहानि ही नहीं होती, बल्कि देश की बदनामी भी होती है। एक ऐसे समय जब देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बातों के साथ इसके लिए प्रयत्न भी हो रहे हैं, तब फिर सार्वजनिक स्थलों में भीड़ नियंत्रण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। हमारे नीति-नियंता इन उपायों से अनभिज्ञ नहीं और सच तो यह है कि भीड़ नियंत्रण के नियम-कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन मुश्किल से होता है।

अपने यहां नियम-कानूनों के उल्लंघन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कारण केवल यह नहीं कि लोगों को उनकी परवाह नहीं होती, बल्कि यह भी है कि शासन-प्रशासन के स्तर पर उनके अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता। प्रायः यह अनुपालन मनचाहे तरीके से होता है। बीते वर्ष 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की जांच के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें आयोजन की अनुमति मांगने वालों को तो भगदड़ का जिम्मेदार माना गया, लेकिन बाबा की कोई गलती नहीं पाई गई। उनका नाम एफआइआर तक में नहीं था। इसके विपरीत जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के समय थियेटर में भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी तो अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहना कठिन है कि एक जैसे मामले में अलग-अलग तरह की कार्रवाई में कौन उचित थी और कौन नहीं, लेकिन अपने देश में भगदड़ जनित घटनाओं में कार्रवाई होने या न होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे हादसों से जरूरी सबक सीखे जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मृग मरीचिका

मृग मरीचिका को मृगतृष्णा भी कहा गया है। इसका अर्थ है जीवन में उन भ्रामक आकर्षणों एवं इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहना, जो कभी पूरी होना संभव नहीं। इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन मृग मरीचिका के वशीभूत मनुष्य उन सपनों के पीछे भी दौड़ने लगता है, जिनका कोई औचित्य नहीं। मृग मरीचिका ही तमाम मिथ्या लालसाओं का आकर्षण उत्पन्न करती है। उनके लिए मनुष्य प्रयास भी करता है, लेकिन अंततः परिणाम शून्य ही रहता है। कारण यही कि वह भ्रामकता दिवास्वप्न होती है, जिसका कोई यथार्थ भावी अस्तित्व नहीं होता। क्षितिज के उदाहरण से मृग मरीचिका को सहज ही समझा जा सकता है। दूर से पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, किंतु उस छोर तक पहुंचने पर उस मिथ्या भ्रम की वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार होता है।

मनीषियों का मत है कि ऐसी भ्रामकता के आकर्षण में निरर्थक दौड़-भाग के बजाय निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए अपने मूल लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। यह सदैव याद रहे कि मनुष्य को ऐसी अनेकों मृग मरीचिकाओं ने अपने अंतहीन जंजाल में सम्मोहित कर रखा है, जिनका शमन और सृजन अबाध गति से सतत चलता रहता है। इसके परिणामस्वरूप इस राह में कुछ लालसाएं छूटती हैं तो बहुत कुछ नई जुड़ती रहती हैं। अतः उनके पीछे दौड़-भाग करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बदहवासी में अपनी अंतरात्मा में बैठे विवेक की शरण लेकर मन की निरंकुश चंचलता को नियंत्रित करने के लिए उद्यत रहना ही श्रेयस्कर होता है।

भ्रामक आकर्षण का संबंध लालसा एवं आकांक्षा जैसे सांसारिक विकारों से होने के कारण उम्र का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वृद्धावस्था में भी अक्सर तरुणाई की लालसा देखी जा सकती है। इसलिए मन की चंचलता पर विवेक की लगाम लगाए रखना ही मृग मरीचिकाओं से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

साझा प्रयासों से ही विकसित होगा देश

'विकसित भारत के लक्ष्य की बाधाएं' शीर्षक से लिखे आलेख में विवेक काटजू ने बताया है कि विकसित भारत का लक्ष्य एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन आवश्यक लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने इसमें विज्ञान तकनीक एवं एआइ के महत्व को भी दर्शाया। भारत का विकास केवल सरकार के प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी का 'विकसित भारत' का लक्ष्य 2047 तक, जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण है। यह लक्ष्य मात्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति तक विस्तृत है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कैसे अपनी शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में समग्र सुधार लाते हैं। शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाना चाहिए, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में निवेश करना सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से एक सशक्त आधार तैयार करना आवश्यक है। डिजिटल क्रांति, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ ने विश्व को नए युग में प्रवेश करा दिया है। भारत को भी इस क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करना होगा, ताकि हम वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए निजी क्षेत्र को अधिक शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि हम अपने संसाधनों के आधार पर नवाचारों को बढ़ावा दे सकें। भारत का विकास केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं हो सकता। यह एक साझा प्रयास होना चाहिए, जिसमें सभी नागरिक और अन्य क्षेत्र मिलकर काम करें। केवल ऐसे समन्वित प्रयास ही विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।

bhubaaman2020@gmail.com

शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र सराहनीय

जीवन में मातृभाषा का बहुत महत्व होता है। भाषा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की कड़ी है। भाषा के सहारे किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति और उसकी सामूहिक मानस को समझा जा सकता है। राष्ट्र की बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया गया है। पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई केवल मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में ही होगी। मातृभाषा के सहारे बच्चे आसानी से किसी भी विषय को समझ सकते है और रचनात्मकता का विकास होता है। दुनिया के सभी विकसित देश अपनी मातृभाषा को अपनाकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को सम्मिलित किया गया है। इससे दक्षिण भारत के बच्चे आसानी से हिंदी जान सकते हैं और उत्तर भारत के बच्चे भी आसानी से तमिल, कन्नड़, तेलुगू या मलयालम जान पाएंगे। इससे उन्हें रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे और देश की एकता को मजबूती मिलेगी। इसलिए शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र सराहनीय है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

आपदा घोषित हो भगदड़

भगदड़ की स्थिति अपने देश के लिए नई बात नहीं है। लोग समूह में एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी विशेषता होती है कि स्वयं की भावना समाप्त कर समूह की बातों को लेकर चलना। वर्तमान में कुंभ की भगदड़ जहां चर्चा में है, वहीं दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। भगदड़ का अपना एक मनोविज्ञान है। भगदड़ जैसी स्थिति में सामान्य लोगों में घबराहट होना स्वभाविक है। सामान्य तौर पर जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, वहीं भगदड़ जैसी स्थिति में केवल स्वयं को बचाने के प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सहयोगात्मक व्यवहार समाप्त हो जाता है। ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति जहां व्यक्तियों की त्वरित सक्रियता का परिणाम होती है, वहीं प्रशासनिक अकुशलता को भी उजागर करती है। ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति को आपदा घोषित करना चाहिए और इससे बचाव का प्रशिक्षण प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी के साथ सामान्य लोगों को भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे सामान्य स्थिति में भगदड़ जैसी स्थिति में स्वयं को कैसे बचाएं, कैसे पैर को स्थिर रखें, कैसे सिर को ऊंचा रखें, कैसे अपनी छाती के सामने मजबूती से हाथ रखें, कैसे अपनी पसलियां सुरक्षित रखें, कैसे फेफड़ों में सांस भरते रहें आदि। आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

पोस्ट

पहले कहा गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई। यात्रियों के एक-दूसरे पर गिरने से हादसा हुआ। प्लेटफार्म बदलने की मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया गया। अब आरपीएफ की जांच रिपोर्ट कह रही है प्लेटफार्म बदलने से भगदड़ हुई ...।

पंकज झा@pankajjha_

लगभग 79 देशों के स्कूलों में बच्चों को मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया जाता है। इन देशों में फोन मुक्त अधिनियम लागू किए गए हैं। अमेरिका के भी 50 में से करीब 20 राज्यों में स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी है। मोदी सरकार को भी भारत में यह व्यवस्था लागू करने के बारे में सोचना चाहिए।

पंकज शर्मा@Pankaj__Sharma

चैंपियंस ट्राफी में बुमराह के बिना हमारी गेंदबाजी अधूरी है। स्पिन विभाग ठीकठाक है। अगर हमें खिताब जीतना है तो बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा। धीमी पिचों पर भारत को बल्लेबाजी में महारत भी हासिल है। विराट और रोहित का फार्म में लौटना भी टीम के लिए शुभ संकेत है।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जनपथ

पित्रोदा जी चीन की करो आरती आप,
भाई-भाई बोलकर क्यों पालें हम सांप।
क्यों पालें हम सांप पालते थे जो चच्चा,
समझ चीन की चाल रहा है बच्चा-बच्चा।
बासठ में इक बार चचा ने गड्ढा खोदा,
फिर दोहराना चाह रहे गलती पित्रोदा!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 306

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अश्लीलता के खिलाफ

यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उनके गहरे निहितार्थ हैं। शीर्ष अदालत ने रणवीर से पूछा कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के कार्यक्रम में आपने जो कुछ कहा, 'इस देश में यदि वह अश्लीलता नहीं है, तो फिर अश्लीलता के मानक क्या हैं?' न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित ही कहा कि रणवीर और उनके साथियों ने जैसी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया और जो शब्द उन्होंने चुने, उनसे माता-पिता, बहनें-बेटियां व भाई शर्मिंदा होंगे। हालांकि, बतौर नागरिक उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए अदालत ने उन्हें वैधानिक उत्पीड़न से बचाने के लिए इस मामले में अतिरिक्त एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी और राज्य प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के प्रसारण के चंद घंटों के भीतर हुई भारी फजीहत के बाद रणवीर को न सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी, बल्कि यूट्यूब से इस श्रृंखला के सारे एपिसोड हटाने पड़े थे। मगर जगह-जगह रणवीर और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों ने अश्लील सामग्री के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

स्वस्थ प्रहसन भारतीय लोक का हमेशा से हिस्सा रहा है और समाज-निर्धारित मर्यादाओं से पोषित इस कला के प्रति आज भी कम आकर्षण नहीं है। इस विधा के कलाकारों की जहानत उनकी बारीक उपहास-व्यंग्य क्षमता से तय होती रही। कामसूत्र के रचयिता तो दार्शनिक तक कहे गए। ऐसा भी नहीं कि वाचिक अश्लीलता हमारे समाज में थी ही नहीं और रणवीर व समय रैना ने पहली बार उसका विस्फोट किया है, सच तो यह कि यहां की गालियों के समाजशास्त्र पर गंभीर अध्ययन तक हो चुके हैं। मगर वास्तविकता यही है कि भद्र लोक ने हमेशा इस प्रवृत्ति का बहिष्कार किया। अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की हिफाजत करते हुए लगातार मानवीय संबंधों की गरिमा और सार्वजनिक-सामाजिक शुचिता की पैरोकारी की गई। इस कसौटी पर आरोपी यूट्यूबर के आचरण निकृष्टतम थे, इसमें तो कोई दोराय नहीं हो सकती।

रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथियों के खिलाफ जगह-जगह दर्ज मुकदमों ने अश्लील सामग्री के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

दरअसल, सोशल मीडिया के जरिये जल्दी से जल्दी लोकप्रिय होने और धन कमाने की लिप्सा ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है, जो सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल गाफिल है। उसे लगता है, उसकी आजादी असीम है। ऐसे में, बहुत जरूरी हो गया है कि सोशल मीडिया के कंटेंट की निगरानी के तंत्र को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए। जिस तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए ऐसी अश्लील सामग्रियों की रोकथाम और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे परिवार मूल्य को नुकसान पहुंच सकता है। मगर यह काम आसान नहीं है, क्योंकि अश्लील सामग्रियों के प्रकाशन-प्रसारण पर रोक लगाते हुए तंत्र को अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति भी संवेदनशील रहना होगा, क्योंकि यह हमारी सांविधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्त है। फिर तंत्र को उन लोगों से भी उसी सख्ती से निपटना चाहिए, जो रणवीरों को जान से मारने की धमकी देते हैं या उनके परिजनों की निजता का उल्लंघन करते हैं। यह प्रकरण उन युवाओं के लिए सबक होना चाहिए, जो सोशल मीडिया में करियर तलाश रहे हैं। उन्हें समझना होगा, अश्लील कंटेंट की सनसनी उन्हें क्षणिक सफलता तो दिला देगी, मगर अंततः वे कानून के कठघरे में खड़े होंगे और उनके कलंक को उनका पूरा परिवार ढो रहा होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 19 फरवरी, 1950

प्रधान न्यायाधीश की नसीहत

लखनऊ, १८ फरवरी। सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश श्री हरिलाल कानिया ने आज यहां कहा कि एक ओर जहां एक भाषा का उद्देश्य संगठित भारत का निर्माण करना है, वहीं भाषाई प्रान्तों का निर्माण उस ऐक्य को विश्रृंखलित करना है। श्री कानिया अखिल भारतीय दंडनीति सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि गरीबी और अज्ञान दूर कर दिया जाए तो निश्चय ही अपराधों में कमी हो जाए। उन्होंने अपील की कि अपराध, अपराधी, दंड और दंडित व्यक्तियों के प्रति अधिक दयापूर्ण दृष्टिकोण रखा जाए।

श्री कानिया के भाषण का सार यह था कि साधारण मनुष्य मूलतः ईमानदार होता है। परिस्थितियां उसे अपराधी बनाती हैं और यदि ये परिस्थितियां दूर कर दी जाएं तो अपराधों की संख्या में कमी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी के साथ जेल में ठीक ढंग से बर्ताव हो और जेल से छूटने के बाद समाज को चाहिए कि वह उसे जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता दे न कि उससे कतराए।

आरम्भ में श्री कानिया ने कहा कि यदि भारत को एक इकाई होना है, तो यह आवश्यक है कि उसकी जनता की भाषा भी एक ही हो। यह बात एक साथ नहीं हो सकती। परन्तु भाषा को आधार मानकर यह कहना कि प्रान्त की पृथक इकाई होनी चाहिए- समस्त भारत की एक भाषा के उद्देश्य का सीधा विरोध करना है। छोटे-छोटे प्रान्त बनाना निश्चित रूप से शासन व्यवस्था के मान को गिराने वाला है और अनिवार्य रूप से उसमें कार्य-क्षमता का अभाव होगा। दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक छोटी इकाई के लिए अलग गवर्नर, मंत्री, ऊंचे से ऊंचे दर्जे के कर्मचारी, अदालती व धारा सभाई अधिकारियों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा :- अपराधी भावना को जन्म देने वाली दो मुख्य बातें हैं- गरीबी और शिक्षा का अभाव। यदि कोई जुर्म रोकने और बुराई ठीक करने के साधन का पता लगा ले, तो अवश्य ही और बहुत सा सिरदर्द न करना पड़े। भारत में जासूसी और जांच के काम में बहुत उन्नति की आवश्यकता है और पश्चिमी देशों की तुलना में इनमें हमारी प्रगति बहुत धीमी है। जिस ढंग से सूचना प्राप्त की जाती है और पुलिस जांच करती है- उसमें अभी बहुत उन्नति की जा सकती है।

चुनाव आयुक्तों के चयन से जुड़ी चिंताएं

यहां स्कैन करें

राज कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव आयोग में अनुकूल नौकरशाहों की नियुक्ति से किसी सत्तारूढ़ दल ने कभी संकोच नहीं किया, पर जब वह विपक्ष में आता है, तो उसे आयोग की निष्पक्षता की चिंता सताने लगती है।

नव नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पदभार संभालने से पहले ही सवालों में घिर गए हैं। नियुक्ति-प्रक्रिया से जुड़े ये सवाल उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को संदेहास्पद बनाने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति नए कानून के मुताबिक 17 फरवरी को हुई। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी भी नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बड़ा सवाल तो विपक्ष यही उठा रहा है कि जब नियुक्ति से जुड़े नए कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में 19 फरवरी को सुनवाई है, तब इस नियुक्ति की जल्दबाजी क्यों? 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नामित कैबिनेट मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी तर्क के साथ अपनी असहमति की टिप्पणी देकर निकल भी गए थे। फिर भी, ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई।

एक संयोग यह भी है कि चुनाव आयुक्त के रूप में भी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति 14 मार्च, 2024 को अचानक कर दी गई थी। निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त रहे अनूप चंद्र पांडेय 14 फरवरी को रिटायर हो चुके थे, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 9 मार्च को दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। तब सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अकेले राजीव कुमार लोकसभा चुनाव करा सकेंगे?

याद नहीं पड़ता कि टीएन शेषन के बाद किसी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल निर्विवाद गुजरा हो। एक अनुशासित नौकरशाह की छवि वाले शेषन अपनी सख्ती से तमाम राजनीतिक दलों के लिए आतंक-सा बन गए थे। बेशक, देश भर में शेषन की साख और जनता के बीच भी सम्मान, उसके बाद चुनाव आयोग के लिए बेहद कठिन कसौटी बन गए हैं। यह स्वाभाविक तो है, पर सवाल भी पैदा करता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता पर सवाल और संदेह हमेशा विपक्ष की ओर से ही उठते हैं, जबकि सत्ता पक्ष को वह आदर्श संस्था नजर आता है। आज कांग्रेस चुनाव आयोग की साख को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित नजर आती है, लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही चुनाव आयोग को एक से तीन सदस्यीय बना दिया गया था, ताकि अंकुश और संतुलन की गुंजाइश बनी रहे।

दरअसल, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या को लेकर संविधान मौन है। संविधान का अनुच्छेद 324 (2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करेगी। इसलिए, आजादी के बाद देश में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहे। नौवीं लोकसभा के चुनाव से पहले 16 अक्तूबर, 1989 को राजीव गांधी सरकार ने दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए, जिससे आयोग बहु-सदस्यीय संस्था बन गया। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरीशास्त्री पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा किया गया।

सांविधानिक संस्था चुनाव आयोग से सत्ता का खिलवाड़ आगे भी जारी रहा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था फिर बदली। 2 जनवरी, 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने चुनाव आयोग को फिर एक सदस्यीय बना दिया। फिर जब 1991 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता में वापसी हुई, तो 1 अक्तूबर, 1993 को मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त नियुक्त कर चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया गया। शायद बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग बाद की सरकारों को भी उचित लगा, इसलिए यह व्यवस्था जारी है।

ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुनवाई के अलावा, सरकार से उनकी निकटता के चलते भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू पर भी उत्तराखंड कैडर के चलते सवाल उठाए जाते रहे हैं, तो अब नियुक्त दूसरे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को भी सरकार का विश्वस्त माना जाता है। वैसे, एक दिलचस्प आकलन यह भी है कि साल 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के समय विवेक जोशी मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार 27 जनवरी, 2029 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

ठीक इसी तरह की गणना को लेकर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने तब उठाए थे, जब 2005 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। चावला के मुख्य चुनाव आयुक्त काल में ही साल 2009 के आम चुनाव हुए। उन पर, खासकर पत्नी रुपिका की कांग्रेस से निकटता को लेकर सवाल उठाए गए थे। और अतीत में झांकें, तो शेषन की सेवानिवृत्ति के बाद 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल को कांग्रेस ने न सिर्फ राज्यसभा सदस्य, बल्कि मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी बनाया। जाहिर है, चुनाव आयोग सरीखी सांविधानिक संस्था में अपने अनुकूल व्यक्तियों की नियुक्ति में संकोच किसी भी सत्तारूढ़ दल ने कभी नहीं किया, पर जब वही दल विपक्ष की भूमिका में आता है, तो उसे आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की चिंता सताने लगती है।

इस सांविधानिक संस्था में नियुक्ति की बाबत सात दशक तक किसी कानून का न होना भी सवाल खड़े करता है। कानून न होने के चलते सत्तारूढ़ दल पसंदीदा नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते रहे, जिनका आचरण अक्सर सवालों व संदेह के दायरे में रहा, इसीलिए यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2 मार्च, 2023 को दिए फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश का पैनल करेगा, जब तक कि इस बाबत संसद कोई कानून नहीं बना लेती। संसद ने वह काम 21 दिसंबर, 2023 को कर दिया। संसद द्वारा बनाए गए कानून में नियुक्ति पैनल से प्रधान न्यायाधीश को बाहर करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। विपक्ष समेत कुछ संगठनों की मुख्य आपत्ति यही है कि पैनल में सत्ता पक्ष के बहुमत से फिर नियुक्ति-प्रक्रिया संदेहास्पद हो गई है।

बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम में सबके अपने-अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन साझा चिंता चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की होनी चाहिए, जिसके बिना चुनाव-प्रक्रिया पर सवाल और संदेह से नहीं बचा जा सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बदल जाएगा कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का कायदा

यहां स्कैन करें

सुखदेव थोरात | पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने तेजी से नए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। उसने नियमों को जल्दी लागू करने के लिए एक अभिनव तरीका खोजा है- जटिल मुद्दों पर भी ऑनलाइन फीडबैक मंगाना। तेजी से बनाए गए नियमों की श्रृंखला में नवीनतम है- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता व पात्रता शर्तों का मसौदा। राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रावधानों को दूरगामी परिणाम वाला माना जाता है, जिसमें कुलपति की नियुक्ति भी शामिल है। हालांकि, एक विवादास्पद मुद्दा 15 साल से चल रही स्कोर-आधारित शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक प्रणाली (एपीआई) को खत्म करने का कदम है। एपीआई को खत्म करने का कदम शिक्षकों के मूल्यांकन, पदोन्नति और सीधी भर्ती प्रक्रियाओं को व्यक्तिपरकता की ओर ले जाता है।

अभी लागू एपीआई प्रणाली का क्या अर्थ है? एपीआई प्रणाली गुणवत्ता मूल्यांकन समिति के लिए आवश्यक योग्यता, शिक्षण अनुभव, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक योगदान को निर्धारित करती है। इसकी परिकल्पना 2010 में यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान की गई थी। हालांकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि संकाय के लिए इसका उपयोग काफी पहले शुरू कर दिया था। इसे क्यों शुरू किया गया था?

सचेत रहना होगा, हम वस्तुनिष्ठ नियुक्ति, पदोन्नति के बजाय विवेकाधीन नियुक्ति, पदोन्नति की ओर बढ़ रहे हैं।

दरअसल, यूजीसी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान ही विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों के लिए वेतनमान तय करने का प्रयास किया था। काफी मान-मनौव्वल के बाद मंत्रालय इस शर्त पर राजी हुआ कि आईएएस अधिकारियों की तरह शिक्षकों का भी नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यूजीसी ने इस पर सहमति जताई और एपीआई प्रणाली विकसित की गई। इस प्रणाली के तहत, सहायक प्रोफेसर के वेतनमान में बढ़ोतरी और एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए संकाय सदस्य को शिक्षण, शोध व अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर न्यूनतम एपीआई स्कोर हासिल करना जरूरी था। साक्षात्कार में केवल डोमेन ज्ञान का आकलन किया जाएगा। दूसरा कारण यह था कि अकादमिक प्रदर्शन को मापने से व्यक्तिपरकता खत्म होगी और वस्तुनिष्ठता व पारदर्शिता आएगी। इससे पक्षपात, भेदभाव, भाई-भतीजावाद, पूर्वाग्रह और यहां तक कि भ्रष्टाचार की आशंका कम या खत्म हो जाएगी। इसने शिक्षण समुदाय को अनुसंधान, शिक्षण में सुधार, ओरिएंटेशन कोर्स सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से पदोन्नति के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अब नई व्यवस्था में वस्तुनिष्ठ नियुक्ति, पदोन्नति के बजाय विवेकाधीन पदोन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पदोन्नति संबंधी फैसलों को पूरी तरह से चयन समिति के हवाले कर दिया जाएगा। इतिहास देखें, तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने व उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विवेक का शायद ही कभी सही उपयोग किया गया है। ऐसे में, वैचारिक मतभेद की स्थिति में पक्षपात और भेदभाव की आशंका रहेगी। यूजीसी ने चयन समिति को शक्तिशाली बना दिया है।

नई प्रणाली या ताजा नियमन ने नौ नई योग्यताएं पेश की हैं। ये हैं- अभिनव शिक्षण योगदान, अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला विकास, परामर्श/प्रायोजित अनुसंधान निधि, भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणालियों में शिक्षण और अनुसंधान, छात्र इंटर्नशिप/परियोजना पर्यवेक्षण, डिजिटल सामग्री निर्माण, सामुदायिक जुड़ाव व सेवा और स्टार्टअप। इन योग्यताओं को अच्छी तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। ध्यान रहे, शिक्षण या अनुसंधान पर सीमित प्रभाव वाली ये योग्यताएं संभावित रूप से शिक्षण व अनुसंधान के मौलिक कर्तव्यों से हमारा ध्यान भटका सकती हैं।

अब चयन समिति सर्वव्यापी है। यह तय करना चयन समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि शोध प्रकाशन यथोचित पत्रिका में हुआ है या नहीं। जाहिर है, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पदोन्नति के समय अब ज्यादा सचेत रहना होगा, ताकि एपीआई स्कोर के अभाव में पूर्वाग्रह और भेदभाव की गुंजाइश न बढ़ जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

वेद ने जो कहा वही धर्म

संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं, उसमें संशोधन हुए हैं, और होने भी चाहिए। न्यूटन के अनुसंधान में संशोधन हो रहा है, आइंस्टीन की खोज में संशोधन हो रहा है। जो टेप रिकॉर्डर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, वह छोटा हो गया; जो मोबाइल बहुत भारी होता था, आज छोटा और हल्का हो गया। पहले इंजन बड़ा होता था, अब छोटा होने लगा है। धीरे-धीरे मानव बुद्धि का विकास होता गया, तो तकनीकी विकास भी हुआ। अच्छे संविधान का प्रतिपादन यह धर्म है। यह राष्ट्र-धर्म है कि हम भारतीय संविधान का पालन करें। कौन कहता है कि बायीं तरफ से नहीं चलना चाहिए, दायीं तरफ से चलना चाहिए? एक चले बाएं से दूसरा चले दाएं से, दोनों ही चलें। यही नियम है।

जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वह पूरी दुनिया के लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक विकास के लिए बनाया था। जब कोई नियम नहीं था, तब वेद ने बताया। वेद जो करने के लिए कहता है, वह धर्म है; वेद जो कहता है नहीं करो, वह अधर्म है। वेद कहता है *सत्यम् वद्।* जब कोई संविधान नहीं था, तब दुनिया का एक ही संविधान था, वेद, जिसने कहा- *सत्यम् वद्।* आज भी यही कहा जाता है, माना जाता है। अमेरिका के लोगों में हर तरह की आजादी है, लेकिन जब अमेरिका का एक राष्ट्रपति झूठ में पकड़ा गया, तो पूरे देश ने कहा कि इस राष्ट्रपति को बाहर करो, झूठा आदमी हमारा राष्ट्रपति नहीं होगा। *सत्यम् वद्।* व्यभिचार की भावना सभी के जीवन में होती है। हमारे यहां ब्रह्मचर्य के तमाम भेद बताए गए। अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को बुरी नीयत से देखता, तो यह व्यभिचार है। यदि बुरी नीयत से स्पर्श करता है, मधुर बातें करता है, तो यह भी व्यभिचार है। सबको कहा गया है कि व्यभिचार से बचो। निश्चित रूप से हमारे देश की तुलना में अमेरिका में वर्जनाएं कम हैं, हमारे यहां से वहां खुलापन ज्यादा है। जब लेविंस्की कांड हुआ, तब लोगों ने कहा बिल क्लिंटन नहीं चाहिए। एक छोटी-सी कर्मचारी राष्ट्रपति की चहेती हो जाए, तो राष्ट्र चहेता नहीं हुआ उसका। बड़ा आदमी, जिसका उद्देश्य बड़ा है, जिसे पूरा देश अपनी उंगली पकड़ा चुका है, यदि वह आदमी किसी सामान्य कर्मचारी को अपनी उंगली पकड़ा दे, तो वह अक्षम हो जाएगा। व्यभिचार कतई नहीं चलेगा। उन्मुक्तता के पक्षधर अमेरिका में भी हल्ला मच गया, बहुत मुश्किल से क्लिंटन की गद्दी बची।

वेद जो करने के लिए कहता है, वह धर्म है; वेद जो कहता है नहीं करो, वह अधर्म है। जब कोई संविधान नहीं था, तब दुनिया का एक ही संविधान था, वेद, जिसने कहा- *सत्यम् वद्।*

धर्म का सीधा सा स्वरूप है- जो हमारे जीवन का विकास करे, जिससे दूसरे को कोई कष्ट न हो, दूसरे की कोई हानि नहीं हो, दूसरे को कोई पीड़ा न हो, यह जो विकास की पद्धति है, यह जो कर्म का स्वरूप है, वही वास्तव में धर्म है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह प्रसन्नता की बात है कि देश में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के जरिये लगभग सवा लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है।

प्रबंधन के मामले में फिसड्डी रही व्यवस्था

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद कई ऐसे सवाल हैं, जो किसी भी संवेदनशील इंसान को मथ सकते हैं। पहला तो यह कि नई दिल्ली देश की राजधानी का सबसे बड़ा व उन्नत रेलवे स्टेशन है, किसी दूरस्थ क्षेत्र या छोटे कस्बे का स्टेशन नहीं। यहां हर प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्टेशन में घुसने से पहले यात्रियों की पर्याप्त जांच होती है। पहाड़गंज और अजमेरी गेट, दोनों ही तरफ से अंदर आने और बाहर जाने के तय रास्ते हैं। फिर भी क्या रेलवे प्रशासन को पता नहीं चला कि कितने यात्री स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं और क्या स्टेशन इतने लोगों का प्रबंधन करने में सक्षम है? अगर अनुमान से ज्यादा लोग आ रहे थे, तो उन्हें प्लेटफॉर्म से या स्टेशन में प्रवेश करने से पहले बैरिकेडिंग करके क्यों नहीं रोका गया? अगर यात्रियों के नाराज होने या किसी और बात का डर था, तब भी अर्द्धसैन्य बल की मदद से ऐसा किया जाना चाहिए था, क्योंकि लोग इससे बेशक नाराज होते, लेकिन उनकी जान तो बच जाती।

अगर रेलवे को महाकुम्भ के बहाने कमाई ही करनी थी और अधिक से अधिक टिकट बेचना था, तब भी उसका यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब तो जितनी कमाई नहीं की, उससे अधिक उसे मुआवजा देना पड़ेगा। प्रश्न यह भी है कि सारी स्पेशल ट्रेनें एक ही स्टेशन और खास प्लेटफॉर्म से क्यों चलाई जा रही हैं? दिल्ली में और भी कई स्टेशन हैं। नई दिल्ली में ही कई प्लेटफॉर्म हैं। खबर यह भी है कि प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल को लेकर भी भ्रम पैदा हुआ। क्या रेलवे स्पेशल ट्रेनों को कुछ और नाम नहीं दे सकता था? वैसे भी, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई स्पेशल ट्रेन अचानक कैसे आ सकती है? उसकी तैयारी तो रेलवे ने पहले से कर रखी होगी। बहरहाल, इस घटना के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े अधिकारी मुस्तैद हैं, लेकिन उस दिन अगर इसकी आधी भी व्यवस्था की गई होती, तो शायद भगदड़ नहीं मचती।

देखा जाए, तो महाकुम्भ ही नहीं, हर भीड़ में रेलवे की व्यवस्था चौपट हो जाती है। बिहार की ओर जाने वाली ट्रेन तो हमेशा ही भरी होती है, जिससे यह बात जरूर मन में उठती है कि जब रेलवे राजस्थान और लखनऊ के लिए डबल डेकर ट्रेन चला सकता है, तो बिहार के लिए क्यों नहीं? जाहिर है, कहीं-न-कहीं व्यवस्था में ही दोष है। इन प्रश्नों पर रेल प्रशासन और जिम्मेदार लोगों को विचार करना चाहिए और जो कोई भगदड़ की घटना का दोषी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

आशा सिंह बैस, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

दिल्ली भगदड़

बिना सोचे-समझे भीड़ बढ़ाने का नतीजा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ और मौतों को लेकर रेलवे की जितनी भी निंदा की जाए, कम है। मगर इसमें दोष सिर्फ व्यवस्था का नहीं है। जगह-जगह यदि भगदड़ मच रही है और लोगों की जान जा रही है, तो इसमें हम लोग भी कुछ कम कुसूरवार नहीं हैं। इसको इस तरह समझिए। भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें कुम्भ स्नान करने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि हर तीन में से एक भारतीय कुम्भ स्नान करने गया है। अब कोई सामान्य ज्ञान रखने वाला भी यह बता सकता है कि लगभग 30 दिन में यदि 50 करोड़ लोग एक शहर की तरफ जाने लगें, तो सब कुछ व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता है। प्रशासन किसी का भी हो, इतनी बड़ी संख्या होगी, तो जगह-जगह व्यवस्था फेल होगी ही। साफ है, हम सब भी कम दोषी नहीं हैं, जो बिना सोचे-समझे भीड़ में तब्दील हो रहे हैं।

शांतिभूषण राव, टिप्पणीकार

सोच बदलें लोग

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ बेहद हृदय विदारक घटना है। इससे पहले भी महाकुम्भ में भगदड़ की घटना हो चुकी है। महाकुम्भ जाने की होड़ में लोग बेतहाशा प्रयागराज भागे जा रहे हैं, बिना यह सोचे-समझे कि इतनी भीड़ में महिलाओं और बच्चों के साथ जाना कितना उचित है? यह कैसी आस्था है, जिसमें लोग अपनी एवं अपने परिजनों की जान तक दांव पर लगा रहे हैं? माना कि महाकुम्भ विरले को ही नसीब होता है और आम धारणा के मुताबिक, इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यह कैसा पुण्य-कर्म है, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं? आजकल कितने लोग हैं, जो महाकुम्भ के लिए जितनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, उतनी अगर अपने वृद्ध माता-पिता के लिए दिखाते, तो हमारा समाज और अधिक खूबसूरत होता। अगर बुजुर्ग माता-पिता की सेवा हो रही है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने कोई बड़ा पुण्य-कर्म किया है। श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए, जिसमें हम अपने परिवार का कोई नुकसान नहीं होने दें, बल्कि उनका अधिकाधिक संबल बनें। मगर महाकुम्भ के नाम पर तो जैसे होड़ मची हुई है। देखा जाए, तो कोई धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम बेतहाशा भीड़ में अपनों को ही गंवा दें। ऐसा पुण्य भला किस काम का, जिसमें किसी इंसान को अपनी जान देनी पड़े? इसलिए महाकुम्भ को लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

एक कुशल कूटनीतिज्ञ वह होता है, जो कुछ न कहने से पहले भी दो बार सोचता है। -एडवर्ड हीथ

भुवनेश्वर के एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान की छात्रा प्रकृति लामसाल की आत्महत्या वाकई क्षुब्ध करने वाली है। सच तो सामने आ ही जाएगा, पर ऐसे मामलों में शिक्षण संस्थान भी कम दोषी नहीं, जो छात्रों की शिकायतों पर लापरवाही दिखाते ही हैं, कोई अनहोनी होने पर पर्दा डालने की भी भरसक कोशिश करते हैं।

प्रकृति के दोषी

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान में अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या, जैसा पुलिस बता रही है, जितनी क्षुब्ध करने वाली है, कॉलेज प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप भी उतने ही संगीन हैं। छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला उसका कथित प्रेमी हिरासत में है। अस्तु, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन जिस तरह आनन-फानन अन्य नेपाली छात्रों को हॉस्टल से निकालते हुए बसों में बैठाकर कटक रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया, जबकि 28 फरवरी को उन्हें परीक्षा देनी थी, उससे संस्थान के इरादों पर संदेह तो गहराता ही है। यह मान भी लिया जाए कि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था, तो वैसी सूरत में मामले के तूल पकड़ने पर संस्थान ने अपना फैसला वापस लेते हुए नेपाली छात्रों को दोबारा छात्रावास में रहने की अनुमति क्यों दे दी? ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी छात्र या छात्रा की मौत की घटना को लेकर सवाल उठे हों। अक्सर देखा गया है कि कॉलेज प्रशासन ऐसे मामलों में लीपापोती करने की कोशिश करता है, ताकि संस्थान की छवि खराब न हो। कोलकाता में पिछले वर्ष प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज ने भी यही रवैया दिखाया था, लेकिन क्या यह सही तरीका है? किसी भी संस्थान की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण छात्रों की सुरक्षा और उनका भरोसा होता है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामले में तो यह और भी महत्वपूर्ण है। होना तो यह चाहिए कि विदेशी छात्रों के लिए एक अलग से सहायता तंत्र हो, ताकि वे किसी भी कठिनाई में कॉलेज प्रशासन से उचित मदद पा सकें। लेकिन इस मामले में प्रथमदृष्टया जो स्थितियां दिख रही हैं, वे एकदम उलट हैं। सोशल मीडिया पर नेपाली छात्रों के साथ संस्थान के शिक्षकों की बहस के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अगर वे वास्तविक हैं, तो उनमें शिक्षकों का नेपाली छात्रों के प्रति रवैया

वाकई बेहद शर्मनाक दिख रहा है। यदि हम अपने शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्र, चाहे वह किसी भी देश से हो, सुरक्षित व सम्मानित महसूस करे। ऐसे में, जरूरी है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में शीघ्र व निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और छात्रों का भी भरोसा बना रहे। यह महज एक संस्थान का नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का भी सवाल है। नेपाली छात्रा की मौत सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यवस्था से पूछा गया एक सवाल भी है, जिसका सही जवाब 'न्याय' ही होगा।

ट्रंप, मोदी और चाणक्य नीति

मोदी व ट्रंप की मुलाकात में संकेत मिला कि 2025 में भारत एक आत्मविश्वासी वैश्विक नेता बनकर उभरेगा। यह कहकर कि उन्होंने ट्रंप से सीखा कि देश को सर्वोपरि रखना कितना अहम है, मोदी उसी चाणक्य नीति का पालन करते दिखे, जो कहती है कि प्रतिद्वंद्वी को आदर्श बताकर उसे निहत्था करना सर्वोत्तम कूटनीति है।

दीपक वोहरा
पूर्व राजनयिक

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में मिले। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे चौथे विदेशी नेता थे, जो दूसरी पारी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं। उनसे पहले अमेरिका के कट्टर सहयोगी इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के राजा ट्रंप से मिल चुके हैं, जो गाजा पट्टी से निकाले जाने वाले फलस्तीनियों को अपने यहां लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो इस बार की मुलाकात में क्या खास बात रही? इससे यह संकेत मिला है कि वर्ष 2025 में भारत एक आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर वैश्विक नेता के रूप में पहचाना जाएगा।

हालांकि, दो दिग्गज वैश्विक नेताओं की यह मुलाकात पूरी तरह से व्यापार को लेकर थी। व्यापार एक ऐसा विषय है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और उनके भारतीय गुजराती समकक्ष, दोनों पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फोकस के क्षेत्र होंगे-प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, लचीली आपूर्ति, ऊर्जा (विशेष रूप से छोटे परमाणु रिएक्टर)। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत अमेरिका से बहुत सारा तेल और गैस खरीदेगा, जिसकी भारत को जरूरत है और अमेरिका के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से सीखा है कि देश को सर्वोपरि रखना कितना महत्वपूर्ण है और वह भी यही कर रहे हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना और उसे आदर्श बताकर निहत्था करना चाणक्य की प्राचीन रणनीति है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को हल करने की पहल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, दोनों से समाधान खोजने का आग्रह किया। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा चीन था। हाल ही में बीजिंग ने अमेरिका, भारत तथा सामान्य रूप से विश्व को दी जाने वाली धमकियों में नरमी बरती है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ते हैं।

अपने शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने बांग्लादेश की हिंसा और शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद वहां अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की आलोचना की थी। ट्रंप अपने देश को वैश्विक संकटों से अलग रखना, न कि नए संकटों में उलझाना चाहते हैं। इसके अलावा, कमजोर बांग्लादेश अमेरिका से कोई भी सार्थक वस्तु नहीं खरीदता, इसलिए व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप को वास्तव में उसकी परवाह नहीं है। लगता तो यही है कि हिलेरी क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस के करीबी मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता से हटा देंगे। भारत और अमेरिका, दोनों इस्लामी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इसलिए संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि आतंकवाद के वैश्विक संकट से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरे देखे द्विपक्षीय संयुक्त बयानों में यह पहला ही है, जिसमें अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा (अंतिम दो पाकिस्तान में स्थित हैं) सहित आतंकी गुटों का विशेष उल्लेख किया गया है। 'हमारे नागरिकों' को नुकसान पहुंचाने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की साझा इच्छा के चलते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी और पूर्व पाकिस्तानी सेना कप्तान तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की घोषणा की। संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान से आग्रह किया गया कि वह 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमलों के दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाए तथा यह सुनिश्चित करे कि उसके भू-भाग का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न किया जाए।

भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते हुए। इस तरह अमेरिका ने भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण के साथ एक प्रमुख रक्षा साझेदार और एक प्रमुख क्वाड साझेदार के रूप में मान्यता दी। जाहिर है, नरेंद्र मोदी की यह यात्रा रक्षा सहयोग पर केंद्रित थी, जिसमें अमेरिका भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार कर अंतर-संचालन और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों में अमेरिकी और भारतीय सेनाओं की विदेशी तैनाती का समर्थन करते हैं और उसे बनाए रखेंगे। साफ है कि दोनों देश इस अहम क्षेत्र में अपने अड्डे साझा कर सकते हैं।

अरब सागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद के लिए संयुक्त समुद्री सेना नौसैनिक टास्क फोर्स में भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भारत को अमेरिका का खुला समर्थन स्पष्ट रूप से चीन के कारण है। इस यात्रा से अमेरिका-भारत ट्रस्ट की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत तेल एवं गैस (ऊर्जा) के लिए भूखा है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। भारत ने अमेरिका से अवैध भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया, और यात्रा से ठीक पहले 104 भारतीयों को वापस भेजने के तरीके पर भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को देखते हुए ट्रंप को अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया।

ट्रंप चाहते थे कि भारत विशिष्ट अमेरिकी उत्पादों पर अपने सीमा शुल्क (टैरिफ) को कम करे व भारत ऐसा कर रहा है। ट्रंप ने माना कि नरेंद्र मोदी उनसे भी बेहतर सौदेबाज हैं। इसके अलावा, अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं के आव्रजन व आसान वीजा प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के बारे में भी चर्चा हुई। यात्रा से कुछ दिन पहले, अमेरिकी विदेश विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया कि कैसे अमेरिकी डार्क स्टेट ने 2019 में नरेंद्र मोदी की लगातार चुनावी जीत से भयभीत भारतीयों को शामिल करके भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2025 को भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में याद किया जाएगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

परमहंस योगानंद

प्रशंसा आपको बेहतर नहीं बनाती, न ही निंदा बदतर बनाती है। फिर इन दोनों पर ध्यान क्यों दें? जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उससे मुग्ध होने के बजाय खुद का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें।

प्रशंसा और निंदा दोनों पर ध्यान दें

__रचनात्मक__ आध्यात्मिक चेतना मनुष्य की आत्मा में निवास करती है। ईश्वर द्वारा दी गई इस शक्ति का उपयोग करेंगे, तो आप खुद के भाग्य के स्वामी बन जाएंगे। हम इस चेतना का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से ही खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। इस विषय पर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि 'विचार ही वस्तु है।' हम अक्सर एक कहावत कहते हैं कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में विचार करता है, वैसा ही वह होता है। इस बात ने हजारों लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है और उन्हें पहले से बदल दिया है। इस चेतना को विकसित करें कि आप ब्रह्मांड के सम्राट की संतान हैं और अपने पिता के सबसे प्रिय। अपने पिता के प्रिय होने के नाते आपको अधिकार है कि इस चेतना को आप अपने अनुसार इस्तेमाल करें। कभी भी किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगें, बल्कि यह विचार रखें कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। ईश्वर की संतान के रूप में आपको आत्मविश्वास हासिल करना है। हमें उस बच्चे की तरह रहना चाहिए, जो अपने माता-पिता के समक्ष सुरक्षित होकर सुखपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ सभी भय को त्याग देता है। इसके विपरीत, जो इन्सान अपने भीतर छिपे हुए बालसुलभ गुणों को विकसित नहीं कर पाता, वह आत्मग्लानि से लगातार पीड़ित रहता है। इस तरह शर्म, चिंता, भय और आसक्ति, उसकी शांति को दुख के सागर में डुबो देती है और असफलताएं बार-बार घेरती हैं। इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर मौजूद रचनात्मक आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। असफलता के बाद हर नए प्रयास को अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए और ध्यान के माध्यम से खुद को ऊर्जावान बनाना चाहिए। अगर कोई बुरी आदत आपको परेशान करती है, तो दो काम करें, इसके नकारात्मक रूप से बचने की कोशिश करें और हर उस चीज से बचें जिससे यह उत्पन्न हुई है, बिना उस पर ध्यान केंद्रित किए। वहीं, सकारात्मक रूप से अपने दिमाग को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें और इसे तब तक पूरी तरह से विकसित करने में व्यस्त रखें, जब तक कि यह आपका एक हिस्सा न बन जाए। जितना अधिक आप स्वयं में सुधार करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने आसपास के अन्य लोगों को भी बुलंद करेंगे। चूंकि, प्रशंसा आपको बेहतर नहीं बनाती, न ही निंदा आपको बदतर बनाती है। फिर इन दोनों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उससे मुग्ध होने के बजाय खुद का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। दूसरी ओर, जब लोग निंदा करें, तो उसका बुरा न मानें। यह विचार करें कि हमारे अंदर ऐसी कौन-सी बात है, जिसको हम सुधार सकते हैं।

गलती स्वीकार करना सीखें

सूत्र

अगर आपकी गलती के लिए कोई भी आपको दोषी ठहराता है और आप वाकई दोषी हैं, तो तुरंत खुद की गलती को स्वीकार कर लें और उसमें सुधार करें। लेकिन अगर आप दोषी नहीं हैं, तो हंसें और उसे भूल जाएं। साथ ही बुरी आदतों को अपने विचारों की धारा में बहने न दें। एक समय बाद सत्य खुद आपके लिए बोलेगा।

दूसरा पहलू

हवाई हादसे टालने के लिए लगभग सभी यात्री विमान टीसीएएस तकनीक से युक्त होते हैं, फिर भी चूक हो रही है।

अत्याधुनिक विमान क्यों हो रहे क्रैश

बीते माह अमेरिका में यात्री विमान और सेना के हेलिकॉप्टर के टकराने से 60 लोगों की मौत हो गई थी, तो इससे पहले दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान में सवार 181 लोगों में से दो को छोड़कर सभी की मौत हो गई। हाल ही में कनाडा के टोरंटो में हुए विमान हादसे में 18 लोग घायल हो गए। अमेरिका के पास विमान हादसे रोकने के लिए सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, जिसे इस तरह से विकसित किया गया है कि वह पायलटों को हवा में विमान के टकराने की आशंका होने पर सूचित कर देती है। इस तकनीक को ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (टीसीएएस) कहते हैं। टीसीएएस ट्रांसपोंडर से युक्त अन्य विमानों के लिए विमान के आसपास के हवाई क्षेत्र की निगरानी करती है। इसके उपकरण आने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं।

क्रिस्टल झांग

यह तकनीक पायलटों को संभावित टकराव के प्रति सचेत करती है, ताकि पायलट विमान को ऊपर या नीचे कर या दिशा मोड़कर हादसे को टाल सकें।

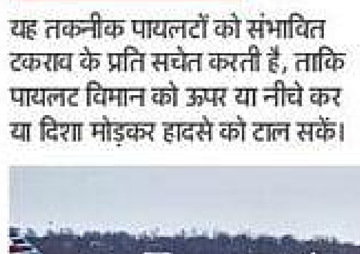

टीसीएएस तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं। लगभग 300 मीटर ऊंचाई से नीचे विमान के उड़ने पर टीसीएएस ठीक से काम नहीं करती। हादसे के वक्त यात्री विमान 90 व सैन्य विमान 60 मीटर की ऊंचाई पर थे।

बाहरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से स्वतंत्र रूप से संचालित इस प्रणाली को कभी-कभी एयरबोर्न कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (एसीएएस) भी कहा जाता है, जो पायलटों को पास के विमानों और संभावित टकराव के प्रति तुरंत सचेत करती है, ताकि पायलट विमान को ऊपर या नीचे कर या फिर उसकी दिशा मोड़कर हादसे को टाल सकें। ये नई प्रणालियां एक-दूसरे से संवाद करने में भी सक्षम हैं। वर्ष 1974 में विकसित हुई यह तकनीक धीरे-धीरे उन्नत होती गई। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी विमान को शिकागो कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, टीसीएएस से सुसज्जित होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सैन्य हेलिकॉप्टर इस नियम के तहत नहीं आते। इसलिए रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टकराए सैन्य हेलिकॉप्टर में टीसीएएस प्रणाली नहीं थी।

टीसीएएस तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं। लगभग 300 मीटर ऊंचाई से नीचे विमान के उड़ने पर टीसीएएस ठीक से काम नहीं करती। बताया जाता है कि जब हादसा हुआ, तब अमेरिकी एयरलाइंस के विमान की अंतिम ऊंचाई करीब 90 मीटर और सैन्य हेलिकॉप्टर की ऊंचाई 60 मीटर के आसपास थी। इतनी कम ऊंचाई पर विमानों के आमने-सामने होने की स्थिति में उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल होता है। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट अमेरिका का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। फिलहाल जांच की जा रही है कि हादसा तकनीकी खामी की वजह से हुआ या किसी अन्य चूक की वजह से।

-द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

पर्यटकों की पसंद

वर्ष 2024 में पर्यटकों ने विभिन्न देशों की यात्रा की, लेकिन उनकी पहली पसंद फ्रांस के पर्यटन स्थल रहे।

फ्रांस	8.94
स्पेन	8.37
अमेरिका	7.93
चीन	6.57
इटली	6.45

आंकड़े करोड़ में, भारत में बीते वर्ष 1.79 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे | स्रोत : UNT

एक व्यक्ति ने दयालदास स्वामी से कहा कि स्वामी कभी दास नहीं होते। उन्होंने कहा, हर कोई अपने शिष्यों का स्वामी और गुरु का दास होता है।

सदाचार ही साधु का जीवन है

दयालदास स्वामी का जन्म पंजाब के कपियाल गांव में हुआ था। उनके पिता साधु-संतों की सेवा करते थे, जिसके कारण दयालदास को बाल्यकाल में ही साधु-संगति प्राप्त हुई। बारह वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया व पटियाला के बेसरा गांव में परमहंस बाबा ठाकुरदास से दीक्षा ग्रहण की।

इसके बाद उन्होंने पंद्रह वर्ष तक गुप्त साधना की। गुरुदेव के समाधि लेने पर दयालदास ने बहुत बड़ा भंडारा किया। अब उनकी सिद्धि सब ओर फैल गई। इसलिए वह उस स्थान को छोड़कर तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। दयालदास स्वामी जी स्वतंत्र आसन या गद्दी पर नहीं बैठते थे। वह कुशासन या बालू का आसन ही पसंद करते थे। राजा से लेकर साधारण पुरुष तक उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन अपने ज्ञान के अभिमान में चूर व्यक्ति ने दयालदास स्वामी के पास जाकर पूछा, 'आप कौन स्वामी हैं?' दयालदास स्वामी जी बोले, 'मैं केवल स्वामी ही नहीं हूं, बल्कि दासस्वामी भी हूं।' उन्होंने कहा, 'संन्यासी तो कभी दास नहीं होते, स्वामी होते हैं।' इस पर दयालदास स्वामी बोले- 'भैया! अपने शिष्यों के सामने सभी स्वामी होते हैं और गुरुओं के सामने सभी दास होते हैं।' दयालदास स्वामी के इस विचारपूर्ण वार्तालाप से उसका का भ्रम दूर हो गया और वह उनके शरणागत हो गए। दयालदास स्वामी दैवी संपत्ति पर बड़ा जोर देते थे। उनका कहना था कि सदाचार ही साधु का जीवन है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 27 अगस्त, 1965

स्वरक्षा के लिए हमला करना भी जरूरी: डॉ. राधाकृष्णन

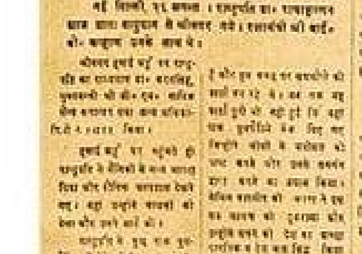
रक्षा के लिए हमला करना भी जरूरी: डा. राधाकृष्णन

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने कहा कि हम शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन कभी-कभी अपनी रक्षा के लिए हमला करना भी जरूरी है।

अब तदर्थ न्यायाधीशों पर दारोमदार

उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में अब तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिका बढ़ जाएगी।

सीवीपी श्रीवास्तव | **कानून**

न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर चर्चा में रहती है। कई बार विवादों में या फिर प्रक्रियाओं की व्यावहारिकता को लेकर। 30 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अनुमति दी है कि वे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति करें, ताकि लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके। तदर्थ न्यायाधीश एक प्रकार से अस्थायी न्यायाधीश होते हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती है, जबकि अस्थायी न्यायाधीश एक निश्चित समय-सीमा के लिए नियुक्त होते हैं।

उच्च न्यायालयों के लिए कई प्रकार के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के प्रावधान संविधान में हैं। कारण यह है कि उच्च न्यायालय की विषय वस्तु अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है और मामलों का बोझ भी उन पर अधिक है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति दो

वर्षों के लिए तब की जाएगी, जब उच्च न्यायालय पर कार्य का बोझ बढ़ गया हो, जबकि यदि कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, तो अस्थायी रूप से कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ये दोनों ही नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी।

चूंकि नियुक्ति करने की शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति है और राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कार्यपालिका का प्रधान भी है, अतः उसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 से अनुच्छेद 224-ए जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी जरूरत पड़ने पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। ध्यातव्य हो कि उच्चतम न्यायालय ने 2021 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिए गए दिशा-निर्देश में कहा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तब की जाएगी, जब रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20 फीसदी से अधिक हैं, या एक श्रेणी के मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं, या 10 फीसदी से अधिक लंबित मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं या निपटान दर नए केस दायर करने की दर से कम है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 2021 के अपने निर्णय में परिवर्तन करते हुए यह कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय दो से पांच तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो उसकी स्वीकृत क्षमता के 10 फीसदी से अधिक नहीं होंगे। ऐसे न्यायाधीश आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर सकेंगे, जिससे लंबित मामलों की संख्या घटेगी। उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जोर दिया कि प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। विचारणीय है कि उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। 2021 के फैसले से 80 फीसदी कार्य क्षमता की स्थिति ने कई उच्च न्यायालयों में तदर्थ नियुक्तियों को रोक दिया था। उल्लेखनीय है कि कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, न्यायालय ने 'निरंतर परमादेश' के माध्यम से लोक प्रहरी मामले में कार्यवाही को खुला रखा था। निरंतर परमादेश न्यायालय का वह आदेश है, जिसका उपयोग जांच की निगरानी करने, उचित जांच सुनिश्चित करने और कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

न्यायालय के ऐसे निर्णय के बाद कई प्रश्नों का उत्तर देना समीचीन होगा। पहला, क्या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से नियमित नियुक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? यहां विचारणीय है कि नियमित और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक-दूसरे से स्वतंत्र है। अतः ऐसी कोई आशंका नहीं है। दूसरा, यह प्रश्न कि क्या इससे कार्यरत न्यायाधीशों की वरिष्ठता प्रभावित होगी, भी प्रासंगिक प्रतीत नहीं होती। कारण यह कि तदर्थ न्यायाधीश एक विशेष उद्देश्य (आपराधिक अपील की सुनवाई) और एक निश्चित समय-सीमा (लगभग दो से तीन वर्ष) के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे। अतः वरिष्ठता के प्रभावित होने की भी कोई आशंका नहीं है।

न्यायालय के इस निर्णय से कई प्रकार के लाभ मिलने की संभावना है। पहला, यह कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी होगी। दूसरा, जेलों में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारण जेल प्रबंधन पर होने वाले व्यय में कमी। तीसरा, कई अत्यधिक क्षमतावान सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की क्षमता के दोबारा उपयोग में लाए जाने से न्याय तंत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि की भी संभावना है। कुल मिलाकर, यह कहना उपयुक्त होगा कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय न्याय प्रणाली को अधिक व्यवहार्य बनाने और प्रति व्यक्ति न्याय उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

-लेखक सेंटर फॉर अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली के अध्यक्ष हैं।

कल्पमेधा

समाज के दिए हुए पक्षपात और संस्कारों की दासता को जो नहीं तोड़ सकता है, वह सत्य को और स्वयं को जानने का अधिकारी ही नहीं है।

– ओशो

पारदर्शिता का प्रश्न

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन को लेकर जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार वही हुआ। विपक्ष मांग करता रहा कि इस पद पर नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई तक बैठक को टाल दिया जाना चाहिए। मगर सरकार ने उस मांग को अस्वीकार करते हुए राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले ही बैठक बुला ली और नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उसका बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदोन्नत किया गया है। मगर विपक्ष इसे उचित नहीं मान रहा। दरअसल, पिछले कुछ समय से जिस तरह निर्वाचन आयोग के कामकाज और उसकी कर्तव्यनिष्ठा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसमें नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की हड़बड़ी संदेह की गुंजाइश पैदा करती है। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता की अपेक्षा स्वाभाविक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्षता की मांग इसलिए उठती रही है कि इसी संस्था से लोकतंत्र की रक्षा का भरोसा बनता है। पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचन आयुक्तों के सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने, मतदाता सूची और मतदान मशीनों में गड़बड़ी कराने, मतदान संबंधी ब्योरों में तालमेल न होने आदि के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्ष व्यवस्था की गुहार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था।

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी सरकार पर अपनी पसंद के व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी सौंपने का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इस पद पर नियुक्ति करते थे। मगर जब निर्वाचन आयोग के कामकाज में पारदर्शिता धुंधली होने लगी, तो इस नियुक्ति प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई थी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यों वाली समिति इस पद पर नियुक्ति करेगी। मगर सरकार ने उस व्यवस्था को पलट कर कानून बना दिया कि तीन सदस्यों में एक सदस्य प्रधान न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री होगा। इसी पर स्थगन की याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। अगर सरकार सचमुच इस पद की निष्पक्षता को लेकर गंभीर होती, इस संस्था की स्वायत्तता को मूल्यवान समझती, तो शायद इतने विवादों के बावजूद इस पद पर नियुक्ति की ऐसी जल्दबाजी न दिखाती।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक संकल्प है। यह तभी संभव हो सकता है, जब निर्वाचन आयुक्त स्वायत्त और निष्पक्ष ढंग से काम कर सके। अगर उसका झुकाव किसी दल विशेष या सत्तपक्ष की तरफ होगा, तो इसका असर चुनाव नतीजों पर नजर आएगा। स्वायत्तता के साथ-साथ यह मांग भी लगातार उठती रही है कि निर्वाचन आयोग को एक नखदंत विहीन संस्था के बजाय अधिकार संपन्न संस्था बनाया जाना चाहिए, जो आचार संहिता के उल्लंघन आदि के मामले में कठोर कार्रवाई कर सके। मगर ऐसा कोई चुनाव नहीं गुजरता, जब निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप नहीं लगते। सबसे अधिक तो मतदान मशीनों को लेकर सवाल उठते हैं। मगर इस शंका के निवारण के लिए कोई भरोसेमंद तरीका नहीं निकाला गया। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में परस्पर सहमति की अपेक्षा स्वाभाविक है।

त्रासदी के बाद

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की त्रासद घटना के बाद अब कुछ सख्त नियम-कायदे लागू किए गए हैं, ताकि आगे वैसी स्थिति से बचा जा सके। सवाल है कि सरकार और संबंधित महकमों की नींद तभी क्यों खुलती है, जब कोई हादसा हो जाता और मामला तूल पकड़ लेता है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने के लिए सभी राज्यों से भारी संख्या में लोग रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं, तो यह कोई अचानक पैदा होने वाली स्थिति नहीं है। इस बात की संभावना बिल्कुल शुरू से थी कि नई दिल्ली स्टेशन से महाकुंभ के लिए जाने वाले लोगों की संख्या कभी भी बेलगाम हो जा सकती है। विडंबना है कि इसके मद्देनजर स्टेशन पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी, जिससे लगे कि सरकार किसी त्रासद घटना को न होने देने की इच्छाशक्ति के साथ काम कर रही है। इसका नतीजा इस रूप में सामने आया कि नई दिल्ली स्टेशन पर बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे और महाकुंभ में जाने के लिए गाड़ी पकड़ने की कोशिश में भगदड़ मच गई।

सच यह है कि कुछ पूर्व सुरक्षा इंतजाम और सख्त नियम-कायदे लागू करके जिस त्रासद घटना को होने से रोका जा सकता था, वहां सिर्फ व्यवस्थागत बदइंतजामी, शासकीय अदूरदर्शिता और लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली गई। समझना मुश्किल है कि सामान्य समझ के मुताबिक भी जो परिस्थिति संभावित थी और हादसे की आशंका लगातार बनी हुई थी, उसके बारे में उच्च स्तर के संबंधित अधिकारियों को अंदाजा क्यों नहीं हुआ। अब नई दिल्ली स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, प्लेटफार्म टिकट की बिक्री को नियंत्रित किया गया है, बिना वैध कारणों के रेल-पुल पर लोगों के खड़ा होने की मनाही की गई है, स्टेशन परिसर में अस्थायी तंबुओं में यात्रियों को रोका जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और आपात प्रतिक्रिया दल भी तैयार किए गए हैं। निश्चित तौर पर यह रेल महकमे से लेकर स्टेशन पर मौजूद उच्च स्तर के अधिकारियों की अदूरदर्शिता का सबूत है कि ये सुरक्षात्मक इंतजाम इतनी देर से किए गए। यही सब उपाय पहले किए जाते तो शायद अव्यवस्था न फैलती और उसके नतीजे त्रासद न होते।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की नई चुनौतियां

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नया ढांचा बनाने के लिए देश के बजट में प्रावधान किए गए हैं, उससे लगता है कि भारत में भी इसकी रफ्तार बढ़ेगी। वित्तमंत्री ने देश में एआइ की शिक्षा पर खास ध्यान देने की योजना के तहत 'एआइ सेंटर आफ एक्सीलेंस' का प्रस्ताव दिया है।

अभिषेक कुमार सिंह

प्रौद्योगिकी का एक अलिखित नियम यह है कि वह जिस जगह सबसे कम लागत और सर्वश्रेष्ठ दक्षता के साथ तैयार होती है, पूरी दुनिया अपनाने के लिए उसी तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे, एक दौर था जब दुनिया में आइटी प्रतिभाओं की बात होती थी, तो हर कोई भारतीय मेधा का सम्मान करता था। यह रुतबा आज तक कायम है। इसी का असर है कि अमेरिकी सत्ता पर दोबारा काबिज डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार में आप्रवासियों के योगदान में कटौती करने के इरादे से एच1-बी वीजा में तब्दीली के संकेत दिए, तो अमेरिकी कंपनियां ही विरोध करने लगीं। इसलिए कि आइटी तकनीक और इंजीनियरिंग के मामले में आज भी अमेरिका-यूरोप में भारतीयों की तूती बोलती है। एच1-बी वीजा पर पाबंदियां लगती हैं, तो अमेरिकी कंपनियां मेहनती भारतीय युवाओं से वंचित हो सकती हैं।

कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। नवंबर 2022 में जबसे अमेरिकी कंपनी 'ओपनएआइ' ने 'चैटजीपीटी' के नाम से नया 'टूल' विकसित किया, तो माना जाने लगा कि दुनिया के किसी और देश को इसका मुकाबला करने या इसकी बराबरी करने में ही कई दशक लग सकते हैं, लेकिन यह मिथक करीब सवा दो साल में ही टूट गया। एक चीनी कंपनी ने डीपसीक आर-1 बना कर न सिर्फ चैटजीपीटी के सामने नई चुनौती पेश कर दी, बल्कि लागत और इस्तेमाल की बेहद कीमत के आधार पर यह साबित कर दिया कि कोई जरूरी नहीं कि विज्ञान-तकनीक के सारे आविष्कार अब अमेरिकी या यूरोपीय जमीन पर हों। इसमें चीन और भारत जैसे देश भी नया करिश्मा कर सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नया ढांचा बनाने के लिए देश के बजट में प्रावधान किए गए हैं, उससे लगता है कि भारत में भी इसकी रफ्तार बढ़ेगी। वित्तमंत्री ने देश में एआइ की शिक्षा पर खास ध्यान देने की योजना के तहत 'एआइ सेंटर आफ एक्सीलेंस' का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए आबंटित 500 करोड़ रुपए, 2023-24 के बजट में आबंटित 255 करोड़ रुपए से करीब दोगुना है। यह कदम देश को एआइ शिक्षा में अग्रणी शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल माना जा सकता है। लेकिन चर्चा चीनी एआइ डीपसीक आर-1 की है। इसने चैटजीपीटी को इस मामले में पछाड़ दिया है कि यह उससे दहाई लागत में तैयार हुआ है और उपयोग के लिए तकरीबन मुफ्त उपलब्ध है।

चीन ने हाल के वर्षों में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार करने में जो तेजी दिखाई है, उससे इस देश के आगे निकल जाने की संभावना बन रही है। यह आकलन अब 'डीपसीक आर-1' और चीनी कारोबारी जैकमा की कंपनी- अलीबाबा की ओर से तैयार किए गए 'एआइ चैटबाट क्वेन 2.5 मैक्स' के साथ बिल्कुल सही साबित हो गया है। यही नहीं, इसी अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया था। इसमें लिखा गया था कि चीन की तरह ही भारत में भी अब एआइ से जुड़े शोधकर्ताओं को अच्छा माहौल मिल रहा है और वे देश में ही रह कर तकनीक-प्रौद्योगिकी की इस नई जमीन पर नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर यह जरूरी क्यों है कि भारत-चीन जैसे देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर अंतरिक्ष के उन अभियानों पर अधिक संसाधन खर्च करें, जिनमें अमेरिका-यूरोप या कहें कि पश्चिमी देश

> **चीन ने हाल के वर्षों में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार करने में जो तेजी दिखाई है, उससे इस देश के आगे निकल जाने की संभावना बन रही है। यह आकलन अब 'डीपसीक आर-1' और चीनी कारोबारी जैकमा की कंपनी- अलीबाबा की ओर से तैयार किए गए 'एआइ चैटबाट क्वेन 2.5 मैक्स' के साथ बिल्कुल सही साबित हो गया है। इसी अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया था। इसमें लिखा गया था कि चीन की तरह ही भारत में भी अब एआइ से जुड़े शोधकर्ताओं को अच्छा माहौल मिल रहा है और वे देश में ही रह कर तकनीक-प्रौद्योगिकी की इस नई जमीन पर नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं।**

काफी तरक्की कर चुके हैं। खुले वैश्विक कारोबार का कायदा तो यह कहता है कि अगर कोई चीज दुनिया के किसी बाजार में सहजता से उपलब्ध है, तो उसे पैदा करने में संसाधन और ऊर्जा झोंकने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बाजार में उपलब्ध सामान को अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद लेना चाहिए। दाल, अनाज, कपड़ों, दवाओं से लेकर तमाम चीजों को लेकर यही नियम अपनाया जाता है, लेकिन तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-चीन की सक्रियता और तेजी का आखिर कोई तो मतलब होगा। यह बेवजह तो नहीं होगा कि ये दोनों मुल्क अंतरिक्ष में चांद-मंगल की दौड़ लगा रहे हैं, तो जमीन पर एआइ से लेकर सेमीकंडक्टर की फैक्टरी बनने पर आमादा हैं।

जिस तरह भारत-चीन की सरकारों ने इधर अंतरिक्ष अभियानों के संचालन और सेमीकंडक्टर के उत्पादन और फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवाचारों को प्रश्रय दिया है, उससे तस्वीर बदलने लगी है। इसी का एक नतीजा डीपसीक आर-1 के रूप में निकला है, जिसने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। अभी तक माना जा रहा था कि अमेरिकी कंपनियों- ओपनएआइ, गूगल और फेसबुक आदि ने चैटजीपीटी, जेमिनी, को-पायलट और मेटा एआइ के रूप में जो 'एआइ टूल' बनाए हैं, उन्हें कोई उल्लेखनीय चुनौती दुनिया के किसी कोने से नहीं मिलेगी, लेकिन डीपसीक आर-1 ने भरोसा जगा दिया है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी-यूरोपीय कंपनियों के एकछत्र साम्राज्य में सेंध लगाई जा सकती है और एक विकासशील देश भी अपने मामूली संसाधनों के बल पर समान या ज्यादा क्षमता हासिल कर सकता है।

डीपसीक कैसे गरीब और विकासशील देशों के मामले में एक मिसाल बन सकता है, इसकी गवाही अमेरिका में इसके पहुंचने की खबरों के साथ ही देखने को मिली है। जब पता चला कि डीपसीक लागत और उपयोग में चैटजीपीटी से कई गुना सस्ता और मुफ्त है, तो अमेरिकी शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। इसकी असल वजह यही है कि अमेरिकी कंपनियों को अब एआइ में अपना एकाधिकार खत्म होता दिख रहा है। इससे यह भी साबित हुआ कि तकनीक के आविष्कार और उसे आजमाने की जो लागत तथा कीमत अमेरिकी कंपनियां बताती रही हैं, वे बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई हैं। बताया गया कि ओपनएआइ ने चैटजीपीटी को जिस लागत में बनाया था, डीपसीक के निर्माण की लागत उससे दस गुना कम आई है। इससे साबित हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले वही काम सस्ते में या फिर मुफ्त में हो सकते हैं, जिनके लिए अमेरिकी कंपनियां दस गुना ज्यादा पैसा लेती रही हैं। हालांकि डीपसीक एक चीनी आविष्कार है और टिकटाक और पबजी से लेकर चीनी उपकरणों के जरिए जिस तरह डेटा चोरी के आरोप चीनी कंपनियों पर लगते रहे हैं, उन्हें देखते हुए डीपसीक को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत बनती है।

भारत को इस संबंध में सावधानी बरतने के साथ-साथ यह कोशिश भी करनी होगी कि ऐसे तकनीकी और प्रौद्योगिकी आधारित आविष्कारों के भारतीय संस्करण जितनी जल्दी हो सकें, तैयार किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां देश से बाहर जाने से रुक सकें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ग्राहकों की निजी जानकारियों की चोरी से दुनिया भर से साइबर जालसाजी की जाती रही है। एआइ से बराबरी करने में अभी कोई देरी इससे जुड़े ढांचे को लेकर हो सकती है।

अकेलेपन का घेरा

अमित चमड़िया

कुछ समय पहले आई एक खबर के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में पचास वर्ष की उम्र के बाद तलाक के मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई। अकेले इंदौर शहर में जनवरी, 2023 के बाद करीब पौने दो वर्ष के भीतर करीब ढाई सौ मामले सामने आए। तलाक हमारे समाज में कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर चालीस या पचास वर्ष साथ रहने के बाद पति और पत्नी के बीच ऐसी नौबत आ रही हो तब यह बात थोड़ी अचंभित करने वाली जरूर है। जब इन मामलों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि 'घोंसला सिंड्रोम' यानी 'खाली घर' उम्रदराज पति-पत्नी के बीच तलाक की बड़ी वजह है। ज्यादातर मामलों में इन बुजुर्गों के बच्चों के बाहर दूर किसी शहर में या फिर विदेश में बस जाने या फिर बच्चों का मां-पिता का साथ छोड़ देने की वजह से बुजुर्ग पति-पत्नी को दुख और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और उससे उपजी पीड़ा को झेलना पड़ता है। अकलेपन के कारण उनकी दिनचर्या में आने वाले नोकझोंक तलाक तक पहुंच जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में तलाक सहमति से हो रहे है।

दुनिया मेरे आगे

इसी संदर्भ में देखें तो दूसरी खबर अमेरिका से आई, जिसमें 'फ्रेंड होर्डिंग' नाम के नए चलन वहां के समाज में देखे जा रहे हैं। इस 'फ्रेंड होर्डिंग' का मतलब यह है कि लोग अपने दोस्त को दूसरे दोस्तों से नहीं मिलने दे रहे हैं। इसकी वजह यह बताई गई कि लोगों में कई तरह का असुरक्षाबोध और दोस्तों को खोने का डर है। हालांकि लोगों का मानना है कि दोस्ती में असुरक्षा और डर एक सामान्य मानवीय भाव हैं, लेकिन आधुनिक दौर की जीवनशैली और सोशल मीडिया के प्रभाव से और यह लगातार गहरा होता गया है। लोगों में कहीं न कहीं यह डर भी है कि दोस्त के खोने से उनके जीवन में अकेलापन आ जाएगा। दूसरी तरफ, अपने दोस्त को दूसरे दोस्त के न मिलने देने की वजह से भी कुछ लोग अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति अभी भारत में नहीं आई है, लेकिन खासतौर पर शहरों में जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें इसकी संभावना बहुत ज्यादा हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि अब ज्यादातर रिश्ते आभासी मंचों पर ही तय किए और निभाए जा रहे हैं।

> **दोस्ती में असुरक्षा और डर एक सामान्य मानवीय भाव हैं, लेकिन आधुनिक दौर की जीवनशैली और सोशल मीडिया के प्रभाव से और यह लगातार गहरा होता गया है। लोगों में कहीं न कहीं यह डर भी है कि दोस्त के खोने से उनके जीवन में अकेलापन आ जाएगा।**

मौजूदा दौर में वर्तमान समाज में संबंधों के मामले में सबसे ज्यादा बदलाव की वजह तेजी से बढ़ता-पसरता अकेलापन है। इंसान ने तकनीक का आविष्कार अपने फायदे और सुविधा के लिए किया है, लेकिन आभासी दुनिया के चलते समाज में ज्यादातर अभौतिक बदलाव की दिशा नकारात्मक है। इंटरनेट पर लोग अलग-अलग समूहों से जुड़े हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन इस तरह के जुड़ाव का कोई ठोस आधार नहीं होता हैं। ये जुड़ाव केवल चंद 'लाइक' और हल्की-फुल्की टिप्पणियों तक ही सीमित रहते हैं। अमेरिकी साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक रपट के अनुसार, अमेरिका में हर तीसरा व्यक्ति अकेलापन का शिकार है। यह आंकड़ा युवाओं में अधिक है और तेजी से बढ़ रहा है। भारत के युवाओं के बीच भी यह समस्या तेजी से पांव पसार रही है।

हालांकि इस समस्या की गंभीरता को चिह्नित और विश्लेषित किया गया है और इस अकेलेपन के कारण उत्पन्न प्रभाव को कम करने के प्रयास भी हो रहे हैं। इसी तरह के एक प्रयोग की खबर अमेरिका से आई, जिसमें 'प्रोजेक्ट गैदर' को अपनाया गया है। इस प्रयास में लोग सामूहिक भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अपने समूह के लोगों को उनके बचपन में भोजन प्रिय थे, उसी को भोज में शामिल किया जाता है। इससे न केवल सामूहिकताबोध में मजबूती आती है, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मकसद भी यही है। इस तरह बचपन का पसंदीदा भोजन परोसने के पीछे यह भी सोच है कि इसके बहाने हम अपनों-अपनी दादी-नानी और मां को याद कर पाएंगे, क्योंकि बचपन में हमारी पसंद का खयाल वही रखती थीं। स्वाद की यह साझा संस्कृति उन्हें खुशी दे रही है और लोग आपस में जुड़ कर बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसी तरह के एक अन्य प्रयास का नाम 'कनेक्शन कल्चर' रखा गया है। वहां के लोगों का मानना है कि अकेलेपन से जीत इसी तरह के प्रयासों से मिलेगी।

भारत में भी अकेलेपन से निजात पाने के लिए इस तरह की कई कोशिश हो रही हैं। इसमें एक प्रयास केरल के कोट्टायम के करीब हो रहा है, जहां एक साथ आसपास दो कमरों के कई घर बनाए गए हैं, जिनमें किसी घर में रसोईघर नहीं हैं। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग पति-पत्नी डाक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशे से जुड़े रहे हैं। इन घरों के समूह के सिद्धांत हैं- 'अपना काम खुद करें और जो असमर्थ हैं, सब उनकी मदद करें'। खाना बनाने के लिए दो रसोइए का इंतजाम किया गया। मन बहलाने के लिए कई स्तर पर अच्छा-खासा इंतजाम किया गया है।

अब महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं। आज का मनुष्य, जो अपने आप को सबसे ज्यादा आधुनिक समझ रहा है, उसे इस इस समस्या का कितना अहसास है। सच यह है कि तकनीक की दुनिया में गुम होते जा रहे ज्यादातर लोग इस पर गौर नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी किस अंधेरे की ओर बढ़ रही है। वे शायद आधुनिकता के मतलब को नहीं समझ पा रहे है। आधुनिकता का मतलब सामूहिकता से है, न कि गंभीरता और निजता के नाम पर बढ़ रहे ऐसे अकेलेपन से, जो भीतर ही भातर इंसान को खोखला कर दे या फिर खा जाए।। इस बात को सबको समझने की जरूरत हैं, खासकर युवाओं को।

सहयोग का सफर

'दोस्ती के आयाम' (संपादकीय, 14 फरवरी) में सही लिखा गया है कि भारत और फ्रांस के बीच प्रगाढ़ हो रही दोस्ती से चीन और अमेरिका कदापि खुश नहीं होंगे। निस्संदेह अमेरिका और चीन अपने को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए भारत की प्रगति नहीं देख सकते। मगर भारत की साख बढ़ने से इन दोनों देशों को अपनी कूटनीति में बदलाव जरूर करने पड़े हैं। इसी का नतीजा है कि सीमा पर चीनी सैनिकों का मिजाज ठंडा पर गया है। वर्ष 1998 में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के बाद से, फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय संस्कृति को फ्रांसीसी लोगों में व्यापक सराहना मिली है। फ्रांस में आयोजित होने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्पष्ट है, जिसमें भारतीय कला, संगीत, नृत्य, सिनेमा और साहित्य को शामिल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली द्विपक्षीय वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेजबानी की। ट्रंप की शुल्क नीति से दुनिया भर में हलचल मच गई है, ऐसे में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाशिंगटन द्वारा भारत के खिलाफ किसी भी दंडात्मक व्यापार कार्रवाई को रोकना है।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

हक की कमाई

जब हम पैसा कमाने के लिए दूसरों का हक मारते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं। दूसरों का हक मार कर या बेईमानी से कमाया पैसा हमें कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसी का हक मार कर जो कमाते हैं, वह भविष्य में हमारे काम आएगा भी या नहीं! जरूरी नहीं कोई गैरों का हक मार कर ही पाप का भागी बनता है, बल्कि जो अपनों के साथ बेईमानी कर जमीन-जायदाद और धन दौलत हड़पने की कोशिश करता है, वह भी पाप का भागी बनता है। महाभारत में दुर्योधन ने अपने भाइयों का ही हक मारने के लिए बहुत चालें चली थीं, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? उसने अपने सौ भाइयों को खो दिया। अपनी नगरी की बर्बादी का कारण बना। कमाई हमें भौतिकतावाद के सुख तो दे देगी, लेकिन इसके लिए जो हम गलत कर्म करेंगे, तो उसका बुरा फल हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

बदलाव की हवा

जब से दुनिया में तकनीकी क्रांति आई है, तब से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इसमें हर चीज ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बदलाव के दौर में बच्चों का कोमल बचपन प्रायः कहीं पीछे छूटा नजर आता है। बदलाव की हवा ने बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डाला है। अब बच्चे शाम होते ही गलियों-मोहल्लों में खेलते हुए कम दिखते हैं। अब पुराने टायर को सड़क पर दौड़ाने वाली, गिल्ली-डंडा, कंचे और बाहर अन्य खेल खेलने वाली पीढ़ी लगभग विलुप्त हो चुकी है। अब 'आनलाइन गेम्स' ने बच्चों की नन्ही अंगुलियों को डिजिटल स्क्रीन तक सीमित कर दिया है। आजकल बच्चों का समय सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल गतिविधियों में बीतता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। जहां एक ओर यह डिजिटल दुनिया नई संभावनाएं और ज्ञान का द्वार खोल रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों की खेलकूद और सामाजिक कौशल में कमी भी महसूस हो रही है।

– नितिन रावत, फिरोजाबाद

खैरात पर सवाल

सर्वोच्च न्यायालय ने अहम मुद्दा उठाया है कि राजनीतिक दल राहत के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। यह मानव शक्ति को निठल्ला और कामचोर बना रही है। बेरोजगारी का जो शोर मचाया जा रहा है, असल में उतनी बेरोजगारी है नहीं। स्वरोजगार से भी रास्ते निकल सकते हैं। करने वालों के लिए सौ काम हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों की मंशा ही नहीं है काम करने की, तो कोई क्या करे। इन दिनों मुफ्त की योजनाओं से यह कहावत 'मुफ्त मिले खाने को, तो कौन जाए कमाने को' चरितार्थ हो रही है। सच यह है कि जो मानव शक्ति राष्ट्र निर्माण में संलग्न होनी चाहिए, वह निस्तेज और गुमराह हो रही हैं। शीर्ष न्यायालय ने 'परजीवियों' की जमात बनने की बात कही है. उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। करोड़ों लोगों को लंबे समय से मुफ्त सामान मुहैया कराना कहां तक सही है?

– हुकुम सिंह पंवार, टोड़ी, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

यूक्रेन के बिना यूएस-रूस वार्ता सिरे नहीं चढ़ेगी

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन शायद जल्दी में है। रूस व यूक्रेन जंग समाप्त कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की जल्दी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सीधे रूस के साथ वार्ता-ए-आगाज की है। रूस व यूक्रेन के बीच शांति कायम करने के लिए यह वार्ता सऊदी अरब में हो रही है। चौंकाने वाली बात है कि युद्ध के अहम भागीदार यूक्रेन को इस वार्ता में शामिल ही नहीं किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस वार्ता को लेकर नाराजगी जताई है और दोनों को साफ संदेश दिया है कि यूक्रेन वार्ता के किसी निर्णय को नहीं मानेगा। बड़ा सवाल है कि युद्ध यूक्रेन व रूस के बीच है, इसलिए वार्ता का पहला हक इन दोनों मुल्क को है। आखिर अमेरिका किस हैसियत से यह वार्ता कर रहा है? यूक्रेन ने न ही उसे अपना वार्ताकार नियुक्त किया है व न ही उसे मध्यस्थता के लिए कहा है। तो अमेरिका कहां खड़ा है? यदि अमेरिका रूस का मन टटोलने के लिए बात कर रहा है, तो उसने यूक्रेन को विश्वास में क्यों नहीं लिया? यूक्रेन अगर इस वार्ता के नतीजे को नहीं मानेगा तो आखिर इस वार्ता का औचित्य क्या रह जाएगा? हड़बड़ी में की गई अमेरिकी पहल से यह संदेश निकल रहा है कि यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाने में व साथ निभाने में अमेरिकी हाथ रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ने की जल्दी में है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को सबक सिखाने की अमेरिकी मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। ट्रंप से पहले की डेमोक्रेट सरकार की नीति रूस को अलग-थलग करने की थी, इसलिए खुले तौर पर यूक्रेन का साथ यूएस दे रहा था। अब ट्रंप प्रशासन दुनिया के पटल पर रूस को अलग-थलग करने की अमेरिकी नीति को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम में वह वार्ता कर रहा है, किंतु यूक्रेन को विश्वास में लेकर भी यह पहल अमेरिका कर सकता था। माह के शुरू में ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के प्रति अमेरिकी नीति को बदल दिया था। अच्छा होता अमेरिका वार्ता टेबल पर रूस व यूक्रेन के साथ होता, जो भी बात होती, उसमें पारदर्शिता होती। यूक्रेन की संप्रभुता की अनदेखी करके कोई भी शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती है। अतीत में कई उदाहरण हैं, जिसमें एक पक्षकार के बिना अंतरराष्ट्रीय मुद्दे सुलझाने की पहल औंधे मुंह गिरी है। अफ्रीकी महाद्वीप के बंटवारे के लिए वर्ष 1884-1885 की सर्दियों में जर्मनी ने यूरोप के शक्तिशाली देशों के साथ वार्ता की थी, पर इसमें अफ्रीका का कोई देश शामिल नहीं था। नतीजा 20वीं सदी का पहला नरसंहार व अत्याचार के रूप में निकला था। समोआ को लेकर जर्मनी, ब्रिटेन व अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन में समोआ शामिल ही नहीं था। समोआ आज भी बंटा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिनिधि के बीच ऑटोमन साम्राज्य के बंटवारे को लेकर साइक्स-पिकॉट समझौता हुआ, इसमें ऑटोमन शामिल नहीं था। ब्रिटेन व जर्मनी के बीच चेकोस्लोवाकिया को लेकर म्यूनिख समझौता को विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। वर्ष 1938 में फ्रांस समेत 32 देशों ने जर्मनी में यहूदी शरणार्थियों की स्थिति पर एवियन सम्मेलन किया, जिसमें जर्मनी शामिल नहीं था। पोलैंड को लेकर जर्मनी व सोवियत संघ के बीच समझौता में पोलैंड शामिल नहीं था। वर्ष 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन व सोवियत रूस के बीच यूरोप के भाग्य के फैसले को लेकर याल्ट सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रभावित कोई मुल्क नहीं था। इसलिए अमेरिका को अतीत से सबक लेते हुए शांति वार्ता में रूस व यूक्रेन दोनों को शामिल करना चाहिए।

कूटनीति
डॉ. एन.के. सोमानी

गाजा पर ट्रंप के बयान से हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में एक प्रेस-कांफ्रेंस में गाजा के भविष्य को लेकर एक योजना प्रस्तुत की। ट्रंप ने कहा कि फिलीस्तीनी जनता को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर गाजा को लग्जरी रिजॉर्ट में तब्दील किया जाएगा, जहां दुनिया का कोई भी व्यकित आ सकेगा। ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध में तबाह हुए गाजा का पुनर्निर्माण करेंगे। पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने तक गाजा के लोगों को दूसरे अरब देश में बसाया जाएगा। अरब देश इसलिए भी हतप्रभ हैं, क्योंकि उन्होंने परियोजना को वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए सेना भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया।

पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर नियंत्रण कर उसे लग्जरी पर्यटन केंद्र (मध्यपूर्व का रिवेरा) के रूप में तब्दील करने का ऐलान किया तो पश्चिम एशिया सहित पूरी दुनिया में कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी। मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर फिलिस्तीन अथॉरिटी और अरब लीग ने संयुक्त रूप से ट्रंप की इस योजना की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका गाजा पर कब्जा करता है तो इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरिता को खतरा हो सकता है और संघर्ष और बढ़ सकता है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ट्रंप के बयान की आलोचना की। उनका कहना है कि गाजा पर समाधान की खोज में किसी भी प्रकार के जातीय सफाए से बचना आवश्यक है। अब मिस्र भी कूद गया है।

गुटेरेस के बयान से साफ है कि ट्रंप की इस योजना से क्षेत्रीय शांति पर असर पड़ सकता है। दरअसल, कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में एक प्रेस-कांफ्रेंस में गाजा के भविष्य को लेकर एक योजना प्रस्तुत की। ट्रंप ने अपनी योजना को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि फिलीस्तीनी जनता को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर गाजा को लग्जरी रिजॉर्ट में तब्दील किया जाएगा, जहां दुनिया का कोई भी व्यकित आ सकेगा। ट्रंप ने योजना का खुलासा करते हुए यह भी कहा कि वो युद्ध में तबाह हुए गाजा का पुनर्निर्माण करेंगे। पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने तक गाजा के लोगों को दूसरे अरब देश में बसाया जाएगा। ट्रंप की परियोजना से अरब देश इसलिए भी हतप्रभ हैं, क्योंकि उन्होंने परियोजना को वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए सेना भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। ट्रंप मूल रूप से एक अरबपति बिल्डर हैं। वो कारोबार की दुनिया से राजनीति में आए हैं। इसलिए जब गाजा के पुनर्निर्माण की बात आई तो उन्होंने यह कह दिया कि अगर गाजा को फिर से बसाना है तो उसके नागरिकों को मलबे में शरण नहीं देनी चाहिए। लेकिन 15 महीनों के युद्ध में जिस तरह से गाजा तबाह हुआ है उसे देखते हुए गाजा के पुनर्निर्माण में दशकों का समय लगेगा। यूएन के आंकड़ों के अनुसार इस समय गाजा में जितना कचरा जमा है उसे हटाने में कम से कम 21 साल का समय लग सकता है। उसका कहना है कि गाजा में 2008 से अब तक हुए संघर्ष में जितना मलबा पैदा हुआ है, उससे 17 गुना अधिक कचरा पिछले 15 महीने के युद्ध में हो गया है।

ऐसे में पहले तो बिना फटे हथियारों और मलबे के पहाड़ों को हटाना होगा। पानी-बिजली की सप्लाई बहाल करनी होगी। इसके बाद स्कूलों, अस्पतालों व दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे। इस काम में कई साल लग सकते हैं। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि जब तक गाजा के पुनर्निर्माण का काम पूरा हो, तब तक फिलिस्तीनियों को कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। सवाल यह है कि जिस जमीन को लेकर बीते सवा साल में 50 हजार से अधिक फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवा दी, उसे छोड़ने के लिए वे कैसे राजी हो सकते हैं।

पूरे मामले का सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की पूरी परियोजना ही न केवल सवालों और संदेह के घेरे में हैं, बल्कि पूरी तरह से हवा-

हवाई, अनैतिक और कानूनी पेचिदगियों से भी भरी हुई है। पहला और सबसे अहम सवाल तो यह है कि इजरायल-हमास शांति समझौते के बीच उद्घोषित इस योजना को लागू करने का अर्थ क्या मीडिल ईस्ट को लेकर अमेरिकी नीति में आए बदलाव का संकेत है। अब तक अमेरिका 'टू-स्टेट सॉल्यूशन'को मान्यता देता था। वह इजरायल के साथ-साथ एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थक रहा है। गाजा में फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने से क्या फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा खत्म नहीं हो जाएगा। क्या ट्रंप की परियोजना अमेरिका पोषित 'द्वी राष्ट्रवाद' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। दूसरा जिस तरह से फिलिस्तीनियों के विस्थापन की बात कही जा रही है, क्या उससे हमास-इजरायल शांति समझौता लागू होने से पहले ही खत्म नहीं हो जाएगा। नेतन्याहू के साथ बैठक से पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि गाजा में मौजूदा युद्धविराम समझौता कायम रहेगा। ऐसे में गाजा में बंधकों की रिहाई की उम्मीद क्या फिर खत्म हो जाएगी। तीसरा, योजना को उद्घाटित करने से पहले क्या ट्रंप ने गाजा की राजनीतिक, ऐतिहासिक और सुरक्षा संबंधी जटिलताओं पर भी कोई होमवर्क किया है। परियोजना पर अमेरिकी समर्थक अरब राष्ट्र भी विश्वास के लिए तैयार नहीं है। उनके संदेह के भी जायज कारण है। जिस तरह से ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने, कनाडा को अमेरिका में मिलाने, मैक्सिकों की खाड़ी का नाम बदलने और पनामा नहर पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं उससे भी ट्रंप की 'सद्इच्छा' पर संदेह होता है। संदेह की दूसरी बड़ी वजह बेंजामिन नेतन्याहू का 'ग्रेटर इजरायल' का सपना भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाजा के पुनर्निर्माण का काम पूरा होने के बाद ट्रंप सजा-संवरा गाजा इजरायल को सौंप दे। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका किस कानूनी आधार पर गाजा में इस तरह का कदम उठा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर बड़ी आबादी को जबरन विस्थापित किया सकता हो। गाजा फिलिस्तीनियों का घर है। 1948 के युद्ध के दौरान भी वे विस्थापन की पीड़ा भुगत चुके हैं, इसलिए जाहिर है कि ट्रंप की योजना कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टि से उचित नहीं हैं। अरब नेताओं ने दशकों तक फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्रीय तत्व के रूप में रखा है। ट्रंप की योजना अरब राजनीति की इस केन्द्रीय तत्व को भी कमजोर करती है। फिलिस्तीनियों को जबरन दूसरी जगह भेजने की योजना न केवल टू-स्टेट सॉल्यूशन को खत्म करेगी बल्कि इसे अरब देशों द्वारा जातीय सफाए के रूप में भी देखा जाएगा।

जैसा कि यूएन महासचिव कर रहे हैं। योजना के पटाक्षेप के बाद जिस मुखरता से अरब देशों ने इसका विरोध किया है, उससे जाहिर है वे ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने के मूड में कतई नहीं है। ट्रंप की योजना पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने और मिडिल ईस्ट के देशों पर कड़ी नजर रखने (खासकर ईरान) का प्रयास भी हो सकती है। इसके अलावा लाल सागर पर भी अमेरिका अपना प्रभाव कायम करने की मंशा रखता है जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर बढ़त हासिल हो सके। हूती जैसे संगठनों पर लगाम लगाने के लिए भी यह योजना कारगर साबित हो सकती है। गाजा पर कब्जा कर वह हूती के गढ़ यमन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। संदेह के तमाम कारणों के बीच अरब राष्ट्रों को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वह यह कि क्या यह ट्रंप का महज एक विवादित बयान है या इसके पीछे कोई गंभीर रणनीति छिपी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप अपनी इस योजना के जरिए पश्चिमी हितों को पूरा करने के लिए अरब शासन के विघटन का कोई नुस्खा दे रहे हैं।

(लेखक एमजेजीसी सूरतगढ़ (राजस्थान) में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

काशी तमिल संगमम
सुभाष चन्द्र

विश्वनाथ के साथ भारती का घर भी बन गया तीर्थ

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी, 2025 को काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया। पतित पावनी गंगा के तट पर नमो घाट पर दो संस्कृतियों के मिलन को सहज ही समझा जा सकता है। तमिलनाडु से संगमम में शामिल होने के लिए जो भी जत्था आता है, वो पहले गंगा में स्नान करता है। मंदिरों में पूजन-परिक्रमा आदि करता है। बाबा विश्वनाथ का आशीष लेता है। साथ ही हनुमान घाट स्थित स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात कवि सुब्रह्मणयम भारती के घर जरूर जाता है। दरअसल, सनातन धर्म में मोक्ष की कामना लिए हर व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक बार काशी आना चाहता है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी। यहां आदिदेव महादेव विराजते हैं। पुराणों और वैदिक ग्रंथों में इस नगरी की काफी महत्ता बताई गई है। विदेशी भी यहां घूमने आते रहे हैं। उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे बसा यह नगर हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है। हाल के दिनों में यहां एक नया तीर्थ बन गया है। वह तीर्थ है - स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात कवि सुब्रह्मणयम भारती का घर। यूं तो तमिलनाडु से आने वाले अधिकतर लोग हनुमान घाट और केदार घाट पर गंगा में स्नान करते हैं। यहां से वह कई मठों में पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते रहे हैं। लेकिन, काशी तमिल संगमम के आयोजन से हनुमान घाट पर शंकर मठ के सामने स्थित सुब्रह्मणयम भारती का घर स्वयमेव तीर्थ बन गया है। हर खास और आम उनकी देहरी को नमन करना चाहता है, जहां सुब्रह्मणयम भारती ने अपना लगभग पूरा जीवन बिता दिया। असल में, केदार घाट और हनुमान घाट को काशी में मिनी तमिलनाडु कहते हैं। यहां सैकड़ों तमिल परिवार सदियों से निवास करते हैं। यहां इनकी पूरी संस्कृति दिखती है। पं. वेंकट रमण घनपाठी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का गहरा रिश्ता है। ये समागम महज एक पखवाड़े का नहीं सदियों पुराना है। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ऐसे साहित्यकार थे, जो सक्रिय रूप से 'स्वतंत्रता आंदोलन' में शामिल रहे, जबकि उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये ऐसे महान कवियों में से एक थे, जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेज़ी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका 'गद्य' और 'पद्य' दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी देश प्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि इन्हें भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। सुब्रह्मणयम भारती का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहे। स्वतंत्र रूप से सोचना-विचारना केवल मातृभाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है और उसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली सफल हो सकती है, जो मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी। विलायती भाषा द्वारा पढ़ाई से राष्ट्रभाषा मन्द पड़ने लगेगी और कालान्तर में मिट ही जाएगी। आज की शिक्षा मस्तिष्क के विकास की है, जबकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मा का विकास महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अपने अतीत के साथ न्याय करते हुए भविष्य की मांग के अनुरूप बन सकें। सुप्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्य भारती की प्रारंभिक कविताओं में तमिल राष्ट्रवाद का उल्लेख मिलता है, किन्तु स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आने के बाद उनकी जीवन के उत्तरार्ध में लिखी कवितायें भारतीय हिन्दू राष्ट्रवाद का गुणगान करती हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि यह परिवर्तन उनकी गुरु भगिनी निवेदिता और स्वामीजी के कारण उत्पन्न हुआ। भारती का प्रिय गान बंकिम चन्द्र का 'वन्दे मातरम्' था। 1905 में काशी में हुए 'कांग्रेस अधिवेशन' में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने यह गीत गाया। भारती भी उस अधिवेशन में थे। मद्रास लौटकर भारती ने उस गीत का उसी लय में तमिल में पद्यानुवाद किया, जो आगे चलकर तमिलनाडु के घर-घर में गूंज उठा।

'अन्न चत्रम आथिरम वैत्तल आलयम पतिनारियम नाट्टल
अन्न याविलुम पुण्यम कोड़ो आंकोर एवैकु एलुत्तरिवित्तल'

यह उद्गार हैं, सुब्रह्मण्य भारती के, जो हर तमिल पाठक के हृदय में वास करते हैं। शिक्षा दान को सर्वोपरि मानने वाले भारती केवल एक लेखक या कवि ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। उनके विचारों और लेखन में अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। वे कथनी और करनी के बीच अंतर नहीं रखते थे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है

संकलित
दर्शन

योग प्रकृति की स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। योग के ही चलते मां के गर्भ में आना और जीवन धारण करना संभव होता है। उसके बाद जन्म लेते ही सांसारिक-योग आरंभ होता है। घर-परिवार और समाज के साथ योग जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है तथा जीवन के समापन पर फिर प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाकर विलीन होना भी योग है। ऋषियों ने प्रकृति की गूंज सुनकर उसमें त्रिस्तरीय योग का जो स्वरूप देखा उसमें 'ऊं' शब्द दिखाई पड़ा। इस 'ऊं' में 'अ', 'उ' और 'म' का योग है। गर्भ में अस्तित्व में आना 'अ', जन्म के बाद उत्थान 'उ' तथा मृत्यु 'म' का संयुक्त होना भी योग है। ऋषियों ने अंतिम अक्षर 'म' को हलंत कर आधा इसलिए कर दिया, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु पूरी नहीं होती। पंच भौतिक शरीर प्राकृतिक पदार्थों के साथ योग कर पुनः अनंत में विलीन हो जाता है, जबकि आत्मा जीवंत रहता है और पुनः नए शरीर के साथ योगभाव में आता है। प्राकृतिक योग को भी देखा जाए तो क्षिति तत्व धरती के साथ योगनिष्ठ होकर धरती में मिल जाता है, अग्नि आकाश की ओर अपने देही सूर्य के साथ योग करने को ऊपर की ओर उठती है तो जल, जल के साथ, वायु, वायु के साथ तथा गगन तत्व शून्य के साथ योग-भाव में हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो कदम-कदम पर योग का प्रकट भाव दिखाई पड़ता है। मानव शरीर के अंदर और बाहर जो योग हो रहा है, उसे नियमित जीवन में अपनाकर कोई भी व्यक्ति उर्ध्वमुखी जीवन प्राप्त कर सकता है।

काम शुरू करने से ज्यादा है काम करते रहना

संकलित
प्रेरणा

एक प्राचीन कथा के मुताबिक, ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग के मस्तक और पैरों की खोज शुरू की। ब्रह्मा को शिव का मस्तक ढूंढने का और विष्णु को शिव के पैर ढूंढने का कार्य सौंपा गया। सभी देवता इसके आरंभ और अंत के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा आरंभ की और वे आगे बढ़ते गए। कई लोक पीछे छूट गए और कई युग बीत गए। फिर भी ब्रह्मा शिव के मस्तक का पता नहीं लगा पाए। सृष्टि का एक अंत है। सृजन एक बिंदु पर समाप्त होता है। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा उसके बाद भी जारी रखी। उन्होंने एक केतकी का पुष्प देखा जो आकाश से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से पूछा, 'तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने शिव का मस्तक देखा है? यहां से शिव का मस्तक कितनी दूर है?'केतकी पुष्प ने कहा, 'मैं शिव के मस्तक से आ रहा हूं।' तो ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि शिव का एक मस्तक था और वे पुष्प लेकर नीचे आए। विष्णु का कार्य शिव के पैरों की खोज करना था। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु बहुत विनम्र हैं। पालनकर्ता को हमेशा बहुत विनम्र होना चाहिए। रचयिता जैसा भी हो, यदि पालनकर्ता विनम्र हो, तभी पालन कार्य संभव है। व्यवसाय आरंभ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सतर्क, बहुत विनम्र रहना पड़ेगा, अन्यथा व्यापार डूब जाएगा। विष्णु की विनम्रता ने ही उन्हें शिव के चरणों को ढूंढने का कार्य करने योग्य बनाया। युगों तक यात्रा करने के बाद, विष्णु शिव के चरणों को ढूंढने में सक्षम नहीं हुए।

कुंभ से पहुंचे वाराणसी

प्रयागराज कुंभ से वाराणसी पहुंचे आवाहन अखाड़े के साधुओं ने मंगलवार को यहां शोभायात्रा निकाली जिसमें नागा साधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

आज की पाती

महंगाई को मिलकर नकेल दें सरकारें

देश के लोग इस वक्त महंगाई से त्रस्त हैं। सरकार को महंगाई रोकने के अपने वादों को पूरा करना चाहिए। अकसर यह देखा जाता है कि चुनाव के दौरान भारी भरकम वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने भी चुनाव के दौरान महंगाई पर नकेल कसने का वादा किया था, लेकिन वह इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। प्राय: हर प्रदेश में खाद्य पदार्थों के दाम ऊपर ही जा रहे हैं। आटा, चावल, सब्जियां, तेल, दालों आदि के भाव अपनी ऊंचाई पर हैं। फलों के दाम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी कदम उठाने चाहिए। यह एक सामूहिक दायित्व है।

- पवन खेड़ा, महासमुंद

ट्रेंड

विवादित बातों का निषेध

छत्रपति संभाजी महाराज इनको लेकर विकिपीडिया पर लिखी गई विवादित बातों का हम निषेध करते हैं, राज्य सरकार ने आईजी साइबर को विकिपीडिया से बात कर विवादित बातों को हटाकर सही जानकारी प्रेषित करने का आदेश दिया है।

-देवेन्द्र फड़नवीस, सीएम, महाराष्ट्र

मतदाताओं की चिंता

भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर, मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। नई सीईसी का चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और असभ्य दोनों है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

शहीदों का महत्व

ये बेहद निंदनीय और अशोभनीय है कि देश के लिए शहीद होने से अधिक महत्व किसी और को दिया जा रहा है। जिन्होंने न आज़ादी दिलाने में कोई भूमिका निभाई, न ही आज़ादी बचाने में वो शहीदों का महत्व क्या जानें।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

मल्टीटास्किंग मजेदार

मैं हमेशा अच्छी चीजें करने वाले अच्छे लोगों के साथ मिलती हूं... जब आप हंसते हैं, काम करते हैं और बुनाई करते हैं तो मल्टीटास्किंग मजेदार होती है!

-काजोल, अभिनेत्री

करंट अफेयर

दक्षिणी लेबनान के ग्रामीण घर लौटने की तैयारी में

इजराइली सेनाएं मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती गांवों से वापस लौट गईं। यह वापसी अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते में तय समय सीमा के अंतर्गत हुई, जिसके साथ ही इजरायल-हिजबुल्लाह के बीच नवीनतम युद्ध समाप्त हो गया। लेबनानी सैनिक उन इलाकों में पहुंच गए हैं जहां से इजरायली सैनिक वापस चले गए थे और उन्होंने इजराइली सेना द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही वे बिना विस्फोटकों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने गांवों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को बंद कर दिया ताकि किसी को भी अंदर जाने से रोका जा सके। ऐसा सेना द्वारा वहां मौजूद विस्फोटकों की तलाश कर उन्हें नष्ट करने के मद्देनजर किया गया है। गांव के अधिकांश लोग अपने घरों की जांच करने के लिए सड़क के किनारे अनुमति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग सड़क के अवरोधकों को हटाकर अंदर चले गए। हालांकि, इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर पांच रणनीतिक निगरानी बिंदुओं पर बने हुए हैं। यह लेबनानी अधिकारियों और उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह समूह के लिए एक गंभीर मुद्दा है, जिन्होंने कहा है कि इजरायल को मंगलवार तक पूरी तरह से वापस लौटना होगा।

ऑफ बीट

पृथ्वी से बाहर खनन की होड़ ने पकड़ा जोर

जैसे-जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण और उपनिवेशीकरण का विस्तार होगा, पृथ्वी से बाहर के संसाधन तेजी से बढ़ता एक बाजार बनाएंगे। अंतरिक्ष में गहराई से खोज करने और अन्य ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करने का अभियान पिछले दशक में तेज हो गया है। विषम वातावरण में भी मूल्यवान संसाधन और खनिज प्राप्त करना लंबे समय से मनुष्यों के लिए आकर्षक रहा है। बहुमूल्य संसाधनों की तलाश में खतरों का सामना करने का हमारा इतिहास रहा है। 1800 के दशक में सोने की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष संसाधनों में हालिया उछाल तक, मनुष्य दुर्लभ और लाभदायक सामग्रियों को खोजने और इकट्ठा करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, हम सोने की अगली दौड़ के मुहाने पर हैं - लेकिन पृथ्वी पर नहीं। हाल की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सफलताओं और व्यावसायिक हितों के आधार पर, अगले दशक में पृथ्वी से बाहर खनन शुरू होने की उम्मीद है। संभावित खनन स्थलों में चंद्रमा, मंगल, क्षुद्रग्रह और यहां तक कि धूमकेतु भी शामिल हैं। अनुमान है कि 2050 तक चंद्रमा पर खनन, विशेष रूप से चंद्रमा पर मौजूद जल का बाजार अरबों डॉलर तक का हो सकता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

अनुशासन चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है

विदेश में नौकरी

इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पंजाब में युवाओं को सुहाने सपने दिखाकर और मोटा पैसा लेकर अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगता यही है कि अमेरिका की ओर से अपने यहां अनुचित तरीके से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी रही है, उससे बचने के लिए ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा भी नहीं है कि यह किसी से छिपा हो कि हमारे युवा अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यह बार-बार सामने आ रहा था कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में युवाओं को अवैध तरीकों से पश्चिमी देशों में भेजने वाले तथाकथित ट्रैवल एजेंट बेलगाम होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन न तो इन राज्यों की सरकारों ने उन पर कोई शिकंजा कसा और न ही केंद्र सरकार ने इसकी चिंता की कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगे। यदि अमेरिका अपने यहां अवैध तरीके से घुसे लोगों को हथकड़ी-बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजता तो शायद अभी भी सरकारों की नींद टूटने वाली नहीं थी।

यह ठीक है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी का सिलसिला कायम होने के बाद केंद्र सरकार इसके उपाय करने जा रही है कि दूसरे देशों में नौकरी के इच्छुक युवा वहां जाने के लिए अवैध तौर-तरीके न अपनाएं, लेकिन सच तो यह है कि वह भी इस बारे में समय रहते सक्रिय नहीं हो सकी। कम से कम अब तो उसे गंभीरता दिखानी ही चाहिए, क्योंकि अवैध प्रवासी देश की बदनामी का कारण भी बन रहे हैं। देखना है कि कौशल विकास मंत्रालय युवाओं को विधिवत ढंग से विदेश भेजने और उनके वहां रोजगार के अवसर भुनाने में समर्थ बनने के लिए जो प्रयास करने जा रहा है, उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि तमाम संभावनाओं के बाद भी अभी तक इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। हाल के समय में यह बार-बार सामने आता रहा है कि विदेश में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब हमारे दूतावास और उच्चायोग यह देखेंगे कि भारतीय युवाओं के लिए किस देश में रोजगार के कैसे मौके हैं? यह देखने के साथ ही इसके भी जतन करने होंगे कि हमारे युवा विदेश में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता-दक्षता से भी लैस हों।

जंगल की आग

उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर राज्य सरकार समय रहते सजग हो गई, यह अच्छी बात है। प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है, उन्हें जिलों में नोडल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में हर वर्ष आग से वन संपदा को व्यापक क्षति पहुंचती है। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि यहां किसी भी मौसम में जंगल धधकने लगते हैं। सामान्य तौर पर फायर सीजन की शुरुआत पंद्रह फरवरी से मानी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में इस वर्ष जनवरी के दूसरे पखवाड़े से ही जंगल धधकने लग गए। अब तक पंद्रह से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शीत ऋतु में कम वर्षा को जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने का एक कारण माना जा रहा है। अगले चार महीने इस दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील हैं। ऐसे में, वन विभाग को अति सतर्क रहने की जरूरत है। जिस हिसाब से सूर्य की तपिश अभी से महसूस की जा रही है, उसमें जंगलों पर आग का खतरा और गहराने के आसार बन रहे हैं। वन विभाग को जंगलों को आग से बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि विभाग जनसहभागिता पर जोर दे रहा है तो उसकी भी वजह है, क्योंकि विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जंगलों में आग लगने पर स्थानीय लोगों की मदद से ही उस पर काबू पाया जाता रहा है। आग लगने के कारणों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कई बार छोटी-छोटी मानवीय भूल जंगलों में आग लगने का कारण बन जाती हैं। दोनों ही स्थितियां घातक हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की जरूरत है।

जंगलों को आग से बचाने की जिम्मेदारी कुछ हद तक आमजन की भी है, उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए

बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता

आदित्य सिन्हा

भारत में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है, ताकि वह अर्थव्यवस्था की क्षमताएं बढ़ाने में सहायक हो

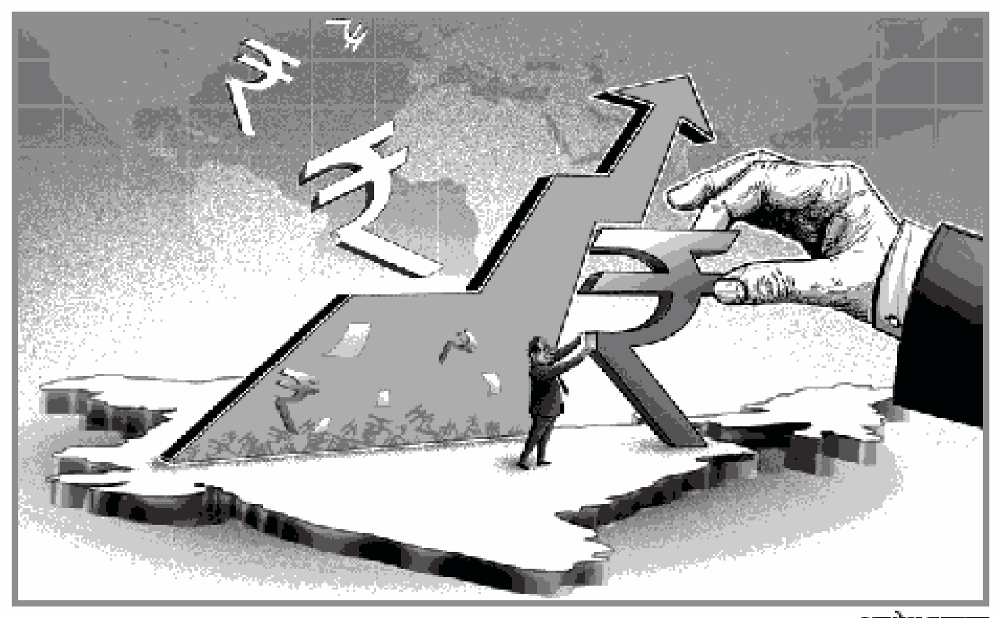

अवधेश राजपूत

अमेरिका पर दुनिया भर के तमाम मामलों मे दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में हुए तखापलट के पीछे भी अमेरिकी हस्तक्षेप की बातें सामने आईं। भारत में भी चुनावों एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में बड़ी रकम दांव पर लगाने की बात सामने आई है। अपने ऐसे अभियानों को सफल बनाने से लिए अमेरिका को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह रकम मुख्य रूप से सरकारी खजाने से आती है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि इस सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के पक्ष में वहां तमाम आवाजें बुलंद हो रही हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन एलन मस्क की अगुआई में डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) यानी सरकारी दक्षता विभाग के जरिये बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। इसमें अनावश्यक नौकरशाही के आकार को घटाने से लेकर फिजूलखर्च रोकने के उपाय तलाशे जाएंगे। डीओजीई की इस पहल ने दुनिया भर में सरकारी मशीनरी के दायरे और उसकी प्रासंगिकता को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत भी ऐसे सवालों से अछूता नहीं है, लेकिन अगर इस पर गहराई से विचार करें तो क्या भारत में सरकारी खर्च को घटाया जाना आवश्यक है? इसका जवाब है-नहीं। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। अगर वर्ष 2022 के दौरान भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो यह जीडीपी का 28.62 प्रतिशत रहा। यह चीन (33.4 प्रतिशत), ब्राजील (46.38 प्रतिशत), अमेरिका (36.2 प्रतिशत) और फ्रांस (58.32 प्रतिशत) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। पूंजीगत व्यय में सड़क और राजमार्गों को ही लें तो उन पर किया जाने वाला खर्च बहुत गुणात्मक प्रभाव वाला होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सड़कों पर किया जाने वाला एक रुपये का खर्च समग्र अर्थव्यवस्था में ढाई रुपये के बराबर लाभ दिलाने वाला होता है। इससे कनेक्टिविटी की स्थिति सुधरती है। परिवहन लागत घटती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। हालांकि यह गुणात्मक प्रभाव पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाता है, क्योंकि यदि उसमें हीलाहवाली की जाती है तो फिर उसके अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से रहे। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बुनियादी ढांचे में न केवल मात्रात्मक, बल्कि गुणात्मक रूप से भी सुधार हो। इसके बावजूद, यह पूरी प्रक्रिया अभी प्रगति में ही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हों।

डीओजीई को लेकर भारत के दृष्टिकोण से यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है कि नियामकीय स्तर पर सुगमता कैसे स्थापित की जाए। ये नियामकीय बाधाएं ही आर्थिक वृद्धि में अवरोध बनती हैं। भारत के मामले में तो यह कोई दबी-छिपी बात नहीं है। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार ने नियामकीय बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें सुसंगत बनाने के हरसंभव प्रयास किए हैं। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ी है, जो ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग में भी झलकती है। फिर भी इस दिशा में बहुत किया जाना अभी शेष है। इन्हीं प्रयासों को और विस्तार देते हुए सरकार ने जन विश्वास अधिनियम, 2023 पारित कराया है। इस कानून के जरिये कई पुरातन प्रविधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त किया गया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस विधेयक के नए स्वरूप को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य नियमन के पहलुओं को तार्किक बनाते हुए व्यापक कारोबार हितैषी परिवेश तैयार करना है। एक फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट में नियामकीय तालमेल बेहतर बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा भी हुई है। इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में नियामकीय सुगमता एवं आर्थिक सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पुनः रेखांकित भी किया। अब सभी की नजरें उच्चस्तरीय समिति पर टिकी हैं। इस समिति को आखिर क्या करना चाहिए? वैसे तो अभी तक न तो इस समिति का औपचारिक खाका सामने रखा गया है और न ही उसके स्वरूप एवं सदस्यों के विषय में कुछ बताया गया है। ऐसे में, उसके लिए कुछ बिंदुओं को सामने रखना उपयोगी होगा कि उसे किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समिति को किस्तों में सुधार के बजाय निरंतर रूप से साहसिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो उसे नियामकीय मोर्चे पर कायम विसंगतियों एवं विरोधाभासों को दूर करना होगा। ऐसे कानून बनाने होंगे जो उद्यमों के अनुकूल हों। दांडिक प्रविधानों को सीमित करना होगा। संसदीय गतिरोधों का तोड़ निकालकर प्रक्रियाओं को गति देने वाले तौर-तरीके तलाशने होंगे। पुराने कानूनों को अनिश्चितकाल तक कायम रखने के बजाय सनसेट क्लाज का सहारा उपयोगी होगा। नियामकीय ढांचे की निरंतर समीक्षा और उसमें सुधार के सतत प्रयास भी आवश्यक होंगे। श्रम सुधारों के लिए भी कोई रूपरेखा तैयार करनी होगी। अनुपालन बोझ घटाने के उपाय भी तलाशने होंगे।

विधायी परिवर्तनों से इतर उच्चस्तरीय समिति को नियामकीय संस्थाओं की मनमानी और अप्रत्याशितता को भी नियंत्रित करना होगा। उसे नियामकीय अधिसूचनाओं के लिए एक नियत शेड्यूल बनाना होगा और उद्यमों को अप्रत्याशित एवं एकाएक किए जाने वाले परिवर्तनों की तपिश से बचाना होगा। निरीक्षण भी जोखिम आधारित ढांचे के आधार पर ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। स्व-नियमन और थर्ड पार्टी आडिट से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ उत्पीड़न एवं अक्षमताओं के लिए गुंजाइश खत्म करनी होगी। इस प्रकार के समन्वित प्रयासों से हमारे उद्यम लालफीताशाही के भंवर में फंसने के बजाय कारोबारी वृद्धि और नवाचार पर अपनी ऊर्जा एवं संसाधन लगाने में सक्षम हो सकेंगे।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

भगदड़ की घटनाओं से त्रस्त भारत

राजीव सचान

भगदड़ वहीं मचती है, जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है और भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं

भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि यहां के लोग भीड़ वाले स्थानों में बदइंतजामी के कारण रह-रह कर मरते रहें। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म पर भगदड़ मचने से 18 लोग मारे गए और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। इनमें अधिकांश वे थे, जो प्रयागराज जाने के लिए आए थे। इसके पहले महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से 30 लोग मारे गए थे। भगदड़ वहीं मचती है, जहां भीड़ के साथ अव्यवस्था भी होती है और भीड़ नियंत्रण के उपाय नाकाफी या नदारद होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण के उपाय नदारद थे। रेलवे की ओर से कितना भी कहा जाए कि ऐसा नहीं था, लेकिन सच यही है कि इसकी परवाह नहीं की गई कि रेल यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से यात्रा कर सकें। इसकी पुष्टि भगदड़ में मौतों के बाद रेलवे की ओर से किए गए इन उपायों से होती है कि अब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें निर्धारित प्लेटफार्म से जाएंगी, यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और इतनी से इतनी अवधि के बीच प्लेटफार्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? केवल यही कि हादसे के बाद होश आया। यदि ये सारे उपाय पहले कर लिए जाते तो 18 जिंदगियों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता था।

देश की राजधानी में प्रमुखतम रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के उपायों की अनदेखी और उसके चलते 18 यात्रियों की मौत से भी खराब बात यह रही कि हादसे के बाद अधिकारी भगदड़ मचने और उसमें यात्रियों के मारे जाने-घायल होने की बात छिपाने के जतन करते रहे। अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की सूचना नहीं है। इसी कारण इस पर यकीन करना कठिन है कि जांच सही तरह होगी और लापरवाह अधिकारी दंड के पात्र बनेंगे। महाकुंभ में भगदड़ से 30 श्रद्धालुओं की मौत की भी जांच हो रही है। जांच पुलिस भी कर रही है और न्यायिक आयोग भी। पता नहीं कि इन दोनों जांच से क्या सामने आएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महाकुंभ में भगदड़ के करीब 15 घंटे बाद यह बताया गया कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके उपरांत मृतकों की सूची और मृत्यु प्रमाणपत्र देने में भी देरी की खबरें आईं। इसके चलते विपक्षी नेताओं को यह आरोप लगाने का अवसर मिला कि महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा छिपाया जा रहा है। अपने देश में यह सदैव देखने को मिलता है कि सरकारी अधिकारी पहले तो किसी घटना-दुर्घटना की गंभीरता कम करके बताते हैं और फिर उसमें मारे गए लोगों का विवरण देने में। यह हमारी नौकरशाही की वह विचित्र प्रवृत्ति है, जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कारण उन जांच पर भी भरोसा नहीं होता, जिनमें अधिकारी ही अधिकारी की जांच करते हैं।

भगदड़ वाले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फाइल

जब भी कहीं भीड़ भरे स्थलों में कोई हादसा होता है और उसमें लोग मारे जाते हैं तो घटना की जांच करने-कराने वालों से यही सुनने को मिलता है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि भविष्य में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए? ऐसा केवल सुनने को ही मिलता है, क्योंकि बार-बार वैसे ही हादसे होते रहते हैं, जैसे पहले हो चुके होते हैं। कभी-कभी तो उन्हीं स्थलों पर हो जाते हैं, जहां पहले हो चुके होते हैं। इसका उदाहरण कुंभ भी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी। भगदड़ की घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो केवल जनहानि ही नहीं होती, बल्कि देश की बदनामी भी होती है। एक ऐसे समय जब देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बातों के साथ इसके लिए प्रयत्न भी हो रहे हैं, तब फिर सार्वजनिक स्थलों में भीड़ नियंत्रण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। हमारे नीति-नियंता इन उपायों से अनभिज्ञ नहीं और सच तो यह है कि भीड़ नियंत्रण के नियम-कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन मुश्किल से होता है।

अपने यहां नियम-कानूनों के उल्लंघन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कारण केवल यह नहीं कि लोगों को उनकी परवाह नहीं होती, बल्कि यह भी है कि शासन-प्रशासन के स्तर पर उनके अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता। प्रायः यह अनुपालन मनचाहे तरीके से होता है। बीते वर्ष 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की जांच के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें आयोजन की अनुमति मांगने वालों को तो भगदड़ का जिम्मेदार माना गया, लेकिन बाबा की कोई गलती नहीं पाई गई। उनका नाम एफआइआर तक में नहीं था। इसके विपरीत जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के समय थियेटर में भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी तो अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहना कठिन है कि एक जैसे मामले में अलग-अलग तरह की कार्रवाई में कौन उचित थी और कौन नहीं, लेकिन अपने देश में भगदड़ जनित घटनाओं में कार्रवाई होने या न होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे हादसों से जरूरी सबक सीखे जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मृग मरीचिका

मृग मरीचिका को मृगतृष्णा भी कहा गया है। इसका अर्थ है जीवन में उन भ्रामक आकर्षणों एवं इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहना, जो कभी पूरी होना संभव नहीं। मृग मरीचिका तमाम मिथ्या लालसाओं का आकर्षण उत्पन्न करती है। उनके लिए मनुष्य प्रयास भी करता है, लेकिन अंततः परिणाम शून्य ही रहता है। कारण यही कि वह भ्रामकता दिवास्वप्न होती है, जिसका कोई यथार्थ भावी अस्तित्व नहीं होता। क्षितिज के उदाहरण से मृग मरीचिका को सहज ही समझा जा सकता है। दूर से पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, किंतु उस छोर तक पहुंचने पर उस मिथ्या भ्रम की वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार होता है।

मनीषियों का मत है कि ऐसी भ्रामकता के आकर्षण में निरर्थक दौड़-भाग के बजाय निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए अपने मूल लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। यह सदैव याद रहे कि मनुष्य को ऐसी अनेकों मृग मरीचिकाओं ने अपने अंतहीन जंजाल में सम्मोहित कर रखा है, जिनका शमन और सृजन अबाध गति से सतत चलता रहता है। इसके परिणामस्वरूप इस राह में कुछ लालसाएं छूटती हैं तो बहुत कुछ नई जुड़ती रहती हैं। अतः उनके पीछे दौड़-भाग करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बदहवासी में अपनी अंतरात्मा में बैठे विवेक की शरण लेकर मन की निरंकुश चंचलता को नियंत्रित करने के लिए उद्यत रहना ही श्रेयस्कर होता है।

भ्रामक आकर्षण का संबंध लालसा एवं आकांक्षा जैसे सांसारिक विकारों से होने के कारण उम्र का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वृद्धावस्था में भी अक्सर तरुणाई की लालसा देखी जा सकती है। इसलिए मन की चंचलता पर विवेक की लगाम लगाए रखना ही मृग मरीचिकाओं से बचे रहने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

प्राकृतिक आपदाएं, नुकसान और चुनौतियां

सुधीर कुमार

प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका नहींजा सकता है, लेकिन सुदृढ़ प्रबंधन से इनके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है

केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से कुल 2,936 लोगों की मौत हो गई। इन आपदाओं के कारण केवल मानव संसाधन ही नहीं, अपितु बुनियादी ढांचे और कृषि का भी व्यापक नुकसान हुआ। वर्ष 2024 में आपदाओं से 3.63 लाख से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 14.24 लाख हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित हुई। आपदाओं की चपेट में आने से 61,826 मवेशी भी मारे गए। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती बारंबारता और उससे होने वाले नुकसान के मद्देनजर प्रभावी नीतियों और आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है।

गत वर्ष देश कई प्राकृतिक आपदाओं का साक्षी बना। चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं ने विभिन्न राज्यों में व्यापक क्षति पहुंचाई। मई में आए चक्रवात रेमल के कारण भीषण आंधी आई और भारी वर्षा हुई, जिससे बंगाल, मिजोरम, असम और मेघालय में लगभग तीन दर्जन लोगों की जान चली गई। वहीं जुलाई में केरल में हुई मूसलधार वर्षा के बाद भूस्खलन की भयावह घटना में 420 लोगों की मृत्यु हो गई। जबकि अगस्त-सितंबर में विजयवाड़ा में आई विनाशकारी बाढ़ ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली। वर्ष के अंत में आए फेंगल चक्रवात ने तमिलनाडु के 14 जिलों में अभूतपूर्व तबाही मचाई, जिससे डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हुए और 19 लोगों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश (408), मध्य प्रदेश (373), केरल (355), गुजरात (230) और महाराष्ट्र (206) शीर्ष पांच स्थानों पर रहे। इन आपदाओं के कारण न केवल बड़ी संख्या में मानव जीवन की क्षति हुई, बल्कि कृषि और अचल संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। प्राकृतिक आपदाओं का सीधा असर फसल उत्पादन, पशुधन और मत्स्य पालन पर पड़ता है। इससे लाखों छोटे किसान, चरवाहे, मछुआरे और वन-आश्रित समुदायों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा संकट में आ जाती है। इसमें सबसे अधिक चिंताजनक यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण 61,826 मवेशियों की मृत्यु हो गई। बेजुबान प्राणियों के पास आपदा के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता नहीं होती, जिससे वे आसानी से काल के गाल में समा जाते हैं। आपदाओं के दौरान पशुओं के लिए चारे, आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित होती हैं, जिससे स्थिति और भी विकट हो जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन सुदृढ़ प्रबंधन से इनके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। इसके लिए समय पर चेतावनी प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचे, राहत एवं पुनर्वास योजनाओं तथा सामुदायिक जागरूकता अभियानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

साझा प्रयासों से ही विकसित होगा देश

'विकसित भारत के लक्ष्य की बाधाएं' शीर्षक से लिखे आलेख में विवेक काटजू ने बताया है कि विकसित भारत का लक्ष्य एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन आवश्यक लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने इसमें विज्ञान तकनीक एवं एआइ के महत्व को भी दर्शाया। भारत का विकास केवल सरकार के प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी का 'विकसित भारत' का लक्ष्य 2047 तक, जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण है। यह लक्ष्य मात्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति तक विस्तृत है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कैसे अपनी शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में समग्र सुधार लाते हैं। शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाना चाहिए, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में निवेश करना सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से एक सशक्त आधार तैयार करना आवश्यक है। डिजिटल क्रांति, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ ने विश्व को नए युग में प्रवेश करा दिया है। भारत को भी इस क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करना होगा, ताकि हम वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए निजी क्षेत्र को अधिक शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि हम अपने संसाधनों के आधार पर नवाचारों को बढ़ावा दे सकें। भारत का विकास केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं हो सकता। यह एक साझा प्रयास होना चाहिए, जिसमें सभी नागरिक और अन्य क्षेत्र मिलकर काम करें। केवल ऐसे समन्वित प्रयास ही विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।

bhubaaman2020@gmail.com

परीक्षा का सही उद्देश्य

परीक्षा का उद्देश्य केवल अंकों की प्राप्ति नहीं, बल्कि मानसिक विकास, तार्किक सोच और आत्मविश्वास को परखना होना चाहिए। किंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा एक बोझिल प्रक्रिया बन चुकी है, जहां छात्रों को अंकों के आधार पर आंका जाता है, न कि उनकी मौलिकता और विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पर। प्रयागराज और वाराणसी जैसे शिक्षा केंद्रों में परीक्षा का तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि छात्र मानसिक अवसाद तक पहुंच रहे हैं। अभिभावक और शिक्षक भी परीक्षा को एक निर्णायक कसौटी मानते हैं, जिससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनता है। इस समस्या का मूल कारण पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली और समाज में परीक्षा को लेकर बनी अवधारणाएं हैं। परीक्षा केवल स्मरण शक्ति का परीक्षण बनकर रह गई है, जिससे विद्यार्थी की सृजनात्मकता और तार्किक क्षमता प्रभावित होती है। कोचिंग संस्थान और विद्यालय भी केवल परिणामोन्मुखी पढ़ाई पर बल देते हैं, जिससे परीक्षा भय का पर्याय बन जाती है। समाधान के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रणाली को अधिक समावेशी बनाया जाए। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर छात्रों की योग्यता निर्धारित करने के बजाय प्रायोगिक ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता और रचनात्मकता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें। यदि परीक्षा को भय के बजाय आत्म-मूल्यांकन का साधन बनाया जाए, तो यह छात्रों के संपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

महिलाओं का हो व्यापक सशक्तीकरण

महिला किसी भी पद पर विराजमान हो, मगर घर की जिम्मेदारी भी उन पर होती है। भले ही उन्हें कानूनी अधिकार हों लेकिन उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में भले ही महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ हो, लेकिन अभी भी स्थितियां पूरी तरह उनके अनुकूल नहीं बन पाई हैं। समाज के सोच में बदलाव के बिना उनका व्यापक सशक्तीकरण संभव नहीं।

मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

रेलवे स्टेशन पर भगदड़

भीड़ नियंत्रण जरूरी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से प्रशासनिक कमी तथा बेहतर भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता उजागर होती है। यह घटना त्रासद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ने राजधानी को झकझोर दिया है। शनिवार रात को स्टेशन पर हुई भयानक भगदड़ में पांच बच्चों समेत कम से कम 18 लोगों की जान गई तथा एक दर्जन से अधिक घायल हुए। यह त्रासदी 14 और 15 प्लेटफार्म को जोड़ने वाले फुट-ओवरब्रिज पर हुई जिसका कारण प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों पर चढ़ने के लिए यात्रियों की धक्कामुक्की थी। यह दुर्घटना कुप्रबंधन, ढांचागत कमियों तथा भीड़ नियंत्रण में कमियों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है जिसके कारण यह विभीषिका हुई। दुर्घटना का मुख्य कारण संभवत: अनेक आयाम लगते हैं जिनमें यात्रियों की बहुत अधिक भीड़, भ्रामक घोषणायें तथा खराब भीड़ प्रबंधन शामिल हैं। वर्तमान महाकुंभ मेले को देखते हुए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिससे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हर घंटे लगभग 1,500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। स्रोतों से संकेत मिलता है कि प्लेटफार्म बदलने की एक गलत घोषणा के कारण शायद यात्रियों में भ्रम पैदा हुआ।

इसके कारण जल्दबाजी में कुछ लोग फुट-ओवरब्रिज से उतरते समय सीढ़ियों से फिसल गए जिससे व्यापक अफरातफरी फैल गई। इसके अलावा जाने वाली ट्रेनों का प्रतीक्षा समय लंबा होने के कारण भी

अव्यवस्था फैली। हालांकि, भीड़ बहुत अधिक होने की चुनौती स्पष्ट थी पर खराब नियोजन और कुप्रबंधन ने इसे एक विभीषिका में बदल दिया। यात्रियों की बहुत अधिक भीड़ का अनुमान होने के बावजूद रेलवे अधिकारी लोगों के आवागमन पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने में विफल रहे। अतीत में हुई दुर्घटनाओं ने बहुत अधिक भीड़ के जोखिम उजागर किए थे, पर पैदल यात्रियों के आवागमन को सहज बनाना सुनिश्चित करने वाली कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की प्रतिक्रिया में काफी विलंब हुआ। भीड़ नियंत्रण की ज्यादा जीवन्त और सतर्क व्यवस्था भारी भीड़ का प्रबंधन कर सकती थी और इस दुर्घटना को व्यापक विभीषिका होने से रोक सकती थी। सवाल है कि क्या दुर्घटना रोकी जा सकती थी? निश्चित रूप से यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होने के समय अतिरिक्त रेलवे पुलिस व कर्मचारियों की तैनाती से ऐसी विभीषिकाओं से बचा जा सकता है। इसके साथ ही निगरानी कैमरों और एआई-आधारित भीड़ नियंत्रण व्यवस्थाओं से यात्रियों के घनत्व की तुरंत निगरानी की जा सकती है। इससे ऐसी दुर्घटना से बचा जा सकता था। इस भगदड़ से अब अधिकारियों की नींद टूट जानी चाहिए क्योंकि यह अपने किस्म की पहली त्रासदी नहीं है। यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए फुट-ओवरब्रिजों को चौड़ा करने और उनके विस्तार का काम प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। यात्रियों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा होने से रोकने के लिए स्पष्ट व सटीक डिजिटल बोर्ड लगाना भी बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही प्रति घंटे बेचे जाने वाले जनरल टिकटों की संख्या पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। खासकर महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के अवसर पर यह सतर्कता बरतनी चाहिए। इस दुर्घटना की जवाबदेही तय किए जाने के साथ ही ऐसे दीर्घकालीन उपायों और समस्या समाधानों पर जोर दिया जाना चाहिए जिनसे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। रेलवे अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ढांचागत संरचना, सुरक्षा तथा आपरेशनल प्रोटोकालों को अद्यतन बनाया जाए ताकि वे बहुत अधिक भीड़ वाली स्थितियों से आसानी से निपट सकें।

भारत का प्राकृतिक सौंदर्य

प्रकृति एक खुली किताब है जिसमें भारतीय वनों, जीवों व चट्टानों आदि का सौंदर्य अनेक कहानियां कहता है। इनसे भूमि, जीवन और समय के बीच गहन संबंध उजागर होते हैं।

बीकेपी सिन्हा अरविंद झा

लेखकगण भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

प्रकृति असंख्य जटिलताओं, अनन्त आश्चर्यों और रहस्यों से भरी है। वनों से होकर गुजरने पर प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को समझने और देखने का अवसर मिलता है जिससे अनेक छिपी हुई विस्तृत कहानियां सामने आती हैं। हर पेड़, पत्थर और जीव धरती के समृद्ध इतिहास में अपना योगदान करता है और अनेक परिवर्तनशील प्रक्रियायें उसे नया स्वरूप देती हैं। अपने वलयों से फूलों वाले पेड़ जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय परिवर्तन के हजारों सालों का रिकार्ड रखते हैं और बीतते समय के मौन साक्षी बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक निश्चित आयुवर्ग के पेड़ों की अनुपस्थिति उस समय जंगलों की आग का संकेत देती हैं। प्राकृतिक होने के बावजूद कभी-कभी जंगलों की आग विनाशकारी होती है जो चयनित रूप से छोटे पेड़ों को नष्ट करने तथा बड़े पेड़ों को बचाए रखने का काम करती है। भारत की परिस्थितिकी अत्यधिक विविधतापूर्ण है जिसमें तटीय क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी घाटियां तक शामिल हैं।

ये वनस्पतियों, जीवों तथा उनके परिवेश के बीच नाजुक संबंधों की कहानियां कहते हैं। यहां तक कि हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी भी अनेक आर्गेनिक तत्वों का मिश्रण होती है जो परिस्थितिकी को बनाने में योगदान करने वाले असंख्य जीवन व मरण के चक्र प्रदर्शित करती है। जमीन के उतार-चढ़ाव, खड़ी ढलानों और घाटियों तथा पहाड़ियों की उपस्थिति केवल भूगोल की दुर्घटनायें ही नहीं हैं। वे लाखों सालों से भौगोलिक शक्तियों के फिंगरप्रिंट जैसे हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वत ऐसे भौगोलिक परिवर्तनों की कथा कहते हैं। इससे वे गतिशील प्रक्रियायें सामने आती हैं जो किसी राष्ट्र की भू-दृश्यावली और उसकी जैव-विविधता को स्वरूप देती हैं। जंगल एक असीम कक्षा की तरह हैं जहां प्रकृति हर कदम पर हमें सबक सिखाती है।

लेकिन वनों का रहस्य समझने के लिए इन पर सरसरी नजर डालना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक वैचारिक दृष्टिकोण तथा थोड़ा आराम से हमारे चारों ओर के परिवेश को देखने और समझने की इच्छाशक्ति जरूरी हो जाती है। जंगल से हो कर गुजरने पर आप देखेंगे कि जमीन पत्तियों, टहनियों तथा गल रहे आर्गेनिक तत्वों की मोटी पर्त से भरी रहती है। 'लीफ लिटर' कही जाने वाली यह पर्त उस पोषण चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो अनेक छोटे जीवों को पोषण देती है। वनस्पतियों के प्रकार और उनके वितरण से क्षेत्र के मौसम, मिट्टी की स्थितियों तथा पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारियां मिलती हैं। पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर भारत की तरह हरे-भरे वर्षावनों वाले क्षेत्र प्रचुर बरसात का संकेत देते हैं। इस इकोसिस्टम में अनेक प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें बहुत ऊंचे पेड़ों के साथ नीचे छोटे-छोटे पौधे भी शामिल हैं जो इस नम तथा जल से समृद्ध परिवेश में फलते-फूलते हैं।

इन घनी वनस्पतियों से अनेक प्रकार की जीव प्रजातियों को आश्रय मिलता है जो क्षेत्र की जैव-विविधता तथा परिस्थितिकी स्थायित्व में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके एकदम उलट राजस्थान के सूखे रेगिस्तान एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं जहां जीवन को अपरिहार्य रूप से न्यूनतम जल की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल का जीवित रहना सीखना होता है। यह वनस्पति बहुत कम, पर अत्यधिक विशिष्ट होती है। यहां परिदृश्य पर कैक्टस, अकेसिया, और कांटेदार झाड़ियों का वर्चस्व दिखता है। इन प्रजातियों ने अपने भीतर विशिष्ट परिवर्तन किए हैं जिनमें जल-भंडारण करने वाले ऊतक तथा गहरी-गहरी जड़ें शामिल हैं। इससे वे जल संरक्षण के साथ पानी तक अपनी पहुंच बढ़ाते हैं तथा हर कठोर परिस्थिति में अपना जीवन सुनिश्चित करते हैं।

खास क्षेत्रों में विशिष्ट प्रजातियों पर गौर करने से पौधों और उनके परिवेश के बीच गहन संबंध उजागर होते हैं। उदाहरणार्थ, बाढ़ के मैदानों में साइकामोर, गूलर व ऐश गुर्जन जैसे पेड़ पाए जाते हैं जो उपजाऊ व नम स्थितियों में रहते हैं जहां जल और पोषक तत्व एकत्र हो जाते हैं। दूसरी ओर हार्डी कैज्यूराइना तटीय परिवेश के लिए उपयुक्त है जहां खारी परिस्थितियां अनेक प्रजातियों के लिए चुनौती पेश करती हैं। इसी प्रकार नदियों के तटों पर जामुन और करंज जैसे पेड़ फलते-फूलते हैं जो लगातार नम स्थितियों को पसंद करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पेड़ कैसे स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप स्वयं को ढालते हैं। पेड़ों द्वारा पर्यावरणीय स्थितियों की अभिव्यक्ति की तरह चट्टानों के प्रकार भी भौगोलिक इतिहास व प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति देते हैं।

अक्सर समुद्री फासिलों जैसे शेल, कोरल और मछलियों से समृद्ध सेडीमेंट्री चट्टानें यह संकेत करती हैं कि एक समय यह क्षेत्र पानी के नीचे डूबा हुआ था। इन चट्टानों पर लहरों के निशान या 'मड क्रैक' पाए जाते हैं जिनसे प्राचीन जल भंडारों का पता चलता है। उदाहरणार्थ, फासिलों से समृद्ध शिवालिक पहाड़ियां पूर्व-ऐतिहासिक युग की झलक दिखाती हैं। इनमें उस युग में पाए जाने वाले जीवों के निशान मिलते हैं। इन चट्टानों में जमे तत्वों से उस युग में मौसमी स्थितियों, जैसे सूखे या भारी बरसात के समय का भी पता चलता है। इसी प्रकार मैग्मा के ठंडे होने के बाद बनी इग्नियस चट्टानें क्षेत्र के ज्वालामुखीय इतिहास को प्रकट करती हैं, जबकि मैटामार्फिक चट्टानें धरती की गहराई में हुए गहन परिवर्तनों का संकेत देती हैं। इस प्रकार सतह के नीचे के भूगर्भ को समझना भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो जमीन को स्वरूप देता है और मृदा इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तनों के कारण चट्टानों में गुफायें तथा पत्थरों के स्तंभ बन जाते हैं। यहां मृदा क्षरीय तथा कैल्शियम से समृद्ध होती है। इसके उलट ग्रेनाइट वाले क्षेत्रों में चट्टानें टूट कर अम्लीय मृदा बनाती है जो अक्सर खराब जलनिकास के कारण दलदली क्षेत्रों में बदल जाती हैं।

पवित्र गंगा नदी उत्तर भारत में 2,500 किलोमीटर बहती है और अनेक जलीय व जमीन पर रहने वाली प्रजातियों को जीवन प्रदान करती है। इसके जल से खेतों की सिंचाई होती है जो लाखों लोगों को भोजन देते हैं। इसके साथ ही यह विशाल जनसंख्या के लिए पेयजल का साधन है। इसी प्रकार तिब्बती हिमालय से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत से गुजरती हुई बाढ़ के मैदानों की परिस्थितिकी को बनाए रखती है तथा कृषि व पनबिजली के लिए जल उपलब्ध कराती है। अक्सर 'दक्षिण गंगा' कही जाने वाली गोदावरी मध्य भारत में बहती है, देश की एक सबसे बड़ी नदी घाटी को पोषण देती है तथा विविधतापूर्ण परिस्थितिकियों को बनाए रखती है। भारत के वेटलैंड, जैसे सुंदरबन में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रूव वन पाए जाते हैं। यह गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा में फैली है जो बंगाल टाइगर्स, घड़ियालों, चिड़ियों व वन्यजीवों का स्वर्ग है। इसके मैंग्रूव वन तटरेखा की बाढ़ और तूफान से रक्षा करते हैं। प्रत्येक जीव अपनी विशिष्ट शरीर रचना तथा व्यवहार से अलग छाप छोड़ता है। उदाहरणार्थ, अनेक प्रकार की बिल्लियां अपने पंजों के निशान छोड़ती हैं। इसके उलट खरगोश अपने आने जाने के रास्तों पर बिल्कुल अलग किस्म के निशान छोड़ते हैं। इन संकेतों को समझने से वन्यजीवों के व्यवहार और परिस्थितिकी की उनकी पसंद की जानकारी मिलती है। हमारी तरह जानवरों को भी वे स्थान पसंद होते हैं जहां उनको जीवन के लिए आवश्यक भोजन, पानी और शरण मिलती है।

खुले मैदानों में पेड़ों के झुंड अक्सर जल स्रोत, जैसे झील या तालाब का संकेत देते हैं जो वन्यजीवों के लिए आकर्षक स्थल बन जाते हैं। समग्र रूप से देखें तो जंगल हमें अपने विवेक को समझने, अपनी दृढ़ता से सीखने तथा अपनी विरासत से सहयोग करने को आमंत्रित करते हैं। जंगलों के विभिन्न तत्वों से समुचित सबक सीख कर हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह अमूल्य पुस्तकालय आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा खुला रहे।

कुम्भ से गांधीजी को प्रेरणा

राजदीप पाठक

(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

कुम्भ मेले के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1915 में उस समय सामने आया जब गांधीजी ने 21 साल अफ्रीका में रहने के बाद वापसी पर हरिद्वार की यात्रा की। गांधीजी के राजनीतिक प्रेरणास्रोत गोपाल कृष्ण गांधी ने उनको रणनीतियां बनाने और स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक देने से पहले भारत का सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य समझने के लिए राष्ट्रव्यापी यात्रा की सलाह दी थी। इस यात्रा के दौरान गांधीजी कुंभ मेले गए थे जहां उनका मुख्य उद्देश्य ऋषिकेश में महात्मा मुंशीराम के गुरुकुल में जा कर 'भारत सेवक समाज' की गतिविधियों का अध्ययन करना था। हालांकि, स्वच्छता और सफाई जैसे विभिन्न विषयों तथा खासकर सामुदायिक सामंजस्य पर गांधीजी के विचार अलग थे। गांधीजी सामुदायिक सामंजस्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने इसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में भी किया है। लेकिन हरिद्वार कुंभ मेले से उनका संक्षिप्त राजनीतिक संपर्क देश में सामुदायिक विभाजन पाटने की ओर संकेत करता है जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के सचेतन लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण था। गांधीजी कुंभ मेले में एकत्रित भीड़, बल्कि वहां पैदा अव्यवस्था, अंधविश्वास तथा स्वच्छता की कमी से भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने स्वच्छता की भयानक अनदेखी का उल्लेख करते हुए लिखा कि इससे आयोजन की पवित्रता प्रभावित होती है। एक दशक बाद अपने भाषणों में उन्होंने दु:ख प्रकट करते हुए कहा, 'पवित्रता के प्रतीक गंगा के तट मानव मल से गंदे तथा लापरवाही का शिकार थे।' 1947 में कुंभ के अनुभव की याद करते हुए गांधीजी ने टिप्पणी की थी, 'हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक आयोजन स्वच्छता एवं सफाई के पवित्र स्थल बनें और वे बीमारी तथा अव्यवस्था पैदा करने का आधार न हों।'

हरिद्वार में ही मोहनदास करमचंद गांधी ने पहले भारत की जनता पर दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए विनम्र प्रयासों का गहरा प्रभाव अनुभव किया था। अपने अनुभव को अभिव्यक्ति देते हुए उन्होंने 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' पुस्तक में लिखा था, 'मेरा मुख्य काम टेंट में बैठे रहना, मिलने आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शन देना तथा उनसे चर्चा करना था। इससे मुझे एक मिनट का भी समय नहीं मिलता था कि मैं अपने बारे में सोच सकूं। मैं इन दर्शनार्थियों के साथ ही स्नान करने घाट पर जाता था और भोजन करते समय भी वे मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार हरिद्वार में मैंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी विनम्र सेवाओं का गहरा प्रभाव अनुभव किया जिसका प्रसार पूरे भारत में हो गया था।' हरिद्वार के कुंभ मेले ने महात्मा गांधी के उद्देश्य को स्वरूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई जिससे अंतत: वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।

यह उनकी इस समझ पर आधारित था कि भारत की जनता उनको न केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देखती थी जो राष्ट्र के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम थे। हरिद्वार के कुंभ मेले में हुए इस अनुभव ने गांधीजी में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा की। इससे उनको अपने सेवा कार्य और सत्य मार्ग का विस्तार कर भारतीय स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्य से जोड़ने की प्रेरणा मिली। इसका परिणाम चंपारन में 1917 के पहले अहिंसक सत्याग्रह के रूप में सामने आया। कुंभ मेले में मिले असाधारण प्रेम और लगाव से सामूहिक कार्रवाई में गांधीजी का विश्वास और मजबूत हुआ। इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन खपा देने की उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। यह तथ्य भी प्रेरणादायक और उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी की हरिद्वार यात्रा तथा राजनीति में उनका प्रवेश इतिहास के एक और उल्लेखनीय क्षण से जुड़ा है। कुंभ मेले में ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ था। अप्रैल, 1915 में हरिद्वार कुंभ के समय पैदा आध्यात्मिक ज्वार के समय गांधीजी की मुलाकात अन्य महानुभावों से हुई। इनमें स्वामी श्रृद्धानंद, पंडित मदनमोहन मालवीय तथा 'सर्वदेशक हिंदू सभा' के उद्घाटन सम्मेलन में एकत्र अन्य महानुभाव शामिल थे। यह भारत की सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय था।

कुंभ मेले में गांधीजी की सहभागिता की जानकारी ब्रिटिश खुफिया विभाग को भी थी जिसने उनकी यात्रा के रिकार्ड तैयार किए थे। आज ये रिकार्ड क्षेत्रीय राज्य संग्रहालयों में उपलब्ध हैं। औपनिवेशिक काल ने कुंभ मेले में एक नया आयाम जोड़ा था। यूरोपीय प्रेक्षकों ने इसके महत्व को स्वीकार कर दस्तावेज तैयार किए तथा मूल्यवान ऐतिहासिक संदर्भ जोड़े। तीर्थयात्रियों की विशाल संख्या तथा उनकी विविधता से अभिभूत अंग्रेजों ने कुंभ आयोजनों के विस्तृत रिकार्ड तैयार किए जो महाकुंभ मेले के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के एक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप के अच्छी तरह दस्तावेजीकृत लेखन से महाकुंभ मेले के बारे में विस्तृत और गहन जानकारियां मिलती हैं। इस संबंध में 'द संडे गार्जियन' में प्रकाशित लेख 'बियांड फेथ: हाऊ कुंभ मेला रिशेप्स द कोर्स आफ हिस्ट्री' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुंभ मेले की भूमिका रेखांकित की गई है।

इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित 1920 के ब्रिटिश खुफिया विभाग के दस्तावेज से पता चलता है कि 1918 में मेले के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में राजनीतिक सुधारों के पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर मांग की गई थी कि पंचायतों, स्थाई बस्तियों तथा आसामियों की सुरक्षा के दम उठाए जाएं। इसमें 'यूपी पीजेन्ट्स असोसियेशन' की स्थापना की गई थी। पंडित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में इस असोसियेशन की 50 शाखायें बनी थीं जिन्होंने अनेक किसानों के बीच एकता स्थापित कर जमींदारों के प्रभुत्व का विरोध किया था। 'द संडे गार्जियन' ने भारत में स्वतंत्रता-पश्चात लोकतंत्र को स्वरूप देने में भी कुंभ मेले की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की थी जो खासकर आपातकाल के समय सामने आई थी। इस कुंभ में साधू समाज के समर्थन से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को काफी गति मिली थी। 'धर्म संसद' तथा 'साधू सम्मेलन' जैसे आयोजनों ने हिंदी पट्टी में जनता पार्टी को व्यापक समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 'महाकुंभ मेले' ने आध्यात्मिक आयोजन की अपनी सीमायें पार करते हुए पवित्र और पंथनिरपेक्ष विचारों के सम्मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने जहां गहरे आत्मावलोकन व भक्ति का 'स्पेस' प्रदान किया है, वहीं इसने उन सामाजिक-राजनीतिक धाराओं को अभिव्यक्ति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो भारतीय समाज को स्वरूप दे रही हैं।

महाकुंभ आयोजन की यह अनादि व असीम प्रकृति लगातार विकसित हो रही है तथा आध्यात्मिक व भौतिक आयामों को जोड़ रही है। इस प्रकार कुंभ मेला भारत की महत्वपूर्ण व निरंतर व्याप्त सांस्कृतिक विरासत का शक्तिशाली दस्तावेज बन गया है।

आप की बात

भाषा से खिलवाड़

20-25 वर्ष पहले कुछ लोग आधी अधूरी ही सही, अंग्रेजी बोलकर नहीं बोल सकने वालों को नीचा दिखाते थे। अब प्राथमिक कक्षाओं से ही अंग्रेजी पढ़ाए जाने और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का प्रचलन होने पर जब कई लोग अंग्रेजी बोलने लगे तो स्वयं को अन्य से बेहतर दिखने के लिए भाषा से खिलवाड़ का नया तरीका सामने आया। अब अंग्रेजी के किसी शब्द का सामान्यत: जो उच्चारण अधिकतर लोगों द्वारा किया जाता है, खिलवाड़ करने वाले उस से मिलता जुलता भिन्न उच्चारण करते हैं और यह प्रचारित करते हैं कि जो वे उच्चारित करते हैं, वही असली अंग्रेजी है। जब वह उच्चारण भी कई लोग करने लग जाते हैं तो भाषा से खिलवाड़ करने वाले फिर कोई नया उच्चारण करने लग जाते हैं। हम कई दशकों से जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम का उच्चारण अमेजन है। संभवत: ऑनलाइन कंपनी अमेजन का नाम उसी आधार पर रखा गया। लगभग एक दशक पूर्व उसका उच्चारण एमेजॉन किया जाने लगा जो अब अधिकतर लोग बोलने लगे हैं। तो पिछले एक वर्ष में इस शब्द के दो नए उच्चारण एमजॉन तथा एमाजॉन और सामने आए। स्वयं को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए भाषा को बिगाड़कर उसी को सही दिखाकर खिलवाड़ करना बहुत ही तुच्छ मानसिकता का परिचायक है।

– **ललित दुबे,** रतलाम

संवेदनहीन नेता

ये कैसे राजनीतिक हिन्दुस्तानी हैं। जो सर्वधर्म समभाव व धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं. जिनके अंतर्मन कुछ और बाह्यमन कुछ. माना कि राजनीतिक/सियासी डिप्लोमेट होते हैं। पर इतने गिरे हुए विचारों के होते हैं ये पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है। वोटों की राजनीति के स्वार्थी स्वर इन्हें किस तरह के स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं समझ से परे हैं. कभी ये राम मंदिर की आलोचना करते हैं तो कभी आस्था से परिपूर्ण कुम्भ की। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने पूरे देश की आस्था और विश्वास के केंद्र राम मंदिर की विशाल/भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना ही नहीं की बल्कि वहां उस समय जाने से भी परहेज किया. समाजवादी व अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राजनीतिक भड़ास सत्ता पर निकाली. अभी देश के विशाल ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रह रहे भारतवासियों की आस्था के महाकुम्भ पर आलोचना करने से ये स्वार्थी राजनीतिक चूक नहीं रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने धार्मिक कुम्भ मेले के लिए कहा कि कुम्भ का क्या मतलब है ये सब फालतू कुम्भ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी कह रही है कि ये कुम्भ नहीं बल्कि ये मृत्यु कुम्भ है। राजनीतिज्ञों की इस तरह की कटु वाणी क्या आस्था और विश्वास के श्रद्धालुओं के हृदय को चोट नहीं पहुंचाएगी।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

साईकिल की घटती लोकप्रियता

एक दौर था जब साइकिल की सवारी शान की सवारी हुआ करती थी। गांव से लेकर शहर तक की दौड़ पूरा किया करती थी शायद तब विकास को पंख नहीं लगे थे । मानव ने अब तक सैकड़ों आविष्कार किये हैं। तकनीकी उन्नति ने हमें मोटर वाहन का विकल्प दिया मगर साइकिल जैसा प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाये उसके समानांतर चलने वाला आविष्कार कोई नहीं हुआ। अब छोटे से छोटे काम के लिए भी विशेषकर अपने देश में जिस पर भी मोटर वाहन उपलब्ध है वो उसी का उपयोग करना पसंद करता है। अब साइकिल शान की सवारी नहीं रही अब वो गरीबी का पर्याय की श्रेणी में आ गई है । प्रकृति को शनैः शनैः हो रहे आघात से ज्यादा हमें अपना पल पल कीमती लगता है। वर्तमान युवा पीढ़ी में साइकिल को निम्न स्तर का समझा जाने लगा है जो चिंताजनक और विचारणीय है। साइकिल को खत्म होती लोकप्रियता को रोकने के लिए हमें नीदरलैण्ड जैसे देश से प्रेरणा लेनी चाहिए जहाँ आमजन से लेकर प्रधानमंत्री तक साइकिल की सवारी करना पसंद करते हैं। अगर हम अपने देश में साइकिल की लोकप्रियता को फिर से बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही जागरूकता फैलानी होगी अपने पारंपरिक और सुलभ साधनों की कद्र करनी होगी, ताकि हम न सिर्फ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान दे सकें।

– **नितिन रावत**, फ़िरोजाबाद

हादसे की वजह भीड़

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन की व्यवस्था में हुई चुक की सजा महाकुंभ श्रद्धालुओं को? जान देकर चुकानी पड़ी है। हादसे की प्रमुख वजह स्टेशन पर जरूरत से ज्यादा भीड़ होना था। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो दुर्घटना के समय स्टेशन पर मौजूद लोगों की संख्या ट्रेन की क्षमता से कई गुना अधिक थी। इसके बावजूद सुरक्षा की बजाय टिकटों की बिक्री जारी रखना प्रशासन की गंभीर चूक को दर्शाता है। अगर प्रबंधन ने भीड़ का सही-सही आंकलन करके अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए होते, तो यह हादसा रोका जा सकता था। बेहतर व्यवस्था के लिए टिकटों की संख्या को सीमित करना, प्लेटफार्म पर प्रवेश के लिए कड़ी निगरानी और समय-समय पर भीड़ प्रबंधन की समीक्षा भी जरूरी थी। सुरक्षा उपायों की अनदेखी और समुचित व्यवस्थाओं का अभाव इस दुर्घटना की एक बड़ी वजह रही। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की असफलता को उजागर कर दिया है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे को अपने प्रबंधन में सुधार लाना होगा।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।